

प्रगति के बढ़ते चरण

संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था का
गौरवपूर्ण इतिहास

(सचित्र)

अनुवादक
कृष्णचन्द्र

1964

आत्माराम एण्ड संस
दिल्ली-6

PRAGATI KE BADHTE CHARAN

(Hindi edition of *The Permanent Frontiers*)

By the Staff of Institute of Economic Affairs

New York University

Translated by

Krishna Chandra

Rs 3 75

Copyright 1961 © Institute of Economic Affairs, New York

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक

आत्माराम एण्ड सस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-३

शाखाएँ

हौज खास, नई दिल्ली

चौडा रास्ता, जयपुर

विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़

महानगर, लखनऊ-६

रामकोट, हैदराबाद

मूल्य : तीन रुपया पचहत्तर पैसे

हिन्दी संस्करण 1964

मुद्रक

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस

दिल्ली

प्रकाशक का निवेदन

यूरोप से जब पहले-पहल लोग नई दुनिया के आवागमन के लिए गए थे, तब उन्होंने वहाँ जीवन के अपरिहार्य कष्टों और विपत्तियों की कोई परवाह नहीं की थी। पुरानी दुनिया के बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन यापन कर और सतत् रूप से प्रगति कर अपने भविष्य का नव-निर्माण करने की अदम्य आकांक्षा उन्हें निरन्तर नये-नये क्षेत्रों में आगे लिये जा रही थी।

इस भौगोलिक सीमा का एक दिन अन्त हो गया, किन्तु बराबर प्रगति करते जाने की साहसी प्रवृत्ति अमेरिकन स्वभाव का अंग बन गई। इसीलिए अपने इतिहास के पिछले चार सौ वर्षों में अमेरिकन लोगो ने भौगोलिक दृष्टि से ही नित्य नये क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया, अर्थ-व्यवस्था सामाजिक प्रणाली और राजनीति के भी नये-नये क्षेत्रों में वे नित्य प्रवेश करते रहे हैं। उनकी हर पीढ़ी ने भविष्य की चुनौती को खम ठोककर स्वीकार किया और अपने सामने पड़े अधूरे कामों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए नई मजिल और नया क्षितिज भी खोल दिया।

प्रगति की इस अविच्छिन्न धारा का ही यह परिणाम है कि आज सयुक्त राज्य अमेरिका ससार का सबसे समृद्ध देश है। आज उसके सामने देशवासियों के अभावों को पूरा करने की समस्या नहीं है, वरन् उनके पूर्ण जीवन को पूर्णतर बनाने की समस्या है।

भारत और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों आज ससार के दो महानतम लोकतन्त्रीय देश हैं। दोनों स्वतन्त्र लोकतन्त्र की पद्धति पर चलकर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत जिन कठिनाइयों और समस्याओं में से गुजर रहा है, प्रायः उन सबमें से सयुक्त राज्य पिछले चार सौ वर्षों के इतिहास में गुजर चुका है। दोनों देशों के आर्थिक विकास के इतिहास को बहुत कुछ एक ही धरातल पर रखा जा सकता है। अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था का यह इतिहास, इस दृष्टि से पाठकों को देश की इन समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता दे सकता है।

भूमिका

हमारी इतिहास की पुस्तको में अमेरिका की उन्नति के लिए अमेरिकन लोगो की नये-नये क्षेत्रो में प्रवेश की साहसी वृत्ति की विरासत को आम तौर पर जितना श्रेय दिया जाता है, वास्तव में वह उससे अधिक श्रेय की अविकारिणी है। संयुक्त राज्य के स्कूलों में हर लड़के-लड़की को बताया जाता है कि अमेरिकन लोग आजादी से प्यार करते हैं, स्वतन्त्र वृत्ति को मूल्यवान् समझते हैं, व्यक्तिगत उपक्रम और उद्यम को महत्त्व देते हैं और आम तौर पर एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयत्न करते हैं जिसमें प्रतिभाशाली लोग बिना किसी बन्धन के चाहे जहाँ जा सकते हैं—सिर्फ इसलिए कि हमारे इतिहास के चार सौ प्रारम्भिक निर्माणात्मक वर्षों में नये नये गैर-आबाद क्षेत्रों को आबाद करने की साहसपूर्ण प्रवृत्ति प्रबल रही है। यह सब सच अवश्य है किन्तु इसमें नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश की साहसी वृत्ति के एक अंग के लिए श्रेय का बहुत अधिक दावा किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में विद्यमान इस प्रवृत्ति को उतना महत्त्व नहीं दिया गया।

यदि केवल भौगोलिक दृष्टि से नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश की प्रवृत्ति ही अमेरिका के महान् अद्वितीय राष्ट्रीय चरित्र-प्रेरणा-स्रोत होती तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता कि उन्नीसवीं शताब्दी में नये भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश के अवसर समाप्त हो जाने के बाद उसका पतन प्रारम्भ हो गया होगा।

लेकिन नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश की उद्यमी वृत्ति को जब भौगोलिक जगत् में अपनी चरितार्थता का अवसर मिलना बन्द हो गया, तब उसे मानसिक जगत् के नये नये क्षेत्रों में प्रवेश के द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर अवसर मिलने लगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि अमेरिकन लोगो में अभिनव क्षेत्रों में प्रवेश की साहसपूर्ण वृत्ति स्थायी रूप से विद्यमान है तो उससे हमारा अभिप्राय यही होता है कि हर पीढ़ी के मामले में कुछ ऐसे अचूरे काम होते हैं जिन्हें उसे पूरा करना पड़ता है। संयुक्त राज्य सिर्फ इसलिए

महान् राष्ट्र नहीं बना कि उसकी प्रारम्भिक परिस्थितियों ने उसे अत्यधिक !
सर्वयोग्य और मूल्यवान् परम्पराएँ प्रदान की हैं, और सिर्फ इतने से ही वह
भविष्य में भी महान् राष्ट्र नहीं बना रह सकेगा। वास्तव में अतीत की
फसलों के बीज को वर्तमान परिस्थितियों की मिट्टी में बोने की स्थायी क्षमता
ही संयुक्त राज्य को अविच्छिन्न रूप से महानता के साधन प्रदान करती
रही है।

यह बात हमारी पुरानी प्रथाओं और प्रणालियों की परिवर्तनशीलता
और अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के हमारे प्रयत्नों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती
है। हमारे देश में एक ओर अतीत की विरासत और उसका अविच्छिन्न
सातत्य विद्यमान है और दूसरी ओर आगे प्रगति करने की अटूट आकांक्षा
भी कायम है। इसमें सन्देह नहीं कि इस अविच्छिन्न प्रक्रिया में कोई क्रान्ति-
कारीपन नहीं है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि वह आगे बढ़ने की
आकांक्षा को रोकती या पथभ्रष्ट नहीं करती।

पहले-पहल अधिवासियों ने अमेरिका में आकर यहाँ के जंगलों को
काटने के लिए जो कुल्हाड़ा चलाया उसका वार कोई ऐसा क्रान्तिकारी वार
नहीं था कि उसने रातों-रात जंगल में मगल कर दिया, सूने वन प्रदेश को
मकानों के भुरमुटों में परिणत कर दिया, खाली जमीन को खेतों में बदल
दिया और विशाल औद्योगिक कारखाने खड़े कर दिये। यह सारा परिवर्तन
आहिस्ता-आहिस्ता हुआ और वह इसलिए हो सका, क्योंकि जहाँ-कहीं कोई
नया क्षेत्र दिखाई पड़ा या दिखाई पड़ सकता है, अमेरिकन लोग खिचकर
उसकी ओर चले जाते हैं।

अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को पढ़ने वाला कोई
भी व्यक्ति यह अनुभव किये बिना नहीं रहेगा कि नाजुक क्षणों में जैसे ही
अमेरिकनो को कोई नया क्षेत्र दिखाई पड़ा, उन्होंने तत्काल ही उसमें प्रवेश
करने और उसे खोजने का उद्योग किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज
इस बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है कि राष्ट्र के जीवन में नये मोड़
आने पर अमेरिका के आम लोग क्या महसूस करते और कहते थे। किन्तु उन
लोगों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं जो अपने जमाने में किसी क्षेत्र में
नेतृत्व करते थे। उनकी उक्तियों और कामों से हमें पुरानी परम्परा का नये

परिवर्तन के साथ गठजोड़ करने वाली विकास की प्रक्रिया का एक सिल-मिलेवार विवरण मिलता है।

टामस पेन का स्वतन्त्रेच्छावाद, सेम्युअल ऐडम्स का जनता की इच्छा के सम्मान पर बल, जार्ज वाशिंगटन की उद्देश्य की पवित्रता, बेन फ्रैंकलिन की विशिष्ट अमेरिकन विचक्षणता, टामस जैफर्सन की सामन्तवर्गीय दुनियादारी, अलेग्जेंडर हेमिल्टन का रचनात्मक यथार्थवाद, ऐड्रू जैक्सन का पाँपुलिस्ट पार्टी की नीतियों का सम्मिश्रण (पाँपुलिस्ट पार्टी अमेरिका में 1892 में बनी थी और रेल-परिवहन आदि पर सरकार के स्वामित्व और क्रमिक आय-कर आदि की समर्थक थी), अब्राहम लिंकन की आत्मीयतापूर्ण और कर्मनिष्ठ बुद्धिमत्ता, थ्योडोर रूजवेल्ट की गतिमान् अनुक्रियाशीलता, वुडरो विल्सन की व्यापक दूरदर्शिता, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की साहसपूर्ण प्रयोगवादी वृत्ति, ड्वाइट आइसनहोवर की सन्तुलन और उत्तरदायित्व की भावना—इन सब ने ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्हीं के समान काम करने वाले अन्य लोगों के कार्य-कलापो ने भी अपने जमाने में नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश करने की साहसी वृत्ति और प्रगति के चरणों को आगे बढ़ाने में योग दिया। और अब 1960 के दशक के प्रारम्भ में राष्ट्रपति कैंनेडी ने नवीन क्षेत्रों में प्रवेश की चुनौती का सामना करने के लिए जो आह्वान किया है, वह भी सिलमिलेवार हुई इस प्रगति की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप ही है।

इस प्रकार वर्तमान की सीमाओं के उस पार नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश का आह्वान अमेरिकन लोगों के लिए एक स्थायी, किन्तु साथ ही परिवर्तनशील चुनौती बना हुआ है। हमें आशा है कि संयुक्त राज्य के इस आर्थिक इतिहास में हम नये-नये भौगोलिक और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश के द्वारा हुए राष्ट्र के आर्थिक विकास का विवरण दे सकेंगे और यह बता सकेंगे कि बाधाओं को अमेरिकन लोगों ने किस प्रकार अपने लिए उन्नति के नये अवसरों में परिणत कर दिया।

विषय-सूची

पहला भाग

महाद्वीप की खोज से लोकप्रिय जनतंत्र तक

अन्वेषण का युग	...	3
नई दुनिया की स्थापना		11
उपनिवेश एकता की ओर	.	19
क्रान्ति और स्वतन्त्रता	...	27
नया राष्ट्र	.	36
जैफर्सन काल	•	45
सद्भावनाओं का युग	.	55
लोकप्रिय जनतन्त्र का उदय	..	63

दूसरा भाग

युवा राष्ट्र का संघर्ष

पश्चिम की ओर कूच	..	73
गृह-युद्ध से पूर्व दक्षिण की स्थिति	...	82
अनामो से एण्मेमटोजम तक	..	91
पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान	...	101
नये भूमि-क्षेत्रों में प्रवेश का अन्त	..	110
बड़े पैमाने पर उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था की चुनौती	..	118
महान् व्यवसायी	...	126
रुधिर का युग	...	135
संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय पर	...	145

तीसरा भाग

शक्ति और उत्तरदायित्व

विश्व-युद्ध का प्रभाव	...	155
पुन सामान्य स्थिति की ओर	..	163
गेयर बाजार टूटा		172
मन्दी के प्रारम्भिक वर्ष	.	182
नई नीति		192
दूसरे विश्व-युद्ध-काल की अर्थ-व्यवस्था		204
शान्ति और उसका परिणाम	"	214
आइसनहोवर काल		225
युद्धोत्तर काल की समीक्षा		234
नये युग की चुनौती		242

पहला भाग

महाद्वीप की खोज से लोकप्रिय जनतंत्र तक

अन्वेषण का युग

मानव-विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार अमेरिकन महाद्वीप अब से कोई 25,000 से 40,000 वर्ष पूर्व आबाद हुआ। उनका खयाल है कि सबसे पहले मगोलिया के गोबी मरुस्थल के लोग बेरिंग स्थल डमरूमध्य से होकर अलास्का में आए। ये जन-जातियाँ बाद में धीरे-धीरे सारे अमेरिकन महाद्वीप में फैल गईं। समय आने पर ये जातियाँ राष्ट्रों में बँट गईं और उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की संस्कृतियों का विकास किया। उन्होंने रुई काटना और बुनना, मक्का बोना, किश्तियाँ बनाना और शिकार में मारे हुए जानवरों की खालों को सुरक्षित रखना सीखा।

कुछ जन-जातियों ने काफी उन्नत राजनैतिक संगठनों का भी विकास कर लिया था। इण्डियन लोगों के कम-से-कम तीन राष्ट्र—मय, आज़तेक और इन्का—ऐसे थे जिनकी सभ्यता कुछ दृष्टियों से यूरोप से आकर बसने वाले अधिवासियों की सभ्यता से अधिक ऊँचे स्तर की थी।

लेकिन फिर भी हमारी स्कूली किताबों का यह कथन तत्त्वतः सही है कि नई दुनिया का इतिहास 1492 में कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज से प्रारम्भ होता है। कारण, इस खोज के बाद अमेरिका में जो कुछ हुआ उसे अमेरिका के मूल निवासियों की संस्कृति ने कुछ विशेष प्रभावित नहीं किया। यह ठीक है कि यूरोपियनों ने अमेरिका के आदिवासियों से तम्बाकू पीना (इसमें सन्देह है कि यह उनके लिए वरदान था), मक्का बोना और आलू खाना सीखा। लेकिन और बातों में यूरोपियन 'आक्रमणकारियों' पर मूल निवासियों की आदतों, विश्वासों और प्रथाओं का प्रायः कुछ भी असर नहीं पड़ा। वास्तव में, इससे पूर्व इतिहास में जायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी विजयी जाति पर विजित जाति की संस्कृति का इतना कम असर पड़ा हो।

इस प्रकार वर्तमान अमेरिकन समाज के निर्माण में योग देने वाले कुछ

विचारों और आदर्शों को भली-भाँति समझने के लिए हमें यूरोप के इतिहास की ओर लौटना होगा। कारण, आज जिन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों और संस्थाओं को हम अमेरिकन प्रणालियाँ और संस्थाएँ मानते हैं, उनका मूल उद्भव यूरोप में ही हुआ था।

यूरोप से सबसे पहले नार्वे के लोग नई दुनिया में आए। ग्यारहवीं शताब्दी में वे पश्चिम की ओर ग्रीनलैंड जाने के लिए निकले और बाद में खोजते-खोजते कनाडा के तट पर जा पहुँचे। इस तट के साथ-साथ यात्रा करते हुए वे सेंट लॉरेन्स खाड़ी तक गए। किन्तु उनकी इन यात्राओं का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। नार्वे के लोग अपने देश में लौट गए और बहुत जल्दी ही अपनी इन खोजों के बारे में सब-कुछ भूल गए।

यही बात 1492 की खोज के बारे में क्यों नहीं हुई? उस समय खोज और अनुसन्धान की यात्राओं में लोगों की दिलचस्पी इतनी प्रबल और उत्कट क्यों थी? यह जाहिर है कि इन प्रश्नों का कोई सीधा-सादा उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि अधिकतर इतिहासकारों की दृष्टि में इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। वह कारण यह है कि उस समय यूरोप के लोगों के मन और हृदय में नए-नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की उत्कट और तीव्र आकांक्षा हिलोरे ले रही थी।

इतिहासकारों ने इस आकांक्षा के उदय को 'नव जागरण' या 'नए जन्म' का नाम दिया है। वास्तव में यह 'नए जन्म' या 'नव जागरण' से भी कुछ अधिक ही था। पन्द्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोपियन लोगों की जीवन-पद्धति में और इन आदर्शों और आकांक्षाओं में, जिनके लिए इन्सान उद्योग करता है, एक विशाल और उग्र परिवर्तन हुआ। इस अवधि में सामन्त-प्रणाली, जिसका आधार सर्वथा आत्मनिर्भर जागीरे और सुनिश्चित वशानुगत और सोपानक्रमिक (हायरार्किकल) सामाजिक रचना थी, टूटने लगी और उसका स्थान एक ऐसी विनिमयात्मक आर्थिक व्यवस्था ने ले लिया, जिसमें दस्तकारी का सामान तैयार करने वाले कारीगर और व्यापारिक मध्यवित्त वर्ग अधिकाधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करने लगे।

इन मध्यवर्गों का अपने इर्द-गिर्द के ससार के प्रति बिल्कुल नया रवैया

अन्वेपण का युग

था। उनके लिए जीवन एक महान् साहसपूर्ण अभियोग था जिसमें उपक्रम और उद्यम करने से उनके फल के रूप में मनुष्य-जीवन की अच्छी चीजें पा सकता था—और 'अच्छी चीजों' से उनका अभिप्राय ऐसी वस्तुएँ थी जिन्हें पैसा खरीद सकता है। मध्य युग के सासारिक सुखों के परित्या और वैराग्य के द्वारा मृत्यु के बाद अनन्त आनन्द और मुक्ति के आदर्श उनके लिए कुछ नहीं थे। ये नए मध्यवर्ग बहुत-कुछ इसी ससार और इसी लोक के वर्ग थे। वे अपने सासारिक भौतिक अस्तित्व से उपलब्ध होने वाले मारे सुखों को भोग डालने के लिए अधीर थे।

इस नई मनोवृत्ति का ही यह परिणाम था कि पुनर्जागरण के साथ-ही-साथ वाणिज्य व्यवसाय और अन्वेपण का युग आया और इस युग के बाद नए उपनिवेग और वस्तियाँ बसाने का जमाना आया। मध्ययुगीन समाज के सामन्तवादी सगठनों के स्थान पर राजाओं द्वारा शासित और उभरते हुए मध्यवर्ग द्वारा समर्थित नये राज्यों की स्थापना होने पर सामाजिक सगठनों के आकार और उनकी प्रभावकारिता का एक बार फिर विस्तार हुआ। इन नए राज्यों में मध्यवर्ग सार्वजनिक (राज्य का) हित और अपना हित, दोनों को एक ही समझते थे।

तत्कालीन वाणिज्यवादी सिद्धान्त के अनुसार वाणिज्य का मुख्य काम था राज्य की शक्ति को और उसके द्वारा राज्य की प्रजा की, खासकर व्यापारी वर्ग की शक्ति को बढ़ाना। इन प्रकार वाणिज्यवादियों का यह विश्वास था कि व्यापार-सन्तुलन को अनुकूल, यानी अपने पक्ष में रखना, (अर्थात् आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करना) आवश्यक है क्योंकि उन का यह खयाल था कि देश से जितना सोना बाहर जाए उससे अधिक सोना बाहर से देश के भीतर आना चाहिए। इन नीति को कायम रखने का प्रयत्न किया जाता था, भले ही उनमें व्यक्तिगत वाणिज्य-व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाना पड़े।

इन सिद्धान्त के अनुसार, लाभ के लिए उत्सुक व्यापारियों को राज्य द्वारा महानगरों के उन पार ऐसे अज्ञात और अज्ञात प्रदेशों की खोज के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, जहाँ से सोना प्राप्त किया जा सके। ब्राम्हणों ने बड़े-बड़े व्यवसायी राजाओं और राजनीतिज्ञों के दिवान्दोस्तों ने गोलों

के तरीके इतने क्रूर और अत्याचारपूर्ण थे कि उसका नाम अत्याचार और क्रूरता का पर्यावाची बन गया।

यद्यपि इन सब व्यक्तियों और इनके पीछे आने वाले उपनिवेशवादियों के व्यक्तित्व और सामान्य दृष्टिकोण में बहुत अन्तर था, फिर भी उनमें एक बात की समानता थी, वह थी पुरानी दुनिया की सीमाओं को तोड़कर नये क्षेत्रों में प्रवेश करने, अपने भाग्य को सुधारने और अपने सकीर्ण घरों से बाहर निकलने की आकांक्षा।

ये यूरोपियन कौन-सी दक्षताएँ, ज्ञान और दृष्टिकोण अपने साथ लाए? कई लिहाज से अमेरिकन उपनिवेश-संस्थापक विल्कुल भिन्न किस्म के थे। ब्रिटेन या गॉल में उपनिवेशों की स्थापना करने वाले रोमन लोगों की भाँति ये आम तौर पर किसी सेना के अंग नहीं थे, बल्कि अक्सर वे किसी सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं थे।

विल्कुल प्रारम्भ के कुछ लोगों को छोड़कर अमेरिका में आबाद होने के लिए आए इन यूरोपियनों की स्वदेश लौटने की भी कोई इच्छा नहीं थी। आम तौर पर नया महाद्वीप ही उनका घर और स्वदेश था और एक विशाल महामागर ने उन्हें उनकी पहले की जिन्दगी से अलहदा कर दिया था। यह बात नहीं कि वे इस स्थिति से किसी भी कदर असन्तुष्ट थे। वास्तव में इनमें से बहुत-से लोग यहाँ आए ही इसलिए थे कि पुरानी दुनिया के अत्याचारों से बच सकें।

कुछ लोग, जैसे कि अग्रेज प्योरिटन (गुद्धाचारवादी), इच्छानुसार धार्मिक पूजा करने की स्वतन्त्रता पाने के लिए यहाँ आए थे, किन्तु जैसे ही एक बार उन्हें यह स्वतन्त्रता मिली और उन्होंने अपने निज के धार्मिक सम्प्रदायों की स्थापना की, वैसे ही उन्होंने भिन्न धार्मिक विश्वास रखने वालों को इस स्वतन्त्रता से वंचित करना प्रारम्भ कर दिया।

कुछ लोग इसलिए यहाँ आए थे कि वे अपने पुराने समाज की नज़रों से गिर गए थे और अपने पड़ोसियों और मित्रों की अवज्ञा से दूर भाग जाना चाहते थे। प्रारम्भिक अभियानकारियों में से कुछ लोग सोने की खोज में आए थे। सिर्फ वही लोग यह आशा करते थे कि वे सोने का भंडार साथ ले जाकर अपने पुराने देश में फिर से शेष जीवन विलासिता और आराम के

साथ बिताएँगे ।

लेकिन अधिकतर लोग ज़मीन की लालसा से आए थे । वे अनुभव करते थे कि इस नये विशाल महाद्वीप में अपने देश की अपेक्षा अधिक समृद्धिमय और पूर्णतर जीवन बिताने का अवसर मिलेगा । वास्तव में उनके आब्रजन का कारण बाद में आने वाले आब्रजको के आगमन के कारणों से बहुत भिन्न नहीं था ।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन नर-नारियों का श्रम, सम्पत्ति और वैयक्तिक अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में जो रख था, उसके कारण उन्होंने अत्यन्त स्वल्प काल में ही काफी नवीन और आधुनिक ढंग की आर्थिक प्रणाली की स्थापना कर ली । इसके अलावा, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, जब-जब सरकार ने उन्हें अधिक स्वतन्त्रता और छूट दी, वे अधिक सफल सिद्ध हुए । यह स्वतन्त्रता मिलने पर यूरोपियन लोगों की विचक्षणता और कौशल इस नये अक्षत महाद्वीप की कठोर और दुःसह परिस्थितियों के साथ अपने-आप को ढालने में बहुत सफल साबित हुआ ।

इसलिए इसमें जरा भी आश्चर्य की बात नहीं कि व्यक्तिगत अभिक्रम औपनिवेशिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया और अमेरिकन समाज ने जैसे ही सर्वप्रथम इस नये क्षेत्र में प्रवेश किया, इसने उस पर इतना अधिक प्रभाव डाला कि यह समाज निरन्तर पश्चिम की ओर अग्रसर होता गया ।

उत्तरी अमेरिका के मुख्य अन्वेषक (1492-1609)

अन्वेषक	राष्ट्रीयता	प्रेषक देश	अन्वेषण यात्रा का काल	खोजा गया प्रदेश	उद्देश्य
क्रिस्टोफर कोलम्बस	इटालियन	स्पेन	1492, 1493, 1498-1500	वेस्ट इंडीज	सुदूर पूर्व की ओर जाने के मार्ग की खोज
जॉन कैबट	इटालियन	इंग्लैंड	1497-98	लैब्रेडोर	उत्तरी अमेरिकन तट की खोज
जुआन पोसे द लियोन	स्पेनिश	स्पेन	1513	फ्लोरिडा	विजय और मुनाफा
जियोवानी द वेराजानो	इटालियन	फ्रांस	1524	ग्रैटलार्कि-तट व न्यूयार्क बंदरगाह	सुदूर पूर्व की ओर जाने के मार्ग की खोज
जाक कार्तिये	फ्रेच	फ्रांस	1534	सेंट लॉरेन्स नदी	वाणिज्य और उत्तर-पश्चिमी मार्ग की खोज
हरनाडो डि सोटो	स्पेनिश	स्पेन	1539-41	मिसिसिपी	सोने की खोज
फ्रांसिस्को डि कोरोनाडो	स्पेनिश	स्पेन	1540	दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य	सोने की खोज
फ्रांसिस ड्रेक	अंग्रेज	इंग्लैंड	1577-80	कैलिफोर्निया-तट	विजय और मुनाफा
सेमुअल द श्याम्प्ले	फ्रेच	फ्रांस	1607-9	वर्ग्वेक, उत्तरी न्यूयार्क	समुद्र का व्यापार और उप-निवेश-स्थापना
हेनरी हडसन	अंग्रेज	नीदरलैंड्स	1609	हडसन नदी	सुदूर पूर्व के मार्ग की खोज

नई दुनिया की स्थापना

पश्चिमी गोलार्ध की खोज का पुरानी दुनिया की तत्कालीन व्यवस्था पर गहरा असर पड़ना नितान्त अनिवार्य था। दूसरी ओर पहले से ही स्थापित इस पुरानी व्यवस्था के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका में अग्नेजों द्वारा एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रधान भूमिका अदा करना भी स्वाभाविक था।

सोलहवीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास का अध्ययन करते हुए कुछ इतिहासकारों ने यूरोपियन महाद्वीप के मामलों में राजघरानों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं पर सबसे अधिक बल दिया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यूरोप में शक्ति-संघर्ष के जमाने में भूमध्यसागर पर नियन्त्रण ही शक्ति की सबसे बड़ी कसौटी था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि यूरोप के देशों के इस संघर्ष की बुनियाद में धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक कारण थे। यूरोपियन इतिहास की इन सभी व्याख्याओं में एक बात अपरिहार्य रूप से घूम-घूमकर आती है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह कि यद्यपि अग्नेजों की यूरोप के मामलों में सीधी दिलचस्पी थी, फिर भी वहाँ घटित होने वाली बड़ी-बड़ी घटनाओं और परिवर्तनों में उसका भाग अप्रत्यक्ष ही होता था। प्रत्यक्ष भाग उनमें स्पेनिश, फ्रेंच, आस्ट्रियन हाप्सबर्ग और तुर्क ऑटोमन राजघराने ही लेते थे।

इंग्लैंड को यूरोपियन महाद्वीप से इंगलिश चैनल और भूमध्य क्षेत्र से और भी बड़ी भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं ने अलग कर रखा था। वहाँ जिस राजघराने का शासन था, सिंहासन पर उसका अधिकार बहुत पुराना नहीं था। इंग्लैंड जिस धार्मिक विश्वास का अपने-आपको रक्षक कहता था, पोप ने उसकी निन्दा की थी। इस प्रकार अग्नेज लोग सभी दृष्टियों से बिल्कुल अलग-थलग और रूढ़ व्यक्तिवादी थे, खासकर उस जमाने में उनका व्यक्तिवादिता का यह गुण समुद्र-पार के अभियानों में उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता था।

सोलहवीं शताब्दी में अंग्रेजों का यूरोपियन महाद्वीप में राजनैतिक सत्ता के सर्घर्ष की ओर न कोई झुकाव था और न किसी विशेष पक्ष को उन्होंने कोई बड़े वचन दे रखे थे और न उनके कोई खास दावे थे। इस प्रकार यूरोप के मामलों के प्रति उनकी अनासक्ति का एक बड़ा लाभ भी था और वह यह कि जहाँ यूरोप के अन्य देश आपस में उलझे रहते, इंग्लैंड यूरोप से बाहर अन्यत्र नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए सजग रहा।

नई दुनिया की खोज उसके लिए एक ऐसा ही अवसर था। उसने तुरन्त ही एक ऐसा झूठा खोल दिया जिसमें इंग्लैंड दूसरों का बराबरी से मुकाबला कर सकता था। कारण, कोलम्बस के जमाने के बाद के सौ वर्षों में, न तो स्पेनिश लोग और न बाद में फ्रेंच लोग ही, नई दुनिया के विनाश भूखंड की पूरी तरह खोज कर सके थे, उसे आबाद करने का तो सवाल ही नहीं।

यूरोपीय महाद्वीप के बड़े राष्ट्रों के लिए नई दुनिया अन्यत्र खेले जा रहे अधिक बड़े और घटनापूर्ण नाटक का सिर्फ एक अप्रासंगिक विष्कम्भक थी, किन्तु समुद्र के तट पर चलने वाले और सागर की चंचल लहरों से खेलने वाले अंग्रेजों के लिए पश्चिम की ओर समुद्र-यात्रा करने का विचार तत्काल ही एक प्रधान आकर्षण बन गया। इंग्लैंड के खेतिहरों, माहसी अभियान-कारियों और व्यापारियों, सभी ने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि उन्हें व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए एक अपूर्व अवसर मिला है। अंग्रेज राजाओं का यह मत था कि जिस चीज से अंग्रेज नागरिकों को लाभ हो सकता है, उससे राजवंश को भी लाभ होगा। नये प्रदेशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इंग्लैंड का व्यापारी वर्ग स्पेनिश विजयाकांक्षियों और फ्रेंच मिशनरियों या समुद्र की खोज करने वालों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और समर्थ था।

सौभाग्य से इंग्लैंड के समुद्र का अवगाहन करने वाले नाविकों को अपनी युवती रानी एलिजाबेथ टचूडर के रूप में, जो 1558 में राजसिंहासन पर बैठी थी, एक अत्यन्त साहसी और उत्साही मरक्षक मिल गया। उसका शासन-काल समाप्त होने तक सभी यह महसूस करने लगे थे कि समुद्र पर नियन्त्रण करना विशाल स्थलीय राष्ट्रों की शक्ति से परे है। इस सीधे-सादे

सत्य ने अगले साढ़े तीन सौ वर्ष तक यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और यह उचित ही था कि वह नई दुनिया के उस भाग के इतिहास को भी प्रभावित करता जिसे हम आज सयुक्त राज्य कहते हैं।

नई दुनिया में अंग्रेजों के उपनिवेशों की स्थापना का वास्तविक श्रीगणेश एनिजावेथ के उत्तराधिकारी राजा जेम्स प्रथम के जमाने में हुआ। 20 अप्रैल, 1606 को इस स्टुअर्ट राजा ने लन्दन कम्पनी को, जो नई दुनिया में लाभदायक उपनिवेशों की स्थापना के लिए बनाई गई प्राइवेट कम्पनी थी, अधिकार-पत्र प्रदान किया। आठ मास बाद कम्पनी के बहुत से शेयर-होल्डरों ने सागर के तट पर खड़े होकर नई दुनिया को आवाद करने के लिए प्रस्थान करने वाले 144 व्यक्तियों को सफलता की शुभकामना के साथ विदाई दी। इन लोगों ने जेम्सटाउन, वर्जीनिया की बस्ती बसाई, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहली स्थायी अंग्रेज बस्ती थी।

इससे पूर्व अंग्रेजों के उपनिवेश बसाने के प्रयत्न असफल रहे थे। सर वाट्टर रैले ने 1585 में रोआनोक द्वीप में उपनिवेश बसाने का जो प्रयत्न किया था उसका क्या परिणाम हुआ, यह आज तक ज्ञात नहीं हो सका। रैले के सौतेले भाई सर हम्फ्रे गिल्बर्ट का तो न्यू फाउंडलैण्ड में उपनिवेश बसाने के प्रयत्न में दिवाला ही निकल गया। मई, 1607 में जेम्सटाउन की बस्ती आवाद होने से पहले सिर्फ स्पेनिश और फ्रेच लोगों के ही उपनिवेश नई दुनिया में स्थापित हुए थे।

स्पेनिश लोगों ने मैक्सिको और पेरू की खनिज सम्पदा के खनन के साथ दुनिया को आवाद करने का काम अंग्रेजों से पहले ही प्रारम्भ कर दिया था। फ्रेच लोगों ने, जो अंग्रेजों से कुछ ही वर्ष आगे थे, अपने प्रयत्नों को उत्तर-पूर्वी कनाडा में और ओहायो और मिसिसिपी नदियों की घाटियों में अपने समुद्र के व्यापार को बढ़ाने पर ही केन्द्रित रखा। इन गैर-अंग्रेज उपनिवेशों के एक खास ढंग से आवाद होने में भौगोलिक और मौसम-सम्बन्धी कारणों ने भी योग दिया। स्पेनिश लोगों ने दक्षिण-पश्चिम के गर्म इलाके में अपनी खानों के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर खेती भी आरम्भ की। खेती की इन जमीनों पर धनी और शक्तिशाली जमींदारों का अधिकार था। किन्तु उत्तर के फ्रेच इलाके व्यापारियों, समुद्र के लिए जगली जानवरों का

शिकार करने वालो और धर्म-प्रचारको के कार्यक्षेत्र के रूप में खुले हुए थे। फ्रेच इलाके में जगह-जगह व्यापारिक केन्द्र और किले बने हुए थे।

स्पेन और फ्रांस की औपनिवेशिक नीतियाँ एकतन्त्रीय और अत्यधिक सरक्षणात्मक थीं। उन्होंने पुरानी दुनिया के बहुत-से वर्गभेद कायम रखे थे और वे वर्गभेद की इन दीवारों को तोड़कर लोगों को व्यक्तिगत उद्यम और उपक्रम का साहस करने में निरुत्साहित करते थे। इमीलिए इन उपनिवेशों में आकर बसे गरीब लोगों की हालत आम तौर पर गुलामों से बेहतर नहीं थी। जिन लोगों के पाम जमीनें मिल्कियत के रूप में थी, उन्हें वे प्रायः सामन्तवादी शासन से अनुदान के रूप में मिली थी। स्पेनिश और फ्रेच जमींदार अपनी जमीनें साधारण किसानों को अग्रेजों की भाँति मुफ्त या सस्ती दर पर नहीं देते थे। इसी तरह जेम्सटाउन के कुछ वर्ष बाद स्थापित डच और स्वीडिश उपनिवेशों में भी सारा नया उद्यम और व्यवसाय प्राइवेट व्यापारिक कम्पनियों की ही इजारेदारी बन गया था।

इस प्रकार इन देशों के नई दुनिया में स्थापित उपनिवेश बहुत छोटे ही रहे, क्योंकि उनमें यूरोप से आकर आबाद होने के लिए लोगों को कोई अवसर नहीं दिये जाते थे। फ्रेच वस्तियों में आबादी की विरलता का परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी गोलार्ध में अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस का प्रभाव और महत्त्व बहुत घट गया। इसी तरह न्यू ऐम्सटर्डम की छोटी-सी डच वस्ती भी अग्रेजों के सामने नहीं टिक सकी और 1664 में बिना किसी संघर्ष के उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया।

कैरीबियन क्षेत्र में स्पेनिश उपनिवेशों के लिए आकार कोई बड़ी समस्या नहीं था। लेकिन वहाँ स्पेनिश लोगों ने व्यापार पर जो कठोर एकाधिकार कर रखा था, उसने धीरे-धीरे उनका गला घोटना प्रारम्भ किया। इस एकाधिकार के परिणामस्वरूप अग्रेज और फ्रेच डाकू उनका माल लूटने लगे और तस्कर-व्यापार बढ़ने लगा।

इसमें सन्देह नहीं कि जेम्सटाउन के बाद अटलांटिक के तट पर एक के बाद एक जो बहुत-से अग्रेज उपनिवेश स्थापित हुए उनमें भी इनमें से बहुत-सी कमजोरियाँ थीं। लेकिन इंग्लैंड के शासन के सामने इसके सिवाय दूसरा चारा भी कोई नहीं था कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के साथ-साथ प्राइवेट

उद्यम के प्रति भी स्वार्थपूर्ण, किन्तु उदार, रख अपनाता। फ्रेच और स्पेनिश उपनिवेशों और अंग्रेज उपनिवेशों में एक बड़ा अन्तर यह था कि अंग्रेज उपनिवेश पूर्णतः शेयरो की विक्री से गठित की गई प्राइवेट कम्पनियों की पूंजी पर ही निर्भर थे। अंग्रेज राजघराने के पास कभी भी धन बहुत अधिक नहीं रहा। इसीलिए उसने स्वयं कोई उपनिवेश नहीं बसाया और न ही उसने उनकी स्थापना में धन से कोई योग दिया। इसके विपरीत उसने उन लोगों को, जो अपनी पूंजी को खतरे में डालने के लिए तैयार थे, इसके लिए अधिकार-पत्र ही प्रदान किये।

सौभाग्य से सत्रहवीं शताब्दी के इंग्लैंड में परिस्थितियाँ साम्राज्य-निर्माण के लिए बहुत अनुकूल थी। ट्यूडर राजाओं ने चर्च की सम्पत्ति छीन ली थी, जिससे इंग्लैंड के सामन्तवर्ग के हाथ में प्रचुर धन-दौलत आ गई थी। वाणिज्य और उद्योग उन्नति कर रहे थे। गहरों के व्यापारी और साहूकार इंग्लैंड के कारखानों का पेट भरने के लिए कच्चे माल के स्रोतों और नये-नये बाजारों की खोज कर रहे थे।

इसके अलावा ऊनी कपड़े के कारखानों की उन्नति, खेती की शामिलान-जमीनों की भेड़े चराने के लिए घेराबन्दी और ईसाई मठों के उन्मूलन ने हजारों आदिमियों को आजीविका से वंचित कर दिया था। इन बेकार व्यक्तियों, कजदारों और अन्य अपराधियों में से बहुतों ने यह महसूस किया कि नये उपनिवेशों में चले जाने से उनकी तमाम समस्याएँ हल हो जाएँगी। हर अंग्रेज अधिवामी ने, चाहे उसने अपना सर्वस्व बेचकर इन उपनिवेशों में जाने के लिए किराये के पैसे का जुगाड़ किया हो और चाहे किराये का प्रबंध न होने पर मजदूरी के लिए करार किया हो, यह अनुभव किया कि उपनिवेशों में जाकर वह नये निरे से जिन्दगी शुरू कर सकेगा और वर्ग-भेद की उन बाधाओं को काट सकेगा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि में उसके लिए उन्नति के नव द्वार बन्द कर रखे हैं।

उपनिवेशों की स्थापना मुख्यतः प्राइवेट पूंजी-निवेशकों के प्रयत्नों का ही परिणाम थी। गिल्बर्ट और रैले आदि की अमफलताओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि किसी एक व्यक्ति के लिए उपनिवेशों की स्थापना के लायक विशाल धनराशि का जुगाड़ कर सकना सम्भव नहीं है। इसलिए ज्वायट

स्टाक कम्पनियाँ स्थापित की गई और उन्होंने मुनाफे के लिए उपनिवेश बनाने या फार्म और वागान स्थापित करने के वास्ते सरकार से अधिकार-पत्र प्राप्त किये। अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाली कम्पनियों को अनुदान के रूप में उपनिवेश दिये गए और साथ ही भविष्य में उनमें आकर बसने वालों पर प्रभुसत्ता भी प्रदान की गई। कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़कर, जिनमें न्यू प्लाइमाउथ उपनिवेश मुख्य था, अधिकतर अंग्रेज उपनिवेश प्रारम्भ में उनके सस्थापकों की जागीरदारी मिल्कियत थे। उपनिवेश का मालिक, चाहे वह व्यक्ति हो, जैसे लार्ड वाल्टीमोर, विलियम पैन, जॉन कार्टरेट या ड्यूक ऑफ यार्क (जो बाद में राजा जेम्स द्वितीय बन गया) और चाहे कम्पनी, सारी ज़मीन का मालिक होता था और उसमें आबाद लोगों पर शासन करता था।

प्रारम्भ में इन उपनिवेशों में आबाद अविवासियों के अधिकारों में मत देने या पदाधिकारी बनने के अधिकार शामिल नहीं थे, क्योंकि स्वयं इंग्लैंड में भी सब लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे इंग्लैंड में लोगों के अधिकारों का विस्तार होता गया, वैसे-वैसे उपनिवेशों के लोगों के अधिकार भी बढ़ते गए। इतिहासकार एडवर्ड चैनिंग ने लिखा है “अन्य राष्ट्रों के उपनिवेशों के अविवासियों के भाग्य में यही बढ़ा था कि वे उन राष्ट्रों के निवासियों को प्राप्त अधिकारों और कानूनी सुविधाओं से बाहर समझे जाएँ। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों के उपनिवेश इंग्लैंड के लोगों को प्राप्त कानून के संरक्षणों (जुरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण अधिकार और वाणी की स्वतन्त्रता) का समान रूप से उपभोग करते थे। उन्हें ये समानाधिकार देने से उपनिवेशों की स्थापना के एक नये युग का आरम्भ हुआ।” अनजाने में ही इससे अन्ततः इन उपनिवेशों के अपने मूल देशों से अलग और स्वतन्त्र हो जाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो गया।

सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में प्रचलित विचारधाराओं के अनुसार उपनिवेशों का अपने मूल देशों के समान अधिकारों की माँग करना न केवल अमह्य समझा जाता था, बल्कि वह अयुक्तियुक्त भी था। उपनिवेश-स्थापना के पीछे इंग्लैंड की भावना वाणिज्यवाद (मर्केन्टाइलिज्म) नामक राजनैतिक आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित थी। इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली और दौलतमन्द तभी हो सकता है जबकि आर्थिक

दृष्टि से वह स्वतन्त्र हो। और आर्थिक स्वतन्त्रता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि उस राष्ट्र का व्यापार-सन्तुलन उसके पक्ष में हो, अर्थात् उसका निर्यात आयात से अधिक हो। लेकिन यहाँ 'अनुकूल' शब्द की तह में एक सर्वथा सीमित और स्वार्थपूर्ण भावना निहित है, क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि एक राष्ट्र का लाभ निश्चित रूप से दूसरे का नुकसान होगा। वाणिज्यवादी यह आगा करते थे कि अपने देश की कृषि और उद्योगों को सहायता और रक्षण देकर, आयात से अधिक निर्यात करके, और देश के भीतर ही यथामुम्भव अधिकतम सोना-चाँदी एकत्र कर वे अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बलवान और मजबूत बना सकेंगे।

वाणिज्यवादियों की दृष्टि में उपनिवेश मूल देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ही स्थापित किये गए थे। वे उन देशों के कारखानों के लिए कच्चे माल के स्रोत और उनके कारखानों के तैयार माल के लिए बाजार थे। इंग्लैंड का औपनिवेशिक कानून उस बात को दृष्टि में रखकर ही बनाया गया था।

व्यापारी इस नाटक के रंगमंच पर सबसे प्रमुख अभिनेता था, क्योंकि उसी को वाणिज्य-व्यवसाय सम्बन्धी नीति को अमल में लाने की भूमिका अदा करनी थी। किन्तु स्वयं उसका हित भी गौण था, क्योंकि उसका प्रधान उद्देश्य ब्रिटिश ताज के हितों को समुन्नत करना था और ब्रिटिश ताज (शासन) राजनीति और आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक समन्वित और राजकोष में सोना-चाँदी के प्रवाह को विनियमित करता था।

यद्यपि ये नीतियाँ स्वार्थपूर्ण थीं तो भी वे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करने वाली कदापि नहीं थी। वास्तव में, उपनिवेशों के हित आम तौर पर इंग्लैंड के हितों के समानान्तर यानी विरोधी होते थे। अनेक मूर्खवा इंग्लैंड ने उपनिवेशों को स्वयं इंग्लैंड के लाभ के लिए जो उदार अधिदान (वाउटी) दिए उनसे सचमुच ही उपनिवेशों के आर्थिक विकास को सहायता मिली। इसके अलावा उपनिवेशों में तैयार माल के लिए इंग्लैंड के बाजार बन्द कर दिए जाने पर उपनिवेशों ने उनके लिए वेस्ट इंडीज या दक्षिणी यूरोप में नये बाजार खोज लिये। क्योंकि वास्तव में इंग्लैंड के उपनिवेशों के अधिवासी अंग्रेज इंग्लैंड में विद्यमान अपने भाई-बंदों से किसी भी कदर कम साहसी, हिम्मती, चतुर और प्रगतिशील नहीं थे।

अमेरिका का पूर्वी तटवर्ती प्रदेश कैसे आवाद हुआ

उपनिवेश	स्थापना का काल	नेता	राष्ट्रीयता	धर्म	प्रयोजन
जेम्सटाउन	1607	जॉन स्मिथ	अंग्रेज	ऐंग्लिकन	व्यवसाय धार्मिक अत्याचार से मुक्ति
प्लाइमाउथ	1620	विलियम ब्रैडफोर्ड	अंग्रेज	पिलग्रिम	
न्यू ऐम्स्टर्डम	1626	पीटर मिनुइट	डच	प्रोटेस्टेंट	
मैसाचुसेट्स बे	1629	जॉन विनश्रोप	अंग्रेज	प्योरिटन	व्यवसाय धार्मिक अत्याचार से मुक्ति
मेरीलैंड	1632	लार्ड वाल्टीमोर	अंग्रेज	कैथोलिक	धार्मिक अत्याचार से मुक्ति
कनैक्टिकट	1635	टामस हुकर	अंग्रेज	प्योरिटन	धार्मिक अत्याचार से मुक्ति
रोड आइलैंड	1636	रोजर विलियम्स	अंग्रेज	प्योरिटन	धार्मिक अत्याचार से मुक्ति
न्यू स्वीडन	1637	पीटर मिनुइट	स्वीडिश	प्रोटेस्टेंट	व्यवसाय
न्यू जर्सी	1665	बर्कले और कार्टरेट	अंग्रेज	ऐंग्लिकन	व्यवसाय
कैरोलिना	1670	लार्ड शैफ्ट्सवरी	अंग्रेज	ऐंग्लिकन	व्यवसाय
पेनसिलवेनिया	1681	विलियम पैन	अंग्रेज	क्वैकर	धर्म-प्रचार और व्यवसाय
जॉर्जिया	1732	जेम्स ओगलथोर्प	अंग्रेज	ऐंग्लिकन	कर्ज के तकाजो से मुक्ति

उपनिवेश : एकता की ओर

सन् 1607 में जेम्सटाउन की स्थापना से 1733 में जॉर्जिया कालोनी के आवाह होने तक अमेरिका में तेरह अंग्रेज-उपनिवेशों की स्थापना में 126 वर्ष लग गए। ये उपनिवेश अपने देश में अपराध करने वाले और कर्ज में डूबे हुए अंग्रेजों के लिए आश्रय-स्थल थे। सन् 1630 से 1642 तक, जो सबसे अधिक आव्रजकों के आगमन के वर्ष थे, मैसाचुसेट्स में उपनिवेश में कुल 16,000 नए व्यक्ति आए। यह संख्या इतनी कम थी और इन उपनिवेशों का जीवन इतना कष्टपूर्ण था कि 1650 तक भी यह सन्देह का विषय था कि उस समय मौजूद आठ उपनिवेश बचे भी रहेंगे या नहीं।

इन अधिवासी लोगों का मूल मातृदेश एक खतरनाक महासागर के उस पार तीन हजार मील दूर था। इन उपनिवेशों में अधिवासियों के सामने मूल निवासी इण्डियनों की ओर से तो खतरा हमेशा बना ही रहता था, साथ ही उनके सामने यह भी आशंका थी कि कहीं उन्हें ऐसी लड़ाइयों में न पड़ना पड़े, जिनके वास्तविक कारण सुदूर यूरोप में होने पर भी उत्तरी अमेरिका के इन उपनिवेशों को प्रभावित करते रहते थे। इसके अलावा इन उपनिवेशों का राजनैतिक संगठन बहुत अस्थिर था। सन् 1655 में डच लोगों ने पीटर स्टुइवसेन्ट के नेतृत्व में न्यू स्वीडन उपनिवेश को जीता। लेकिन नौ वर्ष बाद इन्हीं डच लोगों को अपना उपनिवेश न्यू एंगस्टर्डम अंग्रेजों से हारकर उनके सुपुर्द करना पड़ा।

सन् 1650 से 1750 तक सौ वर्षों में इन उपनिवेशों का गर्भावस्था से विकास शुरू हुआ और वे निश्चित राजनैतिक इकाइयाँ बन गए। फिर भी उनके इस विकास से यह संकेत नहीं मिलता था कि भविष्य में ये उपनिवेश मिलकर एक और स्वतन्त्र हो जाएँगे। विचारधारा की दृष्टि से ये उपनिवेश एक-दूसरे से बहुत अलग थे, क्योंकि उनके धर्म और राजनैतिक संगठन अलग-अलग किस्मों के थे। भौतिक दृष्टि से भी वे एक-दूसरे से अलग

थे, क्योंकि उनके बीच मार्ग और संचार के साधन बहुत अपर्याप्त और खराब थे। उनके आर्थिक कारबार में और भी ज्यादा अन्तर था। तीन स्पष्ट और एक-दूसरे से भिन्न क्षेत्र बन गए थे—न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक और दक्षिण—और इस भिन्नता का कारण उनके प्राकृतिक साधनों और आर्थिक गतिविधि की भिन्नता था।

सन् 1650 में न्यू इंग्लैंड विभिन्न कृषि-जीवी इलाकों और समुदायों का एक समूह था। कठोर मौसम, घटिया जमीन और भूमि-सम्बन्धी कानूनों से, जिनमें जमीन को अनेक उत्तराधिकारियों में बाँटने की अनुमति दे दी गई थी, बड़ी जमीनदारियाँ नहीं बन पा रही थी। फार्म छोटे-छोटे और व्यक्तिगत मिल्कियत थे। उनका आकार दस एकड़ से सौ एकड़ तक था। सन् 1700 तक यह हालत थी कि इस प्रदेश की निकम्मी पथरीली जमीन में ओडी-सी भी व्यापारिक फसल नहीं होती थी।

लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, न्यू इंग्लैंड के लोगो ने, जिनकी दक्षता हमेशा प्रसिद्ध रही है, अनेक प्रकार के लाभकारी उद्योग-धन्धे विकसित कर लिये। यूरोपियन अधिवासियों ने जब यह महसूस कर लिया कि इंडियन शिकारियों से शराब के बदले में जानवरों की खालें और बाल प्राप्त किये जा सकते हैं, तो समुद्र के व्यापार का महत्त्व भी बढ़ गया। जहाजों का निर्माण, मछलियाँ पकड़ना और ह्वेल का शिकार करना भी न्यू इंग्लैंड के लोगो की विशेषता बन गया।

उपजाऊ कनेक्टिकट घाटी में आटा-चक्कियों का व्यवसाय फलने-फूलने लगा। फिर भी फालतू उत्पादन बहुत अधिक नहीं था और न्यू इंग्लैंड के लोगो को कारखानों में निर्मित वस्तुएँ अधिकतर इंग्लैंड से मँगानी पड़ती थी। लेकिन इस प्रदेश ने कुछ कामों में जो विशेषता प्राप्त कर ली थी, उससे उसकी जड़े मजबूत हो गईं।

मध्य अटलांटिक उपनिवेशों—न्यूयार्क, न्यूजर्सी और पेनसिलवेनिया—में अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा गैर-अंग्रेज लोगो की संख्या कुछ अधिक थी। इसलिए डच, स्वीडिश, जर्मन, आयरिश और स्कॉच आयरिश लोगो के सम्मिश्रण ने इन उपनिवेशों की सभ्यता को अधिक विविधतापूर्ण बना दिया था। नगरों के प्रशासन अधिवासियों को जमीन दे, इसके बजाय

बड़ी-बड़ी जमीनो के मालिक ही उन्हें अपनी जमीनें बेचते या दान में देते थे। लेकिन इसके बदले में वे उनसे थोड़ा-सा किराया अपने लिए बाँध लेते थे। परन्तु यह किराया (लगान) अधिवासियों को पसन्द नहीं था, इसलिए उनसे इसे वसूल करना बहुत कठिन होता था।

इन उपनिवेशों में जमीन न्यू इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ कृषि-अर्थ-व्यवस्था में अधिक विविधता सम्भव थी। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ थी, लेकिन पशु-पालन का व्यवसाय भी यहाँ चलता था। गेहूँ और पशु देकर ये अधिवासी लोग वेस्ट इंडीज से ब्राडी, शर्वत, चीनी और नमक आयात करते थे। अन्य सभी उपनिवेशों की भाँति यहाँ भी समुद्र का निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान था।

यद्यपि मध्य अटलांटिक उपनिवेशों में न्यू इंग्लैंड की अपेक्षा व्यापारिक फसलों का अधिक महत्व था, तो भी दोनों जगह आम चीजों की भी खेती की जाती थी। इन दोनों क्षेत्रों में घरो पर ही फरनीचर, कपड़ा, साबुन और मोमबत्ती आदि तैयार करना भी जरूरी था।

लेकिन धीरे-धीरे वहाँ कारखानों को संगठित रीति से स्थापित करने और चलाने का काम भी शुरू हो गया, जिसका एक अच्छा उदाहरण पेनसिलवेनिया का लोहे का कारखाना था, जो मध्य अटलांटिक क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक गतिविधि था। इस उद्योग से मुख्यतः घरेलू उपयोग के लिए वर्तन, कढ़ाईयाँ और खेती के लिए कुल्हाड़े, कुदालियाँ और फावड़े आदि बनाने का लोहा तैयार किया जाता था।

यह कारखाना शहर में नहीं, बल्कि देहाती इलाके के बीच में, जहाँ खेती होती थी, खड़ा किया गया था। लोहे की खाने, मजदूरों के मकान, पिसाई की चक्कियाँ, आरे, भट्टियाँ और ढलाईघर हजारों एकड़ जमीन में फैले हुए थे। पूँजी की कमी के कारण कारखाने के मालिक आमतौर पर मजदूरों को खाद्य-पदार्थ और रिहायश के स्थान की शक्ल में मजदूरी देते थे। इसका अर्थ यह था कि लोहे के कारखाने के साथ-साथ अनाज और कपास आदि कृषि-पदार्थों का उत्पादन भी जारी रखना पड़ता था। श्रमिकों की स्थिति खुले बाजार और सामन्तवादी प्रणाली के मिश्रण का परिणाम थी।

दक्षिण के उपनिवेशों की परिस्थितियाँ अन्य दोनों क्षेत्रों के उपनिवेशों की परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न थी। यहाँ व्यावसायिक कृषि और व्यापारिक फसलों का महत्त्व अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक था। मेरीलैंड और वर्जीनिया के तम्बाकू और दक्षिणी कैरोलिना के चावल के लिए बड़े पैमाने

वर्जीनिया, पेनसिलवेनिया, न्यूयार्क और न्यू इंग्लैंड के निवासी का भेद अब नहीं रहा। मैं अब वर्जीनियन नहीं हूँ, बल्कि एक अमेरिकन हूँ।

पैट्रिक हेनरी, 1774

पर खेती की आवश्यकता होती थी। इसलिए दक्षिणी राज्यों के खेत सैकड़ों एकड़ के नहीं, हजारों एकड़ के होते थे। इन खेतों में काम करने के लिए बहुत बड़ी सख्या में ऐसे मजदूरों की आवश्यकता होती थी जो तपते हुए सूर्य की धूप में भी काम कर सकें। कुछ तो मजदूरों की कमी के कारण और कुछ ग़ोरे लोगों के अर्ध-उष्ण परिस्थितियों में काम करने के अनिच्छुक होने से दक्षिणी राज्यों को मजदूरों गुलाम मजदूरों को बाहर से लाना पड़ा। यद्यपि मध्य अटलांटिक उपनिवेशों में भी जमींदारियाँ और जागीरें थी और न्यू इंग्लैंड में भी बड़े-बड़े दौलतमन्द व्यापारी थे, फिर भी दक्षिण के उपनिवेशों में ही एक अभिजात-तन्त्र की स्थापना हो सकी। इस अभिजात-तन्त्र की बुनियाद बड़ी बड़ी कृषि-जागीरों और गुलाम मजदूरों पर खड़ी थी।

सस्ती ज़मीन, सरल भूमि-कानून और तम्बाकू, चावल या नील-जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन—इन तीनों ने मिलकर इन उपनिवेशों की समृद्धि में योग दिया। किन्तु दूसरी ओर एक ही फसल के उत्पादन और कृषि की किस्म की अर्थव्यवस्था ने निर्माण उद्योगों के विकास को निरुत्साहित भी किया। आबादी मारे क्षेत्र में काफी व्यापक रूप में फैली हुई थी। छोटे-छोटे और जिस किसी तरह कठिनाई से निर्वाह करने वाले किसानों की सख्या फार्मों के मालिकों से कहीं अधिक थी, लेकिन हर फार्म या वागान का बहुत न करार से बँधे मजदूरों और गुलामों पर नियन्त्रण था। यद्यपि दक्षिणी उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भर नहीं थी तो भी वह सबसे

अधिक लाभदायक थी ।

दक्षिण के अभिजातवर्गीय जमींदारों, न्यू इंग्लैंड के व्यापारियों और मध्य अटलांटिक और उत्तरी उपनिवेशों के स्वतन्त्र किसानों के हितों में कहीं कोई साम्य नजर नहीं आता था । दक्षिणी उपनिवेशों की फालतू उपज के लिए यूरोप ही स्वाभाविक बाजार था, क्योंकि शेष उपनिवेश न तो उन्हें खरीदकर खपा सकते थे और न उनके बदले में दक्षिण के उपनिवेशों की कारखानों में निर्मित वस्तुओं को जरूरत पूरी कर सकते थे ।

सामाजिक आचार-विचार और आर्थिक हित विभिन्न क्षेत्रों को एक-दूसरे से अलग करते थे । दक्षिण के ऐंग्लिकन लोग उत्तर के प्योरिटन लोगों के निरानन्द जीवन की कभी प्रशंसा नहीं कर सकते थे और प्योरिटन लोग दक्षिण के विलासी अभिजात-वर्ग की क्षुद्र विलासिता और नास्तिकता की निन्दा करते थे ।

जीवन-पद्धतियाँ, आर्थिक हित, जलवायु और राजनैतिक सगठन उपनिवेशों को परस्पर एक करने के बजाय उनमें विभेद पैदा करते थे । फिर भी 1750 के बाद की पीढ़ी में तेरहवें उपनिवेशों में काफी हद तक एकता स्थापित हो गई और उन्होंने सगठित होकर एक सर्वसामान्य शत्रु के खिलाफ विद्रोह किया । वह क्या चीज थी जिसने उन सबको सगठित किया और इंग्लैंड को अपना दुश्मन समझने के लिए मजबूर किया ?

इन प्रश्नों के उत्तर अशत आर्थिक हैं । दक्षिण और उत्तर दोनों को इंग्लैंड की नीति में अनेक बातें सामान्य रूप से असन्तोषजनक लगी । यद्यपि दक्षिण की फालतू उपज की विक्री के लिए यूरोप उत्तम बाजार था तो भी इंग्लैंड का आप्रह्व यह था कि यह फालतू उपज यूरोपियन महाद्वीप के बजाय इंग्लैंड में ही बेची जाए । इससे दक्षिणी उपनिवेशों के उत्पादकों का बहुत-सा मुनाफा खटाई में पड़ जाता था । इसके अलावा दक्षिणी उपनिवेशों के लोग इंग्लैंड से जो निर्मित वस्तुएँ मँगाते थे, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती थी । दक्षिणी उपनिवेशों के लोग दूसरे देशों के लोगों का आतिथ्य करने और उनकी बातों को ज्यों-का-त्यों मान लेने के लिए विख्यात थे और व्यापारिक हिसाब-किताब में कच्चे थे, इसलिए व इंग्लैंड के व्यापारियों के कर्जदार बन गए ।

उत्तर के लोगो को इंग्लैंड से जो शिकायतें थी उनकी सूची और भी लम्बी थी। उन्हें ब्रिटेन के वाणिज्यवाद से, जिसका आधार उपनिवेशों को इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड के तैयार माल का बाजार बनाना था, बहुत शिकायत थी। ममूचे औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश पार्लामेंट ने वाणिज्य-सम्बन्धी जो भी नीतियाँ अपनाई, उनका उद्देश्य उपनिवेशों में कारखानों की स्थापना और उनके निर्यात-व्यापार को सीमित कर इंग्लैंड और उपनिवेशों के उपर्युक्त सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना ही था। इस एक दृष्टिकोण से अगर हम सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों के इतिहास को देखें तो हमें मालूम होगा कि अंग्रेजों ने लगातार वाणिज्यवादी नीतियों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की और अमेरिकनो ने उनसे बचने का प्रयत्न किया।

लेकिन अमेरिकन निर्माण-उद्योगों के सौभाग्य से इंग्लैंड ने अपनी नीतियों को बहुत दृढ़ता से क्रियान्वित नहीं किया, कभी वह इस सम्बन्ध में कुछ दृढ़ता दिखाता और कभी फिर ढील दे देता। सन् 1651 से 1674 तक दो दशक से भी अधिक समय तक इंग्लैंड ने इन नीतियों पर दृढ़ता दिखाई। इस अवधि में ब्रिटिश पार्लामेंट ने जो कानून पास किये उनमें यह निर्धारित कर दिया गया था कि अमेरिकन उपनिवेश किन-किन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। उनमें यह व्यवस्था भी की गई थी कि ये वस्तुएँ इंग्लैंड के जहाजों में ही इंग्लैंड भेजी जाएँ और उपनिवेशों को यूरोप से यदि कोई सामान मँगाना हो तो वह इंग्लैंड से ही मँगाया जाए। सन् 1673 के कानून ने उपनिवेशों के व्यापार को बहुत अस्त-व्यस्त किया, क्योंकि इस कानून में उनके चीनी, तम्बाकू और अन्य उत्पादनों के पारस्परिक निर्यातपर शुल्क लगा दिया गया था। इस कानून का प्रयोजन स्पष्टतः यह था कि उपनिवेशों में परस्पर व्यापारिक सम्बन्ध न बढ़ें और वे एक-दूसरे से अलग-अलग रहें।

सन् 1733 का गीरा कानून (मोलैसेज ऐक्ट) न्यू इंग्लैंड के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कारवार को ठप्प करने का जबरदस्त प्रयत्न था। सन् 1715 के बाद फ्रेंच और डच वेस्ट इंडीज में चीनी का उत्पादन बढ़ गया और फलतः इन उपनिवेशों में चीनी के भाव गिर गए। इसलिए न्यू इंग्लैंड के व्यापारियों को स्वभावतः ऐसा लगा कि उन्हें अपने निर्मित माल के बदले

ब्रिटेन की वैदेशिक नीति की दृष्टि से यह रक्षा करना आवश्यक होगा।

अमेरिका के राजनैतिक चिन्तन में हमेशा पृथक्तावाद का जो तत्त्व विद्यमान रहा, उसका मूल स्रोत ये औपनिवेशिक लड़ाइयाँ ही थी। इस पृथक्तावादी तत्त्व की सबसे अधिक प्रख्यात अभिव्यक्ति हमें जॉर्ज वाशिंगटन के विदाई-भाषण में मिलती है। इन लड़ाइयों का एक लाभ भी हुआ और वह यह कि उन्होंने सब उपनिवेशों के निवासियों को अपने सर्वसामान्य जन्तुओं से अपनी रक्षा के लिए परस्पर सगठित किया और सभी के मन में ब्रिटिश लड़ाइयों के विरुद्ध सामान्य रूप से रोप पैदा किया।

सन् 1750 में से ये तेरहो उपनिवेश परस्पर सगठित नहीं थे। लेकिन 1750 तक उन सभी ने अपनी सीमाओं को और अधिक पश्चिम की ओर बढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया था। इन सभी में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति के प्रति असन्तोष था। न्यू इंग्लैंड ने जब दक्षिणी उपनिवेशों की उपज को खरीदना और उसके कारखानों ने उसके बदले में माल तैयार करना प्रारम्भ किया, तो इन सब उपनिवेशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ भी एक-दूसरी के साथ अधिक अनुकूल और सगत होने लगी।

अगले पच्चीस वर्ष के भीतर इंग्लैंड की कुछ गलत नीतियों और अत्याचारपूर्ण कामों ने उपनिवेशों के लोगों का असन्तोष और भी बढ़ा दिया। पहले जहाँ वे अवीर थे और कानूनों से बचने की चेष्टा करते थे वहाँ अब उन्होंने उनकी अवहेलना और उनके खिलाफ खुल्लमखुल्ला विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया।

संयुक्त राज्य की आबादी में आनुमानिक वृद्धि (1650-1750)

1650—	51,000	1710—	3,57,000
1660—	84,000	1720—	4,74,000
1670—	1,14,000	1730—	6,54,000
1680—	1,55,000	1740—	8,89,000
1690—	2,13,000	1750—	12,07,000
1700—	2,75,000	1760—	16,00,000

1770—22,05,000

“हम इन सत्यो को स्वतःसिद्ध मानते हैं कि जन्म से सब मनुष्य समान हैं, उनके स्रष्टा ने उन सबको कुछ अनपहरीय अधिकार प्रदान किये हैं और इन अधिकारों में जीवन, स्वतन्त्रता और सुख की प्राप्ति शामिल है।”

क्रान्ति और स्वतन्त्रता

उपनिवेशों की ‘लाभदायक उपेक्षा’ की ब्रिटेन की नीति का अन्त 1760 में हुआ। ब्रिटेन द्वारा अपनी वाणिज्यवादी प्रणाली को फिर से शक्तिशाली बनाए जाने का परिणाम उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक था। अब तक सभी उपनिवेश एक तरह से स्वशासन का उपभोग कर रहे थे, किन्तु जब उन पर कठोर राजनैतिक और आर्थिक नियन्त्रण लादे जाने लगे तो इस स्वशासन के लिए खतरा पैदा हो गया। सन् 1763 की घोषणा से जिसमें ऐपलेचियन पर्वतमाला के पश्चिम में भूमि-अनुदान देने और वस्तियाँ बसाने का निषेध किया गया था, मिल्कियत के रूप में बड़ी-बड़ी जमीदारियाँ स्थापित करने वालों, जमीनें सस्ते भाव पर खरीदकर मंहंगे भावों में बेचने के डच्युक मटोरियो और छोटे किसानों का जमीन की प्राप्ति के लिए नए-नए इलाकों में आगे बढ़ना बन्द हो गया।

इससे भी बड़ी बात यह कि ब्रिटेन अपनी वाणिज्यवादी नीतियों को कड़ाई से लागू करने और उपनिवेशों से राजस्व की वसूली के लिए दुगुने उत्साह से जुट गया। उसके द्वारा लगाए गए करो और प्रतिबन्धों से यह स्पष्ट जाहिर था कि इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के हितों में जबरदस्त संघर्ष है।

ब्रिटेन द्वारा वाणिज्यवादी साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न पुनः किये जाने पर उपनिवेशों ने आर्थिक विरोध से लेकर सांविधानिक विवाद तक सभी प्रकार के उपायों से उसकी मुगलफत की। जब उत्तरी उपनिवेशों ने राजस्व-सम्बन्धी कानूनों के आगे झुकने से इन्कार किया और ब्रिटेन से माल

का आयात और उसका उपभोग बन्द करने का तरीका अपनाया तो ब्रिटिश पार्लमेण्ट ढीली पड़ गई। ब्रिटेन ने स्टाम्प कानून और अनेक सामान्य जिन्सों पर शुल्क लागू करने वाले टाउनशैंड कानूनों-जैसे अप्रिय अधिनियमों को रद्द कर दिया। लेकिन पार्लमेण्ट 'कर' उगाहने का अपना अधिकार छोड़ने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थी। लेकिन उपनिवेशों के निवासियों ने तब तक इस अधिकार को स्वीकार करने से इन्कार किया जब तक कि पार्लमेण्ट में उन्हें प्रतिनिधित्व न दिया जाए।

स्वतन्त्रता की लड़ाई अमेरिकन उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उमड़ते हुए ज्वार की अभिव्यक्ति नहीं थी। उपनिवेशों के लोगो ने इसलिए विद्रोह नहीं किया कि उन्हें ब्रिटिश राजा की प्रजा बने रहने में ऐतराज था और न इसीलिए कि वे पार्लमेण्ट के कानून से बचना चाहते थे। बल्कि उनके विद्रोह का कारण उनका यह असन्तोष था कि अंग्रेज होने के कारण उन्हें जो अधिकार स्वभावतः मिलने चाहिए थे, उनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा था। यह असन्तोष इतना बढ़ गया कि अन्त में उन्हें राजा जॉर्ज तृतीय की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इस लड़ाई के बावजूद वे एंग्लो-सैक्सन परम्पराओं के साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करना चाहते थे। वास्तव में उन्होंने राजा और पार्लमेण्ट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वह इन परम्पराओं के अनुरूप समझकर ही लड़ी।

उपनिवेशों ने काफी हिचकिचाहट के बाद 4 जुलाई, 1776 को जो स्वतन्त्रता की घोषणा जारी की उसके मूल में विद्यमान राजनैतिक विचार-धारा ने उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकतर यूरोपियन सुधार-आन्दोलनों को प्रभावित किया। इस प्रसिद्ध घोषणा में, इसके रचयिता टामस जैफर्सन ने इस स्वेच्छातन्त्रवादी दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन किया कि "सरकारों को नासित लोगों की अनुमति से अधिकार प्राप्त होते हैं।" इस प्रकार अमेरिका के अंग्रेज उपनिवेशों में हुई क्रान्ति केवल स्वतन्त्रता की लड़ाई ही नहीं थी, यह उन शक्तिशाली विचारों का, जो अठारहवीं शताब्दी के यूरोप की स्थापित राजनैतिक व्यवस्था के लिए अधिकाधिक खतरा पैदा कर रहे थे, एक सुदूरगामी प्रतिविम्ब थी।

उपनिवेशों की आवादी के चार विभिन्न खंडों ने क्रान्ति-आन्दोलन को

बल प्रदान किया। ये चार खंड थे, दक्षिण के जमींदार, उत्तर के व्यापारी, छोटे किसान और शहरी और समुद्र-तटवर्ती नगरों के मजदूर।

दक्षिण के जमींदारों को इस बात पर बहुत नाराजगी थी कि उत्तर के साहूकार उनके व्यापार पर हावी हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार की नीति इन साहूकारों को मजबूत बनाने की है। उन्हें एपलेचियन पर्वतमाला के पश्चिम में सीमा के बन्द कर दिये जाने पर भी बहुत रोष और असन्तोष था।

दूसरी ओर उत्तर के व्यापारियों को यह गिकायत थी कि ब्रिटिश सरकार उनके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा रही है और उसने पश्चिम की ओर की जमीनों के सट्टे-फाटके से उन्हें रोक दिया है।

छोटे व्यापारी भी व्यापारिक प्रतिबन्धों से दुःखी थे, क्योंकि इनसे उनकी उपज का मूल्य गिर गया था। साथ ही वे भी 1763 की घाषणा के अनुसार सीमा के पश्चिम की ओर की नई जमीनों में आबाद होने से रोक दिए जाने के कारण नाराज थे।

शहरी मजदूरों के असन्तोष का कारण यह था कि सरमायेदार उनका शोषण कर रहे थे। इन सरमायेदारों के हाथ में ही सत्ता थी और पार्लमेन्ट आमतौर पर उनका समर्थन करती थी। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के कारण क्रुद्ध श्रमिक-वर्ग बहुत कट्टर क्रान्तिवादी बन गया था।

क्रान्तिकारी सेना को अधिकतर गस्त्रास्त्र और युद्ध सामग्री फ्रांस से मिलती थी। फ्रांस अमेरिकन उपनिवेशों का सबसे अधिक उत्साही साथी था। वास्तव में फ्रेंच लोगों की सहायता के बिना क्रान्तिकारी सेना युद्ध का भार अधिक समय तक सहन न कर पाती और लड़ाई न जीत सकती। वास्तव में ब्रिटेन यह लड़ाई सिर्फ इसलिए हार गया कि उसके पास कोई निश्चित रण-नीति नहीं थी और ब्रिटेन के लोगों में एकता का अभाव था। जॉन ऐडम्स प्रारम्भ में फ्रांस के साथ किसी भी तरह का 'उलझाने वाला गठबन्धन' करने का उग्र विरोधी था, लेकिन 1776 के साल की समाप्ति से पूर्व ही क्रान्तिकारी सेना की हालत इतनी कमजोर हो गई कि कांग्रेस (अमेरिकन ससद्) ने अन्ततः बैजामिन फ्रेकलिन को फ्रांस के साथ एक

‘आक्रमणात्मक’ गठबन्धन करने की अनुमति प्रदान कर दी।

उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था स्वतन्त्रता की लड़ाई प्रारम्भ होने से पहले ही काफी हद तक आत्म-निर्भर हो चुकी थी। इसलिए युद्ध के दौरान में ब्रिटेन के साथ व्यापार-सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर भी, उपनिवेशों के लोगों को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन और हालैंड के लोग, जो ब्रिटेन के व्यापार को हमेशा ललचाई नजरो से देखते थे, ब्रिटिश जहाजों के औपनिवेशिक बन्दरगाहों से हट जाने पर उनका स्थान लेने के लिए उतावले हो उठे।

इसके अतिरिक्त शायद दो हजार के लगभग अमेरिकन लोग गैरकानूनी तौर पर छोटे-छोटे जहाज और नावे लेकर समुद्र में ब्रिटिश जहाजों को लूटने के लिए उतर पड़े थे। उन्हें ब्रिटिश जहाजों को पकड़ने और तस्करो-व्यापार करने में बहुत भारी मुनाफा होता था जिसका उन्होंने कभी हिमाव नहीं लगाया। दरअसल, ब्रिटिश व्यापारियों को इन समुद्री डाकुओं से जहाजों और माल की जो भारी क्षति उठानी पड़ी उससे तग आकर उन्होंने सरकार से इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की माँग की।

यद्यपि क्रान्ति के दिनों में उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था ठीक चल रही थी, किन्तु उत्पादित सामान के वितरण की कोई केन्द्रीय योजना न होने से कभी-कभी सेना के पास सामग्री की बहुत अधिक कमी हो जाती थी। कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार नहीं था, इसलिए वह राज्यों से सम्मान देने की प्रार्थना के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी और राज्य अक्सर केन्द्रीय शासन द्वारा माँगी गई यह सहायता इसलिए नहीं देते थे कि जनता सब राज्यों का कोई केन्द्रीय शासन पसन्द नहीं करती थी और वह कर लगाने के विचार की भी विरोधी थी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, जो अपने चारों ओर चल रही लड़ाई के प्रति विल्कुल उदासीन थे और किसी भी तरह का व्यक्तिगत त्याग करने का विचार आमतौर पर उनके मन में नहीं उठता था।

दूसरी ओर फ्रांस ने अमेरिकन लोगों की सहायता के लिए जो सैनिक यूरोप से भरती करके भेजे थे, वे अमेरिकन सैनिकों की दृढ़ता के बड़े प्रशंसक थे। जनरल द काल्व ने, जो 1777 के भयकर जाडो में वाशिंगटन और

उनकी टिठुरती और भूखी सेना के साथ वैली फोर्ज में थे, कहा कि “यूरोप के किसी भी देश की सेना इस तरह की कठिनाइयों को इतनी बहादुरी से बर्दाश्त न कर पाती।” एक अन्य फ्रांसीसी सेनापति जनरल लफायेत ने गर्व से लिखा था, “नागरिकों को अपनी भूखी, नगी और मेहनत-मशवकत से चूर सेना की सहायता करनी पड़ रही है, जिसे वेतन भी कतई नहीं मिल रहा।”

वैली फोर्ज के उस भयंकर जाड़े के बाद क्रान्तिकारी सेना की विजय के आसार बढ़ गए। अमेरिकियों की अनेक विजयों ने सेना में नया जोश भर दिया। और ब्रिटिश लोग, जो यह समझते थे कि लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाएगी, इस लम्बे युद्ध से आजिज आ गए। उससे उन्हें भारी कर-भार के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा था, फलतः ब्रिटेन ने शान्ति और समझौते की बातचीत प्रारम्भ कर दी और अन्त में 1783 में दोनों शक्तियों ने पेरिस में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए जिससे अमेरिकन क्रान्ति-युद्ध अधिकृत रूप से समाप्त हो गया।

युद्ध समाप्ति और शान्ति से नये राष्ट्र के कुछ आर्थिक क्षेत्रों में मन्दी आ गई। लड़ाई खत्म होते ही रातों-रात सामान की युद्धकालीन माँग खत्म हो गई और उसके साथ ही एक सर्वसामान्य शत्रु के विरुद्ध एकता की भावना का भी अन्त हो गया। कर्ज के बोझ से दबे लोगों ने कर्जों को कम करने या पूर्णतः समाप्त कर देने की माँग की। किसानों को भी कीमते गिरने से नुकसान होने लगा, क्योंकि एक ओर तो उनके पास सेना की माँग घट जाने से भारी मात्रा में माल का स्टॉक जमा हो गया और दूसरी ओर ब्रिटिश वेस्ट इंडीज आदि के परम्परागत बाजार उनके हाथ से निकल गए। लड़ाई के दिनों में जो उद्योग खूब फल फूल रहे थे, उनके पास अब बहुत फालतू सामान जमा हो गया और उधर यूरोप से भी बेरोकटोक माल आने लगा, जिससे अमेरिका के पहले से ही भरे हुए बाजार और भी भर गए।

लेकिन जहाँ एक ओर अमेरिकन अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र मन्दी के शिकार हो रहे थे, वहाँ कुछ अन्य क्षेत्र खूब सक्रिय थे और उनका विस्तार हो रहा था। दक्षिण के बागान के मालिकों और जमींदारों को विदेशों से उनकी उपज की माँग आने के कारण लाभ हो रहा था। देश के आन्तरिक

सुधारो—जमीन, नहर, चुगी-चौकी और निर्माण कम्पनियो आदि—की ओर से पूंजी की माँग थी। वाणिज्य को भी अनेक माधनों से लाभ हो रहा था। कारण, यूरोप को माल का निर्यात बढ़ रहा था, अनेक अमेरिकन वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के अधिदान अभी तक जारी थे और फ्रेंच वेस्ट इंडीज के द्वार भी अमेरिकन व्यापार के लिए खुल गए थे। साथ ही हालैंड, एशिया और स्वीडन के साथ भी व्यापारिक समझौते किये गए थे।

लेकिन नई अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था और उसके विस्तार और समृद्धि की सम्भावनाओं को महामव नियमावली के अन्तर्गत ही रहना था। अर्थव्यवस्था को कमजोर करनेवाली यह नियमावली नया सविधान बनने तक, जो 1789 में स्वीकृत हुआ, राष्ट्र का काम चलाने के लिए तैयार की गई थी। इस नियमावली में राष्ट्रीय (केन्द्रीय) सरकार के हाथ में प्रायः कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि राज्यों को बहुत-से अधिकार अपने ही हाथ में रखने की अनुमति दे दी गई थी, जिनमें मुद्रा जारी करने का अधिकार भी शामिल था।

राज्य यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय (केन्द्रीय) राजस्व का कोई स्रोत स्थापित किया जाए। उस जमाने की आर्थिक मन्दी और धीरे-धीरे हो रहे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने राष्ट्र की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। राष्ट्र की राजस्व-आय आन्तरिक देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और विदेशी ऋणों के व्याज की देनदारियाँ भी बढ़ गई थी। सन् 1783 में व्याज की ये देनदारियाँ 31 लाख डालर थी और छ वर्ष बाद 1789 में वे 114 लाख डालर हो गईं।

इसलिए दुर्बल महासंघ-नियमावली के स्थान पर सुदृढ़ शासन की नई व्यवस्था अपनाने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। राजनैतिक गड़बड़ी और राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण आर्थिक और राजनैतिक हितों में एक तरह की अराजकता फैली हुई थी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक था कि एक नई शासन-प्रणाली स्थापित की जाए, अन्यथा राज्यों के स्थायी संघ-निर्माण और राष्ट्र की समृद्धि की रही-सही आशाएँ भी खत्म हो जाने की आशंका थी।

एक बार फिर अधिक शक्तिशाली और 'अधिक आदरणीय संघ' के

निर्माण की माँग उठी। यह माँग चार विभिन्न वर्गों की ओर से आई। ये चार वर्ग इस प्रकार थे—(1) वे व्यक्ति जिनके पास काफी मात्रा में कागजी मुद्रा, ब्रॉड और ऋण-पत्र थे, (2) विकासोन्मुख निर्माण उद्योगों के संचालक, जो विदेशी सामान और उद्योगों से संरक्षण चाहते थे, (3) देशी व्यापारी, जो स्थिर मुद्रा और प्रतिबन्धरहित अन्तर्राज्यीय व्यापार के समर्थक थे, और (4) जमीन का सट्टा-फाटका करने वाले, जिनका यह खयाल था कि एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो जाने से उनकी जमीनों की कीमतें चढ़ जाएँगी।

इनके अलावा भी बहुत-से ऐसे लोग थे, जो किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की आशा न होने पर भी एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के समर्थक थे। उनकी इस आकांक्षा का कारण राष्ट्रवाद की भावना थी, जो सारे राष्ट्र में प्रचल रही थी।

लेकिन शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के समर्थकों को ऋणग्रस्त लोगों के, खास तौर से पश्चिमी सीमा के साथ-साथ आबाद छोटे किसानों के, जो यह अनुभव करते थे कि केन्द्रीय सरकार के बजाय अलग-अलग राज्यों की सरकारें उनकी 'सस्ते ऋण', की माँग के प्रति अधिक सहानुभूति का रुख अपनाएँगी, विरोध का सामना करना पड़ा। ऋणग्रस्त वर्ग को उन लोगों का काफी समर्थन प्राप्त था जिन्हें यह भय था कि शक्तिशाली सरकार के बन जाने से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

साहूकारों और ऋण लेने वालों का संघर्ष मैसाचुसेट्स में अधिक उग्र रूप से सामने आया। वहाँ जो कर लगाये गए वे छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल और उन्हें ऋण देने वाले साहूकारों के लिए अनुकूल थे। नतीजा यह हुआ कि 1786 में इन ऋणग्रस्त किसानों ने राज्य सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मैसाचुसेट्स के अधिकारी कई महीनों तक इस विद्रोह को शान्त करने में असफल रहे, इसलिए इस विद्रोह ने ऋणग्रस्त लोगों का उद्देश्य मिट्ट करने के बजाय लोगों पर यह जाहिर किया कि एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की शीघ्र आवश्यकता है। एक अनुदार पन्थी ने तत्कालीन स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "गरीब की महत्वाकांक्षा और धनी के लोभ को राज्यीय शासन के सकरे स्तर पर कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता।"

ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि सविधान के निर्माण के लिए आयोजित महासम्मेलन, जो काफी कठिनाई और प्रयत्नों के बाद 1787 में फिलाडेल्फिया में बुलाया जा सका था, परस्पर-विरोधी आर्थिक हितों के संघर्ष में उलझ जाएगा। सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सामने सवाल यह था कि व्यवसायी पूंजीपति और कृषिजीवी पूंजीपति—दोनों के हितों की रक्षा के लिए समान संरक्षण कैसे निर्धारित किये जाएँ। किन्तु वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा एक शुरुआत थी। इसके बाद और भी अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ सिर उठाकर खड़ी हो गईं, जो एक साथ अनेक मोर्चों पर विकास का प्रयत्न करने वाले एक नवीन राष्ट्र के लिए स्वाभाविक ही थी। महासम्मेलन में विभिन्न प्रतिस्पर्धी वर्गों के बीच जो समझौते हुए वे विभिन्न आर्थिक वर्गों के बुनियादी अनैक्य की अभिव्यक्ति न होकर, राष्ट्र की सर्वाधिक शक्ति के स्रोत बन गए। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में एक समुचित शक्ति सन्तुलन स्थापित कर दिया।

ब्रिटिश पार्लमेन्ट के कानून, जिन्होंने अमेरिकनो को क्रान्ति के लिए मजबूर किया

कानून	मुख्य प्रावधान
1 जहाजरानी कानून, 1651	1 ब्रिटिश साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने वाले सामान ब्रिटिश या अमेरिकन जहाजों में ही टोए जाने चाहिएँ।
2 मुख्य वाणिज्य वस्तु कानून, 1663	2 यूरोपियन सामान इंगलिश बन्दरगाहों की मार्फत उपनिवेशों में भेजा जाना चाहिए।
3 जहाजरानी कानून, 1696	3 पिछले कानूनों पर कड़ाई से अमल की व्यवस्था।
4 ऊनी सामान कानून, 1699	4 उपनिवेशों में परस्पर ऊनी सामान के व्यापार का निषेध।
5 करीगर कानून, 1718	5 दक्षकारीगरो को इंग्लैंड से उपनिवेशों में आकृष्ट करने का निषेध।

6	शीरा कानून, 1733	6	ब्रिटिशतर क्षेत्रों में उपनिवेशों में आयातित चीनी, शीरा और शराब आदि पर भारी आयात शुल्कों की व्यवस्था।
7	चीनी कानून, 1764	7	शीरा कानून में लगाये गए शुल्कों को घटाकर आघात करने, किन्तु कानून को ज्यादा कड़ाई में लागू करने की व्यवस्था।
8	ग्टाम्प कानून, 1765	8	ब्रिटिश दम्नावेजों और विलानिता की वस्तुओं पर कर का प्रावधान।
9	नैतिक आवाज कानून, 1765	9.	अमेरिका में स्थित ब्रिटिश नैतिका का सरायों और खाली मकानों में ठहराने की व्यवस्था।
10	राज-घोषणा कानून, 1766	10	राजा और पार्लमेन्ट को उपनिवेशों में ऊपर स्थापित करने की घोषणा।
11	चाय कानून, 1772	11	अमेरिका में चाय निर्यात करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों

नया राष्ट्र

यद्यपि संयुक्त राज्य का संविधान लगभग 175 वर्ष पूर्व बनाया गया था, तो भी आज भी वह एक संप्राण और सक्रिय अभिलेख है। इन वर्षों में इसे अमेरिका के गतिशील समाज द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है और इसकी व्याख्याएँ भी समयानुसार बदलती रही हैं।

संविधान के स्वीकार किये जाने के बाद दो वर्ष के भीतर ही प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गारंटी देने के लिए उसमें दस संशोधन जोड़े गए। ये संशोधन 'अधिकारों का विधान' (बिल ऑफ राइट्स) कहलाते हैं। इन संशोधनों के अलावा मर्फ वारह अन्य संशोधन 1791 के बाद जोड़े गए हैं। राष्ट्र के स्थापकों के लिए यह बहुत बड़े श्रेय की बात है कि उन्होंने शासन की एक ऐसी पूर्ण प्रणाली तैयार की जिसमें ऐसी समस्याओं का भी समाधान विद्यमान था, जिनकी उस समय शायद कल्पना तक नहीं की जा सकती थी।

तत्काल यह संविधान अमेरिका के सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के बीच एक ऐसे समझौते के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें हर राज्य से अपनी प्रभुता के कुछ अंग का संघीय सरकार के पक्ष में परित्याग करने के लिए कहा गया था। वाशिंगटन के सर्वप्रथम प्रशासन के सदस्यों और प्रशासन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों में प्रारम्भ में विचारवारा सम्बन्धी जो मतभेद पैदा हुए उनका आधार यह विवाद था कि राज्य कितनी प्रभुसत्ता अपने हाथ में रखें और कितनी संघीय शासन के लिए छोड़ दें।

जो गुट केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था, उसके नेता विलियम मन्थी अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। उनके विरोधी, जिनके नेता परराष्ट्र मन्त्री टॉमस जैफर्सन थे, यह समझते थे कि केन्द्रीय सरकार को बहुत शक्तिशाली बनाना खतरनाक है, इसलिए राज्यों के अधिकारों पर

अधिक बल दिया जाना चाहिए। यह प्रारम्भिक बुनियादी विवाद किसी-न-किसी रूप में अब तक चला आ रहा है।

वाशिंगटन के राष्ट्रपतित्व का पहला कार्यकाल समाप्त होते-न-होते (1789-93) ये गुट अन्ततः दो अलग-अलग राजनीतिक दलों में बँट गए। हैमिल्टन का दल 'फेडरलिस्ट' (सघवादी) कहलाने लगा और जैफर्सन का दल 'रिपब्लिकन' (गणतन्त्रवादी)। जैफर्सन न केवल हैमिल्टन द्वारा की गई सविधान की व्याख्या के विरोधी थे, बल्कि वह वित्तमन्त्री के रूप में अपनाई गई उनकी वित्तीय नीतियों का भी विरोध करते थे।

हैमिल्टन के नेतृत्व में सघीय सरकार ने राज्यों के ऋणों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, संयुक्त राज्य का पहला राजकीय शासपत्रित बैंक स्थापित किया और उत्पादन करों की प्रणाली स्थापित की। जैफर्सन का कहना था कि वित्तमन्त्री के इन कार्यों से राज्यों की सरकारें कमजोर होती हैं और सघीय सरकार के हाथ में बहुत अधिक अधिकार आ जाते हैं। उनका यह भी खयाल था कि ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विपक्ष में और शहरों के पक्ष में जाते हैं और उनसे जन-साधारण के हितों को नुकसान पहुँचाकर व्यापारियों और साहूकारों के हाथों में बहुत अधिक ताकत दे दी गई है।

यद्यपि अमेरिका के लोग अक्सर हैमिल्टन की इस बात के लिए आलोचना करते रहे हैं कि उसने प्रारम्भिक अमेरिकन समाज के अभिजात वर्ग के हितों को समुन्नत किया, किन्तु वास्तव में उसकी वित्तीय नीतियों का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और समृद्ध राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के मिद्धान्तों को प्रस्थापित करना था। उसका यह विश्वास था कि देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर है कि "सरकार और व्यक्तियों के हितों के बीच अधिकाधिक स्नायु-सम्पर्क स्थापित किये जाएँ।" खास तौर से वह सरकार की पक्की साख कायम करने के लिए कृतसंकल्प था, क्योंकि उसका विश्वास था कि देश की आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।

सरकार की साख जमाने की समस्या के साथ-साथ एक समस्या और भी थी और वह यह कि क्रान्ति के दिनों में और उसके बाद सरकारों ने

देश और विदेश, दोनों से जो ऋण लिये थे, उनकी अदायगी कैसे की जाय। ये सारी देनदारियाँ (जिनमें विभिन्न राज्यों के युद्धकालीन ऋण भी शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी सघीय सरकार ने अपने ऊपर ले ली थी) 7 करोड़ 70 लाख डालर से अधिक की थी। अठारहवीं सदी में यह राशि निम्नदेह बहुत बड़ी थी।

अलग-अलग राज्यों के युद्धकालीन ऋणों की जिम्मेदारी सघीय सरकार ने हैमिल्टन के आग्रह से ही ली थी, हालाँकि जैफर्सन और अन्य लोगो ने उसका बहुत कड़ा विरोध किया था। उनका खयाल था—और ठीक खयाल था—कि इससे उन लोगो को लाभ नहीं होगा, जिन्होंने वास्तव में राज्य सरकारों को ऋण दिया था, बल्कि लाभ सटोरियों को होगा। लेकिन हैमिल्टन का आग्रह था कि अगर नये राष्ट्रों को सरकार की साख कायम करनी है तो ऋणों का पूरा भुगतान करना अनिवार्य है।

हैमिल्टन का कहना था कि राष्ट्रीय सरकार की साख तब तक कायम नहीं की जा सकती, जब तक कि उसके ऋण-पत्रों पर हस्तान्तरण की गारंटी न हो। उसकी राय में यह प्रश्न अप्रासंगिक था कि इस ऋण की अदायगी से अन्ततः लाभ किसे पहुँचता है।

हैमिल्टन और उसके अनुयायियों को कांग्रेस (संसद्) में यह कानून पास कराने के लिए दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों के काँफी वोट मिल गए, लेकिन इसके लिए उन्हें भी जैफर्सन की यह इच्छा पूरी करनी पड़ी कि नई राष्ट्रीय राजधानी (वाशिंगटन, डी० सी०) दक्षिण में स्थापित की जाय।

इसमें सन्देह नहीं कि वित्तमन्त्री के रूप में हैमिल्टन की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसने सरकार की साख कायम की। राष्ट्र का भावी आर्थिक विकास इसी पर निर्भर था। लोगो ने जो धन छिपाकर रखा हुआ था, वह बाहर निकल आया और लोगो का विश्वास नये गणराज्य पर जम गया।

लेकिन जिस प्रश्न ने अन्त में संयुक्त राज्य को स्पष्टतः राजनीतिक दलों में विभाजित किया और पहले से ही उग्र राजनीतिक विवाद को चरम सीमा पर पहुँचा दिया, वह था संयुक्त राज्य के एक राजकीय शासपत्रित बैंक की स्थापना का हैमिल्टन का प्रस्ताव।

हैमिल्टन की योजना के अनुसार इस शासपत्रित (चार्टर्ड) बैंक को ये कार्य करने थे—(1) नोट जारी करना, जो कागजी मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहे और इस प्रकार मुद्रा की पर्याप्त और स्थिर उपलब्धि में सहायता दे, (2) सरकारी बॉण्डों की विक्री आदि में सघीय सरकार के वित्तीय एजेंट का काम करना, (3) सरकारी निधि के एक सुरक्षित कोष के रूप में काम करना और अवसर पड़ने पर सरकार को ऋण देना, और व्यापारियों को ऋण देकर आर्थिक विस्तार को समुन्नत करना और व्यावसायिक लेन-देन के लिए बैंकिंग की सुविधाएँ प्रदान करना।

इसके जवाब में जैफर्सन का कटुता था कि इस तरह का बैंक एकाधिकारी बैंक होगा और राज्यों के बैंकों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा करेगा। उसने इस प्रस्ताव को 'असंवैधानिक' बताया क्योंकि संविधान में ऐसे बैंक की स्थापना की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैफर्सन के इस कथन से पहली

सभी समाज दो वर्गों में बँट जाते हैं—एक अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक। पहला वर्ग धनियो और कुलीनो का होता है और दूसरा आम जनता का जनता में हमेशा उफान और परिवर्तन आते रहते हैं; वह शायद ही कभी सही निर्णय करती है। इसलिए पहले वर्ग को शासन में एक सुनिश्चित और स्थायी हिस्सा दिया जाना चाहिए।

—अलेग्जेंडर हैमिल्टन

सभी लोगों की आँखें मनुष्य के अधिकारों के प्रति खुल गई हैं या खुलती जा रही हैं। विज्ञान के आलोक के प्रसार ने हर आदमी के सामने इस स्पष्ट सत्य को उद्घाटित कर दिया है कि आम जनता अपनी पीठ पर सवारी की ज़ीन कसकर पैदा नहीं हुई और न ही कुछ धनी और सौभाग्यशाली लोग भगवान् की कृपा से उस पर घुड़सवारी करने के अधिकार के साथ बूट और एड से लैस होकर पैदा हुए हैं।

—टॉमस जैफर्सन

बार यह प्रश्न सामने आया कि संविधान की व्याख्या कठोर होनी चाहिए

या उदार। साथ ही इमने 'विपक्षित शक्तियों' (इम्प्लाइड पावर्स) के सिद्धान्त को भी पहली बार प्रकट रूप में उपस्थित किया।

हैमिल्टन के अनुयायियों का कहना था कि सविधान की व्याख्या लचीली होनी चाहिए, क्योंकि सविधान के निर्माताओं की विवक्षा (कहने का अन्तर्निहित आशय) यह थी कि सयुक्त राज्य की सघीय सरकार के अधिकार केवल उतने ही नहीं होने चाहिएँ जितने कि स्पष्ट रूप में सविधान में विहित है। हैमिल्टन के अनुसार सविधान के 'अनुच्छेद 1' में स्पष्ट रूप में न कहे जाने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार के राजकीय शासपत्रित बैंक की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है, "कांग्रेस को वे सब कानून बनाने का अधिकार होगा जो सविधान द्वारा सयुक्त राज्य की सरकार में निहित अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक होंगे।" हैमिल्टन का तर्क था कि यहाँ 'आवश्यक' का अर्थ 'उपयुक्त' है। एक राष्ट्रीय बैंक मुद्रा जारी करने और सरकार की साख कायम करने के मामले में सघीय सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगा।

किन्तु जैफर्सन इस बात पर अड़ा रहा कि सविधान की व्याख्या गान्धिक ही होनी चाहिए, उसका अभिवेय अर्थ ही लिया जाना चाहिए विवक्षित नहीं। उसका कहना था कि कानूनी तौर पर सरकार सिर्फ वही अधिकार अपने हाथ में ले सकती है जो सविधान में स्पष्ट और प्रत्यक्ष विहित है।

परन्तु अन्त में हैमिल्टन की सिफारिशें ही स्वीकार की गईं। प्रबल विरोध के बावजूद पहला सयुक्त राज्य बैंक (बैंक ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स) 1791 में स्थापित हो गया और कांग्रेस ने उसे 21 वर्ष के लिए शासपत्र (चार्टर) दिया। इसकी एक करोड़ डालर की पूँजी का पाँचवाँ हिस्सा सघीय सरकार को देना था और गेप प्राइवेट निवेशकों से संग्रह किया जाना था। कानून में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि ये प्राइवेट निवेशक (इन्वेस्टर) ही बैंक को सरकार की कठोर देख-रेख में चलाएँगे और वित्तमन्त्री को उसके निरीक्षण का अधिकार होगा।

नई सघीय सरकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाने से उसके लिए और अधिक राजस्व प्राप्त करना जरूरी हो गया। इसलिए 1791 में कांग्रेस ने

घरो में बनाई जाने वाली शराब पर भारी टैक्स लगा दिया। इस टैक्स ने सीमावर्ती इलाको में रहने वाले लोगो में भारी अमन्तोष पैदा कर दिया, जो अक्सर अपने लिए घर पर ही शराब तैयार करते थे। इस असन्तोष ने ही 1794 में पश्चिमी पेनसिलवेनिया में 'व्हिस्की विद्रोह' भड़काया। हैमिल्टन की सलाह पर सघीय सरकार ने मिलीशिया को यह विद्रोह दवाने के लिए बुला लिया और उसने फिर से व्यवस्था स्थापित कर दी। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह नहीं था कि सघीय सरकार का राजस्व बढ़ गया, बल्कि यह था कि इसने नई सरकार को अपने कानूनों को लागू करने के लिए कृतसकत्प और साथ ही सक्षम सिद्ध कर दिया।

नए गणराज्य की शक्ति की परीक्षा अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर हो रही थी। सयुक्त राज्य का व्यापार अब भी मुख्यतः यूरोप पर ही निर्भर था। किन्तु इंग्लैंड ने पेरिस की संधि की शर्तों के बावजूद नियमित व्यापार समझौते की बातचीत करने से इन्कार कर दिया। यही नहीं, उसने उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में अपने किले खाली करने से इन्कार करके भी सन्धि की अवहेलना की।

नए राष्ट्र को मिसिसिपी नदी में नौकानयन, सयुक्त राज्य और स्पेनिश फ्लोरिडा के बीच की सीमा, और स्पेनिश प्रदेश से इंडियन लोगो के हमलो के प्रश्नों पर स्पेन से भी उलझना पड़ा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भी सयुक्त राज्य को निरन्तर परेशानी रही।

वाशिंगटन प्रशासन के सामने सबसे अधिक गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या यह निश्चय करने की थी कि फ्रेंच-क्रान्ति के सम्बन्ध में सयुक्त राज्य की सरकार का रुख क्या होना चाहिए। मन् 1789 में वाशिंगटन के पहली बार पदारूढ होने के कुछ ही दिन बाद वैस्टील पर फ्रेंच क्रान्तिकारियों का अधिकार हो गया। शुरु में फ्रांस के वूर्वी राजवंश के विरुद्ध क्रान्ति के प्रति सयुक्त राज्य में सहानुभूति का रुख था। अमेरिकनो को डम बात पर गर्व था कि स्वयं उन्ही के कारनामो ने फ्रेंच लोगो में क्रान्ति की भावना पैदा की है।

लेकिन जब फ्रेच-क्रान्ति ने आतक के राज्य का रूप धारण कर लिया और अनेक यूरोपियन देशों के राजतन्त्र इस क्रान्ति को कुचलने के लिए आगे आए तो सयुक्त राज्य के लिए फ्रांस का पक्ष लेना कठिन हो गया। जब इंग्लैंड 1791 में लडाई में उतर आया तो सयुक्त राज्य के सामने एक दुविधा पैदा हो गई। उस पर फ्रांस का बड़ा अहसान था, क्योंकि फ्रेच लोगो ने अमेरिकन क्रान्ति में सहायता दी थी। लेकिन अमेरिका खुले तौर पर फ्रेच लोगो की सहायता करता तो इंग्लैंड की ओर से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होना अनिवार्य था।

इस दुविधा और गतिरोध ने अमेरिका में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। जैफर्सन के अनुयायियों की क्रान्तिकारियों से गहरी सहानुभूति थी, किन्तु हेमिल्टन के अनुयायी अंग्रेजों के समर्थक थे।

किन्तु राष्ट्र की सहानुभूति फ्रेच लोगो के प्रति होने और परराष्ट्र-मन्त्री जैफर्सन के विरोध के बावजूद वाशिंगटन ने 1793 की तटस्थता की घोषणा जारी कर दी, जिसे लेकर खूब वाद-विवाद खड़ा हो गया। सब मिलाकर इस घोषणा में फ्रांस के साथ हुई मैत्री और गठबन्धन की सन्धि की अवज्ञा कर दी गई थी। यह सन्धि 1778 में उस समय हुई थी, जब अमेरिकन क्रान्ति के प्रारम्भ में फ्रांस ने अमेरिका को सहायता देनी शुरू की थी।

तटस्थता की घोषणा होते ही फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों ने अमेरिका के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जिससे इस तटस्थता की रक्षा करना कठिन हो गया। ब्रिटेन ने अमेरिकन जहाजों के खिलाफ डिग्रियाँ जारी कर दी और सयुक्त राज्य के जहाज पकड़ लिये और अमेरिकन जहाजियों को जबरदस्ती ब्रिटिश नौसेना में भरती कर लिया। इससे स्वभावतः अमेरिका के राष्ट्रीय अभियान को चोट लगी और राष्ट्र के व्यापार-वाणिज्य को भी धक्का पहुँचा।

सयुक्त राज्य में ब्रिटिश-विरोधी भावना बहुत उग्र हो गई। इंग्लैंड के साथ मचमुच नये युद्ध का खतरा पैदा हो गया, खासतौर से तब, जबकि नई व्यापार सन्धि की वार्ता के लिए वाशिंगटन द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि जॉन जे पर ब्रिटेन ने अपनी मनमानी गतें थोप दी और वह उन्हें स्वीकार करके

चला आया। लेकिन वार्निगटन ब्रिटेन की इन कड़ी शर्तों का कड़वा घूंट चुपचाप पी गया, क्योंकि वह जानता था कि उस समय एक और लड़ाई लड़ना निःसंदेह उसके देश के लिए वातक होगा। उसके प्रभाव और प्रतिष्ठा के फलस्वरूप कांग्रेस में वह सधि स्वीकार हो गई और खतरा टल गया।

सन् 1800 में संयुक्त राज्य की स्थिति

राज्य	संघ में प्रवेश की तिथि	जन-संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मील)
डेलेवारा	7 दिसम्बर, 1787	64,273	2,057
पेनसिल वेनिया	12 दिसम्बर, 1787	6,02,365	45,333
न्यू जर्सी	18 दिसम्बर, 1787	2,11,149	7,836
जार्जिया	2 जनवरी, 1788	1,62,686	58,876
कनैक्टिकट	9 जनवरी, 1788	2,51,002	5,009
मैसाचुसेट्स	6 फरवरी, 1788	5,74,564	41,472
मेरीलैंड	28 अप्रैल, 1788	3,41,548	10,577
इक्षिणी कैरोलाइना	23 मई, 1788	3,45,591	31,055
न्यू हैम्पशायर	21 जून, 1788	1,83,858	9,304
वर्जीनिया	26 जून, 1788	8,80,200	64,996
न्यूयार्क	26 जुलाई, 1788	5,89,051	49,576
उत्तरी कैरोलाइना	21 नवम्बर, 1789	4,78,103	52,712
रोड आइलैंड	29 मई, 1790	69,122	1,214
वरमौट	4 मार्च, 1791	1,54,465	9,609
कैटकी	1 जून, 1792	2,20,955	40,395
टैनेसी	1 जून, 1796	1,05,602	42,244

वाशिंगटन की अन्य राष्ट्रों के साथ 'उलझाने वाले गठबन्धन' न करने की नीति ने, जिसे उसने 1796 में अपने प्रसिद्ध विदाई भाषण में फिर दोहराया, उन्नीसवीं शताब्दी में बरती गई राष्ट्र की विदेश नीति की नींव रख दी। इस नीति का प्रतिपादन करने के कारण उसे और उसकी फेडरलिस्ट पार्टी को अक्सर अपने प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकनों की कठोर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। फिर भी फेडरलिस्ट पार्टी 1796 का चुनाव जीत गई और जॉन ऐडम्स राष्ट्रपति बन गया।

ऐडम्स की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने देश को फ्रांस के साथ, जो 'जे सन्वि' के कारण अमेरिका का अधिकाधिक दुश्मन बनता जा रहा था, लड़ाई में पड़ने से बचा लिया। किन्तु ऐडम्स के शासन में कांग्रेस ने, जिसमें फेडरलिस्टों का बहुमत था, रिपब्लिकनों के विरोध को कुचलने के लिए बहुत-से कानून पास किये, लेकिन उनका वास्तविक नतीजा यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर ही प्रतिबन्ध लग गए। इससे अनेक नागरिक भड़क उठे। फेडरलिस्ट पार्टी को वे 'सम्पत्तिशाली वर्गों की पार्टी' कहने लगे और उसके बारह वर्ष के शासन के बाद ही उनका उस पर से विश्वास उठ गया। सन् 1800 के चुनाव में उन्होंने टॉमस जैफर्सन को राष्ट्रपति चुन दिया और इस प्रकार रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में शासन की बागडोर आ गई। (इस जमाने की रिपब्लिकन पार्टी ही बाद में आज की डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई। आज की रिपब्लिकन पार्टी के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है)।

फेडरलिस्ट पार्टी ने नये राष्ट्र के निर्माण में भारी योग दिया था। शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की नींव डालने और सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने का अविकतर श्रेय उसी को है। यद्यपि जैफर्सन के चुनाव के बाद फेडरलिस्ट पार्टी क्षीण हो गई और अन्त में उसका अस्तित्व भी लुप्त हो गया, तो भी उसका प्रभाव तत्काल समाप्त नहीं हुआ। जैसा कि हम आगे देखेंगे, नई रिपब्लिकन सरकार उसी आर्थिक ढाँचे के भीतर काम करती रही, जो वाशिंगटन और ऐडम्स के फेडरलिस्ट प्रशासनों ने स्थापित किया था।

किसी भी सच्चे अमेरिकन के मन में इस बारे में सन्देह नहीं पैदा हो सकता कि क्या हमें अपने नागरिकों और सम्पत्ति पर किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाना चाहिए या उन्हें स्वतन्त्र रहने देना चाहिए, और सचमुच गम्भीरता से एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो निर्माता और किसान दोनों को एक-दूसरे के निकट ला सके और हर व्यक्ति के लिए पारस्परिक श्रम और सुख-सुविधाओं के विनिमय का अवसर उपस्थित कर सके, जिसकी अब तक हम दूर के प्रदेशों में जाकर खोज करते रहे हैं और जिसके लिए हमने हमेशा लड़ाई तक का खतरा मोल लिया है।...

—(1808 के प्रतिबन्ध कानून पर जैफर्सन के भाषण का एक अंश)

जैफर्सन काल

जिस चुनाव ने 1800 में जैफर्सन की रिपब्लिकन पार्टी को मत्तारुढ़ किया, उसे एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका के उस समय के स्वतन्त्रकालीन इतिहास में 'पहली राजनीतिक क्रान्ति' कहा जाता था। इसका अर्थ यह था कि राजनीतिक सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन आया था। वह उत्तर-पूर्व के हाथ से निकलकर दक्षिण के हाथ में अथवा पूँजीपति व्यापारी वर्ग के हाथ से निकलकर कृषि-जीवी पूँजीपतियों के हाथ में चली गई थी। जैफर्सन और उसकी पार्टी छोटे स्वतन्त्र किसानों, छोटे व्यापारियों और आमूल परिवर्तनवादी (रेडिकल) बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने फेडरलिस्ट पार्टी के हाथों से शासन-सत्ता छीनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि 'वह ऐसे दौलतमन्दों और बुद्धिजीवियों का अल्पतन्त्र (ओलिगार्की) है, जिनमें स्थायी राज्य तन्त्र के लिए आवश्यक मात्रा में व्यापकता और गहराई

नहीं है।”

न केवल अमेरिका के, बल्कि यूरोप के भी, धनी और सम्पत्तिशाली व्यक्ति जैफर्सन की विजय को इस नए राष्ट्र के आसन्न पतन का लक्षण समझने लगे थे। दूसरी और नई सरकार के मित्र और हितैषी यह कहते थे कि अब जल्दी ही ‘अत्याचारी’ प्रशासन का और अलेग्जेंडर हैमिल्टन द्वारा अपनाई गई अनुदार वित्तीय नीतियों का अन्त हो जाएगा। लेकिन वाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि जैफर्सन की सरकार के समर्थक और विरोधी, दोनों के ही विचार गलत थे।

यह मानने का पर्याप्त कारण है कि जैफर्सन की रिपब्लिकन पार्टी के सत्तारूढ़ हो जाने से अमेरिका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों क्षेत्रों में गम्भीर अशान्ति और सकट से वंच गया। हैमिल्टन और न्यू इंग्लैंड के फेडरलिस्टों ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए काफी प्रयत्न किया था। इसका उद्देश्य कुछ तो फ्रांस द्वारा अमेरिकन वाणिज्य-व्यवसाय की लूट का बदला लेना था और कुछ फ्रांस-समर्थक रिपब्लिकन पार्टी को बदनाम करना था। यद्यपि राष्ट्रपति ऐडम्स युद्ध को टालने में सफल हो गए थे, तो भी उनके प्रणामन काल में फ्रांस के साथ हमारे सम्बन्ध इतनी नाजुक स्थिति में पहुँच गए थे कि काफी व्यापक पैमाने पर और काफी महँगी युद्ध की तैयारियाँ आवश्यक समझी जाती थी। और इन तैयारियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के जो उपाय वरते गए, वे किसी भी कदर लोकप्रिय नहीं थे। गुलामो और स्थावर सम्पत्ति पर लगाये गए टैक्स ने दक्षिणी राज्यों में, जहाँ रिपब्लिकनों का प्रभाव था, इतना उग्र विरोध का भाव पैदा किया कि फेडरलिस्ट शासन में वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए एक बार फिर मिली-गिया (militia) का इस्तेमाल करना पड़ा।

देश में बढ़ते हुए विरोध को दबाने के लिए फेडरलिस्ट शासन के अन्तर्गत कांग्रेस ने प्रसिद्ध विदेशी और राजद्रोह कानून (1798) पास किए जिनमें राष्ट्रपति को विदेशी लोगों को निर्वासित करने और सरकार के कानूनों की आलोचना करने वाले देशवासियों को कैद और जुर्माने की सजा देने का अधिकार प्रदान किया गया था। दक्षिण में इन कानूनों की जो प्रतिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप अनेक दक्षिणी राज्य विद्रोह पर आमादा

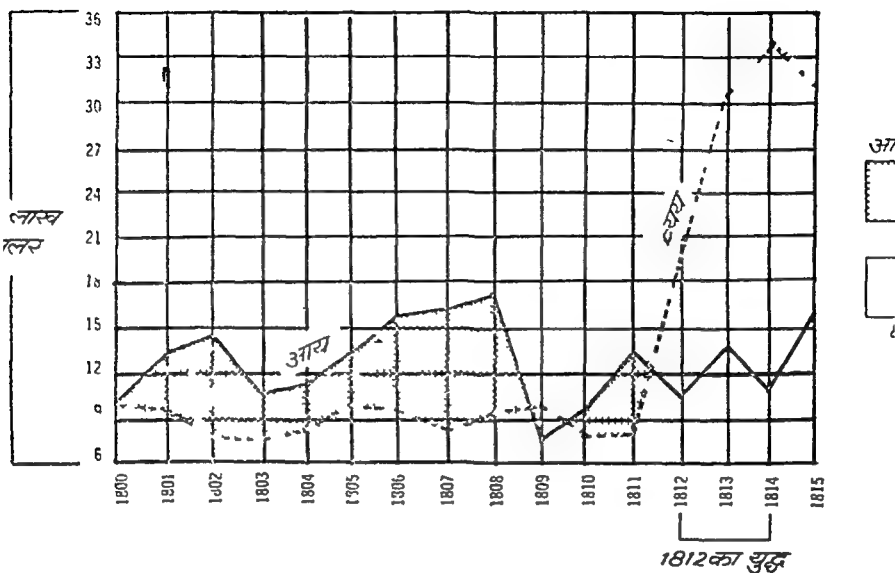
हो गए। सन् 1799 में वर्जीनिया और कैंटकी राज्यो ने प्रस्ताव किये, जिनमें कानूनों के अकृतीकरण (नलिफिकेशन) के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था—इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह था कि कोई भी राज्य किसी भी सघीय कानून को अकृत और शून्य (नल ऐंड वॉयड) घोषित कर सकता है।

एक तरह से जैफर्सन अपने इस विचार के प्रति वफादार रहा कि 'जो कम-से-कम शासन करता है उसी का शासन सर्वोत्तम होता है।' फेडरलिस्टों द्वारा पास किये गए घृणित विदेशी और राजद्रोह कानून की अवधि में वृद्धि नहीं की गई और तमाम मौजूदा आन्तरिक राजस्व-कर रद्द कर दिये गए। (किन्तु अधिकतर सरक्षात्मक तट-कर कायम रखे गए, वल्कि उनकी अवधि बढ़ा दी गई)। सैनिक बजट कम कर दिया गया। पहले जहाँ वह औसतन प्रतिवर्ष 60 लाख डालर का रहता था, वहाँ वह घटाकर 10 लाख डालर कर दिया गया।

जैफर्सन ने अपने आठ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रीय ऋण को एक-तिहाई कम करके एक तरह का वित्तीय चमत्कार ही किया था। हालाँकि लुइसियाना प्रदेश को खरीदने से ऋण की रकम में उसकी कीमत की डेढ़ करोड़ डालर की राशि बढ़ गई थी, तो भी कुल ऋण में एक तिहाई की कमी हो गई। राष्ट्र की औसत वार्षिक राजस्व आय एक करोड़ डालर थी, जिसका आधे के लगभग हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च कर दिया जाता था। उस जमाने में संयुक्त राज्य का शासन चलाने के लिए करीब 60 लाख डालर की राशि ही पर्याप्त होती थी। आज संयुक्त राज्य के सघीय शासन को चलाने के लिए 80 अरब डालर से अधिक खर्च आता है।

किन्तु बजट के आँकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। यद्यपि जैफर्सन ने राष्ट्रीय ऋण और सरकार के व्यय को घटा दिया, तो भी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में फेडरलिस्ट पार्टी जो भूमिका अदा करती थी, वह कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। रिपब्लिकनों को अपने नेता की इच्छा के विरुद्ध ऐसी नीतियों का समर्थन करना पड़ा, जिनका अब तक वे कड़ा विरोध करते रहे थे। वास्तव में स्थिति यह थी कि जैफर्सन हालाँकि राज्यो के अधिकारों को बढ़ाने और सरकारी हस्तक्षेप और शासन को अधिक-से-

संघीय सरकार की वित्त स्थिति, 1800-1815

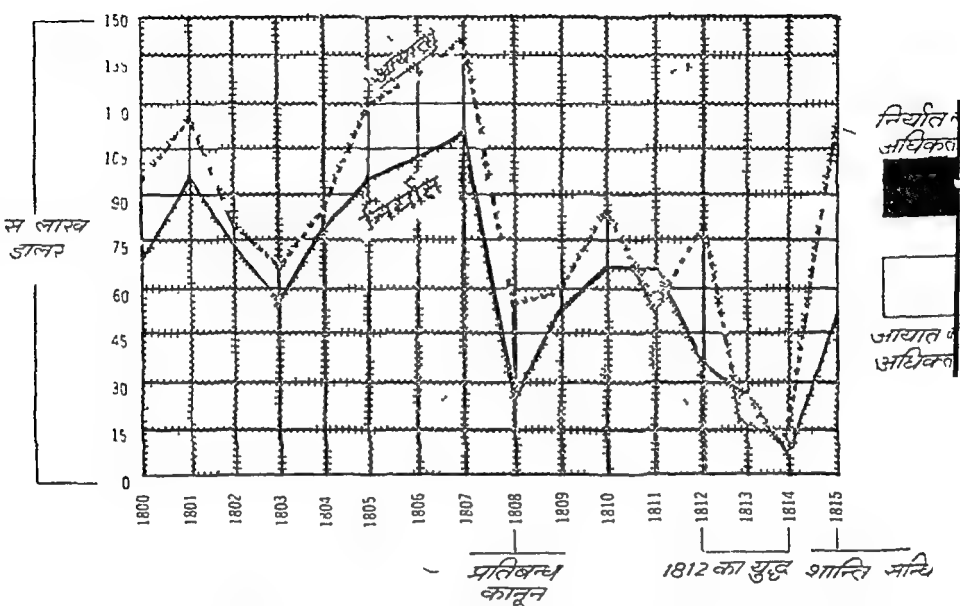


अधिक सीमित करने की नीति का सबसे बड़ा प्रतिपादनकर्त्ता था, फिर भी उसके शासन में संघीय सरकार ने कई नए प्रदेश अपने अधिकार में लिये और केन्द्रीय सरकार के अधिकारों में भी काफी वृद्धि हुई।

मन् 1803 में लुइसियाना प्रदेश को फ्रांस से खरीद लेने पर संघीय सरकार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। इस विशाल प्रदेश ने राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र करीब 40 प्रतिशत बढ़ा दिया। बाद में तमाम के तमाम तेरहों राज्य या उनके कुछ हिस्से इसी प्रदेश में से काटकर बाँटे गए। यह प्रदेश संघीय सरकार की सम्पत्ति बन जाने पर, इसकी भावी आर्थिक अभिवृद्धि और विकास राज्यों की सरकारों के बजाय केन्द्रीय सरकार पर निर्भर हो गया। यह एक विचित्र विडम्बना है कि जिस समय कांग्रेस में लुइसियाना प्रदेश की खरीद की सन्धि पर बहस चल रही थी, उस समय रिपब्लिकनो ने संघीय सरकार के अन्य प्रदेशों को खरीदने के विवक्षित अधिकार का जोरों से समर्थन किया और फेडरलिस्ट पार्टी एक-एक राज्यों के अधिकारों और

नविधान की स्पष्ट और शाब्दिक अभिधेय व्याख्या की समर्थक बन गई ।
 नवय रिपब्लिकनों ने, खानकर पार्टी के पश्चिमी राज्यों के सदस्यों ने ही
 जैफर्सन को उस नये विद्याल पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश की आवश्यकताएँ
 पूरी करने के लिए नई सरकारी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए प्रेरित
 किया ।

संयुक्त राज्य का विदेशी व्यापार, 1800-1 15



की विस्तृत योजना प्रस्तुत की। यह निर्माण-योजना दस वर्ष में पूरी की जानी थी और उस पर बीस लाख डालर वार्षिक खर्च का अनुमान था।

इन सब खर्चों को स्वीकार करते हुए जैफर्सन को फिर फेडरलिस्ट पार्टी के विवक्षित अधिकारों के सिद्धान्त के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि संविधान में कहीं भी सघीय सरकार को स्पष्ट रूप में आन्तरिक सुधार करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

जैफर्सन को लगातार दो बार राष्ट्रपति चुना गया और उसने दोनों बार के अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की, फिर भी इस अवधि में उसकी पार्टी में अन्दर ही-अन्दर फूट बढ़ती गई और साथ ही ब्रिटिश सरकार के साथ भी संयुक्त राज्य सरकार की उलझनों में वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि जैफर्सन के अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यों का प्रभाव नष्ट हो गया। उसके पहले कार्यकाल की समाप्ति पर उसका कोई भी प्रगमक देखकर यह कह सकता था कि "उस समय तक जैफर्सन के शासन

के समान अच्छा और उज्ज्वल शासन और किसी का नहीं रहा।” उसकी इस प्रशंसा का बाद के इतिहासकार खडन नहीं कर सकते थे। किन्तु उसके दूसरे कार्यकाल की समाप्ति पर उसके कट्टर उत्साही समर्थक भी ऐसा दावा करने में हिचकिचाते।

अपने दूसरे कार्यकाल में जैफर्सन के लोकप्रियता खो देने का मुख्य कारण उसकी वैदेशिक नीतियाँ थी। यद्यपि संयुक्त राज्य नेपोलियन के यूरोप-विजय के अभियान से बिल्कुल अलग था, फिर भी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही समुद्र में अमेरिका के अधिकारों की उपेक्षा करते थे। ब्रिटिश लोग अमेरिका के व्यापारिक जहाजों को परेशान करते थे, वे उनके आदमियों को जबरदस्ती पकड़ लेते, माल पर कब्जा कर लेते और कभी-कभी सारा जहाज ही अपने अधिकार में ले लेते। ऊपर से वे यह दिखाया करते कि वे नौसेना से भाग जाने वाले भगोड़े सैनिकों की खोज के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी ओर नेपोलियन ने भी यह आदेश जारी कर दिया कि जो अमेरिकन जहाज ब्रिटेन के साथ व्यापार करते हैं या ब्रिटेन द्वारा ली जाने वाली तलाशियों को वर्दाश कर लेते हैं, उन्हें फ्रेंच जहाज पकड़ सकते हैं।

जैफर्सन ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ‘शान्तिपूर्ण दबाव’ डालने का प्रयत्न किया। उसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1807 के आखिरी दिनों में एम्बार्गो ऐक्ट (प्रतिबन्ध कानून) पास किया, जिसमें नमूचे अमेरिकी व्यापारिक जहाजों वेड़े को विदेशों के साथ व्यापार करने में रोक दिया गया। विश्व के इतिहास में इससे पूर्व ऐसा कदम कभी नहीं उठाया गया था। इस कानून का उद्देश्य युद्ध के खर्चीले तरीके के बजाय आर्थिक मजबूरी के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका के साथ सम्झौते के लिए झुकाना था।

लेकिन जैफर्सन ने यूरोप के राष्ट्रों के साथ अमेरिकन व्यापार को जितना महत्त्व दिया था, वास्तव में उमका उतना महत्त्व नहीं था। इस प्रतिबन्ध का फ्रांस पर प्रायः कोई भी प्रभाव नहीं था। यद्यपि ब्रिटेन को इसमें कुछ कठिनाई हुई, किन्तु ब्रिटिश व्यापारियों ने भी अमेरिका के बजाय स्पेन, दक्षिणी अमेरिका और कनाडा को अपने माल का निर्यात करके इस कठिनाई को काफी हद तक हल कर लिया।

सन् 1808 का 'प्रतिबन्ध वर्ष' जैसे-जैसे गुजरता गया, यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होने लगी कि इस प्रतिबन्ध से सबसे ज्यादा नुकसान न्यू इंग्लैंड के निर्यातको और दक्षिणी राज्यों के किसानों को हो रहा है। संयुक्त राज्य का वार्षिक निर्यात 10 करोड़ 80 लाख डालर से घटकर 2 करोड़ 20 लाख डालर रह गया। जहाज बन्दरगाहों में बेकार खड़े रहते थे और माल गोदामों में पड़ा सड़ता था। इसके साथ ही कृषि-जिन्सों की कीमतें बेहद गिर गईं। आटे का भाव आधा रह गया, दक्षिण के कुछ भागों में घोड़ा ढाई डालर तक की बिकने लगा और सूअर तो लोग मुफ्त ही देने लग गए। लेकिन अन्ततः यह प्रतिबन्ध न्यू इंग्लैंड के निर्माण-उद्योगों के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ क्योंकि विदेशी सामान के न आने से इस क्षेत्र में निर्माण-उद्योगों को खूब बढ़ावा मिला। पर 1808 में इस प्रतिबन्ध के ये लाभकारी परिणाम लोगों को उतने स्पष्ट नजर नहीं आते थे जितना कि निर्यातकों को होने वाला नुकसान।

इसलिए स्वभावतः राजनीतिक असन्तोष ने देश पर जैफर्सन के प्रभाव को कम कर दिया। न्यू इंग्लैंड में फेडरलिस्ट पार्टी फिर उभर आई और उसके समर्थकों और अनुयायियों ने व्यापारियों को इस प्रतिबन्ध की अवहेलना करने के लिए उकसाया। पश्चिम और दक्षिण में, रिपब्लिकन लोग, जो पहले पार्टी के प्रति वफादार थे, जैफर्सन की गान्तिवादी नीतियों से असन्तुष्ट हो रहे थे, और वहाँ के फार्मों में अब लड़ाई की बातें होने लगी थी। अन्त में 1809 के प्रारम्भ में जैफर्सन ने राजनीतिक दबाव के आगे झुककर धृणित 'प्रतिबन्ध कानून' को रद्द करने वाले विधेयक पर दस्तखत कर दिये। ऐसा करके उन्होंने एक तरह से अपनी विदेश नीति की असफलता स्वीकार कर ली और इस निराशापूर्ण स्थिति में ही उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ।

किन्तु जैफर्सन का प्रभाव उम्र समय भी इतना तो था ही कि उनकी प्रेरणा से जेम्स मैडिसन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। खुद जैफर्सन ने ही मैडिसन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसन्द किया था। मैडिसन ने अमेरिका के जहाजरानी सम्बन्धी अधिकारों के लिए ब्रिटेन के साथ समझौते का भरसक प्रयत्न किया। इसी बीच पश्चिमी राज्यों के रिपब्लिकनों ने, जो अब 'वार हॉक' (लडाकू वाज) के नाम से विख्यात हैं, कांग्रेस में

प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया था और वे ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ भड़का रहे थे। 'लडाकू बाज' ब्रिटेन द्वारा अमेरिकन जहाजों को परेशान किए जाने से उतने चिन्तित और क्रुद्ध नहीं थे, जिनने कि इस बात से थे कि ब्रिटेन अमेरिकनो को पश्चिम की ओर बढ़ने और फैलने से रोकने का प्रयत्न कर रहा है। इन लोगों की लुब्ध दृष्टि कनाडा के ब्रिटिश प्रदेशों पर भी लगी हुई थी। इनके आन्दोलन से कांग्रेस ने, जो दो वर्गों में बँट गई थी, 8 जून, 1812 को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मजा यह कि इस घोषणा से दो दिन पूर्व ही मैडिसन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटेन ने अमेरिकन जहाजों को परेशान न करने का वायदा किया था। यदि अटलांटिक महासागर के उस पार से इस पार तक द्रुत गति से सन्देश भेजने के साधन उस समय मौजूद होते और ब्रिटेन का यह वायदा अमेरिका में यथासमय पहुँच जाता तो यह युद्ध टल जाता।

यद्यपि कनाडा पर आक्रमण के संयुक्त राज्य के प्रयत्न असफल हो गए तो भी समुद्र में की गई उसकी कार्रवाइयाँ अधिक सफल रही। वास्तव में 1812 की लड़ाई मुख्यतः अटलांटिक तट और ग्रेट लेक्स के साथ-साथ ब्रिटिश और अमेरिकन जहाजों के बीच की छुट-पुट लड़ाई ही थी। समुद्री लड़ाई से कोई फायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें कभी एक पक्ष जीतता और कभी दूसरा। इस तरह की निरर्थक लड़ाई में जल्दी ही यह भुला दिया गया कि आखिर लड़ाई हो किस लिए रही है। इस निरर्थकता की एक झलक इस बात से मिल सकती है कि 1814 के दिसम्बर महीने में जब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए शान्ति संधि हुई तो उसमें समुद्र में जहाजरानी की स्वतन्त्रता के सवाल की, जिसे लेकर प्रारम्भ में संयुक्त राज्य ने लड़ाई छेड़ी थी, बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई।

युद्ध की शुरुआत जैसे संचार और सन्देश प्रेषण के द्रुत साधनों के अभाव के साथ हुई थी, वैसे ही उसका अन्त भी इस अभाव के साथ ही हुआ। न्यू ऑर्लियन्स में दोनों पक्षों की आखिरी स्थलीय लड़ाई शान्ति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद हुई, क्योंकि दोनों पक्षों की सेनाओं तक यह सन्देश पहुँचा ही नहीं था कि लड़ाई का अन्त कर दिया गया है। और यही एकमात्र ऐसी स्थलीय लड़ाई थी जिसमें अमेरिकनो ने निर्णायक विजय प्राप्त

की थी। इस विजय से अमेरिकन सेना का कमांडर ऐंड्रयू जैक्सन राष्ट्रीय वीर बन गया। इस लड़ाई में प्राप्त विजय से वह इतना लोकप्रिय हो गया कि अन्त में जनता ने उसे राष्ट्रपति चुन लिया।

सन् 1812 का युद्ध बिलकुल निरर्थक था। उसकी शुरुआत तब हुई जब कि राजनयिक जरियो से पहले ही समझौता हो चुका था। और उसका अन्त भी एक ऐसी भयंकर लड़ाई के साथ हुआ, जो गान्ति सवि पर हस्ताक्षर के बाद हुई और जिसमें काफी प्राण हानि हुई। किन्तु इस लड़ाई का एक लाभ भी हुआ। इसने अमेरिका के लोगो में आत्मविश्वास पैदा किया और राष्ट्रीयता की एक नई भावना को जन्म दिया। अनेक अमेरिकनो ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र ने दूसरा स्वातन्त्र्य युद्ध जीता है।

अमेरिका की असली स्वतन्त्रता का कारण है उसका विशाल प्रादेशिक विस्तार और कम आबादी। आप जहाँ जाएँ वही आपको निहायत सस्ती, या यो कहिए मिट्टी के मोल, अच्छी जमीन मिल सकती है, इसलिए हर आदमी अपने मन के मुताबिक जगह पा सकता है। यूरोप के सभी देशों के गरीब मजदूर इस सस्ती जमीन के बारे में सुनते हैं और उसकी ओर खिंचे चले आते हैं वे यहाँ आकर मेहनत करते हैं और खूब खुशहाल हो जाते हैं। यही अमेरिका की असली आजादी है।

—1812 के युद्ध के बाद इलिनॉय में आबाद अंग्रेज जॉर्ज पलावर की उक्ति

सद्भावनाओं का युग

उन्नीसवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में अविकाधिक अमेरिकनो का यह विश्वास होता जा रहा था कि उनके राष्ट्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। किन्तु सरकार के कार्य-कलाप, स्थानीय स्वशासन के स्तर को छोड़कर और कहीं भी, उनके दैनिक कामों पर बहुत कम प्रभाव डालते थे। हालाँकि वे समुद्र तट से लेकर पश्चिम तक फैले विस्तृत भूप्रदेश में रहते थे, तो भी इस जमाने के लोग अधिकतर बाहर नहीं जाते थे और गए भी तो उनकी दौड़ अपने जन्मस्थान से एक दिन के सफर की दूरी तक के स्थानों तक ही सीमित होती थी।

सन् 1800 में संयुक्त राज्य की जनसंख्या लगभग 55 लाख थी। इसमें से पाँचवाँ हिस्सा आबादी गुलामों की थी। यह अनुपात 1775 से इसी तरह चला आ रहा था। सन् 1808 में गुलामों का आयात बन्द हुआ और उसके बाद आजाद अमेरिकनो के साथ उनका अनुपात कम होने लगा। पाँच प्रति-

शत से भी कम वस्तियों की जनसंख्या 6 हजार या इससे अधिक थी। लगभग 94 प्रतिशत आवादी 2500 या इससे भी कम आवादी के गाँवों या दूर-दराज के फार्मों में बने अलग-अलग मकानों में रहती थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिकन गाँवों में काम और खेल एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आदमी को हर हफ्ते औसतन 72 घण्टे यानी प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। लम्बी छुट्टी उन दिनों होती ही नहीं थी। रविवार को छोड़कर साधारण छुट्टियाँ भी बहुत कम थीं। यात्रा बहुत धीमी, कठिन और आम तौर पर महँगी होती थी।

आदमी की पोशाक और भोजन उसकी सामाजिक स्थिति के द्योतक समझे जाते थे। किन्तु सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होने पर रेशम और लिनन के कपड़े का इस्तेमाल जल्दी ही खत्म हो गया और सभी मौसमों में ऊनी कपड़ा पहनने के चलन में भी कमी हो गई। पहरावे का एक सामान्य स्तर स्थापित होता गया, किन्तु अमीर और गरीब के भोजन में उस समय भी बहुत अधिक अन्तर बना रहा।

सन् 1800 में उत्पन्न अमेरिकन की जीवन की आशा 35 वर्ष थी। टाइफाइड, मलेरिया, गठिया और अजीर्ण उस समय की आम बीमारियाँ थीं और एक और बीमारी थी जो प्रायः सभी लोगों को पकड़ती थी। उसका ठीक-ठीक निदान नहीं किया जा सका, इसलिए उसे सिर्फ 'ज्वर' का नाम दिया जाता था।

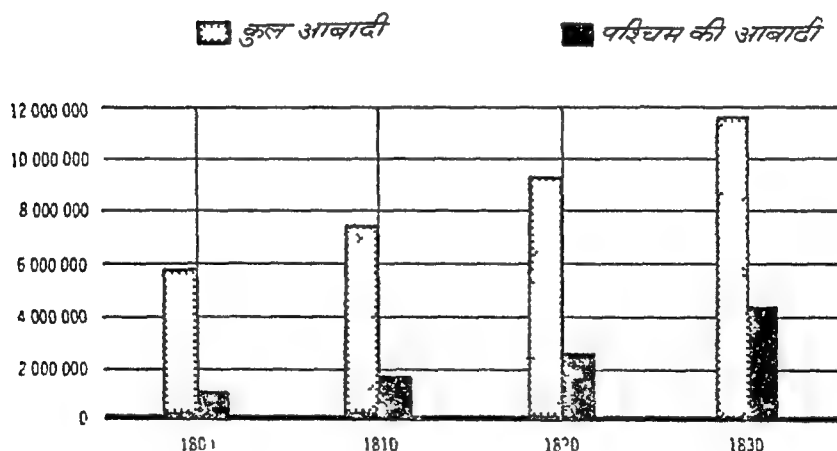
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अमेरिका में ऐसे लोग बहुत कम थे जिन्हें जीवन की अनिवार्य बुनियादी आवश्यकताएँ उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन अमीर लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। वॉशिंगटन, हैमिल्टन और ऐडम्स जैसे लोग एक बहुत छोटे और विशिष्ट धनिक वर्ग के सदस्य थे। इस वर्ग में कुछ बड़े जमींदार, खास पेगा के लोग, राजनीतिज्ञ, आयात-निर्यात व्यापारी और मातृकार शामिल थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अमेरिका वर्ग-भेद की दीवारों को समाप्त करने में यूरोप से काफी आगे था। नई दुनिया में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, मनुष्य के व्यवसाय और वन्ये से ही अधिकतर उसकी सामाजिक स्थिति बनती थी, उसके पूर्वजों की सामाजिक स्थिति से नहीं।

वाद के समाजशास्त्रियों ने जिसे 'उन्मुक्त समाज' का नाम दिया उसका आरम्भ इन सीमावर्ती क्षेत्रों में ही हुआ। जैसे-जैसे शिक्षा के अवसर बढ़ते गए और पुरुषों के मताधिकार में वृद्धि होती गई वैसे-वैसे असमानता कम होती गई और ऊपर की सतह पर नजर आने वाले निरर्थक वर्ग-भेद भी तेजी से अदृश्य होने लगे।

अधिकांश लोग अपनी निज की जमीनें जोतते थे या किसी दस्तकारी या व्यापार में लगे हुए थे। अनुमान है कि 80 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक या द्वितीयक उत्पादन (कृषि, वनसम्पदा का दोहन, मत्स्यपालन, खनन और निर्माण उद्योग) में लगे हुए थे। शेष 20 प्रतिशत वाणिज्य या चिकित्सा और शिक्षा आदि पेशों में लगे थे।

पश्चिम में जनसंख्या की वृद्धि, 1800-1830



निर्माण उद्योग उस समय अपेक्षाकृत प्रारम्भिक अवस्था में थे। अधिकतर निर्माण कार्य कुटीर उद्योग के रूप में ही होता था। किसान लोग अपने घरों पर अपनी आवश्यकता की मोमबत्तियाँ, रस्से, माचुन, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएँ तैयार करते समय स्थानीय बाजार में विक्री के लिए उनका कुछ फालतू उत्पादन कर लेते थे। किन्तु 1815 तक बहुत-से लोगो ने लोहे के ढलाई के छोटे-छोटे कारखाने, चक्कियाँ और कुछ अन्य कारखाने भी

खोल लिये जो विभिन्न परिवारों द्वारा व्यक्तिगत रूप में ही चलाये जाते थे ।

इन प्रारम्भिक उद्योगों में काम बहुत मन्द गति से होता था । मालिक और मजदूर दोनों में से कोई भी उत्पादकता बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देता था । कारखानों का उत्पादन तब तक नहीं बढ़ा, जब तक कि कुछ ऐसे बुनियादी आविष्कार नहीं हो गए, जिनसे छोटे पैमाने के उत्पादन की अपेक्षा बड़े पैमाने पर उत्पादन सस्ता हो सकता था । फिर भी अमेरिका में 'कारखाना प्रणाली'—यानी एक ही जगह एकत्र होकर मशीनी ताकत से बहुत-से श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन—की नींव जरूर पड़ गई थी ।

सन् 1820 तक अर्द्ध मजदूर की दैनिक आमदनी 75 सेंट से 1 25 डालर तक हो गई थी, जबकि अधिक दक्ष कर्मचारी इससे दुगुनी कमाई कर सकता था । स्त्रियों को पुरुषों से आधी या तीन-चौथाई मजदूरी मिलती थी । यद्यपि उस समय डालर की क्रय-शक्ति आज की तुलना में बहुत अधिक थी, फिर भी ये मजदूरियाँ बहुत कम थी ।

सब मिलाकर, उन्नीसवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में विदेशी व्यापार का खूब विस्तार हुआ । इस सारी अवधि में अमेरिका का विदेशी व्यापार इंग्लैंड के साथ उसके सम्बन्धों और यूरोप की सामान्य राजनीतिक स्थिति पर निर्भर था । जब यूरोप में लड़ाइयाँ छिड़ती तो अमेरिका की तटस्थता की वजह से अमेरिकन व्यापारी खूब लाभ उठाते, किन्तु जब यूरोप में शान्ति हो जाती तो अमेरिकन निर्यात-व्यापारियों को ब्रिटेन से बड़ी ज़रूरत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता । सन् 1797 से 1815 तक यूरोप फ्रेंच-क्रान्ति और नेपोलियन के युद्धों में उलझा रहा, जिससे अमेरिकन व्यापारियों और निर्माताओं को यूरोप के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक अपूर्व अवसर हाथ आया । उस समय तक यह व्यापार अधिकतर इंग्लैंड और फ्रांस के जहाजों से होता था ।

जैसे-जैसे विदेशी व्यापार और जहाजरानी में वृद्धि होती गई, अमेरिका के आन्तरिक उद्योगों का भी विस्तार होता गया । न्यू इंग्लैंड के व्यापारियों और मत्स्यपालकों ने व्यापार से जो पूंजी एकत्र की, वह वस्त्र उद्योगों में लगने लगी । सन् 1808 के प्रतिवन्ध कानून के फलस्वरूप इंग्लैंड के कपड़े

का आयात जब लगभग बन्द हो गया तो अमेरिका की नई कपडा मिलो को अपना कपडा स्थानीय बाजारो मे बेचने का मौका मिल गया। इसी बीच कपास की ओटाई के लिए 'कॉटन जिन' का और पावर से चलने वाली कताई-बुनाई की मशीनो का आविष्कार हो जाने पर दक्षिण की समूची अर्थ-व्यवस्था खूब उन्नत होने लगी और उत्तर मे नव-स्थापित निर्माण-उद्योग भी फलने-फूलने लगे।

राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र जितना सगठित 1812 के युद्ध के बाद हो गया, उतना पहले कभी नहीं रहा था। वास्तव मे इस युग को 'सद्भावनाओं का युग' कहा जाता है। इस युग मे प्रगाढ राष्ट्रीयता और देशभक्ति की एक नई भावना सर्वत्र दिखाई देने लगी थी। इस युग के अंग्रेज यात्री ने लिखा था, "सयुक्त राज्य मे राष्ट्रीय गर्व अन्य सभी देशो से अधिक है। वह सभी जगह और सभी अवसरों पर स्पष्ट दिखाई देता है—अमेरिकन लोगो की बातचीत, उनके अखबार, पैम्पलेट, भाषण और किताबे, सभी मे वह स्पष्ट रूप मे विद्यमान है।" किन्तु स्थानीय और राज्यीय स्तरों की राजनीति मे यह राष्ट्रीय गर्व और सन्तोष की भावना व्याप्त नहीं हुई। इन स्तरों पर अनेक छोटे-मोटे नजदीक के विषय विवाद खड़े करते रहे।

इस युग मे अमेरिकन राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रति-विम्ब मुनरो सिद्धान्त के रूप मे दिखाई देता है, जो अब काफी प्रसिद्ध हो गया है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने दिसम्बर, 1823 मे कांग्रेस को दिये अपने सन्देश मे किया था। यह सिद्धान्त दक्षिणी अमेरिका मे विशाल स्पेनिश साम्राज्य के निरन्तर विखंडित होने का परिणाम था। किसी समय इस साम्राज्य के बारे मे तरह-तरह की आश्चर्यजनक बातें कही जाती थी। सन् 1823 तक कनाडा को छोड़कर, पश्चिमी गोलार्द्ध का अत्यन्त स्वल्प भाग ही पुरानी दुनिया की ताकतों के हाथ मे रह गया था। अमेरिकन सरकार ने स्पेन के विरोध के वावजूद अनेक नव-स्वतन्त्र लैटिन अमेरिकन राज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे।

इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए टॉमस जैफर्सन ने अपने एक मित्र को एक पत्र मे लिखा था " अमेरिका अपने-आपमे एक पूरा गोलार्द्ध है। उसके अपने अलग हित होने चाहिएँ, जो किसी भी तरह यूरोप के हितों के

अधीन नहीं होने चाहिएँ।” अधिकतर अमेरिकन इसी विचार के उत्साही समर्थक थे। लेकिन खतरा यह था कि कहीं फ्रांस और स्पेन लैटिन अमेरिका के हितों में हस्तक्षेप न करे। इसके अलावा सुदूर उत्तर-पश्चिम में रूसी प्रतिस्पर्धा का भी खतरा था, क्योंकि रूसी समूर-व्यापारी धीरे-धीरे अलास्का में पाँव फैला रहे थे और वहाँ से प्रशान्त महासागरीय तट के साथ-साथ ओरेगन तक पहुँच रहे थे। मुनरो सिद्धान्त ने इस निश्चय को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया कि अब वक्त आ गया है जबकि नई दुनिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए।

राष्ट्रपति मुनरो के वक्तव्य ने इस बात पर स्पष्ट रूप में बल दिया कि “यूरोपियन राष्ट्र भविष्य में पश्चिमी गोलार्द्ध में उपनिवेश स्थापित करने का स्वप्न लेना बन्द कर दे।” उसमें यह भी कहा गया था कि “यदि यूरोपियन राष्ट्रों ने इस गोलार्द्ध के किसी भी भाग में अपनी शासन-प्रणाली का विस्तार करने का प्रयत्न किया तो संयुक्त राज्य उसे अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा और संयुक्त राज्य के प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य समझेगा।”

पश्चिमी गोलार्द्ध में अमेरिका की इस बुनियादी वैदेशिक नीति की वाद में अनेक शाखा-प्रशाखाएँ हो गईं और उनके अनेक विचित्र रूपान्तर हुए। किन्तु फिलहाल उसका यह उद्देश्य अवश्य पूरा हो गया कि उससे ससार के सामने अमेरिका के स्वतन्त्र गणराज्यीय सिद्धान्तों की उद्घोषणा हो गई और पश्चिमी गोलार्द्ध में यूरोप के प्रभुत्व-स्थापना के मनसूबों को धक्का लगा।

सद्भावनाओं के इस युग में राष्ट्र गौरव और आशावादिता की नई भावनाओं को बढ़ावा देने वाला एक कारण और भी था और वह यह कि साहसी अधिवासियों के लिए पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का और ऐपलेचियन पर्वतमाला के उस पार नये अवसरों की खोज का मार्ग फिर से खुल गया था। सन् 1800 के बाद सरकार ने नये अधिवासियों को कम कीमत पर अच्छी जमीनें दीं। डमका नतीजा यह हुआ कि ऐपलेचियन पर्वतमाला के पश्चिम में जहाँ 1800 में पाँच लाख की आबादी थी, वहाँ 1810 में वह बढ़कर दस लाख से भी अधिक हो गई। सन् 1820 तक राष्ट्र की 96

लाख की आबादी का एक चौथाई से भी अधिक भाग इस पश्चिमी इलाके में रह रहा था ।

पश्चिम की ओर फैलाव का मार्ग प्रशस्त होने में राज्यीय बैंको की वित्तीय नीतियों ने बहुत बड़ा योग दिया । सयुक्त राज्य के पहले शासपत्रित बैंक की, चार्टर की, अवधि 1811 में समाप्त हो जाने पर राष्ट्र की मुद्रा का काम इन राज्यीय बैंको के हाथ में आ गया था । राज्यीय बैंको से सस्ती व्याज दर और शर्तों पर ऋण मिलने से लोगों को पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और वहाँ आबाद होने के लिए प्रोत्साहन मिला, क्योंकि यह सुविधा न मिलती तो अपने ही वित्तीय साधनों से पश्चिम में जमीन खरीदने का सामर्थ्य बहुत कम किसानों में था ।

विभिन्न राज्यों की मुद्राओं में लेन-देन की भारी कठिनाई के कारण 1816 में सयुक्त राज्य सरकार ने फिर से एक सघीय शासपत्रित बैंक स्थापित कर दिया, लेकिन इससे लोगों को सस्ती दरों और सरल शर्तों पर ऋण देने की प्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ा । लेकिन बैंको से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण मिलने के कारण जमीन के व्यापार में जो जबरदस्त तेजी आई थी, वह हमेशा जारी नहीं रह सकती थी । इसलिए नतीजा यह हुआ कि 1818 में विदेशी ऋणों की मात्रा कम हो गई और ब्रिटिश ऋण दाताओं और खातेदारों ने अपना पैसा वापस माँगना शुरू कर दिया । इससे सोना-चाँदी बड़ी मात्रा में देश से बाहर जाने लगा और उसके फलस्वरूप उचित से अधिक फैली हुई बैंकिंग प्रणाली लड़खड़ाने लगी । कीमतों का स्तर तेजी से गिरने लगा और जल्दी ही सारा राष्ट्र '1819 के आतंक' के नाम से प्रसिद्ध सकट में बुरी तरह ग्रस्त हो गया ।

लेकिन पश्चिम की ओर लोगों का बढ़ना उसी तरह जारी रहा, क्योंकि सरकार ने लोगों के सकट को कम करने के लिए अपने भूमि-कानूनों को कुछ उदार बना दिया था । पश्चिम की ओर बढ़ने में खतरे और कठिनाइयाँ बहुत होने पर भी, बहुत-से लोगों ने सस्ती जमीन और स्वतन्त्र रूप से आय के साधन प्राप्त करने की आशा में पूर्वी प्रदेश के अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित जीवन को त्यागने में कोई हिचकचाहट नहीं दिखाई ।

जो लोग पश्चिम के नए-नए क्षेत्रों में प्रवेश के कष्टों और कठिनाइयों

को खेलने के लिए तैयार थे, उन्हें पश्चिम ने भी इन कष्टों का पुरस्कार दिया। धीरे-धीरे ये नए अधिकारी इस बात पर गर्व अनुभव करने लगे कि वे पूर्व से बिलकुल अलग और भिन्न हैं। यह मनोवृत्ति और भावना यूरोप और पुरानी दुनिया की परम्पराओं के बारे में उनके पृथक्कता के सारे स्वैये पर बुरी तरह छा गई। सयुक्त राज्य की जनता के पीछे ऐसी अनेक ठोस सफलताओं का बल था, जिन्होंने उनके राष्ट्र को नई दुनिया में यूरोप की महत्वाकांक्षाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और स्वतन्त्र राष्ट्र बना दिया था। और उनके सामने अपरिसीम प्रतीत होने वाला एक विनाश भौगोलिक क्षेत्र पड़ा हुआ था जो उन्नति के कल्पनातीत अवसरों से भरपूर था। इसलिए यदि अधिकतर अमेरिकन लोगो ने पुरानी दुनिया को बिलकुल विस्मृत कर दिया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब एक नई और उज्ज्वल दुनिया उनके सामने फैली हुई थी।

लोकप्रिय जनतन्त्र का उदय

सन् 1824 से 1836 तक के वर्षों को संयुक्त राज्य में 'जैक्सन के लोकतन्त्र' का नाम दिया जा सकता है। जैक्सन की लोकतन्त्र की अव-

धारणा इस अति सरल, किन्तु गम्भीर कल्पना पर आधारित थी कि लोकतन्त्र का अर्थ 'सबके लिए आर्थिक उन्नति के समान अवसर होना' चाहिए। ग्रसख्य छोटे-छोटे भू-स्वामी और किसान, शहरी कारीगर और श्रमिक, धीरे-धीरे उभर रहे उद्यमी उद्योग संचालक और साहसी सटोरिये इस कल्पना को साकार करने के लिए व्याकुलता से पुकार कर रहे थे। इनमें से अधिकतर लोगों को प्रतिस्पर्धात्मक लोक-तन्त्रीय पूँजीवाद पर कोई आपत्ति



एण्ड्रयू जैक्सन (1767-1845)

नहीं थी, किन्तु उस समय के आर्थिक ढाँचे और राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में जो असमानताएँ दीख पड़ती थी उन्हें वे सहन करने को तैयार नहीं थे।

उनका आदर्श उदाहरण और नायक था एण्ड्रयू जैक्सन जिसका जीवन इस बात की मिसाल था कि किस प्रकार एक साधारण आदमी भी सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एण्ड्रयू का जन्म लकडियों की बनी एक दीन-हीन कुटिया में हुआ था और उत्तरी कैरोलाइना और टैनेसी की

अत्यन्त कष्टपूर्ण, दुःसह परिस्थितियों में वह पला और बढ़ा हुआ था, परन्तु अपने अध्यवसाय और पुरुषार्थ से वह एक उच्च सम्भ्रान्त और धनी आदमी बन गया। उसका जीवन अनेक चित्र-विचित्रताओं से परिपूर्ण था। किसी समय वह इंडियनों से लड़ने वाला योद्धा था, फिर वह 1812 की लड़ाई का नायक बना। इसके बाद राज्य के अनेक उच्च पदों पर भी वह रहा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों का व्यवसाय कर धन कमाया। उसके पास गुलाम भी बहुत बड़ी संख्या में थे।

यौवन में वह जैर्मेन की विचारधारा से प्रभावित आदर्शवादी था। किन्तु 1819 के आतंक के दिनों में साहूकारा वर्ग का सदस्य होने के कारण उसने टैनेसी के ऋणग्रस्त किसानों के कर्जों के भार को कम करने के लोकप्रिय प्रयत्नों का जोरों से विरोध किया। और फिर भी दस वर्ष बाद ही वह सब के लिए समान राजनीतिक और आर्थिक अवसरों के सिद्धान्त का एक आदर्श उन्नेता बन गया।

जैक्सन में जो ये परिवर्तन हुए उनकी व्याख्या जैक्सन के व्यक्तित्व से नहीं, उस युग की परिस्थितियों से की जा सकती है। जैक्सन के लोक-तन्त्रवाद का आर्थिक महत्त्व भी इन परिस्थितियों के कारण ही है। उस समय आवादी तेजी में बढ़ रही थी और लोग घड़ाघड़ पश्चिम की ओर जा रहे थे। सन् 1812 के युद्ध के बाद ऐपलेचियन पर्वतमाला के पश्चिम की ओर के निवासी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत हिस्सा लेने लगे थे। सन् 1830 तक इस प्रदेश की जनसंख्या राष्ट्र की आवादी की एक तिहाई हो गई थी।

उत्तर-पूर्व में व्यापार और उद्योग की समृद्धि एक नए समाज को जन्म दे रही थी—वहाँ एक शहरी मध्यवर्ग और दूसरा कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का वर्ग उभर रहा था। किन्तु यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि कारखाना मजदूरों की संख्या 1820 और 1830 के दशकों में राष्ट्र की कुल श्रम-शक्ति का एक बहुत छोटा भाग थी। अमेरिकन समाज का अधिकांश अब भी ग्रामीण भू-स्वामियों का था। दक्षिण को छोड़कर जेप सब जगह हर पाँच आदमियों में से चार अमेरिकन नागरिक स्वतन्त्र भू-स्वामी थे, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान थे।

ब्रिटिश लेखक टॉमस हैमिल्टन ने अपनी अमेरिका-यात्रा के बाद इस

स्थिति पर टिप्पणी करते हुए अपनी पुस्तक 'मैन एण्ड मेनर्स इन अमेरिका' (1834) में बड़ी चतुराई से यह निष्कर्ष निकाला था कि "इस समय संयुक्त राज्य शायद ससार के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा आन्तरिक क्रान्ति से अधिक सुरक्षित है। यहाँ के अधिकांश लोगों के पास अपनी निज की जमीन-जायदाद है। और इस जमीन-जायदाद को उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है।"

भौगोलिक और आर्थिक विस्तार के साथ-साथ अमेरिकन लोकतन्त्र का भी प्रसाधारण विकास हुआ। सीमावर्ती इलाकों में सभी को नए क्षेत्रों में प्रवेश के अवसरों की समानता और अनेक पूर्वी नगरों में वर्ग-भेद में निरन्तर हो रही कमी से प्रेरित होकर अनेक राज्यों ने अपने यहाँ चुनावों में मत देने या किसी पद के लिए खड़े होने के वास्ते एक न्यूनतम मात्रा में सम्पत्ति का स्वामी होने की शर्त हटा दी। ऐड्र्यू जैक्सन जैसे अभिनव सीमा क्षेत्र के प्रतिनिधि के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से और भी लोगों को अपने मताधिकार के उपभोग के लिए प्रोत्साहन मिला। सन् 1828 से 1848 तक राष्ट्र की आबादी बढ़कर केवल दुगुनी हुई, किन्तु इसी अवधि में मतदाताओं की संख्या बढ़कर तिगुनी हो गई।

इस प्रकार 1728 में ऐड्र्यू जैक्सन के राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके बाद के वर्षों में अमेरिका में 'सामूहिक लोकतन्त्र' का अभ्युदय हुआ। एक बार राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाने के बाद लोगों ने कुछ खास वर्गों के विशेषाधिकारों और सभी प्रकार के कृत्रिम भेद-भाव पर आक्रमण करने के लिए उसका उपयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक समानता के लिए किया जा रहा आन्दोलन समस्त देशवासियों को शिक्षा देने, राज्य द्वारा शासपत्रित एकाधिकारों को खत्म करने, सब पर समान कर लगाने, अनिवार्य सैनिक शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करने, सभी सार्वजनिक पदों के लिए प्रत्यक्ष जन-निर्वाचन कराने और ऋण चुकाने की असमर्थता पर दी जाने वाली कैद की सजा को खत्म करने की माँगों के व्यापक आन्दोलन का अंग बन गया। इन आन्दोलनों से उस सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की एक तस्वीर सामने आती है, जिसे 'जैक्सन के लोकतन्त्र' के आदर्शों की तस्वीर कहा जा सकता है।

जैक्सन के अनुयायी जैफर्सन के अनुयायियों की भाँति यह शिकायत नहीं करते थे कि “शासन ने बहुत कुछ अपने अधिकार में ले रखा है।” वास्तव में उन्हें मुख्य चिन्ता इस बात की थी कि राज्यों और सघ की सरकारों के हाथों में जो अधिकार हैं उनका ‘दुरुपयोग’ न हो। एक ऐसे समाज में, जिसमें छोटी सम्पत्ति वालों का प्राधान्य हो, प्राइवेट कम्पनियों और राज्यीय और सघीय बैंकों को दिये गए विशेषाधिकार सचमुच ही भारी चिन्ता का कारण प्रतीत होते थे।

‘वैक विशेषाधिकार’ के विरुद्ध तथाकथित ‘वैक युद्ध’ भी इसीलिए छिड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राज्य के दूसरे सघीय बैंक (सैंकड बैंक ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स) के शासपत्र (चार्टर) की अवधि बढ़ाने का विधेयक सामने आने पर जैक्सन ने उसे अपने निषेधाधिकार (वीटो) से अस्वीकृत कर दिया।

इस बैंक को कांग्रेस ने 1816 में बीस वर्ष के लिए शासपत्र दिया था और वह सघीय सरकार का वित्तीय एजेंट था। यद्यपि इसकी 350 लाख डालर की पूँजी में से पाँचवाँ भाग सरकार का था, तो भी उसका संचालन पूर्णतः गैरसरकारी लोगों के हाथों में था। निकोलस बिडल की देख-रेख में यह बैंक लोगों को खूब समझ-बूझकर कर्ज और उधार देता था, समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) का काम करता था, एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करता था और राज्यीय और स्थानीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाले हुण्डियों और नोटों और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कड़ा नियन्त्रण रखता था।

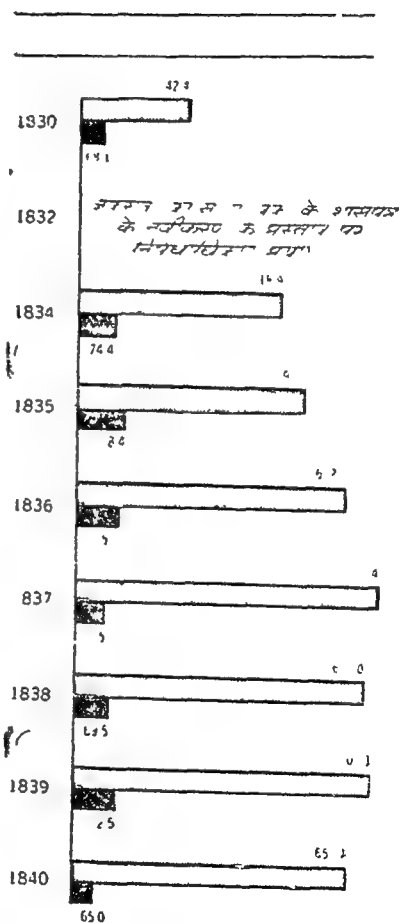
इन बुद्धिमत्तापूर्ण, किन्तु साथ ही अवस्फीतिकारक, कार्यों से कुछ आर्थिक और विशिष्ट वर्गीय हितों में असन्तोष और विरोध का भाव पैदा होना स्वाभाविक ही था। सन् 1833 में राष्ट्र के 502 बैंकों में से कुल 88 बैंकों को छोड़कर शेष सभी बैंक बाल्टीमोर मेरीलैण्ड के उत्तर में स्थापित हुए थे, इसलिए पश्चिम और दक्षिण के किसान और बागान मालिकों को यह शिकायत थी कि उन्हें इन बैंकों के पूर्वी शेयर होल्डरों का घर मुनाफे से भरना पड़ता है।

पूर्वी राज्यों में दो वर्ग इस बैंक के विरोधी थे, किन्तु उनके विरोध के

कारण सर्वथा भिन्न थे। एक ओर प्राइवेट बैंको के मालिक थे, जो बिडल पर यह आरोप लगाते थे कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। वे द्वितीय सघीय बैंक को अनुचित और अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा का दोषी ठहराते थे और कहते थे कि वह आर्थिक गति-विधि पर प्रतिबन्ध लगाने वाली सस्था है। उनका कहना था कि मुद्रा की उपलब्धि और सम्भरण का अधिकार उद्यमों उद्योगपतियों और व्यवसायियों के हाथ में रहना चाहिए, न कि सघीय सरकार द्वारा समर्थित इस 'वित्तीय अष्टभुज' के हाथों में।

दूसरी ओर शहरी आमूल परिवर्तनवादी वर्ग, श्रमिक सुधारवादी वर्ग और छोटे व्यापारियों को सभी बैंको पर अविश्वास था। उनका कहना था कि उनकी कठिनाइयों और मुसीबतों का कारण प्रचलन में विद्यमान नोटों और अन्य वित्तीय हुडियों के भावों में उतार-चढ़ाव था। इसीलिए जिन लोगों के पास ऐसी वित्तीय हुडियाँ या नोट होते थे जिनका मूल्य गिर गया था, वे यही चाहते थे कि इन कागजी मुद्राओं के बदले फिर से धातु के सिक्कों का प्रचलन प्रारम्भ कर दिया जाय।

संयुक्त राज्य के द्वितीय संघीय बैंक का पतन



संयुक्त राज्य के द्वितीय संघीय बैंक का पतन

संयुक्त राज्य के द्वितीय संघीय बैंक का पतन

सघीय बैंक के शासपत्र (1832) की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपने प्रसिद्ध निपेधाधिकार का प्रयोग करते हुए जैक्सन ने जो सन्देश कांग्रेस को दिया था, वह उम आन्दोलन को सार रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका वह (जैक्सन) प्रतीक था। राजनीतिक स्तर पर उसने 'अधिकार के कुछ ही लोगों के हाथों में, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, केन्द्रीकरण' की निन्दा की। दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर उसने यह मत व्यक्त किया कि द्वितीय सघीय बैंक के शासपत्र की अवधि बढ़ाने का अर्थ यह होगा कि "हम बहुमूल्यक लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाकर थोड़े-से लोगों के हितों को समुन्नत करने के लिए अपने शासन का दुरुपयोग करते हैं।"

जैक्सन द्वारा दूसरे सघीय बैंक के खाते से और उमके बाद उसके द्वारा अपनाई गई दूसरी वित्तीय नीतियों से केवल राज्यीय बैंकों के मालिकों को लाभ हुआ, पर उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली, जो कागजी मुद्रा के विरोधी थे। किन्तु बैंकिंग प्रणाली के बारे में उसकी धारणाएँ चाहे कितनी ही दुर्बल और सीमित क्यों न हों, यह निश्चित है कि जैक्सन ने अपने इस विश्वास पर पुनः बल देकर, कि अमेरिकन समाज में कुछ लोगों के विशिष्ट अधिकारों और कृत्रिम वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं है, अपने जमाने के सुधार आन्दोलनों को एक राष्ट्रीय रूप प्रदान किया।

उसके आलोचक अत्यन्त निर्ममता से उस पर प्रहार करने लगे। लेकिन उनके इन प्रहारों का कोई खास असर नहीं हुआ। कारण, एक ऐसे समाज में, जहाँ छोटे-छोटे सम्पत्ति-मालिकों का या अपनी निज की जमीन-जायदाद पाने के इच्छुकों का प्राधान्य हो, जनता की नजरों में जैक्सन ही 'सच्चा' था, उसके आलोचक नहीं। इस प्रकार 1832 में एंड्रयू जैक्सन भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिया गया।

द्वितीय सघीय बैंक का शासपत्र खत्म होने पर ऐसे सैकड़ों बैंकों को, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी या जो सट्टे-फाटके का व्यापार करते थे, किन्तु जिन्हें कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार था, शासपत्र दे दिये गए। खास तौर से पश्चिमी राज्यों में ऐसे अनेक बैंक थे। इस मुद्रा नीति ने हजारों नये अधिवासियों को पश्चिम की ओर आकृष्ट किया,

जिनमे से बहुत-से मॉर्टगेज और साधन-सामग्री के लिए लिये हुए ऋणों में गले तक डूबे हुए थे। सन् 1830 में बैंकों द्वारा लोगों को दिये गए ऋणों की मात्रा 1370 लाख डालर थी, किन्तु सात वर्ष बाद यह मात्रा 5250 लाख डालर हो गई। व्यक्ति ही नहीं, राज्यों की सरकारों ने भी अन्धाधुन्ध ऋण लिये थे। राज्यों के कर्ज 1820 में 130 लाख डालर से भी कम थे, किन्तु 1830 में वे बढ़कर दुगुने हो गए और 1840 में उनकी मात्रा 2,000 लाख डालर हो गई। बैंकिंग की कोई केन्द्रीय अधिकारी सत्ता न होने के कारण सारी बैंकिंग प्रणाली अनियन्त्रित हो गई।

बैंकों द्वारा इस प्रकार अन्धाधुन्ध ऋण दिये जाने से सट्टे-फाटके को भी खूब बढ़ावा मिला। इन दोनों चीजों ने मिलकर मुद्रा स्फीति का एक खतरनाक चक्कर चला दिया। जैक्सन ने जब राज्यों के बैंकों में सरकारी धन जमा कराया और बाद में सघीय राजस्व की फालतू राशि राज्यों में बाँटी तो मुद्रा-स्फीति की गति और भी बढ़ गई। सन् 1836 में उसने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जमीन की कीमते कागजी मुद्रा के बजाय धातु के सिक्कों में चुकाई जाएँ किन्तु वह सट्टे-फाटके और मुद्रा-स्फीति को रोकने में सफल नहीं हुआ। इससे स्वभावतः मुद्रा का आतक पैदा हो गया। यह आतक जैक्सन के स्थान पर मार्टिन वान व्यूरेन के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद 1837 में प्रारम्भ हुआ और उसके बाद एक जबरदस्त आर्थिक मन्दी आई जो 1843 तक जारी रही।

फिर भी जैक्सन के प्रशासन के बारे में यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि आर्थिक अदूरदर्शिता के बावजूद उसने 'सबके लिए समान आर्थिक अवसर' और 'समान अधिकार' की परिकल्पनाओं को परस्पर मिलाकर संयुक्त राज्य के लोकतन्त्रीय विकास में भारी योगदान किया।

जैक्सन के कार्यकाल के आर्थिक परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए ब्रे हैमण्ड ने, गृहयुद्ध से पूर्व की बैंकिंग प्रणाली के अपने अध्ययन में, ठीक ही लिखा है—“जैक्सन के काल के आन्दोलन की इसके सिवाय और कोई विशेषता नहीं थी कि उसने व्यापार-व्यवसाय का लोकतन्त्रीयकरण कर दिया। इस आन्दोलन के फलस्वरूप व्यापार एक विविष्ट और उच्च व्यापारी-वर्ग का ही पेशा नहीं रह गया, जैसा कि हैमिल्टन के जमाने में था, बल्कि

जन-साधारण के लिए भी उसके द्वार खुल गए।”

जैक्सन के युग में एक बात और भी हुई और वह यह कि अब तक जो राजनीति एक विशिष्ट उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, वह जन-साधारण की वस्तु बन गई। जैक्सन के जमाने के बाद राजनीतिक नेता को साधारण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना और हर वर्ग की शिकायतों को दूर करना पड़ता था। अनेक राजनीतिज्ञ तो अपने-आपको ‘साधारण जन’ तक कहने लग गए थे। सन् 1840 में व्हिग पार्टी की ओर से, जो सम्पत्ति-शाली और अनुदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीद-वारी हासिल करने का प्रयत्न करते हुए डेनियल वेबस्टर को यहाँ तक कहना पड़ा कि मुझे अफसोस है, मेरा जन्म किसी दूर-दराज के सीमावर्ती इलाके में किसी लकड़ी की कुटिया में नहीं हुआ। लेकिन, उसने अपनी सफाई में कहा कि मेरे बड़े भाई बहनो का जन्म मेरी अपेक्षा अधिक साधारण परिस्थितियों में हुआ है और मुझे इसके लिए जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। “अगर मुझे कभी इस पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस हो तो मेरा और मेरे वंशजों का नाम मानव-जाति की स्मृति से बिलकुल मिटा दिया जाय।”

दूसरा भाग

युवा राष्ट्र का संघर्ष

हम ऐसे मानवों की सकीर्ण जन-जाति नहीं हैं, जिनका रवत अपने आपको दूसरों से बिल्कुल अलग-अलग रखकर अपनी जाति और वंश की शुद्धता की रक्षा के प्रयत्न में सड़कर विकृत हो गया है। नहीं, हमारा रवत अमेज़न नदी के प्रवाह के समान है, जिसमें हजारों पवित्र और निर्मल धाराएँ मिलकर एक हो जाती हैं। हम दरअसल एक राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि एक पूरा संसार हैं।

—हरमन मैलविल, 1849

पश्चिम की ओर कूच

सन् 1815 से गृह-युद्ध छिड़ने तक समूचे राष्ट्र का भावी विकास पश्चिम की ओर उसके प्रसार पर अवलम्बित था। नई दुनिया में जब सबसे पहले यूरोपियन लोगों की बस्तियाँ बसीं तभी से उत्तर और दक्षिण की अर्थ-व्यवस्थाओं का विकास बिल्कुल परस्पर-विरोधी दिशाओं में हो रहा था। इसलिए राष्ट्रीय विधान मंडल (कांग्रेस) में उनके हितों की आपस में बहुत टक्कर होती थी। इसलिए अब यह अधिकाधिक स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस में किसका शक्ति का पलड़ा भारी हो, इसका निर्णय बहुत कुछ नये पश्चिमी राज्यों पर निर्भर होगा। वे जिसका साथ देगे, उसी की शक्ति अधिक होगी।

राष्ट्रीय मामलों में पश्चिम को एक प्रभावकारी शक्ति बनने में पचास वर्ष से भी कम समय लगा। इस अवधि में संयुक्त राज्य का कुल क्षेत्रफल दुगुने से भी अधिक हो गया। फ्लोरिडा प्रदेश को छोड़कर, जो स्पेन ने 1819 में

संयुक्त राज्य को दिया था, शेष सारी नई वृद्धि पश्चिम में ही हुई। टेक्सास 1845 में, ओरेगन 1846 में और मैक्सिको द्वारा छोड़ा गया प्रदेश 1848 में संयुक्त राज्य को मिला।

इस बीच साहसी अधिवासी निरन्तर बढ़ती संख्या में इन नये विशाल प्रदेशों में बसने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसीलिए यद्यपि 1815 से 1860 तक सारे देश की जनसंख्या बढ़कर केवल चार गुनी हुई थी, तो भी ऐपलेचियन पर्वतमाला के पश्चिम की ओर आवादी दस गुनी बढ़ी थी। सन् 1860 तक राष्ट्र की 3 करोड़ 14 लाख आवादी का लगभग आधा भाग ऐपलेचियन के पश्चिम में रहता था।

पश्चिम की ओर लोगों के प्रसार का एक बड़ा कारण यूरोप से आने वाले अधिवासियों की संख्या में वृद्धि थी। सन् 1844 और 1854 के बीच में लगभग तीस लाख आवासीय संयुक्त राज्य में आए। इनमें अधिकतर संख्या जर्मन और आयरिश लोगों की थी। ये लोग उत्तर में और पश्चिमी सीमान्त के साथ लगे प्रदेशों में खेती, उद्योग और परिवहन के नये अवसरों से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। सन् 1860 में मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन के तीस प्रतिशत निवासी बाहर से आए आब्रजक थे।

किन्तु दक्षिण में बाहर से नये आए अधिवासियों का कोई प्रभाव नहीं था। वहाँ बड़े जमींदारों और बागान मालिकों के वश नेतृत्व में अच्छी ज़मीनों पर अपना एकाधिकार जमा लिया था और छोटे किसानों और कारीगरों को गुलाम मजदूरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए जो आवासीय बाहर से नये उद्यम और साहसिक कार्यों की स्फूर्ति लेकर आए थे, वे दक्षिण की ओर से विमुख होकर पश्चिम की ओर अग्रसर हो गए।

पश्चिम का आकर्षण लोगों को सिर्फ इसलिए था कि वहाँ उन्हें जमीन मिल सकती थी और साथ ही स्वतन्त्र जीवन-यापन की संभावनाएँ भी विद्यमान थीं। पश्चिमी प्रदेशों में केवल कैलिफोर्निया ही ऐसा भाग था, जहाँ ज़मीन के अलावा एक और आकर्षण भी था और वह था सोने का आकर्षण। सन् 1849 में जब वहाँ सोने की खानों का पता चला तो दस वर्षों के भीतर

ही वहाँ की आवादी चार गुनी हो गई।

इन वर्षों में संयुक्त राज्य के पास इस बात के लिए एक अपूर्व अवसर था कि वह पहले से ही स्थापित व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किये बिना भूमि-हीनो को भूमि दे सकता था। इसलिए वहाँ उपनिवेश-स्थापना का जो नया और सर्वथा सफल रूप विकसित हुआ, उसका कारण केवल लोगों की स्वतन्त्र वैयक्तिक अभिकसशीलता ही नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा दिया गया प्रश्रय और प्रोत्साहन भी था।

उत्तर-पश्चिमी प्रदेश पहला ऐसा 'सार्वजनिक प्रदेश' था जो नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से नीलाम किया गया। यह विशाल क्षेत्र—जो अन्ततः ओहायो, मिशिगन, इंडियाना, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन, इन पाँच राज्यों में विभक्त कर दिया गया—1784 से 1787 तक अनेक भूमि अध्यादेश जारी कर बेचा गया। इन अध्यादेशों में घोषित भूमि-नीति की मुख्य बातें ये थी—

(1) जैसे ही नये प्रदेशों की आवादी 60 हजार हो जाएगी, वैसे ही उन्हें पुराने राज्यों के समान दर्जे पर संयुक्त राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, (2) जो व्यक्ति जो नई जमीन खरीदेगा उस पर उसका स्वामित्व होगा, (3) सार्वजनिक जमीनें 640 एकड़ के टुकड़ों में नीलामी द्वारा बेची जाएँगी और उनका मूल्य एक डालर प्रति एकड़ से कम नहीं होगा, (4) हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता होगी और किसी को गुलाम नहीं रखा जा सकेगा, (5) इन प्रदेशों को सार्वजनिक स्कूलों के संचालन के लिए भी जमीनें दी गईं ताकि उनसे होने वाली आय से इन स्कूलों का खर्च निकाला जा सके।

कुछ हद तक इन अध्यादेशों की उपर्युक्त व्यवस्थाओं ने भूमि-वितरण के बारे में सघीय सरकार की भावी नीति को प्रभावित किया। किन्तु गुलाम-प्रथा का निषेध अन्य प्रदेशों पर लागू नहीं किया गया। इसके अलावा इस उत्तर-पश्चिमी प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों को नये राज्यों के रूप में संयुक्त राज्य में शामिल करने के लिए आवादी की शर्त ही एकमात्र शर्त नहीं रखी गई।

यह बात जल्दी ही स्पष्ट हो गई कि 640 एकड़ के बड़े टुकड़ों में जमीनें बेचने से छोटे अधिवासी-किसानों को प्रोत्साहन मिलने के बजाय जमीन की खरीद-बिक्री का घन्घा करने वाले धनी सटोरियों को ही लाभ होता

है। इसलिए 1800 में जनता को बेचे जाने वाले जमीन के टुकड़ों का आकार घटाकर 320 एकड़ कर दिया गया और चार वर्ष बाद उसे भी घटाकर 160 एकड़ तक सीमित कर दिया। इसके बाद 1820 में इन टुकड़ों को फिर घटाकर आधा यानी 80 एकड़ और कुछ समय बाद 40 एकड़ ही कर दिया गया। जमीनों की कीमतों में कुछ घटा-बढ़ी होती रहती थी और यह घटा-बढ़ी उस समय तक जारी रही, जब तक कि 1862 का वास भूमि कानून (होमस्टैड ऐक्ट) पास होने से कीमत का सवाल खत्म नहीं हो गया। यह कानून पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति 160 एकड़ भूमि का कानूनन मालिक हो सकता था, बशर्ते कि उसने पाँच वर्ष तक उस पर खेती की हो और वहाँ रहा हो।

भूमि-नीति के साथ-साथ एक बात और भी जुड़ी हुई थी और वह यह थी कि पश्चिमी प्रदेश आन्तरिक सुधारों, खासकर परिवहन की सुविधाओं के लिए चिन्तित थे। सन् 1815 तक पिट्सबर्ग, जो एक बड़ा निर्माण केन्द्र था 'अमेरिका का बर्मिंघम' कहलाने लगा था, यातायात मार्गों का एक महत्वपूर्ण सगम बन गया था। यहाँ फिलाडेल्फिया और वाल्टीमोर के व्यापारियों ने अपनी शाखाएँ खोली हुई थी। तटीय नगरों से स्थल मार्ग द्वारा लाई गई व्यापारिक वस्तुओं का यहाँ पिट्सबर्ग और ओहायो घाटी के उत्पादनों के साथ विनिमय किया जाता था।

लेकिन स्थल मार्ग से वाणिज्य की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जाने में बहुत लम्बी दूरियाँ तय करनी पड़ती थी और यात्रा बड़ी कठिन होती थी। इसलिए जल-मार्गों का विकास किया गया। 1811 तक प्रति वर्ष गहतीरो के 1200 वेडे ओहायो घाटी के ढलानों की धाराओं से बहते हुए मिसिसिपी नदी में और वहाँ से न्यू ऑर्लियन्स जाने लग गए। यहाँ थोड़ा-बहुत माल तो नकद पैसे के बदले बेचा जाता था और बाकी माल का चीनी और रुई के साथ विनिमय कर लिया जाता था। बाद में यह चीनी और रुई समुद्र मार्ग से अटलांटिक के बन्दरगाहों को भेज दी जाती थी।

इस जलीय परिवहन प्रणाली में कठिनाई यह थी कि इसमें ऊपर के प्रदेशों से ढलानों के साथ-साथ नदी में नीचे तो माल लाया जा सकता था,

लेकिन नीचे से ऊपर माल ले जाने की कोई उचित व्यवस्थानहीं थी। साधारण नावों को मिसिसिपी की धारा में ऊपर की ओर लुइसवील, कैण्टकी तक 1500 मील का मार्ग तय करने में 90 दिन लगते थे। लेकिन रॉबर्ट फुल्टन ने जब 1807 में हडसन नदी में अपनी पहली पैडल युक्त पहिये वाली स्टीम बोट (वाष्प-नौका) चलाई तो उससे धीरे-धीरे यह समस्या हल हो गई। जल्दी ही धुआँ और आग उगलती स्टीम-बोटे मिसिसिपी और अन्य पश्चिमी नदियों में चलती दिखाई देने लगी। परिवहन का यह सुधार ‘पश्चिम के लिए हजारों लडाइयों के लाभों की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण’ बताया जाता था।

किन्तु स्टीम-बोटे भी ओहायो घाटी से पूर्वी समुद्र तट पर अटलांटिक के बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिए मिसिसिपी नदी से मैक्सिको खाड़ी होते हुए अटलांटिक महासागर पहुँचने के लम्बे और टेढ़े रास्ते को कम नहीं कर सकी। इसलिए नहरें और जलपाश (लॉक) बनाकर इन स्थानों के बीच जलयान यातायात का एक अधिक सीधा मार्ग बनाने का प्रयत्न किया गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना एरी नहर की थी। सन् 1825 में जब यह परियोजना पूर्ण हो गई तो मध्य-पश्चिमी प्रदेश की कृषि-उपज ग्रेट लेक्स से एरी नहर में और वहाँ से हडसन नदी होती हुई न्यूयार्क बन्दरगाह पहुँचने लगी, जहाँ से वह विश्व के बाजारों को निर्यात कर दी जाती थी।

एरी नहर ने पश्चिमी प्रदेश को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। इससे अमेरिका के पश्चिमी और पूर्वी भागों के व्यापार का ढग भी बदल गया। पहले जहाँ यह व्यापार मिसिसिपी नदी के रास्ते न्यू ऑर्लियन्स में माल लाकर किया जाता था, वहाँ वह अब इस नये रास्ते से होने लगा। इससे पश्चिम और उत्तर के व्यापार में जहाँ एकाएक असाधारण वृद्धि हो गई वहाँ पश्चिम और दक्षिण का व्यापार घट गया। इससे एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में न्यू ऑर्लियन्स का जो महत्व था, वह धीरे-धीरे क्षीण हो गया। उत्तरी प्रदेशों में उद्योग-व्यवसाय की प्रवृत्तियों की बढ़ती हुई विविधता, पूर्वी प्रदेशों के व्यापारियों की नये-नये व्यवसायों में अग्रसर होने की उद्यमी वृत्ति और उत्तरी प्रदेशों में उपलब्ध ऋण की उदार

सुविधाओं ने अटलांटिक के बन्दरगाहों का व्यापार बढ़ा दिया, जिससे न्यू ऑर्लिन्स के व्यापार को और भी धक्का लगा।

पूर्व और पश्चिम के व्यापार को रेलों ने और भी सुदृढ़ बना दिया। प्रारम्भ में एरी नहर की भाँति रेल-मार्गों का निर्माण भी राज्यों की जिम्मेदारी था। जैफर्सन ने जब देश में सड़कों के निर्माण की अपनी विशाल योजना प्रस्तुत की तभी से पुराने राज्य, जिन्हें इन सड़क-परियोजनाओं से अधिक लाभ की आशा नहीं थी, सघीय सरकार द्वारा परिवहन की सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम अपने हाथ में लिये जाने का विरोध कर रहे थे। फलस्वरूप 1828 में परिवहन-सुविधाओं का निर्माण विशुद्ध रूप से राज्यों की ही जिम्मेदारी बना दिया गया।

किन्तु सड़कों के सुधार और रेल-मार्गों के निर्माण से राज्य सरकारों के कोष पर बहुत बोझ पड़ता था। राज्य सरकारों ने रेल-मार्गों के निर्माण का काम अधिकाधिक प्राइवेट कम्पनियों को देना प्रारम्भ किया, क्योंकि राज्यों के सविधानों में इस प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों का निषेध था। इस प्रकार के राजकीय व्यावसायिक उद्यमों ने 1837 के आतंक के दिनों में राज्य सरकारों की साख को बहुत गिरा दिया था। ये रेल कम्पनियाँ मुख्यतः पूर्वी राज्यों के लोगों और यूरोपियनों की पूँजी से चलती थी, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर राज्यीय और स्थानीय सरकारें भी उन्हें सहायता देती रही। सन् 1850 में जब सरकार ने रेल कम्पनियों को भूमि-अनुदान देने की नीति प्रारम्भ की, तो उन्हें सघीय सहायता फिर मिलने लग गई। इन अनुदानों ने रेल-निर्माण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया। सन् 1850 से 1860 तक संयुक्त राज्य में रेल-मार्गों की लम्बाई 9,000 मील में बढ़कर 31,000 मील हो गई और रेलों में लगी पूँजी भी 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1 अरब डॉलर हो गई, जो राष्ट्र की सक्रिय पूँजी का लगभग एक चौथाई भाग थी।

सन् 1858 में न्यूयार्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर का शिकागो, सैनसिनाटी और सेंट लुई के साथ रेल-सम्पर्क स्थापित हो चुका था। इन शहरों के बीच रेल-मार्ग से सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद उत्तर और पश्चिम के बीच आर्थिक बन्धन और भी मजबूत हो गए और दोनों

पश्चिम की ओर कूच

क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। रेलों के निर्माण-उद्योगों का उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 1860 और 1860 के बीच 86 प्रतिशत बढ़ गया।

इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्रों का कृषि उत्पादन भी असाधारण रूप से बढ़ा। कृषि उत्पादन में वृद्धि और रेलों के विकास ने कृषि ढाँचे में परिवर्तन कर दिया। पहले जहाँ कृषि स्थानीय खपत और आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर की जाती थी, वहाँ अब वह क्षेत्रीय खपत को दृष्टि में रखकर की जाने लगी। इसी प्रकार मक्का, गेहूँ और मसूर आदि विभिन्न खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन किया जाने लगा। कृषि और परिवहन, दोनों में संयुक्त क्रान्ति ने पश्चिमी क्षेत्रों के किसानों को दूर के बाजारों को खोजने और उनमें अपना माल भेजकर लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। इसका एक नुकसान भी हुआ। संयुक्त राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्र का सस्ती कीमतों पर खाद्य पदार्थों की प्राप्ति का स्रोत अब बन्द हो गया, क्योंकि पश्चिम के किसान इस क्षेत्र को खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के बजाय अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्हें उत्तर-पूर्व के दूरस्थ प्रदेशों या यूरोप को भेजने लगे।

पश्चिम और उत्तर के बीच व्यापार में वृद्धि हो जाने से पश्चिम की राजनीतिक नीतियों में भी, खासकर गुलाम प्रथा और तटकरों के मामले में, परिवर्तन हुआ। कांग्रेस में पश्चिमी क्षेत्रों की ताकत बढ़ जाने पर यह परिवर्तन और भी स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो गया। सन् 1820 से लेकर गृह-युद्ध के प्रारम्भ तक बारह पश्चिमी राज्य सभ में शामिल किये गए। सीनेट की 86 सीटों में से 24 सीटें इन राज्यों के हाथ में थी। इन पश्चिमी सीनेटर्स में से चार को छोड़कर वे सभी ऐसे राज्यों के थे जहाँ गुलाम प्रथा नहीं थी। इनसे भी अधिक महत्व की बात यह कि प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी जो राजस्व सम्बन्धी सब कानूनों का उद्गम था, पश्चिमी राज्यों की ताकत बढ़ गई थी।

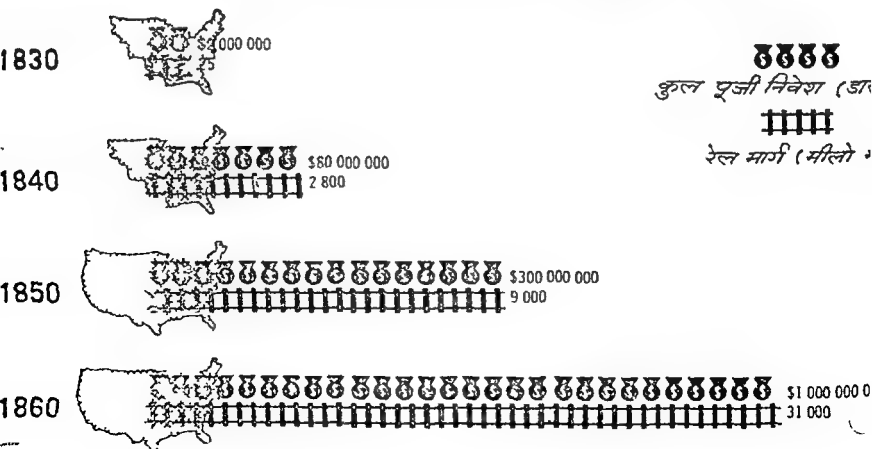
पश्चिम की राजनीतिक नीतियों में हुआ परिवर्तन इस बात से और भी स्पष्ट था कि पश्चिम ने संरक्षणात्मक तटकरों के बारे में बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया। पश्चिम के किसानों को संरक्षणात्मक तटकरों ने कोई लाभ

नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ फसलों का उत्पादन उनकी आवश्यकता से अधिक होता था, और वह फालतू उत्पादन विदेशी बाजारों में अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर विकता था। सरक्षणात्मक तटकरो का असर उनके लिए मिर्फ यह होता था कि वे अपने कृषि-उत्पादनों के बदले में विदेशों से जो निर्मित वस्तुएँ खरीदते थे, उनका मूल्य सयुक्त राज्य में पहुँचकर तटकरो से बढ़ जाता था।

दक्षिण के लोग विदेशों के निर्मित माल पर तटकर के और भी अधिक कट्टर विरोधी थे, क्योंकि इन तटकरो के कारण यूरोप में उनकी रुई की विक्री काफी हद तक सीमित हो गई थी। परिणाम यह हुआ कि 1846 में कांग्रेस ने सरक्षणात्मक तटकरो की प्रणाली पर एक जबरदस्त प्रहार किया, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण के प्रतिनिधि उत्तर-पूर्व के निर्माण-उद्योगों के हितों के विरुद्ध संगठित हो गए थे।

किन्तु 1857 में पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधियों ने तटकरो में कमी के विरोध में मत दिया, क्योंकि उत्तर के प्रतिनिधियों के साथ उनका यह समझौता हो गया था कि उत्तर के प्रतिनिधि एक सामान्य आवास-भूमि कानून के पक्ष में अपने वोट दे देंगे बशर्ते कि पश्चिमी प्रतिनिधि तटकरो के मामले

सयुक्त राज्य में देश के साथ-साथ रेलों का क्रमिक विस्तार



पश्चिम की ओर कूच

मे उनका समर्थन करे। यद्यपि यह विधेयक पास नहीं हो सका तो भी उत्तर-पूर्व के पूँजी-निवेशक उद्योगपतियों और पश्चिम के मेहत्वाकांक्षी कृषि हितों ने मिलकर भविष्य के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच एक राजनीतिक गठबन्धन स्थापित कर दिया।

जैसा कि इतिहासकार चार्ल्स वीयर्ड ने कहा है, पूर्व और पश्चिम 'फौलाद और सोने के बन्धनों से,' एक-दूसरे के साथ बँध गए थे। उत्तर और पश्चिम का यह गठबन्धन मजबूत होने से उत्तरी राज्यों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कानूनों का खूब लाभ उठाया और दूसरी ओर पश्चिमी राज्यों के लोगों ने और अधिक प्रसार और फैलाव के लिए आवश्यक मुक्त भूमि और आन्तरिक सुधारों का फायदा उठाया।

पश्चिम के विकास ने उत्तर का राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की ताकत का पलड़ा भारी कर दिया।

गुलाम मजदूर स्वभावतः अदक्ष मजदूर हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि निर्माण और यान्त्रिक उद्योगों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता। जहाँ एक मजदूर को जानबूझकर अज्ञान में रखा जाता है और साथ ही उसे अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, वहाँ यह सम्भव नहीं है कि वह ऐसे कठिन और सूक्ष्म कामों में दक्षता से भाग ले, जैसे कि अधिकतर निर्माण और यान्त्रिक उद्योगों की प्रक्रियाओं में करने पड़ते हैं।

—गृह-युद्ध से पूर्व के दक्षिणी प्रदेशों की यात्रा के बाद एक आयरिश अर्थशास्त्री के कथन का एक अंश

गृह-युद्ध से पूर्व दक्षिण की स्थिति

गृह-युद्ध से पहले की दक्षिण की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमें उन हालात की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण दक्षिण की अर्थव्यवस्था गुलाम-प्रथा और 'एक फसल' के उत्पादन पर अवलम्बित हो गई।

जैसा कि हमने देखा है, आज जो प्रदेश संयुक्त राज्य कहलाता है, उसमें अफ्रीकी गुलाम सबसे पहले 1619 में लाये गए थे। उसके बाद सत्रहवीं शताब्दी के अधिकतर भाग में अंग्रेजों के उपनिवेशों में ये गुलाम लाये जाते रहे, किन्तु थोड़ी संख्या में। लेकिन इस शताब्दी की समाप्ति पर तम्बाकू और दक्षिण की अन्य कृषि-जिन्सों की माँग बढ़ने लगा, इससे दक्षिण के उपनिवेशों में बड़े पैमाने पर खेतों में गुलामों से मजदूरी कराई जाने लगी। अमेरिकन क्रांति प्रारम्भ होने तक वर्जीनिया की आधी आबादी और दक्षिणी कैरोलाइना की दो-तिहाई आबादी नीग्रो गुलामों की थी।

सन् 1700 के दशक के आखिरी वर्षों में जब तम्बाकू की कीमतों में गिरावट आई और दक्षिण में मन्दी का एक लम्बा झल्ला आया तो जिन लोगों के पास बहुत बड़ी सख्या में गुलाम मजदूर थे, उन्होंने गुलामों की सख्या में वृद्धि को रोककर आपसी प्रतिस्पर्धा को बन्द करने का प्रयत्न किया। साथ ही क्रान्ति प्रारम्भ होने पर गुलाम-प्रथा के विरुद्ध जन-भावना भी फैलने लगी। आजादी के सवर्ष ने लोगों को स्वतन्त्रता और समानता के आदर्शों के प्रति सजग कर दिया। उत्तरी प्रदेशों में, जहाँ उद्योगों और छोटे पैमाने की खेती में गुलाम-प्रथा किसी तरह आर्थिक दृष्टि से अनुकूल नहीं बैठती थी, उसे स्पष्टतः अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था। सन् 1804 तक डेलेवारा के उत्तर में सभी राज्यों ने उस पर कानूनन प्रतिबन्ध लगा दिया था।

यहाँ तक कि दक्षिण में भी अनेक प्रमुख व्यक्ति गुलामों से मजदूरी कराना हानिकारक समझते थे। उदाहरण के लिए वाशिंगटन और जैफर्सन गुलाम-प्रथा को एक अस्थायी चीज समझते थे और यह आशा करते थे कि एक दिन वह समाप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत-से उदाहरण हैं जिनमें कि गुलामों को उनके मालिकों ने स्वेच्छा से ही मुक्त कर दिया था।

गुलाम-प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी में अपनी मौत आप ही मर जाती, अगर दो घटनाएँ उस समय एकसाथ घटित न हो जातीं। पहली यह कि औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैंड की कपड़ा मिलों का यान्त्रिकीकरण कर दिया था, जिससे अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अपनी उत्पादन-वृद्धि को कायम रखने के लिए वे कपास की अधिकाधिक माँग करने लगी। दूसरी घटना थी 'काँटन जिन' (कपास ओटने की मशीन) का आविष्कार। एली व्हिटने द्वारा 1793 में इस मशीन का आविष्कार होने से दक्षिण में कपास के उत्पादन का खर्च कम हो गया। फलतः जिस समय इंग्लैंड की मिलों में रूई की माँग बढ़ी ठीक उसी समय 'काँटन जिन' के आविष्कार से अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में कपास का उत्पादन भी बेतहाशा बढ़ गया।

'काँटन जिन' के आविष्कार से पूर्व गुलाम मजदूर ही हाथों से कपास के रेशे को विनीले से अलग करते थे। जब काफी वक्त खा जाने वाले इस

काम को करने के लिए मज्दूर का उपयोग होने लगा तो खेत में काम करने वाले गुलाम मजदूर की कार्य-कुशलता और क्षमता कई गुना बढ़ गई। मुख्यतः इसी कारण से कपास का उत्पादन बढ़ गया। साथ ही खेतों में गुलामों को रखकर मजदूरी कराने की प्रथा के बढ़ने का भी यही कारण था। सन् 1830 तक दक्षिण में गुलामों की संख्या बीस लाख से भी अधिक हो गई। अगले तीस वर्षों के भीतर नीग्रो लोगों की आवादी लगभग दुगुनी हो गई, हालाँकि गुलामों का व्यापार 1808 में ही बन्द कर दिया गया था।

रुई की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता था। सन् 1799 में वह 44 सेट प्रति पौंड तक ऊँचा चला गया और 1830 और 1840 के मन्दी के दशकों में वह गिरकर औसतन 10 सेट प्रति पौंड पर आ गया। लेकिन कीमतों के गिरने से भी दक्षिण के जमींदार दूसरी फसलों की ओर नहीं भुके, एक ही फसल से चिपटे रहे। मजदूरी और ज़मीन, दोनों इतनी सस्ती थी कि कुछ इलाकों में कपास के उत्पादन का सारा खर्च 8 सेट प्रति पौंड से अधिक नहीं पड़ता था। इसके अलावा, एक ही फसल बार-बार बोने से ज़मीन की उर्वराशक्ति नष्ट हो जाने पर भी ये लोग दूसरी फसल नहीं बोते थे, क्योंकि ज़मीन इतनी अधिक थी कि एक खेत खराब हो जाने पर वे नई ज़मीन पर खेती शुरू कर देते थे। लम्बे अर्से तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन गृह-युद्ध छिड़ने से ठीक पहले के वर्षों में दक्षिण के कपास उत्पादकों को इस नीति को अपनाने की भूल समझ में आई।

गुलाम-प्रथा पर आधारित प्रणाली के दोष दक्षिण की अर्थ-व्यवस्था में विलकुल स्पष्ट थे। यह अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण के कपास उत्पादक फार्मों के गुलाम मजदूरों की कार्यकुशलता और क्षमता उत्तर के स्वतन्त्र ग़ोरे किसानों की अपेक्षा लगभग आधी थी। स्वतन्त्र किसान को अपने परिश्रम का पूरा फल मिलता था, इसलिए वह बहुत मेहनती था। लेकिन गुलाम मजदूरों को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता था इसलिए मजदूरी के परिणाम और फल में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उत्पादन बढ़ाने, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कायम रखने और साधनों और उपकरणों पर कम खर्च करने के लिए कोई उत्साह नहीं था। सामान्यतः वह अपने काम में उतनी ही दिलचस्पी लेता था और उतना ही उत्साह दिखाता था, जितना

कि उसे मालिक के कोडो से बचाने के लिए आवश्यक होता था ।

दक्षिण में कृषि के सुधरे हुए तरीके या मजदूरी की बचत करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना सम्भव नहीं था, क्योंकि गुलामों पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वे इन मशीनों से ठीक काम ले सकेंगे । वे केवल सादे और भारी औजारों का ही प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं । इसलिए गुलाम-प्रथा के कारण दक्षिण के प्रदेश कुछ खास फसलों की उपज तक ही सीमित रह गए और वहाँ निर्माण उद्योगों का विकास नहीं हो सका ।

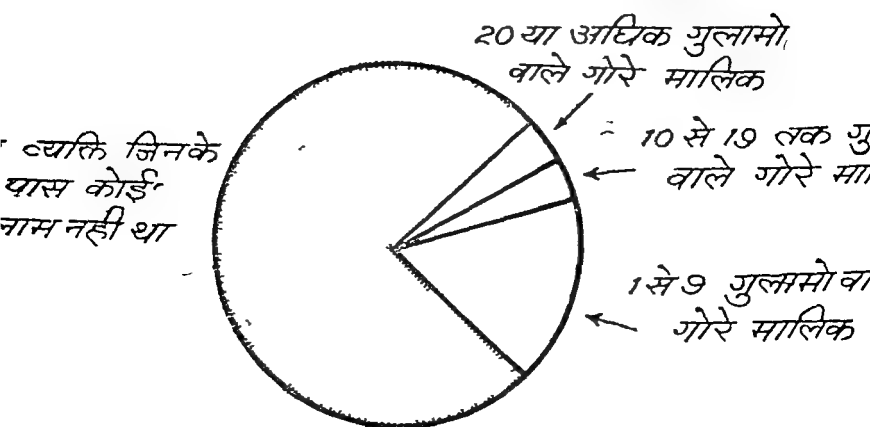
गुलाम-प्रथा वाले राज्यों के जमींदार और बागान मालिक ही दक्षिणी प्रदेश के शासक थे । उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता थी और साथ ही उन्हें अपनी विशेष परम्पराओं का गर्व भी था । इस मद में चूर होकर वे समाज को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने के लिए कृत-संकल्प थे । वे अपने-आपको अन्य देशों के अभिजातवर्ग की भाँति उच्च वर्ग बनाना चाहते थे । एक दक्षिणी जमींदार ने एक बार कहा था कि “जमींदारी ही इस देश में एकमात्र स्वतन्त्र और सम्मानित पेशा है ।”

फिर भी जमींदार एक पृथक् अल्पसंख्यक वर्ग थे । वास्तव में गोरी आबादी का कुल 25 प्रतिशत ही उन परिवारों से सम्बद्ध था, जिनके पास 1860 में दक्षिण में 35 लाख गुलाम थे । इनमें से भी दो-तिहाई परिवार ऐसे थे, जिनके पास दस से भी कम गुलाम थे । लेकिन शेष एक-तिहाई परिवारों का, जिनके पास दस या इससे अधिक गुलाम थे, अमेरिका की समूची नीग्रो आबादी के तीन-चौथाई भाग पर अधिकार था । ये लोग दक्षिण की कुल गोरी आबादी का 85 प्रतिशत भाग थे और इनके हाथों में ही दक्षिण की आय का अधिक हिस्सा था । इस प्रकार दक्षिण में आर्थिक शक्ति एक छोटे-से विशिष्ट वर्ग के हाथ में थी ।

गुलाम-प्रथा की सबसे गम्भीर आर्थिक कमजोरी यह थी कि उसमें पूँजी का संग्रह नहीं किया जा सकता था । गुलाम-प्रथा वाले राज्यों में केवल बड़े जमींदारों को ही बड़ी आमदनियाँ थी और सब मिलाकर वे अपने खर्चों-पन और विलासिता के कारण अपनी दौलत को खा-पीकर हजम कर जाते थे । जो कुछ वे बचाते थे वह जमीन और गुलामों को खरीदने पर व्यय हो

जाता था। दक्षिण की एक पत्रिका ने उन दिनों लिखा था कि दक्षिणी राज्यों में पूँजी-निवेश का एक विचित्र चक्र था, "लोग अधिक कपास का उत्पादन करने के लिए पूँजी का निवेश करते थे ताकि उसकी आमदनी से और अधिक नीग्रो गुलामों को खरीद सकें और वे गुलाम फिर कपास का उत्पादन बढ़ाएँ और उस बड़े उत्पादन से फिर नये नीग्रो गुलाम खरीदे जा सकें।"

सन् 1860 में गुलाम रखने वाले गोरे लोगों की स्थिति



सन् 1860 में दक्षिणी राज्यों की 79,81,000 गोरी आबादी में से केवल 25 प्रतिशत ही ऐसे परिवारों की थी, जिनके पास गुलाम थे।

अफ्रीका में गुलामों का व्यापार बन्द हो जाने पर गुलामों की कीमतें बहुत चढ़ गईं। कृषि-भिन्न कामों में गुलामों का उपयोग प्रारम्भ हो जाने और बड़ी जमीदारियों और बागानों की प्रणाली का विस्तार हो जाने से गुलामों की माँग तो बढ़ गई, किन्तु उनकी उपलब्धि कम रह गई। सन् 1845 में खेत में काम करने वाले जिस नीग्रो गुलाम की कीमत 650 डालर थी, वही 1850 के दशक में 1000 डालर में बिकने लगा और 1860 में उनका दाम और भी बढ़कर 1200 से 1800 डालर तक हो गया। लेकिन इन बीच रुई के दाम वही 9 से 12 सेंट तक प्रति पौंड के नीचे स्तर पर ही चले रहे। इस प्रकार इन वर्षों में गुलाम मजदूर की कीमत और रुई के

विक्रय मूल्य का अनुपात बहुत बदल गया। इसके अलावा गुलामों की खरीद में पैसा लगाना खतरे से खाली भी नहीं था। अगर गुलाम अपनी कीमत और अपने पालन-पोषण का खर्च निकालने से पूर्व ही मर जाता तो उसके मालिक को बहुत बड़ा नुकसान होता।

लेकिन जमींदार लोग किसी भी तरह गुलाम-प्रथा का त्याग करने को तैयार नहीं थे। गुलामों पर उन्होंने पैसा लगा रखा था और उनका मुनाफा इस बात पर निर्भर था कि उनके गुलामों में और अधिक गुलाम पैदा करने की कितनी क्षमता है। उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे सब गुलामों को बेच डालें और उनसे जो पैसा मिले उसे मशीनों की खरीद पर लगा दें। इसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा जिसके पास जितने अधिक गुलाम थे उसका समाज में उतना ही अधिक दबदबा और ऊँचा रुतबा था। अपनी सामाजिक स्थिति को बनाये रखने के लिए ये जमींदार अधिकाधिक गुलामों की खरीद में पैसा लगाते रहते थे।

ये जमींदार लोग गुलाम-प्रथा को बनाये रखने के अपने आग्रह के पक्ष में यह दलील देते थे कि यह दक्षिण की एक 'विशेष सामाजिक प्रथा' है। ये लोग अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों के अनेक दक्षिणवासियों की भाँति यह नहीं कहते थे कि यह 'एक आवश्यक किन्तु अस्थायी बुराई' है। इसके विपरीत वे यह दलील देते थे कि नीग्रो केवल गुलाम बनने के ही लायक हैं और उत्तर के अनेक गोरे श्रमिक दक्षिण के नीग्रो लोगों से भी खराब हालत में हैं। वे दक्षिण की अभिजात-तन्त्रीय परम्पराओं को संयुक्त राज्य में सभ्यता की सबसे अच्छी गारंटी मानते थे।

दक्षिण में पूँजी के संग्रह में एकमात्र यही बाधा नहीं थी कि वहाँ जमींदार अपनी आमदनी का बड़ा भाग जमीनों और गुलामों की खरीद में लगा देते थे। एक बाधा और भी थी और वह यह कि वहाँ की उधार प्रणाली बहुत पेचीदा थी। दक्षिण के जमींदारों को उत्तर के साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इस प्रणाली की पेचीदगी के कारण दक्षिण की रूई की हर गाँठ की विक्री पर विचौलिए एजेंटों को कितनी ही तरह के कमीशन देने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त उधार माल लेने की व्यवस्था के कारण जमींदारों को खाद्य पदार्थ, कपड़ा और कृषि उपकरण आदि चीजें

ऊँची कीमत पर उत्तर से खरीदनी पड़ती थी। जमींदारों के लिए खेती के सीजन में बिना उधार के अपना काम चलाना सम्भव नहीं था, इसलिए वे इस उधार-प्रणाली के चक्कर से किसी भी तरह अपने आपको बाहर नहीं निकाल सकते थे। इससे भी बड़ी कठिनाई यह थी कि ये लोग अपनी अगली फसल का सौदा पहले से ही करके उधार ले लेते थे, इसलिए उनके लिए यह भी संभव नहीं था कि रूई के भाव गिर जाने पर वे कपास की फसल पैदा ही न करे।

दक्षिण के लोगों के पास अगर कुछ पूंजी होती थी तो उसे वे हर सम्भव उपाय से बरबाद कर डालते थे। दक्षिण के लोगों के हाथ में समुद्री जहाजों का व्यापार नहीं था, इसलिए उत्तर के लोग ही उनकी उपज को समुद्र पार भेजते और इसमें वे अच्छा पैसा बनाते। दक्षिण में निर्माण-उद्योग नहीं थे, इसलिए उनकी उपज उत्तर में जाकर बिकती और इस प्रकार उनके बाजार पर भी उत्तर वालों का ही नियन्त्रण रहता। दक्षिण में कृषि अवश्य होती थी, किन्तु कुछ ही चीजों की, इसलिए उन्हें अपने लिए खाद्य पदार्थ दूसरी जगहों से लेने पड़ते। नतीजा यह होता कि पश्चिम के किसान दक्षिण के इन कृषि-जीवियों को, जो अपने लिए अन्न का प्रबन्ध नहीं कर सकते थे, अनाज और मांस आदि भेजते। जब इन चीजों की कीमतें बढ़ जाती तो दक्षिण के लोग चीखते-चिल्लाते। लेकिन पश्चिम से आनेवाली इन चीजों के बिना उनका काम नहीं चल सकता था, इसलिए उन्हें ऊँची कीमतें ही अदा करनी पड़ती।

इस सबका अर्थ यह नहीं था कि दक्षिण में अर्थ-व्यवस्था सभी जगह जड़ स्थिति में थी। दक्षिण की रूई अधिकाधिक मात्रा में निर्यात की जा रही थी और 1859 में तो यह स्थिति थी कि मूल्य की दृष्टि से अमेरिका के निर्यात का लगभग दो-तिहाई भाग रूई का था। इसके अतिरिक्त 1839 और 1859 के बीच बीस वर्षों में तम्बाकू की उपज भी दुगुनी हो गई।

लेकिन रूई और तम्बाकू की खेती ने जमीन को बहुत जल्दी बेकार कर डाला। सन् 1850 तक दक्षिण में परित्यक्त फार्मों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। जिन जमींदारों ने गुलामों पर बहुत पैसा लगा रखा था, उन्हें नई जमीनें प्राप्त करने में बहुत तंगी महसूस होने लगी। दक्षिण

के लोगो की एक शिकायत यह भी थी कि हालाँकि रूई की उपज बढ़ गई थी तो भी उसके वितरण पर उत्तर के लोगो का नियन्त्रण होने से उनकी मुनाफे की दर घट गई थी। इसके अतिरिक्त रूई के उत्पादन-व्यय में रूई के मूल्य की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो गई थी। सन् 1840 के बाद खेती के औजार, ढुलाई के भाड़े और गुलाम अधिकाधिक महँगे पड़ने लगे थे। यह लागत-वृद्धि छोटे जमींदारों के लिए खास तौर से भार बन रही थी।

इन सब समस्याओं ने दक्षिण के लोगो को यह महसूस करा दिया कि उनकी एक ही वस्तु की उपज करने की प्रणाली अत्यन्त हानिकारक है। सन् 1840 और 1850 के दशकों में दक्षिण के लोग इस बारे में गम्भीरता से विचार करने लगे थे कि कपास का उत्पादन घटाया जाय, कृषि में विविधता लाई जाय और स्थानीय निर्माण-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। इन सबका उद्देश्य व्यापार के मामले में उत्तर के नियन्त्रण से अपने-आपको मुक्त करना था। किन्तु स्थानीय उद्योगों को इसलिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि जमींदार लोग शहरी व्यवसायियों पर भरोसा नहीं करते थे। इसके अलावा दक्षिण में दौलत कुछ जमींदारों के हाथों में केन्द्रित थी, इसलिए यदि दक्षिण में उद्योग स्थापित होते भी तो उनके उत्पादनों की विक्री के लिए बाजार बहुत सीमित होता।

दक्षिण में वस्तुओं की विक्री के लिए बाजार की कमी का एक और हानिकारक प्रभाव था और वह यह कि दक्षिण से निर्यात की मात्रा जितनी होती, आयात की मात्रा उसका एक बहुत ही स्वल्प अंश होती। उदाहरण के लिए न्यू ऑर्लिन्स गृह-युद्ध से पहले के दशक में राष्ट्र के कुल निर्यात का चौथाई भाग निर्यात करता था, परन्तु उसका आयात राष्ट्र के कुल आयात का पन्द्रहवाँ हिस्सा था। मोबाइल, अलाबामा भी दक्षिण का एक बड़ा रूई-निर्यातक बन्दरगाह था, लेकिन वह आयात प्रायः कुछ भी नहीं करता था। इस तरह दक्षिण को अपनी रूई यूरोप को निर्यात करने के लिए पहले न्यूयार्क भेजनी पड़ती थी। अगर वह दक्षिण के बन्दरगाहों से ही भेजी जाती तो दक्षिण के जहाजों को आयात के अभाव में यूरोप से खाली लौटना पड़ता। इसका एक कारण यह भी था कि जहाजरानी के व्यापार में लगाने के लिए पैसा भी केवल उत्तर-पूर्व के लोगो के पास था।

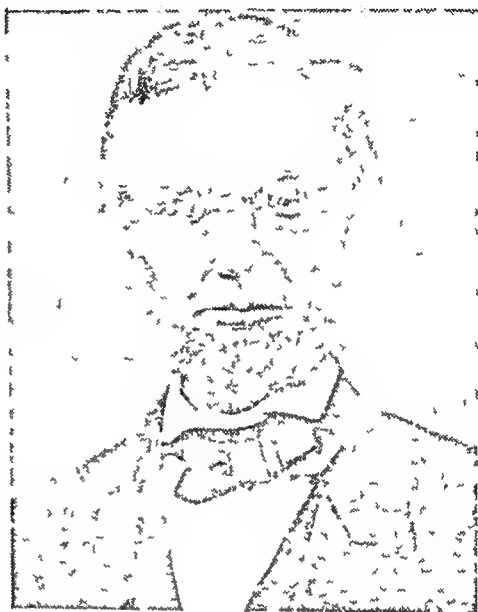
सन् 1860 तक अमेरिका के 'स्वै राज्य' की जमीन बिल्कुल बेकार-सी हो गई थी, क्योंकि एक तो गुलामों से काम लेने की प्रथा लाभकारी नहीं रही थी और दूसरे जमीन में उर्वरा शक्ति पुनः पैदा करने के लिए दक्षिण के लोगों के पान पर्याप्त धन नहीं था। दक्षिण के लोगों के पान एक ही उपाय था कि वे नई जमीनें प्राप्त करें अन्यथा उनकी कृषि के उत्पादन पर आधारित अर्थ-व्यवस्था और गुलाम-प्रथा के अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा था।

लेकिन उत्तर के गुलाम-प्रथा-विरोधी लोग राजनीतिक दृष्टि से इतने सबल थे कि उन्होंने दक्षिण के लोगों को अन्यत्र जमीनें प्राप्त करने और वहाँ भी अपनी गुलाम-प्रथा का विस्तार करने से रोक दिया। गुलाम-प्रथा वाले और स्वतन्त्र राज्यों के बीच सीनेट में मस्यौदा की दृष्टि से जो सन्तुलन चला आ रहा था, वह 1850 में कैलिफोर्निया के एक स्वतन्त्र (गुलाम-प्रथा रहित) राज्य के रूप में नयुक्त राज्य में प्रवेश से बिगड़ गया और स्वतन्त्र राज्यों का पलड़ा भारी हो गया। कुछ ही समय बाद ओरेगन और मिनेसोटा भी स्वतन्त्र राज्यों के रूप में नयुक्त राज्य में प्रविष्ट हो गए। प्रतिनिधि सभा में यह त्राई और भी चौड़ी हो गई। सन् 1850 के दशक के प्रारम्भ में जहाँ हर स्वतन्त्र राज्य के पाँच सदस्य प्रतिनिधि सभा में थे, वहाँ हर गुलाम-प्रथा वाले राज्य के कुल तीन ही प्रतिनिधि थे।

इसलिए दक्षिण के सामने चुनौती स्पष्ट थी कि वह राष्ट्रीय विधान-मंडल में अपनी शक्ति के क्षीण होते जाने पर भी अपनी इस 'विशिष्ट प्रथा' को कैसे कायम रख सकता है और कैसे अपनी आर्थिक समस्याओं का हल कर सकता है। उसे दो रास्तों में से किसी एक को चुनना था। वे रास्ते थे—परिवर्तन या युद्ध। उसने युद्ध का मार्ग चुना और उसमें उसे दोहरी मार नहीं पड़ी—एक ओर तो युद्ध में उनकी बुरी तरह पराजय हुई और दूसरी ओर उसे मजबूरन परिवर्तन करना पड़ा जो युद्ध के क्रूर परिणाम के रूप में उनकी परम-अभिलषित विशिष्ट परम्परा को बहा ले गया।

अलामो से ऐपोमैटोक्स तक

इस संघर्ष में मेरा सर्वोपरि उद्देश्य सघ (संयुक्त राज्य) की रक्षा करना है, गुलाम-प्रथा को बचाना या उसे नष्ट करना नहीं। यदि मैं किसी भी गुलाम को गुलामी से मुक्त किए बिना संयुक्त राज्य को बचा सकूँ तो मैं अवश्य वैसा ही कहूँगा। अगर उसे बचाने के लिए सब गुलामों को मुक्त करना जरूरी होगा तो मैं वह भी जरूर कहूँगा। और अगर मैं कुछ को मुक्त कर और कुछ को गुलाम रहने देकर ही संयुक्त राज्य को बचा सकूँ तो मैं वैसा भी कहूँगा।



—अब्राहम लिंकन, 1862

रुई राज्य के मालिक टेक्सास को अपने राज्य के विस्तार के लिए उसका स्वाभाविक अंग समझते थे। सन् 1820 से ही, जबकि टेक्सास मैक्सिको का भाग था, दक्षिण के अधिवासी वहाँ जाकर अपनी वस्तियाँ बसाने लग गए थे। सन् 1836 तक वहाँ बसे इन अमेरिकनो की सत्या वहाँ की आवादी का लगभग चौथाई हिस्सा हो गई थी। इससे उनकी इतनी शक्ति हो गई थी कि मैक्सिको सरकार की अवज्ञा कर सके। इसलिए इन लोगो ने अपनी स्वतन्त्रता और एक नये टेक्सास गणराज्य की स्थापना की

घोषणा कर दी।

मैक्सिकन सरकार ने विद्रोह को दवाने के लिए स्वयं सान्ता आना के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध की सबसे प्रसिद्ध घटना थी टेक्सास की छोटी-सी अलामो छावनी पर एक विशाल मैक्सिकन सेना का आक्रमण। इस आक्रमण में मैक्सिकन सेना ने छावनी के तमाम निवासियों को कत्ल कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर टेक्सन लोगो ने 'अलामो को याद रखो' का उत्तेजक नारा लगाया और सब टेक्सन वीरो को साथ लेकर सान्ता आना की सेना को सान जासिन्तो की निर्णायक लड़ाई में बुरी तरह तहस-नहस कर दिया। इस प्रकार टेक्सास का मैक्सिको से स्वतन्त्र हो जाना बिल्कुल सुनिश्चित हो गया और नये गणराज्य ने जरा भी वक्त बरबाद किये बिना संयुक्त राज्य में शामिल होने के लिए प्रार्थनापत्र दे दिया।

उत्तर में लोगो की आम भावना यह थी कि टेक्सास की स्वतन्त्रता का आन्दोलन वहाँ के निवासियों की आन्तरिक इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि उसे बाहर से दक्षिण के लोगो ने भड़काया था, ताकि टेक्सास को एक नये गुलाम-प्रथा वाले राज्य में शामिल किया जा सके। इसलिए उत्तर के सीनेटरो ने टेक्सास को संघ में मिलाने के विधेयक का तीव्र विरोध किया। अन्त में 1845 में वह पास अवश्य हो गया, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति टेलर के, जो गुलाम-प्रथा के समर्थक वर्जीनिया-निवासी थे, दबाव के कारण।

इसके बाद एक वर्ष के भीतर ही संयुक्त राज्य ने टेक्सास के इस दावे के समर्थन में, कि उसकी सीमा रायो ग्रान्द तक है, मैक्सिको के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। उत्तर-पूर्व के लोग इस लड़ाई के विरुद्ध थे, किन्तु, दक्षिण और पश्चिम के लोग उसका जोरदार समर्थन कर रहे थे। संयुक्त राज्य की कहीं अधिक शक्तिशाली सेना के साथ दो वर्ष तक लड़ने के बाद अन्त में थककर मैक्सिको ने उसके साथ शान्ति-सन्धि कर ली। यह सन्धि उसे बहुत महँगी पड़ी क्योंकि उसकी कीमत के रूप में उसे अपना एक तिहाई प्रदेश छोड़ देना पड़ा। संयुक्त राज्य ने इस प्रदेश के लिए उसे 1 करोड़ 50 लाख डालर दिए। इस प्रदेश में समूचे टेक्सास के अलावा वह प्रदेश भी शामिल था, जिसमें बाद में कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और एरिजोना बने। इसके अलावा संयुक्त राज्य ने अमेरिकन नागरिकों को हुई

व्यक्तिगत क्षतियों की भरपाई के रूप में भी मैक्सिको से 32,50,000 डालर लिये।

मैक्सिकन युद्ध की समाप्ति पर दक्षिण के लोगो ने इन नये अवाप्त प्रदेशो और लुइसियाना की खरीद से प्राप्त प्रदेशो में, जो अभी तक राज्यो का दर्जा प्राप्त नहीं कर सके थे, गुलाम-प्रथा के विस्तार का आन्दोलन तेज कर दिया। इसके साथ-ही-साथ इलिनॉय के सीनेटर स्टीफन डगलस ने भी अपनी वह योजना प्रस्तुत की जिसमें लुइसियाना की खरीद में प्राप्त विरल आबादी वाले भागो को 'प्रदेशो' के रूप में गठित करने के लिए कहा गया था, ताकि अटलांटिक तट से प्रशान्त तक महाद्वीप के आर-पार रेल-मार्ग स्थापित किया जा सके।

डगलस को अपनी इस योजना के पक्ष में उत्तर के उद्योगपतियों का प्रबल समर्थन प्राप्त था, खास तौर से उन लोगो का, जिनके पास शिकागो में स्थावर सम्पत्ति थी, क्योंकि प्रस्तावित रेल-मार्ग वन जाने पर स्वभावतः शिकागो ही, जिसका बहुत तेजी से विकास हो रहा था, उसका केन्द्र बनता। लेकिन डगलस की कन्सास और नेब्रास्का को 'प्रदेशो' (टेरिटरी) के रूप में गठित करने की योजना तभी सफल हो सकती थी, जबकि उसे दक्षिण का भी समर्थन प्राप्त होता। (प्रदेश यानी 'टेरिटरी' का अभिप्राय ऐसे भूभागो से है, जिनका शासन संयुक्त राज्य के हाथों में रहने पर भी, जिन्हें अभी तक राज्य यानी स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।)

किन्तु 1820 के मिसूरी समझौते के अनुसार, जिसके द्वारा मिसूरी प्रदेश को गुलाम-प्रथा वाले राज्य के रूप में संयुक्त राज्य में प्रविष्ट किया गया था, यह निर्णय हो चुका था कि लुइसियाना के 36°-30' अक्षांश के उत्तर में अवस्थित शेष भाग में गुलाम-प्रथा का विस्तार नहीं होने दिया जाएगा। कन्सास और नेब्रास्का भी इस उत्तरवर्ती क्षेत्र में ही शामिल थे। इसलिए पश्चिम का इस क्षेत्र में विस्तार दक्षिण के लोगो को कभी पसन्द नहीं आ सकता था।

डगलस ने इस समस्या के हल के लिए एक और तरीके से प्रयत्न किया। उसने अपना प्रसिद्ध कन्सास-नेब्रास्का विवेक कांग्रेस में पेश किया जिसमें मिसूरी समझौते को नमोदित करने और नये प्रदेश के लोगो को स्वयं यह

निर्णय करने का अधिकार देने के लिए कहा गया था कि वे 'स्वतन्त्र' राज्यों के रूप में संयुक्त राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं या 'गुलाम-प्रथा वाले' प्रदेशों के रूप में। विधेयक के अनुसार यह विशाल क्षेत्र इस आगा से दो भागों—कन्सास और नेब्रास्का—में बाँटा जाना था कि पहले में दक्षिण के लोगों का और दूसरे में उत्तर के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा।

इससे दक्षिण के सीनेटर तो सन्तुष्ट हो गए, परन्तु पश्चिम के बहुत-से सीनेटरों ने उसका जमकर विरोध किया। मध्य-पश्चिम के किसान यह मानकर चलते थे कि पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और फैलने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। उस समय तक मध्य-पश्चिम के किसानों का कहना था कि यदि हर व्यक्ति को, जो पश्चिम जाकर कहीं बसा हो, 160 एकड़ वास-भूमि (होमस्टैड) मुफ्त देने की व्यवस्था कर दी जाय तो वे इस भूमि-नीति को स्वीकार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह होता कि पश्चिमी प्रदेश में सैकड़ों एकड़ भूमि की जो बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ बन गई थी, उनमें से बहुत-सी वास-भूमियाँ किसानों को मुफ्त दे देनी पड़ती। वास्तव में पश्चिम के किसान गुलाम-प्रथा के इतने अधिक विरोधी नहीं थे—बल्कि वे यह महसूस करते थे कि 160 एकड़ के वास-भूमि फार्म इतने छोटे हैं कि उनमें गुलामों को रखकर उनसे काम लिया ही नहीं जा सकता।

इस तरह विभिन्न पक्षों के बीच विवाद चलता रहा, किन्तु इस विवाद के बावजूद 1854 में कन्सास-नेब्रास्का कानून पास हो गया। कानून पास होते ही उत्तर और दक्षिण दोनों ने कन्सास में बसने के लिए अपने-अपने हजारों आदमी भेजने शुरू कर दिए, ताकि वे 'स्वतन्त्र प्रदेश' और 'गुलाम-प्रथा वाले प्रदेश' के बारे में फैसला होने पर मत संग्रह में अपने-अपने पक्ष को अपनी सख्या के बल से मजबूत कर सकें। नतीजा यह हुआ कि कन्सास में गुलाम-प्रथा के विरोधियों और समर्थकों में खूनी लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में प्रारम्भ में गुलाम-प्रथा की विरोधी ताकतों को अनेक बार मात खानी पड़ी, लेकिन अन्त में गुलाम-प्रथा के कट्टर विरोधी जॉन ब्राउन द्वारा उत्तेजित और भड़काई गई इन ताकतों ने लड़ाई जीत ही ली और कन्सास एक 'स्वतन्त्र' राज्य के रूप में 1861 में संयुक्त राज्य में शामिल हो गया।

कन्सास-नेब्रास्का कानून पार होने और दक्षिण द्वारा उत्तर और पश्चिम

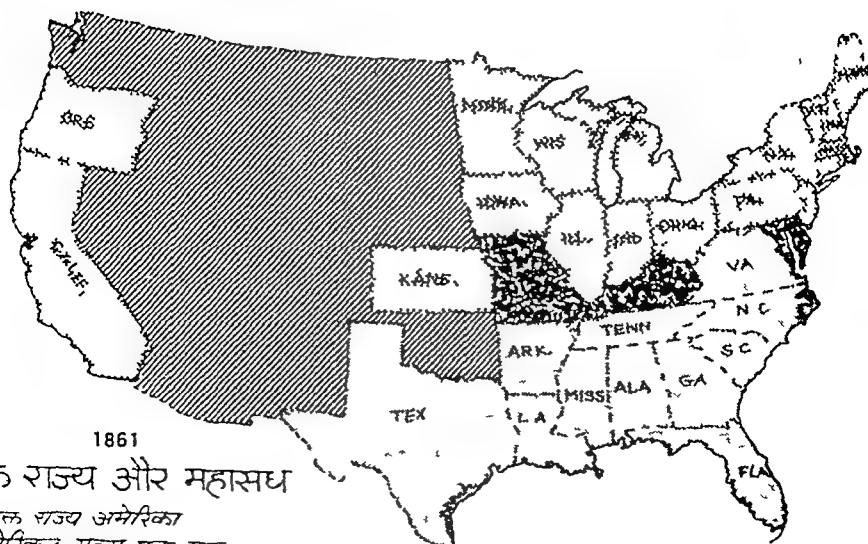
के विकास को रोकने के लिए किये गए प्रयत्नों का परिणाम बड़ा उत्तेजना-जनक हुआ। 'प्रदेशों' में गुलाम-प्रथा का विस्तार करने या न करने का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उत्तरी और दक्षिणी सदस्यों में इस प्रश्न पर झगड़ा हो जाने से इस पार्टी का राष्ट्रीय रूप नष्ट हो गया और एक नये शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में रिपब्लिकन पार्टी का उदय हुआ। (जैफर्सन के जमाने में जो रिपब्लिकन पार्टी थी वह इससे भिन्न थी। वही पार्टी काफी समय पूर्व डेमोक्रेट-रिपब्लिकन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई थी)।

इलिनॉय का एक तरुण वकील अब्राहम लिंकन इस नई पार्टी के नेताओं में से एक था। अमेरिकन 'प्रदेशों' में गुलाम-प्रथा के विस्तार का रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उमने तीव्र विरोध किया जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर और पूर्व में इस पार्टी को बहुत बड़ी सख्या में समर्थक और अनुयायी मिल गए। इस नई पार्टी के उदय से गुलामी का प्रश्न, जो 1850 से पूर्व मुख्यत एक नैतिक और राजनीति-भिन्न प्रश्न था, राजनीतिक प्रश्न बनने लगा। पश्चिम के किसान, छोटे व्यवसायी और नये आवासी लोग, जिन्हें गुलाम-प्रथा से प्रतिस्पर्धा की आशंका थी, इस नई पार्टी के समर्थक बन गए।

अब्राहम लिंकन धीरे-धीरे इन लोगों का प्रवक्ता बन गया। सन् 1854 में प्योरिया, इलिनॉय में एक भाषण करते हुए लिंकन ने कहा था कि "इन प्रदेशों को हमें स्वतन्त्र गोरे लोगों का निवास-स्थान बनाना है और अगर गुलामी का बीज उनके भीतर लाकर बो दिया गया तो वे स्वतन्त्र गोरो का निवास-स्थान कभी नहीं बन सकते। हमें गरीब गोरे लोगों को गुलाम राज्यों में हटाना है न कि उनमें ले जाकर बसाना। नये स्वतन्त्र राज्य ऐसे स्थान होंगे, जहाँ जाकर गरीब लोग स्वतन्त्रता के साथ बन सकें और अपनी स्थिति सुधार सकें। इसी काम के लिए राष्ट्र को नये प्रदेशों की आवश्यकता है।" दो वर्ष बाद लिंकन ने फिर कहा "हमें गुलाम प्रथा वाले राज्यों के चारों ओर एक घेरा डाल देना चाहिए। तब यह अग्नि प्रथा, अपने ही विष में मर जाने वाले सर्पिल की तरह, स्वयं अपनी बदनामी में मर जाएगी।"

दिन की इस सीधी-सादी और सरल वाक्पटुता व सरल अग्नि और सुविचारित दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि 1860 में निर्वाचन

पार्टी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उसे अपना उम्मीदवार मनोनीत किया। इसमें सन्देह नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव आन्दोलन में सबसे



1861

संयुक्त राज्य और महासंघ

- संयुक्त राज्य अमेरिका
- अमेरिकन राज्य महासंघ
- ▨ संयुक्त राज्य से अलग न होने वाले 'गुलाम राज्य'
- ▩ संयुक्त राज्य के सेस प्रवेश जो अभी राज्य नहीं बने थे

शक्तिशाली नारा था गुलाम-प्रथा के विस्तार का तीव्र विरोध। लेकिन उसके कार्यक्रमों में कुछ और जबर्दस्त चीजें भी शामिल थी, जैसे किसानों को मुफ्त जमीन देना, उद्योगों की रक्षा के लिए सरक्षात्मक तटकर लगाना, रेल-मार्गों का निर्माण आदि आन्तरिक सुधार सघीय सरकार द्वारा कराना। इन कार्यक्रमों ने उत्तर में भी इस पार्टी के बहुत-से नये समर्थक बना दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के दक्षिणी और उत्तरी सदस्यों में आपस में जो झगडा चल रहा था उससे रिपब्लिकन पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई और दक्षिण की स्थिति संयुक्त राज्य में हमेशा के लिए अल्पसंख्यक की हो गई।

दक्षिण के अभिमानी लोगों के गर्व को इससे बहुत चोट लगी और उन्होंने संयुक्त राज्य से अलग होने और एक अमेरिकन राज्य महासंघ (कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका) बनाने का निश्चय किया। निःसन्देह

दक्षिण के बहुत-से लोग यह समझते थे कि दक्षिण शान्ति से ही सयुक्त राज्य से अलग हो सकेगा। किन्तु उत्तर के लोग सघ से दक्षिणी राज्यों के विच्छेद को क्रान्ति या विद्रोह समझते थे। अपने प्रारम्भिक अभिभाषण में लिंकन ने दक्षिण में सयुक्त राज्य की सरकार के अधिकार को बनाये रखने के अपने कर्तव्य पर बल दिया। उसने कहा—“मैं समझता हूँ कि हमारा सघ (नयुक्त राज्य) विच्छिन्न नहीं हुआ है। और मैं शक्ति-भर इस बात का प्रयत्न करूँगा कि सघ के कानूनों का सभी राज्यों में पूरी वफादारी में पालन हो।”

गृह-युद्ध का जो खतरा इन घटनाओं के दौरान में निरन्तर काली घटा की भाँति राष्ट्र के सिर पर मडराता रहा था, वह अन्त में एक दिन फॉर्ट सुमटर, दक्षिणी कैरोलाइना में फूट ही पड़ा, जबकि वहाँ की सघीय सेना के कमांडर ने 12 अप्रैल, 1861 को राष्ट्रपति लिंकन के कार्यालय से प्राप्त आदेश का पालन करते हुए अपना किला महासघ (कन्फेडरेट) की सरकार के हाथों में सौंपने में इन्कार कर दिया। महासघ ने इस अवज्ञा का जवाब किले पर तोप का गोला चलाकर दिया। उस एक गोले के फटते ही सारे देश में गृह-युद्ध की आग पूरी तरह फैल गई।

दोनों युद्ध-रत पक्षों ने जब इस महान् युद्ध के लिए अपने नव साधन संगृहीत करने प्रारम्भ किए तो उनमें अत्यधिक दयनीय असमानता थी। महासघीय राज्यों की कुल आबादी 90 लाख थी, जिसमें 35 लाख गुलाम भी शामिल थे, सयुक्त राज्य के अन्तर्गत राज्यों की आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी। कुल 16 अरब डालर की सम्पत्ति में से महान् सघीय राज्यों की सम्पत्ति 6 अरब डालर में ज्यादा नहीं थी और इसमें से भी एक तिहाई सम्पत्ति गुलामों की कीमत के रूप में थी। दक्षिण के पान प्राय एक भी जहाज नहीं था, उनके निर्माण-उद्योग राष्ट्र के निर्माण-उद्योगों का पाँचवाँ भाग थे और उनमें फैली रेलें देश के कुल रेल-मार्गों का एक-तिहाई भी मुश्किल में थी।

इन असमानताओं और कमजोरियों को देखते हुए दक्षिण का उत्तर को युद्ध के लिए ललकारना नितान्त मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। किन्तु फिर भी कुछ बातें ऐसी थी, जो दक्षिण के लिए अधिक अनुकूल थीं। दक्षिण की समाज-रचना नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छी थी। वहाँ प्रचलित नैतिक

अधिकारियों की सरया बहुत बड़ी थी। यूरोपियन देशों की सहानुभूति दक्षिण की ओर ही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दक्षिण एक बड़े ध्वेय को लेकर लड़ाई कर रहा था—वह ध्वेय था एक खास ढंग की सम्पत्ता की रक्षा करना।

उत्तर को अपने सामारिक साधनों का संग्रह करने में जिस सबसे बड़ी और बुनियादी बाधा का सामना करना पड़ा वह थी अपनी गक्ति पर उचित से अधिक भरोसा। उत्तर के नेताओं ने अपने-आपको अधिक साधन-सम्पन्न देखकर यह समझ लिया था कि युद्ध तीन महीनों में ही खत्म हो जाएगा। उत्तर के लोगों का यह अत्यधिक आत्म-विश्वास और दक्षिण के लोगों का साधनहीन होने पर भी ऊँचा हौसला—सम्भवतः इन दोनों के सम्मिश्रण का ही यह परिणाम था कि यह खूनी युद्ध चार वर्ष तक चलता रहा।

उत्तर और दक्षिण, दोनों ने युद्ध के लिए पैसा जुटाने को ऋण लिये, नए कर जारी किये और दबादब कागजी मुद्रा चलाई। उत्तर में ये तीनों उपाय अधिक कारगर हुए, वहाँ दो अरब डालर से अधिक राशि सरकारी बाड़ों से संग्रह की गई। करो से भी, जिनमें उत्पादन कर, आयात कर और आय-कर शामिल थे, 66 करोड़ 70 लाख डालर और प्राप्त हुए। लेकिन महासंघ (दक्षिण) द्वारा जारी किये गए बाड़ बहुत सफल नहीं हुए। ये बाड़ आम तौर पर डालरों के बजाय रूई, तम्बाकू तथा अन्य जिनसों के बदले में बेचे जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि महासंघ सरकार के पास जल्दी ही इन जिनसों का भारी स्टॉक जमा हो गया। करो से होने वाली प्राप्ति भी दक्षिण में आम तौर पर निराशाजनक थी। अनुमान है कि महासंघ को करो से 10 करोड़ डालर से अधिक की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों सरकारों द्वारा जारी की गई कागजी मुद्रा का परिणाम यह हुआ कि उत्तर और दक्षिण दोनों में आम मुद्रा-स्फीति हो गई। युद्ध समाप्त होने तक उत्तर के नोटों की कीमत गिरकर 40 सेंट प्रति डालर रह गई थी। लेकिन फिर भी दक्षिण में ये नोट वहाँ के अपने नोटों की अपेक्षा, जिनकी कीमत तेजी से गिर रही थी, अधिक मूल्य पर चल रहे थे।

राष्ट्रीय विधान मंडल से दक्षिण के सदस्यों के अलग हो जाने का परिणाम यह हुआ कि उत्तर के उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने विधान मंडल

से अपनी बातें बिना किसी कठिनाई के मनवा ली। वास्तव में गृह-युद्ध के वर्षों में एक ऐसी आर्थिक विचार-धारा की स्थायी विजय हुई जो देश के वाणिज्य और उद्योगों के विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल और महत्वपूर्ण थी। इन वर्षों में उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयातित वस्तुओं पर ऊँचे सघीय तटकर लगाये गए, महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक रेल-लाइने बिछाने वाली कंपनियों को सघीय सरकार की ओर से सहायता दी गई, राज्यों के बैंकों के बजाय एक राष्ट्रीय बैंक-प्रणाली स्थापित की गई, और वास-भूमि कानून (होमस्टैड ऐक्ट) भी, जिसकी पश्चिम के किसान एक असें से प्रतीक्षा कर रहे थे, अन्ततः पास हो गया। उत्तर के व्यवसायी वर्ग और पश्चिम के व्यापारी कृषक वर्ग के बीच गठबन्धन पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गया।

गृह-युद्ध ने संयुक्त राज्य में केवल औद्योगिक विकास को ही प्रगति नहीं दी, बल्कि गुलाम-प्रथा का भी अन्त कर दिया और दक्षिण की सारी अर्थ-व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया। युद्ध खत्म हो जाने पर दक्षिण इतना गरीब हो गया था कि उसकी आने वाली अनेक पीढ़ियों का भविष्य अन्धकार-मय दीखता था। उसकी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, उसकी चिर-अभिलषित सामाजिक परम्पराएँ और प्रथाएँ युद्ध के प्रवाह में बह गई थी और संयुक्त राज्य से पृथक् होकर एक महासंघ की स्थापना का उमका पवित्र ध्येय भी, जिसके लिए उसने इतने कष्ट महे और कुर्बानियाँ की थी, हमेशा के लिए दफना दिया गया था। अब उसके लिए सिर्फ धीरे-धीरे पुनर्निर्माण करने का व्यापार्य काम ही शेष रह गया था।

उदाराशय लिंकन को, जो युद्ध-जन्य कष्टों की पीड़ा को बहुत अन्तरिकता से महसूस करता था यह आशा थी कि वह दक्षिण के डम बोझ को कुछ हल्का कर सकेगा। इसलिए मार्च, 1865 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर उसने अपने प्रारम्भिक भाषण की समाप्ति इन उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ की थी—“किसी के भी प्रति द्वेष और दुर्भावना मनमें लाये बिना, सब के प्रति उदारता बरतते हुए, और भगवान् हमें जिसे मृत्यु समझने की प्रेरणा देता है उनमें दृढ़ आस्था रखते हुए हमें अपने सम्मुख उपस्थित कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। वह कार्य है राष्ट्र के

घावों को मरहम-पट्टी करना, जिन लोगो ने युद्ध का भार वहन किया उनकी विधवाओं और अनाथ बच्चों की देख-भाल करना और ऐसे सब काम करना जिनसे हममे परस्पर भी और अन्य सब राष्ट्रों के साथ भी न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति बनी रह सके।”

लेकिन इस देश के एक महान्तम सपूत के नेतृत्व में कटुताहीन पुनर्निर्माण की यह आकांक्षा और आशा पूरी होने वाली नहीं थी। अप्रैल, 1865 में लिंकन की हृदय-विदारक हत्या ने इस आशा को धूल में मिला दिया कि राष्ट्र का यह दूसरा जन्म शान्ति से और बिना किसी कटुता के सम्पन्न हो सकेगा। वास्तव में यह कार्य इतना कठिन था कि जिस लिंकन ने युद्ध के अधियारे वर्षों में संयुक्त राज्य का सफल नेतृत्व किया था, उसके जीवित और सत्तारूढ़ रहने पर भी आसानी से न हो सकता। और उसके चले जाने पर तो वह असम्भव ही हो गया।

पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान

महान् मुक्तिदाता की हत्या के बाद उपराष्ट्रपति ऐंड्रयू जॉनसन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के रूप में पदारूढ हुए। उनका विचार लिकन की योजना के अनुसार दक्षिण के पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने का था। लेकिन जॉनसन उन उग्र रिपब्लिकनो को भूल गए थे, जो यह अनुभव करते थे कि दक्षिण को अपने विद्रोह की पूरी कीमत चुकानी चाहिए।

धीरे-धीरे कांग्रेस (संसद) के अधिकतर सदस्य भी इन उग्र रिपब्लिकनो के विचार की ओर ही झुकने लगे, जिससे राष्ट्रपति और उनके राजनीतिक शत्रुओं के बीच संघर्ष उग्रतर होता गया। अन्त में 1868 में ऐंड्रयू पर अपने पद के दुरुपयोग का महाभियोग लगाया गया। जॉनसन ही संयुक्त राज्य का पहला और एकमात्र राष्ट्रपति था, जिस पर राष्ट्रीय विधान मंडल के उच्च सदन में महाभियोग लगाया गया और जिसे अभियुक्त के रूप में सदन में खड़ा किया गया। सीनेट में काफी गर्मागर्म बहस के बाद मत लिये जाने पर उसे राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए केवल एक मत की कमी रह गई।

इस बीच एक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप दक्षिण से पूरी तरह घुटने टिकवा दिये गए थे। उत्तर की सेना ने दक्षिण पर अधिकार कर लिया था, राज्यों की विधान-सभाओं से 'पुराने दक्षिण' के सब अनुदार तत्वों का सफाया कर दिया गया था और तमाम नीग्रो लोगों को भी नागरिक अधिकार प्रदान कर दिये गए थे। इस सबका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में एक तरह की राजनीतिक अराजकता पैदा हो गई।

जो लोग पहले गुलाम थे, वे जब बिना किसी अनुभव के एकाएक ऊपर उठाकर राजनीति में धकेल दिये गए, तो उत्तर के राजनीतिज्ञों ने, जिनका कोई उसूल नहीं था, उनसे मनमाना लाभ उठाने का प्रयत्न किया। धोखा-घड़ी और रिश्वतखोरी आम चीजें हो गईं और बिना किसी शर्म-हया के किये गए अपव्यय से देखते-देखते राज्यों और नगरपालिकाओं के कोश

खाली हो गए। भूतपूर्व महासच के ग्यारह राज्यो पर भारी कर्जे लाद दिये गए। सन् 1868 के बाद के छ वर्षों में उनके कर्जे 10 करोड़ डालर और बढ़ गए।

फिर भी दक्षिणी राज्यो ने मजबूर होकर जो नए सविधान बनाए वे उनके पुराने सविधानो की अपेक्षा कहीं अधिक लोकतन्त्रीय थे। अन्ततः वे एक अधिक सुचारु शासन का आधार प्रस्तुत करते थे। अनेक दक्षिणी राज्यो में मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा, धर्मार्थ सस्थाओं की स्थापना और नीग्रो किसानो की सहायता आदि के प्रगतिशील कानून पास किये गए। यद्यपि इन राज्यो में लोकतन्त्र का स्वरूप बहुत अपरिपक्व था, फिर भी लोकतन्त्र सक्रिय अवश्य हो उठा था।

किन्तु इन सामाजिक प्रगतियों के बावजूद, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर के अधिकारियों द्वारा ऊपर से लादा गया यह पुनर्निर्माण कार्यक्रम असफल रहा। नागरिक अधिकारो को सगीन के बल से लागू करने के कार्यक्रम ने निस्सन्देह जातीय विद्वेष और तनाव पैदा किया। यदि गुलामी से मुक्त लोगो को यह समझाने का प्रयत्न किया जाता कि स्वाधीन होने से उन पर क्या जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और उन्हें क्या विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं तो यह तनाव आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाता। इसके अतिरिक्त पुनर्निर्माणकी कठिनाइयो ने दक्षिण की समस्त गोरी आबादी को रिपब्लिकन पार्टियों का कट्टर विरोधी और डेमोक्रेटिक पार्टियों का समर्थक बना दिया। इस प्रकार गृह-युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण नीतियों के कारण दक्षिण के लोगो को जो कष्टपूर्ण वर्ष बिताने पड़े, उनसे दक्षिण डेमोक्रेटिक पार्टियों का ठोस समर्थक बन गया और वहाँ जातीय तनाव बढ़ गया। यह स्थिति आज तक उसी तरह चली आ रही है।

दक्षिण के आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम था ज़मीन को उत्पादक उपयोग में फिर से लगाना। गुलाम-प्रथा के खत्म हो जाने से यह काम बहुत पेचीदा हो गया। कल तक, जो लोग गुलाम थे, वे रातो-रात स्वतन्त्र हो गए थे और अधिकतर गुलामो ने, पहले-पहल स्वतन्त्रता का अर्थ कुछ न करने का अधिकार समझा था। नतीजा यह हुआ कि एक ओर ज़मीन श्रमिको के अभाव में बेकार पड़ी थी और दूसरी ओर नीग्रो लोग अपने

‘अधिकारों’ का अधिकतम उपभोग करने के लिए देहातो में व्यर्थ चक्कर लगा रहे थे।

वेचैन नीचो श्रमिक लोग जब अपने घरों पर फिर से लौटे भी तो यह समस्या पैदा हो गई कि उन्हें काम की मजदूरी कहाँ से दी जाय। बहुत कम जमींदारों के पास मजदूरी देने लायक पैसा बचा था। इसलिए खेती की सबसे अच्छी प्रणाली यही रह गई कि मजदूरों को फसल की उपज में से हिस्सा दिया जाय। इस प्रणाली के अन्तर्गत जमींदार मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं देता था और मजदूर जमीन का कोई लगान नहीं देते थे और दोनों मिलकर फसल की उपज में से हिस्सा बाँट लेते थे। इसके बावजूद जमीन के मालिक के लिए अनेक बार यह जरूरी हो जाता था कि वह बीज, औजार या अन्य वस्तुओं के लिए कर्जा ले। इस तरह युद्ध में पहले फसल को बन्धक रखने की जो प्रणाली प्रचलित थी वह युद्ध के बाद दक्षिण में और भी दृढ़ता से बढ्मूल हो गई।

फसल की हिस्सा-बाँटई के कई नुकसान भी थे—इनमें से एक नुकसान कपास का आवश्यकता के अधिक उत्पादन था, जो एक पुरानी समस्या बन गया था—और उसमें सन्देह नहीं कि यह प्रणाली अपनी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी चलती रही, लेकिन इसका एक लाभ भी हुआ और वह यह कि इनमें दक्षिण की बेकार पड़ी जमीन में फिर खेती होने लगी।

जमींदारियों के तबाह हो जाने पर जमींदार वर्ग के बहुत-से लोगों को जीवन-साधन के दूसरे तरीके अपनाने पड़े। उनका एक परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने दक्षिण में उद्योगों की स्थापना के लिए सगठित होकर प्रयत्न

कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकेगा जिसमें संप्रुक्त राज्य के नागरिकों के अधिकार या कानूनी प्रतिरक्षण सीमित होते हों और न ही कोई राज्य जिना कानूनी कार्रवाई के सिद्धांतों को उससे जीवन, स्वतंत्रता या सम्पत्ति में व्यर्थ पर सहेगा **

—1868 में संयुक्त राज्य के संविधान में लिखा गया 14वां संशोधन

किया यद्यपि पूंजी के अभाव से दक्षिण के व्यवसायियों को अपने क्षेत्र के उपलब्ध साधनों को विकसित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो भी वहाँ निर्माण-उद्योग स्थापित करने में पर्याप्त प्रगति हुई। वर्मिंघम, अलाबामा, जो युद्ध से पूर्व कपास-उत्पादक क्षेत्र था, शीघ्र ही लोहे का सामान तैयार करने का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। सूती वस्त्र, लोहा और इस्पात, लकड़ी की चिराई और फर्नीचर तथा तम्बाकू की चीजों का निर्माण आदि शीघ्र ही दक्षिण के महत्वपूर्ण उद्योग बन गए। सन् 1900 तक करीब एक अरब डालर की राशि दक्षिण के निर्माण-उद्योग में लग चुकी थी।

वैसे सारे देश में कुल मिलाकर निर्माण-उद्योगों की और भी अधिक उन्नति हुई। गृह-युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तक देश के मुख्य धन्ये कृषि और वाणिज्य ही थे। सिर्फ न्यू इंग्लैंड और मध्य अटलांटिक राज्यों के कुछ भाग ही ऐसे थे, जहाँ उद्योग स्थापित थे। लेकिन 1890 तक स्थिति बदल गई और कारखानों में निर्मित वस्तुओं का मूल्य कृषि-उत्पादनों के मूल्य से अधिक हो गया। दस वर्ष बाद तो वह कृषि-उत्पादनों के मूल्य से दुगुना हो गया। सन् 1860 में संयुक्त राज्य में कारखानों में निर्मित वस्तुओं का मूल्य 19 अरब डालर था, परन्तु 1890 तक वह इससे सात गुना हो गया।
















बीसवीं सदी प्रारम्भ होने से पहले के दो दशकों में कोयले का उत्पादन 63 करोड़ टन वार्षिक से बढ़कर चार गुना हो गया। इसी अवधि में शोधित तेल का उत्पादन तीन गुना और ताँबे का उत्पादन दस गुना हो गया और लोहे तथा इस्पात का उत्पादन भी चौगुना होकर 1900 तक तीन करोड़ टन वार्षिक हो गया।


इस औद्योगिक उन्नति में योग देने वाले अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था—रेलमार्गों के जाल का देश-भर में विस्तार। सन् 1843 से 1893 तक के काल को 'रेल पूंजीवाद का युग' कहा जा सकता है। इन पचास वर्षों में अमेरिका की रेल-मार्ग प्रणाली सप्ताह में सबसे बड़ी प्रणाली हो गई। रेल लाइनों की लम्बाई 1865 से 1873 तक दुगुनी हो गई, जब कि इस अवधि में रेलों में लगी पूंजी की मात्रा 12 अरब डालर से बढ़कर

37 अरब डालर हो गई। सन् 1880 के दशक में 73,000 मील लम्बी रेल लाइनें और भी बनाई गईं और 1914 तक संयुक्त राज्य की रेल लाइनों का विस्तार यूरोप के समस्त राष्ट्रों की रेल लाइनों की कुल लम्बाई से भी अधिक हो गया।

रेलें केवल सामान के परिवहन का ही साधन नहीं थी, वे अपने-आप में एक बड़ा बाजार भी थी। सन् 1870 के दशक में राष्ट्र के कुल पूंजी निर्माण का 20 प्रतिशत रेलों में हुआ था और उससे अगले यानी 1880 के दशक में यह मात्रा 15 प्रतिशत थी। रेलों को इजनों, डिब्बों, मशीनरी, लोहा और इस्पात, लकड़ी और कोयले की भारी मात्रा में आवश्यकता थी, इसलिए रेलों ने अन्य पूंजीगत सामग्रियों के उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ी और देश की तेजी से बढ़ रही श्रम शक्ति के लिए नये काम और रोजगार उपलब्ध हुए। आमदनी बढ़ने से उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला।

संयुक्त राज्य का औद्योगिक विकास, 1859-1899

1859	 +  = 
1869	 +  = 
1879	 +  = 
1889	 +  = 
1899	 +  = 

 1859 में 1 अंग्रेजी टन में 10 पैसे का था। 1869 में 2 अंग्रेजी टन में 10 पैसे का था। 1879 में 3 अंग्रेजी टन में 10 पैसे का था। 1889 में 4 अंग्रेजी टन में 10 पैसे का था। 1899 में 5 अंग्रेजी टन में 10 पैसे का था।

इस्पात उद्योग एक ऐसे विशाल उद्योग का उदाहरण है, जो एक तरह से सिर्फ रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही स्थापित हुआ। सन् 1879 में संयुक्त राज्य में उत्पादित इस्पात का तीन-चौथाई भाग केवल रेल की पटरियाँ बनाने में ही प्रयुक्त हुआ। सन् 1885 में इस्पात में बने डिब्बों ने रेलों की परिवहन क्षमता को बढ़ा दिया। पहले लकड़ी के डिब्बे जहाँ मात या आठ टन माल ले जा सकते थे, वहाँ इस्पात के नये डिब्बे तीस टन माल ले जाने लगे। सन् 1900 तक इस्पात के रेल के डिब्बों की

परिवहन क्षमता बढ़कर चालीस और पचास टन के बीच हो गई। इस्पात उद्योग में मुनाफा इतना ऊँचा था कि बहुत-से इस्पात निर्माता बाहरी पूँजी की मदद के बिना अपने ही मुनाफे से अपना उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सके।

रेलो में स्थावर सम्पत्ति बहुत बड़ी मात्रा में लगती है और अनिवार्य खर्च भी बहुत ऊँचे होते हैं, इसलिए उनमें प्राइवेट लोगो का व्यक्तिगत रूप में पूँजी लगा सकना सम्भव नहीं था। दूर दृष्टि से न देखने पर अक्सर ऐसा लगता था कि रेलो का संचालन खतरनाक और घाटे का सौदा है। खासकर कम आवादी वाले और कम विकसित क्षेत्रों में तो ऐसा और भी अधिक लगता था। इसलिए रेल-मार्ग स्थापित करने वालों ने इस खतरनाक काम के लिए पूँजी जुटाने के लिए साहसपूर्वक कम्पनियों का निर्माण किया, ताकि उसमें किसी एक व्यक्ति के वजाय बहुत-से व्यक्ति अपनी पूँजी लगाने का खतरा मोल ले सकें।

किन्तु दुर्भाग्य से अक्सर ये कम्पनियाँ उनके सस्थापकों के व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूँजी जुटाने के वास्ते बाहरी दिखावा मात्र थी। जे गोल्ड, जिम फिस्क और कॉर्नेलियस वाडरविल्ट आदि के नाम 'रेल पूँजीवाद' के उस 'स्वर्ण युग' के महादैत्यों में आज भी लिए जाते हैं, जब कि बड़े पूँजीपति सरकार की ओर से कोई भी रोक-टोक और नियन्त्रण न होने के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था के एक बड़े भाग पर निर्विघ्न होकर शासन करते थे।

उद्योगपति और व्यवसायी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मनमाने व्यापारिक हथकड़ों से विशाल धन राशियाँ कमाकर या गँवाकर उनके वारे-न्यारे करते थे। इनमें से बहुत-से व्यापारिक सौदों में सार्वजनिक हित की भारी अवहेलना की जाती थी। एरी रेलरोड कम्पनी के शेयरों के एक सनसनीखेज सौदे के बाद जिम फिस्क ने निर्लज्जता से टिप्पणी करते हुए कहा था, "इस सौदे में इज्जत के सिवाय और किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ।" इसी तरह एक अन्य मौके पर कमोडोर वाडरविल्ट ने भी इसी तरह की निर्लज्ज विचाराधारा का प्रतिपादन करते हुए उच्छृंखलता से कहा था, "कानून की मुझे क्या परवाह है? मेरे हाथ में क्या ताकत नहीं है?"

आज यह विचारधारा नैतिक दृष्टि से हमें कितनी ही भयकर क्यों न लगे, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमेरिकन जन-जीवन में जो सक्रियता और गतिमयता थी, उसकी पृष्ठभूमि में देखने पर उसमें कोई असोभनीयता प्रतीत नहीं होगी। दौलत पैदा करने के लिए उस समय इतना विशाल क्षेत्र पड़ा था कि बहुत कम लोगों ने इससे पूर्व इसकी कल्पना की होगी। उन्नति करने और धन कमाने के अवसर इतने विशाल और विस्तीर्ण थे, और एक क्षेत्र में असफल हो जाने पर दूसरे क्षेत्र में प्रयत्न न करने के लिए भी कोई कारण नहीं था, इसलिए राष्ट्र की साधन-सम्पदा के विकास और दोहन के लिए तरह-तरह के परीक्षण करना अनुचित नहीं कहा जा सकता था।

इसलिए नैतिक व्यवहार का जो मानदंड किसी अधिक सुसंगठित और अधिक सुस्थिर समाज में असह्य समझा जाता, वही उस जमाने के कम-संगठित और कम स्थितिशील अमेरिकन समाज के लिए उपयोगी बन गया। क्योंकि आखिर इस अनैतिक विचारधारा से रेलें बन तो गईं और पश्चिम की ओर खूब विस्तार भी हो सका। जिस तरह गृह-युद्ध से पूर्व वैकिंग-व्यवसाय में हुई अनैतिक ज्यादतियों को हम उनसे हुए पश्चिम के विकास की दृष्टि में रखकर क्षम्य समझ लेते हैं, वैसे ही रेल-निर्माण के क्षेत्र में हुई अनैतिक स्वार्थसाधक ज्यादतियों को भी हमें उसी प्रकार के उपयोगितावादी पैमाने से देखना होगा।

यदि सयुक्त राज्य में उपलब्ध सीमित प्राइवेट आन्तरिक पूंजी पर ही भरोसा किया जाता और विदेशी पूंजी और सरकार के धन की सहायता न ली जाती तो सयुक्त राज्य में रेलों का यह विशाल साम्राज्य कभी स्थापित न हो पाता।

सन् 1850 के दशक से ब्रिटेन, हालैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पूंजीपतियों ने अमेरिकन रेल-कम्पनियों के शेयर खरीदने प्रारम्भ किये। विदेशी पूंजी-निवेश की इस सहायता ने रेल-निर्माण में समय-समय पर आने वाली तेजी को कायम रखा। इससे अमेरिका की देशी पूंजी पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हुआ और उसे अमेरिका के अन्य उद्योगों में लगाने का रास्ता साफ हो गया।

स्थानीय राज्यीय, और सघीय सरकारों ने रेल-कम्पनियों में पूँजी का निवेश करने के साथ-साथ अन्य कई रूपों में भी उनकी सहायता की। सरकारी ज़मीनों का अनुदान, रेल-कम्पनियों के बाड़ों की खरीद, बन्धक ऋण और रेलों के लिए उपहार के रूप में दी गई धनराशियाँ, इन सबने मिलकर रेल-कम्पनियों की पूँजी की 'भूख' को कुछ शान्त किया। यह अनुमान लगाया गया है कि 1870 से पूर्व रेलों के निर्माण के कुल खर्च का, जिसमें ज़मीनों के अनुदान शामिल नहीं हैं, 40 प्रतिशत भाग सरकारी स्रोतों से ही पूरा होता था।

सघीय सरकार की दिलचस्पी खासतौर से महाद्वीप के एक तट से दूसरे तट तक देश के आरपार रेलों की स्थापना में थी। सन् 1850 से 1871 तक रेलों के बारे में जो सघीय कानून पास हुए उनमें महाद्वीप के आरपार रेलें विछाने वाली कम्पनियों को मार्ग का अधिकार और लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और काफी भूमि खंडों के उपयोग की खुली छूट दी गई। सब मिलाकर इन रेल-कम्पनियों को वित्तीय सहायता तो काफी दी ही गई, साथ ही सघीय सरकार ने उन्हें 15 करोड़ एकड़ से अधिक भूमि भी दी। यह भूमि न्यूयार्क, पेनसिलवेनिया और न्यू इंग्लैंड के कुल क्षेत्रफल के बराबर थी।

संयुक्त राज्य में रेलों के इस समूचे विकास ने पश्चिम की कृषि के विकास को काफी प्रभावित किया। वास्तव में रेलें पश्चिम के विकास के लिए बहुत अधिक हद तक जिम्मेदार थीं। कृषि-उत्पादनों को फार्मों से मंडियों तक पहुँचाने के लिए परिवहन के साधन न रहने पर किसानों के लिए पश्चिम के नए-नए क्षेत्रों में प्रवेश करना और उन्हें आबाद करना वदापि सम्भव न होता, इसलिए नए सीमावर्ती क्षेत्रों के कितने ही लोगों ने रेल कम्पनियों के शेयर खरीदे ताकि वहाँ रेलों के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन दे सकें। कुछ किसानों ने इस काम के लिए अपनी ज़मीनें तक बन्धक रख दीं।

किन्तु इसके बाद ऐसा वक्त आया कि किसान रेल-कम्पनियों के हाथों में मौजूद शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। कारण यह था कि रेल-कम्पनियों को मुफ्त ज़मीन के रूप में सघीय और राज्यीय सरकारें जो सहायता दे रही थी, उससे वे बास-भूमि कानून के अनुसार नई भूमि पर

आवाद हो रहे किमानो की जमीनों पर दखल करने लगी थी। किसानों और रेल-कम्पनियों के भागड़े का दूसरा कारण यह था कि गृह युद्ध के बाद से गेहूँ और आटे की कीमतें तो बराबर बहुत नीची चली आ रही थी, लेकिन रेल भाड़े की दरें बहुत ऊँची थी। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति किमानो के हाथ में निकलकर धीरे-धीरे देश के व्यवसायी वर्ग के हाथ में जा रही थी। जे० गोल्ड और जिम फिस्क जैसे रेल-कम्पनियों के नञ्चालकों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए जो अनियमित कार्रवाइयाँ और गडबडें की, उनकी खबरे फेलने पर किमानो का बिगड उठना और उद्योग जगत् के नए दैत्यों की शक्ति को नामित और नियन्त्रित करने के लिए आन्दोलन करना स्वाभाविक ही था।

यह 'किमानो का विद्रोह' अमेरिका के विकास के इतिहास में उस गी अभिवृद्धि की पहली शताब्दी के अन्तिम वर्षों का एक अन्य अध्याय है।

नये भूमि-क्षेत्रों में प्रवेश का अन्त

पश्चिमी सीमा-क्षेत्रों को 1860 से 1900 तक धीरे-धीरे जिस ढंग से संयुक्त राज्य में मिलाया गया, वह एक कठोर यथार्थता की एक रोमाचकारी तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 'ग्रेट प्लेन्स' (विशाल मैदान) हमारे मानस पर मूल निवासी इंडियनो और नए अधिवासियों के संघर्ष, कोलोराडो और नेवडा के खनिज नगरों की अपरिपक्व वैयक्तिकता, टेक्सास के चरवाहों की कन्सास के रेल-डिपो तक की लम्बी यात्राओं, और अर्ब-मरुस्थलीय मैदानों में प्रकृति के साथ अग्रणी किसानों के संघर्ष का रोमाचकारी चित्र खींच देते हैं।

इस युग की जो तस्वीर हमारे सामने है, वह चाहे यथार्थवादी हो, चाहे काल्पनिक, पश्चिम की ओर प्रगति को अभिरूपित करने वाले सक्रिय और गतिशील पूंजीवाद पर ही आवृत है।

अटलांटिक तट से मिसिसिपी घाटी तक सभ्यता के प्रसार, नई आबादियों की स्थापना और स्थिर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूरी दो गतावधियाँ लगी। ग्रेट प्लेन्स में, जो क्षेत्र की दृष्टि से अधिक विशाल, किन्तु कम आकर्षक थे, नई आबादियाँ बसने और उनके स्थायी होने में चालीस वर्ष से भी कम समय लगा। गृह-युद्ध के बाद के जमाने में उद्योगों और रेलों का जो भारी विकास हुआ, उसके बिना इस प्रदेश का इतनी तेजी से आबाद और विकसित होना कभी सम्भव न होता।

पश्चिम में रेल-मार्गों ने सिर्फ बाजारों और मंडियों को ही एक-दूसरे के नजदीक नहीं पहुँचाया, बल्कि उन्होंने नई बस्तियाँ आबाद करने और नये उद्योग-व्यवसाय स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया, ताकि रेल कम्पनियों ने रेलों के विस्तार में जो धन-निवेश किया है, वह सुरक्षित रहे और निरन्तर बढ़ता रहे। औद्योगिक विस्तार ने पूर्व में शहरों के विस्तार और

ग्रीक लोगों के लिए रीति-रिवाज और व्यापार की सीमाओं और बन्धनों को तोड़कर, नये अनुभवों के द्वार खोलकर और नई-नई परम्पराओं, प्रथाओं और प्रवृत्तियों का आह्वान देकर, भूमध्यसागर ने जो महत्त्व प्राप्त किया, वही महत्त्व, बल्कि उससे भी अधिक महत्त्व सयुक्त राज्य के लिए, और अप्रत्यक्षतः समूचे यूरोप के राष्ट्रों के लिए, निरन्तर पीछे हटती और सिकुड़ती सीमाओं ने प्राप्त किया है।

—फ्रेडरिक जैक्सन टर्नर, 1893

अभिवृद्धि को बढ़ावा दिया, और उनसे ग्रेट प्लेन्स के किसानों को अनाज और पशु-पालकों को मांस की विक्री के लिए अच्छे बाजार उपलब्ध हुए।

परिवहन और उद्योग में हुई इन क्रान्तियों ने किमान की हर बात में पूर्णतः आत्म-निर्भर और अपने में ही सीमित रहने की प्रवृत्ति को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में नये-नये क्षेत्रों में कृषि के विस्तार को ही सार्वकालिक आर्थिक पुनरुद्धार और विकास का प्रतीक मानने की प्रवृत्ति का भी अन्त होने लगा। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सयुक्त राज्य की कुल आबादी में किमानों की आबादी का अनुपात क्रमशः कम होने लगा। सन् 1820 में 83 प्रतिशत आबादी बेती के काम में लगी थी, किन्तु 1860 में यह अनुपात गिरकर 60 प्रतिशत रह गया। सन् 1918 में इसमें और भी ह्रास हुआ और 30 प्रतिशत हो गया। आज कुल आबादी का सिर्फ 11 प्रतिशत ही बेती में लगा है।

उद्योगों और शहरों के द्रुत विकास से और उनके साथ ही आबादी के एक बड़े भाग के बेती के बन्धे और गाँवों में हटकर उद्योगों और शहरों में चले जाने से किमानों का अपनी उपज की विक्री के लिए बाजारों के द्वारे में दृष्टिकोण बहुत बदल गया। उद्योगों के विकास ने कृषि-जिन्नों की माँग घटी और व्यापारिक फसलों की बेती पर अधिक बल दिया जाने लगा। इसने किमान अपनी आवश्यकता-पूर्ण और आत्म-निर्भरता के लिए हर तरह की जित्ते पैदा करने के बजाय खान-पान जिन्नों के उत्पादन में विशेषज्ञता

प्राप्त करने लगे। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति और भी कम होने लगी।

इतिहासकार हैरी कारमैन और हैरल्ड सिरेंट ने लिखा है कि “आत्म-निर्भर गाँव धीरे-धीरे नष्ट होने लगे और उनके स्थान पर व्यावसायिक किसान पैदा हो गए जो अपने उपभोग के लिए दूसरों से सामान खरीदते थे और उसके बदले में दूसरों को अपनी उपज बेचते थे।” व्यावसायिक किसान की आजीविका अब मुख्यतः प्रकृति के साथ उसके सवर्ष पर ही निर्भर नहीं थी, “क्योंकि उसका मुनाफा अब केवल प्रकृति के वरदान पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि ढुलाई के भाड़ों, विज्व की माँग, और उपलब्धि की स्थिति और द्रव्य बाजार की हालत पर भी निर्भर होता था।”¹

सरकारी जमीनों की बिक्री के कानून और भूमि वितरण के वास्तविक ढाँचे ने ग्रेट प्लेन्स में व्यापारिक कृषि के द्रुत विस्तार को कायम रखा। यह एक विशेष दिलचस्पी की बात है कि ग्रामीण और शहरी सुधारों के समर्थकों ने किसानों को मुफ्त जमीनें देने के लिए वर्षों तक आन्दोलन करके 1862 में जो वासभूमि कानून (होमस्टैड ऐक्ट) पास कराया, उसका महत्त्व बहुत मामूली था। ग्रेट वैस्ट (पश्चिम का विशाल प्रदेश) की बहुत थोड़ी जमीन ही वासभूमियों के रूप में किसानों को मिली। सन् 1890 से पूर्व वास-भूमि प्राप्त करने के इच्छुक हर तीन किसानों में से दो प्रयत्न असफल हुए।

ऐसा क्यों हुआ? पहली बात यह है कि फार्म की स्थापना इतनी महँगी पड़ती थी कि वास-भूमि प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं था और कांग्रेस ने वास-भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसके अलावा किसानों ने जल्दी ही यह अनुभव कर लिया कि यद्यपि जंगली और नम इलाकों में 160 एकड़ भूमि जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त है, परन्तु ग्रेट प्लेन्स के अर्ध-मरुस्थली प्रदेश में वह काफी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कानून की कुछ धाराएँ और उनमें किये गए कुछ संशोधन ऐसे थे जिनसे जमीनों का सट्टा और मुनाफा-खोरी करने वालों और अन्य गैर-अधिवासियों को धोखाधड़ी करने का

1 ‘ए हिस्ट्री ऑफ दि अमेरिकन पीपल’ खंड I, न्यूयार्क, ऐल्फ्रेड ए कनोप, 1952।

मौका मिलता था ।

वास्तव में गृह युद्ध के बाद भूमि वितरण का ढग कुछ ऐसा था कि उससे किसानों को जरा भी फायदा नहीं था । वाम-भूमि कानून को छोड़कर और जितने भी भूमि-सम्बन्धी कानून बनाये गए, उनसे अनधिवासी भू-स्वामियों के हाथ में बहुत-सी जमीन चली गई । उदाहरण के लिए किसानों के हाथों में जितनी 'मुफ्त जमीन' थी उससे चार गुनी मुफ्त जमीन रेल-कम्पनियों के हाथ में थी ।

अन्य कानूनों के अन्तर्गत राज्यों को भी कृषि-शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत-सी जमीनें मिल गईं और इंडियनों के लिए सुरक्षित रखी गई बहुत-सी जमीन भी सटोरियों के हाथों में चली गई । और इस सारी अवधि में सघीय सरकार ने नकद मूल्य लेकर जमीनें बेचना भी जारी रखा । इस प्रकार सब मिलाकर 10*8 करोड़ एकड़ जमीन इस ढग से बेची गई ।

कन्सास, नेब्रास्का और उत्तरी एवं दक्षिणी डकोटा राज्यों में दस हजार एकड़ से छ लाख एकड़ तक के विशाल भूखंड सटोरियों और भूमि का व्यवसाय करने वाली कम्पनियों को बेचे गए । उदाहरण के तौर पर 1886 में 26 विदेशी सिडिकेटो और व्यक्तियों के पास संयुक्त राज्य में करीब 2 1 करोड़ एकड़ जमीन थी । इसी तरह इमारती लकड़ी की 11 फर्में के पास जंगलात की 1 2 करोड़ एकड़ जमीन थी ।

कृषि-उपकरणों में सुधार, व्यापारिक उर्वरकों के उपयोग और अर्ध-मरुस्थली जमीनों में खेती की विशिष्ट पद्धतियों ने जमीन की उपज और खेत-मजदूर की उत्पादकता, दोनों में ही काफी वृद्धि की । सन् 1860 से 1900 तक खेती की मशीनरी में लगाई गई पूंजी तिगुनी हो गई । सन् 1900 की अपेक्षा सन् 1830 में एक बृशल गेहूँ उपजाने में 18 गुना अधिक मानवीय श्रम लगता था । इस प्रकार 1870 से 1900 तक खेतिहर आबादी में कमी हो जाने पर खेत मजदूर की उत्पादकता बढ़ जाने से कृषि की उपज में कमी के वजाय वृद्धि ही हुई । उदाहरण के लिए 1860 में मक्का की खेती करने वाले किसानों ने 80 करोड़ बृशल उत्पादन किया, किन्तु 1915 में यही उपज बढ़कर साढ़े तीन गुनी हो गई ।

लेकिन उत्पादन में इस भारी वृद्धि से नईतर्ज के व्यावसायिक किसानों

को समृद्धि प्राप्त नहीं हुई और न उनके व्यवसाय में 'स्वर्ण युग' ही आया। इसके विपरीत यह अत्यन्त भयकर कृषि-संकट का जमाना था। नई व्यावसायिक कृषि की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के साथ ममन्वय आसानी से बिना कष्ट के नहीं हो सका। यद्यपि इन वर्षों में फार्मों की संख्या और कृषि भूमि का रकबा, दोनों में वृद्धि हुई थी तो भी 1865 और 1896 के बीच कृषि की कुल आय में बहुत मामूली वृद्धि हुई। आधुनिक 'कृषि-समस्या' अब धीरे-धीरे पैदा होने लगी थी।

गृह-युद्ध के बाद के जमाने में किसान के सामने सबसे विकट समस्या यह थी कि कृषि-उत्पादन की कीमतें गिर रही थी और उससे किसान की आय भी कम हो रही थी। और यह बात कम दिलचस्पी की नहीं कि इसके लिए अशत स्वयं किसान ही जिम्मेदार था। पश्चिम की ओर किसानों के उत्साह के साथ निरन्तर आगे बढ़ने का कारण यह नहीं था कि उन्होंने माँग और उपलब्धि के सिद्धान्त के आधार पर उसके लाभों को अच्छी तरह समझ लिया था। इसका कारण वास्तव में उनकी स्वतन्त्रता की भूख और अपना एक स्वतन्त्र और निजी फार्म प्राप्त करने की आकांक्षा थी। स्वतन्त्रता के इस प्रलोभन से ही वे पश्चिम में जाकर आबाद हो रहे थे और खेती कर रहे थे। परिणामस्वरूप कृषि-जिन्सों का, खासकर गेहूँ और कपास का, आवश्यकता से अधिक उत्पादन एक पुरानी समस्या बन गया।

गृह-युद्ध के उपरान्त कुछ समय तक अमेरिका में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित फालतू कृषि-जिन्सों के लिए यूरोप का बाजार उपलब्ध होता रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इस प्रकार की चीजों का विदेशी बाजार और भी बढ़ा, परन्तु कनाडा, अर्जेंटाइना और रूस के अनाज, अर्जेंटाइना के गोमास, भारत और मिस्र की रूई और न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया के ऊनी सामान और मक्खन-पनीर आदि ने अमेरिका के कृषि उत्पादनों की कीमतें विश्व के बाजारों में गिरा दी। अमेरिका द्वारा तटकरो में वृद्धि कर दी जाने से अमेरिकी माल के संभावित ग्राहकों का दूसरे बाजारों में खरीद के लिए जाना और भी तेज हो गया।

किसानों की आमदनी में कमी का एक कारण और भी था और वह था द्रव्य की उपलब्धि में कमी। सन् 1865 से 1890 तक अमेरिका की

आवादी दुगुनी और आर्थिक गतिविधि तिगुनी हो गई थी, फिर भी सोना और कागजी मुद्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इससे पूर्व किसान हमेशा अपनी द्रव्य-प्राप्ति की समस्या का हल करने के लिए मुद्रा-स्फीति का सहारा लेते थे, लेकिन इससे डालर की कीमत गिर जाती और उसके साथ ही उनके कर्जों के स्तर में भी कमी आ जाती। लेकिन गृह-युद्ध समाप्त होने के बाद किसानों के हाथों में इतनी राजनीतिक शक्ति नहीं रही थी कि वे कांग्रेस में 'सस्ती मुद्रा' की उपलब्धि के लिए पहले की भाँति कानून पार कर सकें।

इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर किसानों में हर प्रकार की जिन्मों के उत्पादन से आत्म निर्भर बनने की प्रवृत्ति का अन्त होकर व्यापारिक-दृष्टि से खास-खास फसलें पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा होने से उनकी कृषि-यन्त्रों की आवश्यकता बढ़ी और दूसरी ओर इन यन्त्रों की खरीद के लिए मुद्रा की उपलब्धि कम हो गई। मुद्रा की उपलब्धि में कमी होने से किसानों को अपनी ज़मीनें या फसलें बन्धक रखकर जो कर्ज लेना पड़ता था उसकी व्याज-दरें बहुत ऊँची हो गईं। एक पश्चिमी राज्य में सन् 1870 में व्याज की औसत दर 9 4 प्रतिशत थी। फिर भी किसान के पास कृषि-यन्त्र खरीदने, अपने फार्म में उपज का स्टॉक जमा करने या नया खेत खरीदने के लिए ज़मीन बन्धक रखकर ऋण लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। सन् 1890 में यह अनुमान लगाया गया था कि कन्सास, नेब्रास्का, डकोटा और मिनेसोटा राज्यों का एक भी फार्म ऐसा नहीं था जो बन्धक न रखा गया हो।

परिवहन के भाड़े की दरों में किसानों के साथ भेद-भाव किये जाने और उनसे अधिक ऊँची दरों की वसूली से किसानों की समस्या और भी विकट हो गई थी। एक बुझल गेहूँ के परिवहन का भाड़ा उतना ही था जितनी कि उसकी मूल कीमत। कभी-कभी निकागो से लिवरपूल तक गेहूँ भेजने पर जितना जहाज-भाड़ा लगता था, उसने ज्यादा भाड़ा डकोटा राज्य से मिने-पोलिस तक उसे भेजने पर लग जाता था। यही नहीं, कृषि-जिन्मों की कीमतें घटने पर भी उनके भाड़े की दरों में कोई कमी नहीं होती थी।

इनके अलावा हर इलाके में परिवहन के भाड़े की दरें अलग-अलग थीं तथा छोटे और बड़े परिवहन-व्यवसायियों की दरें भी जुदा-जुदा थीं। रेल-

कम्पनियों के माल गोदामों में अनाज रखने के लिए भाड़े की दरे भी बहुत ऊँची थी, जिससे रेलों से माल की ढुलाई और भी महँगी हो जाती थी। इससे सन्देह नहीं कि रेल-कम्पनियों ने किसानों पर ढुलाई भाड़े और गोदाम भाड़े की जो शर्तें लादी थी उनमें से कुछ आवश्यक भी थी, क्योंकि उनके बिना रेलें मुनाफा न कमा सकती। लेकिन जब किसानों को रेल-कम्पनियों के संचालकों के रिश्वतखोरी, बिना वास्तविक परिसम्पत्ति के गेयर जारी करने और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाने के अन्य हथकण्डों का पता चला तो उनका रेल-कम्पनियों के प्रति क्रुद्ध हो उठना स्वाभाविक ही था।

कृषि-जिन्सों के उत्पादन और वितरण के व्ययों में वृद्धि और उनके मूल्यों में कमी से हजारों किसान बरबादी के कगार पर पहुँच गए। एक समय ऐसा आ गया कि किसान को एक बुगल गेहूँ की कीमत 42 सेंट मिल रही थी, जबकि उसका उत्पादन व्यय 52 सेंट था। ऐसे वक्त भी आये, जबकि कन्सास और डकोटा राज्यों के मक्का और गेहूँ उत्पादक किसानों को अपना अनाज बेचकर ईंधन खरीदने के बजाय खुद अनाज का ही ईंधन के रूप में जलाना अधिक सस्ता प्रतीत होता था।

कई किसानों की जमीनें अपने कर्जों पर व्याज न चुका सकने के कारण बैंकों या अन्य ऋणदाता साहूकारों के हाथों में चली गईं। इस प्रकार पट्टे पर खेत लेकर काश्त करने वाले किसानों की तादाद बढ़ गई। सन् 1880 में खुदकाश्त के बजाय पट्टेदारी वाले फार्मों की संख्या कुल फार्मों का चौथाई भाग थी। बीस वर्ष बाद यह संख्या 35 प्रतिशत हो गई।

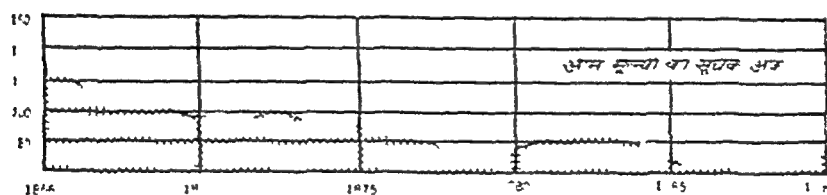
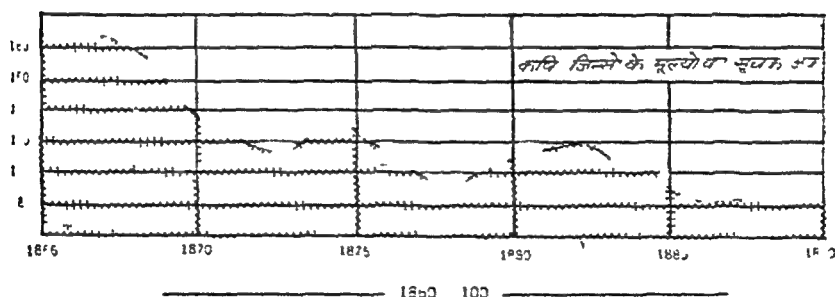
सन् 1870 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में समस्त पश्चिमी राज्यों में किसान इतने सकटग्रस्त हो चुके थे कि वे अपने रोप और क्षोभ को प्रकट करने के लिए किसी प्रभावकारी उपाय की खोज करने लगे। इसके लिए सबसे प्रमुख साधन 'पैट्रन्स ऑफ हम्बेडरी' (कृषि के संरक्षक) नामक संगठन था, जिसका अधिक प्रचलित नाम 'ग्रेज' था। किसान जैसे-जैसे यह अनुभव करने लगे कि एक ओर विश्व के बाजार में उनकी उपज की कीमतें गिर रही हैं और दूसरी ओर संयुक्त राज्य में उद्योग-सम्पन्न पूर्वी राज्यों की राजनीतिक शक्ति बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे उनका क्षोभ और भी बढ़ने लगा। फलतः 'ग्रेज' ने स्वतन्त्र (खुदकाश्त करने वाले) किसानों की क्लबों

के साथ मिलकर राष्ट्र की रेल-कम्पनियों और अन्य 'विचौलियों' से किसानों के लिए अधिक न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न किया।

किसानों ने सरकार द्वारा रेल-कम्पनियों और अन्य व्यवसायों को अनु-पूर्तियों (सब्सिडीज) के द्वारा सहायता दिये जाने के तरीके पर भी कड़ा विरोध प्रकट किया। उनका उद्देश्य किसानों को नये औद्योगिक परिवेश में आय के अधिक न्यायपूर्ण वितरण का साधन बनाना था।

किसानों ने इस सम्बन्ध में सुधार-कानून पास कराने के लिए जो आन्दोलन चलाया था, वह बहुत आसान नहीं था और न वह जल्दी प्रभावकारी बनने वाला ही था। फिर भी वह आन्दोलन शुरू अवश्य हो गया था।

किसानों की दुर्दशा, 1866-1890



गृह-युद्ध की महँगाई के बाद कीमतों में गिरावट का जमाना आया। लेकिन किसानों को अपने उत्पादनों के बढ़ते में मिलने वाली कीमतें 50 प्रतिशत गिरी, जबकि वे जो चीजें खरीदते थे, उनकी कीमतों में कुल 37 प्रतिशत गिरावट आई। इससे किसानों की आय में काफी कमी हो गई।

दो मुझे तुम अपने श्रान्त और दरिद्रजन,
 दो स्वतन्त्रता की साँस लेने के इच्छुक जनगण,
 भेजो अपने लहराते सागर तट के इस तलछट को,
 इस बेघर, तूफान-प्रताडित मानव दल को,
 मैं लिए खड़ा हूँ दीप इनके लिए स्वर्ण-द्वार पर।
 —स्वतन्त्रता की प्रतिमा पर अंकित एमा लजारस की कविता

बड़े पैमाने पर उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था की चुनौती

उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी दशकों में औद्योगिक पूंजीवाद ने जहाँ सयुक्त राज्य के कृषि के ढाँचे में परिवर्तन किया वहाँ उसने राष्ट्र की श्रम-शक्ति को भी बहुत रूपान्तरित कर दिया। नये ढंग की कम्पनियों की स्थापना, नई उद्योग-विद्या (टेक्नोलॉजी) और 'फैक्टरी प्रणाली' के द्रुत विकास से ऐंड्र्यू जैक्सन और अब्राहम लिंकन के जमाने के ग्राम-प्रधान अमेरिका के अस्तित्व का अन्त हो जाना स्वाभाविक था। सन् 1890 में यह स्थिति थी कि राष्ट्र की कुल श्रम-शक्ति का मुश्किल से चालीस फीसदी भाग ही कृषि के व्यवसाय में लगा हुआ था। और 1920 तक तो खेती में राष्ट्र की कुल 25 प्रतिशत ही श्रम-शक्ति रह गई।

नए औद्योगिकवाद ने शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सन् 1840 में राष्ट्र की आबादी का कुल बारहवाँ हिस्सा 8,000 से अधिक आबादी के कस्बों में रहता था। सन् 1860 में यह अनुपात छठा हिस्सा हो गया। परन्तु सन् 1900 में हर तीन अमेरिकनो में से एक शहर का निवासी था। गिकागो की आबादी तो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। सन् 1850 में उसकी आबादी 30,000 थी किन्तु 1880 में वह 5,00,000 हो

गई और सन् 1900 तक शिकागो की आबादी बीस लाख के आन-पास थी।

बड़े शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे थे। सन् 1894 में न्यूयार्क के 32 एकड़ के एक इलाके में आबादी की घटना 9064 व्यक्ति प्रति एकड़ थी। उन्नीसवीं सदी के सबसे अधिक सघन आबाद शहर प्राग में सबसे घनी आबादी वाले खण्ड की जनसंख्या कुल 4854 व्यक्ति प्रति एकड़ थी।

शहरों की आबादी में इतनी तेजी से वृद्धि होने का एक बड़ा कारण यह था कि 1865 के बाद यूरोप से आवासीय लोग अमेरिका में बसने के लिए घटाघड़ आ रहे थे। गृह-युद्ध के बाद के पन्द्रह वर्षों में 45 लाख आदमी संयुक्त राज्य में बाहर ने आए। अगले चालीस वर्ष में 235 करोड़ व्यक्ति और आए। इन वर्षों में संयुक्त राज्य की आबादी में आधी वृद्धि इन आगुन्तक आवासियों के कारण ही हुई।

सन् 1880 में पूर्व 90 प्रतिशत आवासीय जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और स्कैंडेनेवियन देशों के थे। इन लोगों को अक्सर 'पुराने आवासीय' कहा जाता है। अगली पीढ़ी में आवासियों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया और पोलैंडिया, हंगरी, रूस, पोलैंड, इटली और बाल्कन देशों में बहुत अधिक संख्या में लोग संयुक्त राज्य में आने लगे। ये लोग अक्सर 'नए आवासीय' कहलाते हैं। सन् 1900 तक न्यूयार्क में इटालियनों की संख्या नेपल्स शहर की कुल आबादी के बराबर हो गई। शिकागो की आबादी का 80 प्रतिशत भाग या तो आवासीय लोग थे या उनके बच्चे।

थियो के रूप में भी अमेरिका आ रहे थे ।

फिर भी यूरोप से अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका आने के लिए लोगो की मुख्य प्रेरणा आर्थिक थी । अमेरिका में लोग रोजगार पाने की, अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की और स्वयं अपने लिए नहीं तो कम-से-कम अपने बच्चों के लिए नए अवसरों की आशा करते थे । दुर्भाग्य से ये आशाएँ हमेशा पूरी नहीं होती थी । नए आवासियों को अमेरिका में आकर इतनी कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था कि उसमें मुश्किल से उनका निर्वाह ही हो पाता था और अनेक बार जिन परिस्थितियों में वे काम करते थे, वे उनके पुराने देश से, जहाँ से वे नई दुनिया में आते थे, किसी भी कदर बेहतर नहीं होती थी । अपने नए देश की भाषा का अज्ञान और अमेरिका के रहन-सहन के तौर-तरीके की अनभिज्ञता उनकी परेशानी को और भी बढ़ा देती थी ।

उद्योगों की दृष्टि से देखा जाय तो नए आवासियों का अमेरिका में आगमन और 'फैक्टरी-प्रणाली', दोनों का बहुत अच्छा मेल था । अर्द्ध-खेतिहर नवागन्तुक एक ऐसे देश में आ रहे थे, जहाँ कारखानों का निरन्तर विस्तार हो रहा था और जहाँ अर्द्ध और आसानी से प्रशिक्षित होने वाले अर्द्ध-दक्ष श्रमिकों की बहुत आवश्यकता थी । एक अनुमान के अनुसार, 1910 में 'नए' आगन्तुक आवासियों की जिनमें दक्षिण से आने वाले नीग्रो भी शामिल थे, संख्या अमेरिकन उद्योगों की 21 प्रमुख शाखाओं में लगे कुल कर्मचारियों की संख्या का दो-तिहाई भाग थी ।

कारखानों की नई प्रणाली ऐसी थी कि उसमें स्त्रियाँ और बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में काम पर लगाए जाते थे । सन् 1880 की जनगणना के अनुसार दस से पन्द्रह वर्ष तक की आयु के दस लाख से कुछ अधिक बच्चे रोजगार पर लगे हुए थे । सन् 1910 में राष्ट्र की कुल श्रम शक्ति का 52 प्रतिशत भाग, यानी बीस लाख के लगभग, बच्चे थे ।

श्रमिक स्त्रियों की संख्या भी बढ़ गई थी । सन् 1830 में 25 लाख स्त्रियाँ काम पर लगी हुई थी । बीस वर्ष के भीतर श्रमिक स्त्रियों की संख्या बढ़कर दुगुनी यानी कुल श्रम-शक्ति का 14 प्रतिशत भाग हो गई ।

औद्योगिकीकरण के द्रुत विकास के इस युग में मजदूरी, कमाई और

श्रमिकों की काम की परिस्थितियाँ क्या थी, इस बारे में पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी सन् 1895 में इन मामलों पर सीनेट की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार गैर-खेतिहर मजदूरों की प्रति घण्टा आय 1860 और 1890 के बीच 85 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि रहन-सहन का व्यय केवल 18 प्रतिशत बढ़ा था।

लेकिन अदक्ष मजदूरों की आमदनी दक्ष मजदूरों की आमदनी की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ी क्योंकि दक्ष मजदूर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। सन् 1890 में आय के वितरण के बारे में जो मोटा अनुमान लगाया गया था, उसके अनुसार दो लाख परिवारों की वार्षिक आमदनी 5,000 डालर से अधिक थी, 13 लाख परिवारों की 1,200 डालर से 1,500 डालर तक और 1 करोड़ 10 लाख परिवारों की 1,200 डालर से कम थी। इस अन्तिम वर्ग की औसत वार्षिक आमदनी 380 डालर थी।

इन आँकड़ों में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की काम की परिस्थितियों को हिसाब में नहीं लिया गया है। सन् 1860 में आम तौर पर लोगों से प्रतिदिन दस से चौदह घण्टे तक काम लिया जाता था। यद्यपि 1890 तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि कुछ उद्योगों में दक्ष श्रमिकों से अन्य श्रमिकों की अपेक्षा कम घण्टे काम लिया जाता था, तो भी इस्पात, कागज और तेल-शोधन के कारखानों और अन्य 'भारी' उद्योगों में सामान्य मजदूर सप्ताह में छ या सात दिन काम करते थे और प्रतिदिन उनसे 12 घण्टे काम लिया जाता था।

निर्माण-उद्योगों में वर्ष की कुछ खास अवधियों में श्रमिक बेरोजगार रहते थे और इस मौसमी बेरोजगारी से उनकी कठिनाई और बढ़ जाती थी। सेंसाचुसेट्स में 1895 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार उस वर्ष उस राज्य के 30 प्रतिशत मजदूर पाँच महीने के लगभग बेकार रहे। व्यापार में आने वाले मन्दी के चक्रों से श्रमिकों का सकट बढ़ता रहता था। उदाहरण के लिए 1873 और 1878 के बीच और 1893 और 1897 के बीच ज़बरदस्त मन्दियाँ आईं और समय-समय पर इसी तरह के मन्दी के कुछ और झल्ले भी आए।

यही नहीं, कभी-कभी काम की परिस्थितियाँ बहुत खराब और

खतरनाक भी होती थी। कारखानों के निरीक्षण के लिए सरकारी इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था बहुत धीरे-धीरे और बेतरतीब ढंग से हुई। कोयला खानों में रोशनी और हवा की व्यवस्था बहुत अपर्याप्त होती थी। कई कारखाने 'स्वैट शॉप' (पसीना चुआने वाले कारखाने) कहलाते थे क्योंकि वहाँ बहुत कम मजदूरी पर घटो श्रमिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। बड़े शहरों के बाहर श्रमिक अक्सर कम्पनियों के बनाए क्वार्टरों में रहते थे और कम्पनियाँ उन्हें वेतन के रूप में अपने निज के कूपन देती थी, जो कम्पनियों की अपनी दुकानों में ही चलते थे।

कारखाना-मजदूरों को जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी, उनमें से बहुत-सी कठिनाइयाँ ऐसी थी, जिन्हें महज दुष्टतापूर्व शोषण ही नहीं कहा जा सकता। दरअसल प्रगति सभी के लिए सकट का आह्वान कर रही थी और स्वयं उद्योग-व्यवसायों के मालिक भी अकसर दिवालिये हो जाते थे। ये वर्ष बहुत ज़बर्दस्त औद्योगिक परिवर्तन के वर्ष थे, इनमें कष्ट उठाकर भी पूँजी को संग्रह करना आवश्यक था। कीमतों की प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। अकुशल और कम योग्य उद्योगपतियों पर व्यापारिक मन्दी के चक्र भयकर मुसीबत बरपा कर देते थे। लोगों के पास पैसा अपर्याप्त होने से बहुत लम्बे अर्से तक कीमतों में मन्दी का दौर चलता था। ये सब कारण थे, जिनको दृष्टि में रखकर ही कारखानों के मालिक मजदूरों के बारे में अपना रुख निर्धारित करते थे। व्यापारियों को एक के बाद एक सकटों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वे अपने माल के उत्पादन-व्यय पर बहुत नज़र रखते थे और मजदूरी उस समय अधिकतर मालिकों के लिए उत्पादन-व्यय का एक बड़ा अंग थी।

फिर भी परिस्थितियों में सुधार की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पूँजीगत सामग्री के उद्योगों में ग्राई तेज़ी ने मानवीय आवश्यकताओं को बढ़ा दिया था। लेकिन सामान्य आर्थिक समृद्धि के बावजूद जब श्रमिकों की स्थिति में गिरावट आती चली गई तो उनमें अशान्ति और निराशा बहुत बढ़ गई और उसके परिणामस्वरूप बार-बार हड़तालें और श्रमिक-विद्रोह होने लगे।

श्रमिकों की परिस्थितियाँ उन उद्योगों में अधिक खराब थी जिनमें मशीनरी का अधिक उपयोग किया जाता था, जैसे कि लोहा और इस्पात के

कारखाने, मशीने बनाने के कारखाने, डलाई और जूते के कारखाने और छापाखाने। देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ जो श्रमिक आन्दोलन चले, उनका नेतृत्व इन्हीं कारखानों के लोग करते थे।

सन् 1873 से पहले के दस वर्षों में इन उद्योगों में 24 राष्ट्रीय मजदूर यूनियन बनी। इनमें रेल इजनों के ड्राइवरो, लोहा ढालने वालों, मशीने बनाने वालों, लुहारों, खान मजदूरों और जूता बनाने वालों की यूनियन शामिल थी। इजनों ड्राइवरो की यह यूनियन रेल कर्मचारियों की सबसे पहली यूनियन थी। इन यूनियनों की सदस्य संख्या 1873 में लगभग तीन लाख थी।

किन्तु अलग-अलग उद्योगों में राष्ट्रीय यूनियन संगठित करना पर्याप्त नहीं था। अगला कदम उन्हें मिलाकर एक संगठन में बाँधना था। सन् 1866 में नेशनल लेबर यूनियन (राष्ट्रीय मजदूर संघ) बनाकर यह कदम उठाया गया। इस संगठन ने अपने सबसे पहले सम्मेलन में ऐसा कानून पास करने की माँग की, जिसके अनुसार काम के दैनिक घण्टे आठ कर दिये जाएँ। इसका दूसरा उद्देश्य था सहकारी समितियों के निर्माण, मुद्रा सुधार, बाहर से आने वाले आवासियों पर रोक और एक संघीय श्रम विभाग की स्थापना के लिए आन्दोलन करना।

नेशनल लेबर यूनियन का भुकाव और दृष्टिकोण अधिकाधिक राजनीतिक होता जा रहा था, इसलिए उसका ध्यान श्रमिकों के तात्कालिक हितों से दूर हटता गया और यही कारण है कि कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी। फिर भी संयुक्त राज्य के श्रमिक आन्दोलन के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी ने सबसे पहले एक राष्ट्र-व्यापी मोर्चे पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, इसी ने श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को श्रमिकों की सर्वसामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मंच पर एकत्र किया और इसीने श्रमिकों की निकायता के बारे में एक राष्ट्रव्यापी चेतना पैदा की।

सन् 1880 के दशक के मध्य में श्रमिकों का एक अन्य संगठन नेशनल लेबर यूनियन में भी अधिक महत्व प्राप्त करने लगा था। सन् 1869 में एक गुप्त संगठन के रूप में गठित 'नाइट्स आफ लेबर' (श्रमिकों के संरक्षक)

नामक इस सगठन का विकास प्रारम्भ में बहुत धीरे-धीरे हुआ, क्योंकि इस पर गोपनीयता और रहस्य का जो आवरण पड़ा हुआ था, उससे उसके बारे में कुछ गलतफहमियाँ रहती थी। सन् 1878 में इस सगठन ने रहस्य का पर्दा उतार दिया और उसकी सदस्य सख्या तेजी से बढ़ने लगी और 1885 में वह एक लाख तक पहुँच गई। उस वर्ष इस सगठन ने वैवास और मिन्सूरी पैनिफिक रेल-कम्पनियों में श्रमिकों की हड़ताल की इतने ज़बर्दस्त पैमाने पर तैयारी की कि जे गोल्ड जैसे चतुर और धूर्त पूँजीपति को भी हड़ताल रुकवाने के लिए उससे बातचीत करने को झुकना पड़ा। 'नाइट्स ऑफ लेबर' की इन मनमनीखेज विजय ने अगले वर्ष ही उसकी सदस्य संख्या एक लाख से बढ़ाकर 7,30,000 कर दी और इस प्रकार वह सबसे बड़ी और प्रभाव-शाली मजदूर यूनियन बन गई।

किन्तु 1886 के बाद नाइट्स ऑफ लेबर की शक्ति भी क्षीण होने लगी। कई बड़ी हड़ताले, जिनके लिए यह सगठन पूरी तरह से तैयार नहीं था, असफल हो जाने से श्रमिकों में उसकी इज्जत कम हो गई। यद्यपि नाइट्स ऑफ लेबर के नेताओं ने इन हड़तालों के साथ किसी भी तरह की हिंसात्मक या तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों का आयोजन नहीं किया था, फिर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ मजदूरों ने की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम जनता इस सगठन को कानून की अवहेलना करने वाला सगठन समझने लगी। शिकागो में श्रमिकों की एक सभा में एक अराजकतावादी ने एक बम फेंक दिया, जिससे 11 व्यक्ति मारे गए और बीमियों घायल हो गए। हालाँकि इस अराजकतावादी का नाइट्स से कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी बहुत-से लोगो ने नाइट्स को ही इस प्रकार की आतंकवादी अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया।

नाइट्स के सहकारी समितियाँ स्थापित करने के परीक्षण और उसकी कुछ अन्य सुधारात्मक प्रवृत्तियों के असफल हो जाने से भी उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति को बहुत धक्का लगा। किन्तु उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण उसके सदस्यों में सगठन का अभाव था। भ्रातृत्व के अस्पष्ट विचार और आदर्श विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों को समान और संयुक्त कार्रवाई की एकता के बन्धन में बाँधने के लिए काफी नहीं थे। दक्ष और अदक्ष श्रमिकों

मे अक्सर शत्रुता चलती रहती थी। दक्ष मजदूर जानते थे कि हड़ताल मे विजय पाने के लिए अदक्ष मजदूरों की अपेक्षा वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर हड़ताल सफल हो जाती तो वे दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के मजदूरों को उसका समान लाभ मिलने पर बिगड़ते और यदि हड़ताल असफल हो जाती तो भी नाराज़ होते।

नाइट्स ऑफ़ लेबर के धीरे-धीरे अस्त हो जाने पर बची हुई ट्रेड यूनियनों ने, जिनमें अधिकतर विभिन्न व्यवसायों के दक्ष मजदूर शामिल थे, एक अधिक स्थायी राष्ट्रीय श्रमिक संगठन बनाने के लिए कदम उठाया। सेम्युअल गोम्पर्स के नेतृत्व में इन संगठनों ने मिलकर अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ लेबर (अमेरिकन श्रमिक संघ) का निर्माण किया। गोम्पर्स ने स्वप्नलोक की बड़ी-बड़ी कल्पनाओं से भरे आदर्शों, अस्पष्ट सुधारों और राजनीति में फँसने की प्रवृत्ति से बचने की चेष्टा की, क्योंकि यही चीज़ें नेशनल लेबर यूनियन और नाइट्स ऑफ़ लेबर को ले डूबी थी। उसका विश्वास था कि यूनियन को मजदूरी बढ़वाने, काम के घटे कम कराने और अपने सदस्यों की काम की परिस्थितियों में सुधार कराने के व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। और सामूहिक सौदेबाज़ी, जिसके पीछे हड़ताल का बल हो, इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होनी चाहिए।

विभिन्न श्रमिक आन्दोलनों की प्रगति के बावजूद बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक राष्ट्र के 170 करोड़ मजदूरी अर्जन करने वाले लोगों में से पाँच लाख से अधिक व्यक्ति ट्रेड यूनियनों के सदस्य नहीं थे। इनमें से भी अधिकतर दक्ष मजदूर थे, जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ लेबर के अन्तर्गत संगठित थे। अदक्ष मजदूर सौदेबाज़ी की वात्ताओं में तब तक प्रभावकारी नहीं बन सके, जब तक कि बीसवीं शताब्दी में निर्मित श्रमिक सुधार कानून पास नहीं हो गया।

महान् व्यवसायी

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत पश्चिमी यूरोपियन देशों की तुलना में संयुक्त राज्य को एक अल्पविकसित



एण्ड्रयू कार्नेगी

देश कहा जा सकता था। राष्ट्र उम्र समय भी आधार-भूत उद्योगों के विकास और श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण में लगा हुआ था ताकि अपनी प्राकृतिक सम्पदा के दोहन के लिए एक बुनियाद तैयार कर सके।

यद्यपि ये उद्देश्य आश्चर्यजनक गति से पूरे कर लिये गए तो भी एक सर्वथा अनगढ़ और अछूते महाद्वीप को तेजी से उद्योग-सम्पन्न बनाने के

लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। संयुक्त राज्य ने, तरह-तरह की नई तकनीकों के परीक्षण किये, जो कभी असफल हो जाते और कभी सफल हो जाने पर बड़े अवांछनीय परिणामों को जन्म देते। इस प्रक्रिया में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के विचार को जो 'अमेरिका के स्वप्नों' का मध्यबिन्दु था, बहुत आघात लगा। साथ ही अठारहवीं शताब्दी की यह धारणा भी अस्त-व्यस्त हो गई कि यदि लोग अपने निजके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें तो उससे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था स्वतः विनियमित हो जाएगी और सही राह पर चल पड़ेगी।

ये धारणाएँ नये समाज के भीतर नई किस्म की ताकतो के उद्भव के कारण नष्ट हुई। उद्योगों के विकास के साथ-साथ औद्योगिक और वित्तीय सगठनों में शक्ति अधिकाधिक केन्द्रीभूत होने लगी। सफल उद्योगपति और कम्पनियों के अधिकारी परम्परा से चले आ रहे भूमिपति और व्यवसायी वर्गों का स्थान लेने लगे और इस प्रकार एक नया सामाजिक और आर्थिक उच्चवर्ग धीरे-धीरे उभरने और समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने लगा। गृह-युद्ध के बाद दोनों राजनीतिक दल इस नये सत्ताधारी और शक्तिशाली वर्ग के प्रभाव को अनुभव करने लगे।

औद्योगिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक और वित्तीय शक्तियों का परस्पर मिलन होने लगा और वे कुछ थोड़े-से हाथों में केन्द्रित होने लगी। सन् 1860 में कुछ रेल-कम्पनियों को छोड़कर बाकी अधिकतर उद्योग-व्यवसाय सार्वजनिक न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में थे अथवा कुछ व्यक्तियों की साझेदारी में चल रहे थे। किन्तु 1904 में स्थिति कुछ बदली हुई दिखाई दी। एक गणना के अनुसार उस समय 5,300 औद्योगिक संस्थान, जिनमें 7 अरब डालर से अधिक पूँजी लगी हुई थी, 318 औद्योगिक कम्पनियों के हाथों में थे। ये कम्पनियाँ राष्ट्र की निर्माण-उद्योगों की 40 प्रतिशत क्षमता का नियन्त्रण करती थी। संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी 92 कम्पनियों में से 78 के हाथों में 50 प्रतिशत अमेरिकन उद्योग थे।

गृह-युद्ध के बाद हर दशक में बड़े पैमाने के उद्योग अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त करने लगे। सन् 1870 के दशक में निर्माण-उद्योगों की फर्मों की संख्या तो लगभग स्थिर और अपरिवर्तित रही, किन्तु उनमें लगी पूँजी 65 प्रतिशत और उनके उत्पादन का मूल्य 58 प्रतिशत बढ़ गया। सन् 1850 से 1909 तक निर्माण कारखानों के कर्मचारियों की औसत संख्या तिगुनी हो गई और निर्माण कम्पनियों में लगी औसत पूँजी 17 गुनी बढ़ गई।

अलग-अलग उद्योगों के विकास का ढाँचा भी सामान्य विकास के ढाँचे के अनुरूप ही था। सन् 1869 के बाद के दो दशकों में लोहा और इस्पात के कारखानों की संख्या 808 से गिरकर 719 हो गई, किन्तु लोहा-इस्पात फर्मों में लगी औसत पूँजी 1,49,000 डालर से बढ़कर 5,75,850 डालर हो गई। इसी अवधि में कृषि उपकरण बनाने वाली फर्मों की संख्या लगभग

एक-तिहाई कम हो गई, लेकिन इन फर्मों में लगी औसत पूँजी 14 गुनी बढ़ गई।

टैकनोलॉजी के क्षेत्र में हुए नये आविष्कारों ने छोटे कारखानों के वजाय बड़े कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया, जो आर्थिक दृष्टि में अधिक लाभकारी ढंग से चलाये जा सकते थे। यद्यपि कारखानों का यान्त्रिकीकरण और उनमें नई तकनीकों का प्रयोग, दोनों के लिए पूँजी की बहुत आवश्यकता थी, किन्तु उसे जुटाने में बहुत कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि कम्पनी गठित कर उसके शेयर जारी करने में पूँजी आसानी से मिल जाती थी। एक बार लग जाने के बाद नये ढंग की मशीन, उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाकर और उत्पादन व्यय को घटाकर औद्योगिक दौलत पैदा करने का स्रोत बन जाती थी। कम्पनी और कारखाने का विस्तार करने से उत्पादन व्यय घट जाता है, इसलिए दूरदर्शी उद्योगपति अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो अपने प्रतिस्पर्धी कारखानों को खरीद लेते थे, या उनके साथ मिलकर अपने कारखानों का विस्तार कर लेते थे।

इन वर्षों में व्यापार में कई बार खूब तेजी आई और बाजारों का खूब विस्तार हुआ। हर आर्थिक उन्नति और तेजी के समय सामान की माँग बढ़ती, जिससे व्यापारी ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए आपस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा में जुट जाते। इसका परिणाम अनेक बार यह हुआ कि उद्योगों ने अनियन्त्रित होकर इतना उत्पादन बढ़ाया कि वह जनता की आवश्यकता से अधिक हो गया और उसने बाजार कुछ समय के लिए असन्तुलित हो गया। इस प्रकार आधुनिक व्यापार में आने वाले तेजी और मन्दी के क्रमिक चक्र दिखाई देने लगे। हर मूर्तवा नमृद्धि के बाद मन्दी का जबरदस्त भोका आता। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मन्दी के ऐसे चार सकटकाल आए—1857 से 1862 तक, 1873 से 1879 तक, 1883 से 1885 तक और अन्त में 1893 से 1897 तक।

मन्दी के इन सकटों के समय कारखानों के यान्त्रिकीकरण में होने वाले नये भारी और दूधे हुए खर्चों ने औद्योगिक संस्थानों में कटु और तीव्र प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ाया। अन्य कई दृष्टिकोण भी कीमते घटाने की इस तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले थे, जिसका परिणाम स्वयं उमके

अपने उद्देश्य को नष्ट कर देता था। रेलों का राष्ट्रव्यापी जाल बिछ जाने से हर जगह स्थानीय व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। सन् 1860 के दशक के मध्य से 1890 के दशक के मध्य तक कीमतों में जो विष्वव्यापी मन्दियाँ आईं उन्होंने मुद्रा की अवस्फीति (डिफ्लेशन) को प्रोत्साहन दिया। इससे इन वर्षों में राष्ट्र की द्रव्योपलब्धि की अपर्याप्तता ने व्यावसायिक उदार-चढ़ाव के इन चक्रों की कठोर वास्तविकता को और भी अतिरजत कर दिया।

प्रतिस्पर्धा की इस निर्भय दौड़ में ऐसे सभी उद्योगपति और व्यवसायी, जो कार्यकुशल नहीं थे और जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य भी पर्याप्त नहीं था, पीछे रह गए और छिटककर दूर जा पड़े, जो बच गए वे अपने उद्योग-व्यवसाय को नियन्त्रित करने और उनमें स्थिरता और स्थायित्व लाने के उपाय करने लगे। आत्म-रक्षण की भावना से प्रेरित होकर इन लोगों ने बाजारों को अपने हाथ में करने की कोशिश प्रारम्भ कर दी। इसके लिए उन्होंने अनेक तरीकों से 'मेल' कर अपने सघ बनाये। कम्पनियों के सघ बनाने की इस पद्धति को जॉन डी० रॉकफेलर के 'आधुनिक आर्थिक प्रशासन की सारी प्रणाली का मूलस्रोत' कहा है।

प्रारम्भ में कम्पनियों ने परस्पर मिलकर जो 'मेल' किये, वे सिर्फ आपस में किये गए अलिखित समझौते थे। रेल कम्पनियों ने इस कार्य में विशेष रूप से हिस्सा लिया। अनेक रेल-कम्पनियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर पारस्परिक सहयोग से 'रेल-भाड़े' तय किये और हर कम्पनी ने यह वचन दिया कि वह अपना भाड़ा इस निर्धारित भाड़े से कम नहीं करेगी। कुछ रेल-कम्पनियों ने अपनी कुछ वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आमदनियों को भी मिलाकर एक 'पूल' बना लिया (उनका एकत्रीकरण किया)। इस प्रकार उन्हें इस 'पूल प्रणाली' द्वारा निर्धारित भाड़े की दरों को कायम रखने के लिए प्रोत्साहन मिला।

उद्योगों के स्थायित्व के लिए रेल कम्पनियों के अलावा जिस अन्य उद्योग में सबसे पहले इस तरह का समझौता हुआ, वह था जहाजी रस्से का उद्योग। इस उद्योग में हुए समझौते के अनुसार जहाजी रस्से बनाने वाली सभी कम्पनियों ने यह स्वीकार किया कि वे इस उद्योग के कुल]

व्यापार में समान हिस्सा बटाएँगी। यदि कोई कम्पनी निर्धारित मात्रा से अधिक माल बेचती तो उस पर जुर्माना किया जाता और वह जुर्माना निर्धारित कोटे से कम बिक्री करने वाली कम्पनी को क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया जाता। इसी प्रकार का एक उदाहरण मिनिगन के नमक उत्पादकों का सघ था, जिसने आपसी समझौते से सारे क्षेत्र में नमक का उत्पादन सीमित कर दिया था ताकि अधिक उत्पादन से नमक की कीमतें न गिरे। मास के व्यापारियों, ढलवाँ लोहे के पाइपों और तार की कीलों के निर्माताओं ने भी इसी तरह के समझौते कर अपने-अपने लिए व्यापार के प्रदेश बाँट लिये थे।

किन्तु जब माँग बहुत घट जाती तो ये अनौपचारिक, अलिखित समझौते अनिवार्यतः पालनीय नहीं रहते थे और विभिन्न कम्पनियों के व्यापार के आपसी मेल और उस पर प्रतिबन्ध के लिए और भी कड़े तरीके अपनाने की आवश्यकता होती थी। इसलिए अमेरिका के इतिहास में ही सबसे पहला वास्तविक ट्रस्ट (कम्पनियों का गुट) स्थापित किया गया। गृह-युद्ध के बाद जॉन डी० रॉकफेलर के सञ्चालकत्व में स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी ने अनेक वर्षों तक बहुत-सी तेल-कम्पनियों के व्यापार में परस्पर मेल स्थापित किया। रॉकफेलर के चतुर निर्देशन में कम्पनियों के इस संयोजन ने परिवहन के भाड़ों में बहुत कमी करा ली, तेल ढोने के लिए अपनी निज की ढोलों (वैरल) की फैक्टरियाँ स्थापित की और पाइप लाइनों के जरिये तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए पूँजी लगानी शुरू कर दी। एक-न-एक तरीके से इस संयोजन ने सभी तेल कम्पनियों को अपने भीतर मगाना शुरू किया और यदि कोई कम्पनी इसके लिए तैयार न होती तो उसे खत्म ही कर दिया जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी के हाथ में तेल की प्रायः सभी पाइप लाइनों का और 90 प्रतिशत तेल शोधक कारखानों का नियन्त्रण आ गया।

सन् 1879 में इस संगठन को विधिवत् एक ट्रस्ट (कम्पनियों के गुट का न्यास) बना दिया गया। यह ट्रस्ट बन जाने पर इसमें सम्मिलित सब कम्पनियों के अधिकांश शेयर नौ ट्रस्टियों के हाथ में आ गए और वे इन सब कम्पनियों के संयोजित कार-बार की देख-रेख करने लगे। अगले कुछ

वर्षों में 'ट्रस्ट' का अर्थ मोटे-तौर पर किसी खास उद्योग का नियन्त्रण उसकी किसी एक कम्पनी के हाथ में चला जाना समझा जाने लगा।

स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट की सफलता का परिणाम यह हुआ कि 'विनौले' का तेल बनाने वाली कम्पनियों, चीनी शोधक कारखानों और इसी प्रकार के अन्य कारखानों ने भी मिलकर ट्रस्ट बनाने शुरू किये। इनमें से अधिकतर ट्रस्टों के हाथ में इतनी अधिक ताकत थी कि पुरानी गल-घोट प्रतिस्पर्धा के जमाने में उतनी ताकत किसी भी कम्पनी के हाथ में नहीं रही थी। गुगर ट्रस्ट के बारे में न्यूयार्क के एक जज ने एक बार कहा था, "यह ट्रस्ट जब चाहे तमाम चीनी शोधक कारखानों को बन्द कर सकता है और नये कारखाने खोल सकता है, कच्चे माल की खरीद को सीमित कर सकता है, शोधित चीनी के उत्पादन पर कृत्रिम रूप से सीमा लगा सकता है, जनता को लुटकर अपनी कम्पनियों को धनी बनाने के लिए चीनी की कीमतें बढ़ा सकता है और जब चाहे अपने वेवकूफ प्रतिस्पर्धियों को कुचलने के लिए कीमतों को कृत्रिम रूप से गिरा भी सकता है।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के व्यावसायिक ट्रस्टों की स्थापना की अधिकाधिक आलोचना होने लगी। किन्तु नई-नई विचार-धाराएँ और नए-नए शक्ति स्रोत अमेरिकन समाज पर धीरे-धीरे प्रभाव डाल रहे थे। भौतिकवाद, प्रत्ययवाद और 'वैज्ञानिक नियतत्ववाद' ने अधिकतर व्यवसायियों के मन में यह आश्वसन पैदा कर दिया था कि स्वार्थ और परार्थ यानी आत्महित और जनहित में कोई विरोध नहीं है। वे यह अनुभव करने लगे कि सरकार की अवन्व नीति (लेसेफेयर अर्थात् व्यापार-वाणिज्य में हस्तक्षेप न करने की नीति) न केवल 'न्यायपूर्ण' है बल्कि प्रगति और सभ्यता के लिए आवश्यक भी है।

इस विचारधारा के समर्थन में अधिक निराशावादी पुराने अर्थशास्त्रियों के मत उद्धृत किये जाने लगे और डार्विन के 'प्राकृतिक चयन' (नेचुरल सिलेक्शन) और 'योग्यतम की अतिजीविता' (सर्वाइवल ऑफ़ दि फिट्टेस्ट) आदि के नियमों की दुहाई दी जाने लगी। सामाजिक डार्विनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्तों की आर्थिक जगत् में भी अनुकूलता प्रकट करने लगा। जब एक आलोचक ने इस बात की ओर संकेत किया कि समाज को

औद्योगिकीकरण की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, तब उसे यह उत्तर दिया गया, “हम केवल समुचित विकास की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। यह सम्भव है कि चार या पाँच हजार वर्षों में विकास के द्वारा मनुष्य आज की सामाजिक परिस्थितियों से बहुत आगे पहुँच जाएँ।”

उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति के नज़दीक पहुँचकर आर्थिक अभिवृद्धि में एक नया मोड़ आया और औद्योगिक पूँजीवाद के स्थान पर वित्तीय पूँजीवाद का अर्थात् बैंकों और साहूकारों का सामान्य व्यापारिक गति-विधि पर अधिक प्रभाव और नियन्त्रण होने लगा। निवेश बैंकर (इन्वेस्ट-मेंट बैंकर) निवेशक और उद्योग स्थापना के इच्छुक उद्यमी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। जैसे-जैसे लागते बढ़ने लगी और कारखानों का यान्त्रिकीकरण होने लगा, उद्योगपतियों को अधिकाधिक पूँजी की आवश्यकता होने लगी और वे निवेश-बैंकरों पर निर्भर करने लगे। लेकिन निवेश-बैंकर किसी उद्योगपति को तब तक पैसा नहीं देते थे, जब तक कि उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता था कि वह जिसका पैसा उद्योगपति को निवेश के लिए देगे, उसका यह धन सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार बैंकर कुछ उद्योगों का पुनर्गठन कर देता था और इस प्रकार उस पर अक्सर नियन्त्रण भी स्थापित कर लेता था।

सन् 1890 के दशक की मन्दी के दिनों में और उसके बाद भी पूँजीगत सामग्री (कैपिटल गुड्स) के उद्योगों में पूँजी-निवेश की गति कम हो गई और निवेश-बैंकर लोगों के पास जमा धन के अप्रयुक्त और ‘वेकार’ पड़े अश को उनसे लेकर इस्तेमाल कर सकते थे। उद्योगों के परस्पर विलय के प्रयत्नों ने भी बैंकरों के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता दी। वास्तव में उद्योगों के पुनर्गठन ने कम्पनियों के प्रवर्तक बैंकरों को भारी लाभ पहुँचाना शुरू किया।

किन्तु निवेश-बैंकर अक्सर उद्योग में स्थिरता और स्थायित्व लाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते थे। जिस तरह अमेरिका के आर्थिक टोटम स्तम्भ (अमेरिका की पुरानी जन जातियों द्वारा अपने जातीय प्रतीक पशु, पक्षी या वनस्पति का चिह्न अंकित करने के लिए लगाया जाने वाला खम्भा) के शिखर पर किसान के चिह्न का स्थान किसी समय उद्योगपति के

चिह्न ने ले लिया था, उसी प्रकार अब उद्योगपति के स्थान पर उद्योगों के लिए पैसा देने वाला पूंजीपति अमेरिका की आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन गया था, क्योंकि वह उद्योगपति को उसकी अपनी ज्यादातियों के दुष्परिणामों से बचाता था।

इस नये वित्तीय पूंजीवाद का एक विशिष्ट प्रतीक था जॉन पीयरपीट मॉर्गन। उसने पूर्व की मुख्य रेल-कम्पनियों को पैसा देकर वित्तीय दृष्टि से अधिक शुद्ध आधार पर प्रस्थापित करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद उसने डगमगाते इस्पात और अन्य उद्योगों को भी इसी प्रकार का वित्तीय सहारा देना प्रारम्भ किया। वित्तीय क्षेत्र में उसके बराबर शक्तिशाली आदमी इस देश में और कोई नहीं हुआ।

सन् 1901 में मॉर्गन मस्थान ने युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन का गठन किया जिसमें छोटी बड़ी 800 इस्पात फर्में शामिल थीं। ये फर्में राष्ट्र का आधा पिण्ड लोह, कोक और लोह की पटरियाँ तैयार करती थीं और राष्ट्र का कँटीले तारों, कीलों, डिब्बे बनाने वाली इस्पात की चादरों और इस्पात के पाइपों का तो प्रायः समूचा उत्पादन ही इन कम्पनियों के हाथ में था। इनके अनिर्लिप्त उत्पादों का भी आधे से अधिक उत्पादन ये फर्में करती थीं। मॉर्गन मस्थान ने इन सब कम्पनियों को मिलाकर उस 'युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन' का गठन किया था, इसलिए अमेरिका के इस विशाल औद्योगिक कम्बाइन (कम्पनियों का संयोजन) पर उसका नियन्त्रण हो गया। जब मॉर्गन ने उस नई नियोजित कम्पनी में अपने शेयरों के मूल्य के रूप में आधा अरब डॉलर की रकम इस्पात उद्योगपति एण्ड्रयू कार्नेगी को दी, तो उन विमान राशि का हस्तान्तरण उद्योगपतियों पर पूंजीपतियों की विजय का एक प्रतीक बन गया।

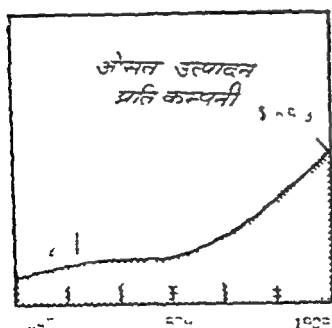
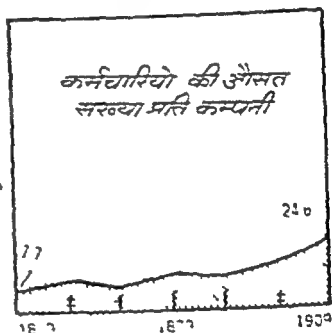
बीनबी मताब्दी प्रारम्भ होते-होते उद्योगों की आत्म-रक्षण के उपायों की तलाश ने नाने आर्थिक ढांचे को ही बदल दिया। उन्नीसवीं मताब्दी के 'पतिम्पदा' और 'स्वतन्त्र बाजार' के स्वप्न को नई औद्योगिक और वित्तीय ताकतों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिष्कृत कर दिया गया। वन्य उन ताकतों के दुरुपयोग और उनमें अमेरिका के आर्थिक जीवन में उत्पन्न असमानताओं ने विरोध का एक बड़ा तूफान मचा दिया तो भी अमेरिका उन

ताकतो के प्रभाव से पैदा हो रही नई दौलत का उपयोग कर रहा था और वही आर्थिक जीवन की इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा औचित्य और लाभ था।

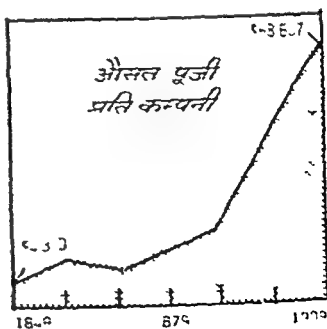
लेकिन इन नई ताकतों को लोगों ने वस्त्रा नहीं, भले ही वे नई दौलत पैदा कर रही थी। जैसे-जैसे ये ताकतें बढ़ रही थी, वैसे-वैसे उन पर अंकुश लगाने के लिए कानून भी बढ़ते गए। धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता से लोकतन्त्रीय व्यवस्था यह सिद्ध करती जा रही थी कि सबके लिए अवसरों की समानता के राष्ट्रीय आदर्श को आँच आने पर वह आवश्यक सुधार भी कर सकती है।

निर्माण उद्योगों में पूँजी द्वारा अदा किया गया भाग 1849-1909

औसत निर्माण करवन्ने
में कर्मचारियों की
संख्या में तीन गुनी
वृद्धि की गई



जिस में उत्पादन में
नौ गुनी वृद्धि हो गई
किन्तु -----



इस वृद्धि के लिए पूँजी में
17 गुनी वृद्धि करने की
आवश्यकता पड़ी

सुधार का युग

आर्थिक इतिहास के प्रसिद्ध लेखक रॉस रॉबर्ट्सन ने लिखा है “सन् 1870 तक हमारे पूर्वजों के लिए यह सम्भव था कि वे अर्थ-नीति वाली अर्थ-व्यवस्था में बिना इस भय के रह सकें कि कोई उन पर हावी हो मकेगा, यह व्यवस्था लगभग वैसी ही थी, जैसी कि ऐडम स्मिथ ने चाही थी—यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार देश के लोगों को बाहर के शत्रुओं और अन्दर के अपराधियों से बचाने और कुछ आवश्यक सेवाएँ करने के सिवाय समाज में और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी”।

लेकिन सरकार के शासन सम्बन्धी हस्तक्षेप-हीन कर्तृत्व के बारे में यह आशावादी दृष्टिकोण सन् 1870 के बाद कायम नहीं रह सका। उद्योग-व्यवसाय की तेजी से बढ़ रही शक्ति ने राष्ट्र के इस विश्वास को हिलाना शुरू कर दिया कि लोकतन्त्र के हितों को समुन्नत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय बन्धन और हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त अर्थ-व्यवस्था को खुलकर अपना काम करने देना है।

सन् 1900 से पहले के दो दशकों के बारे में लिखते हुए एक और इति-हासकार मार्क सुलिवन ने अमेरिकन जनता की भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया था—“अमेरिका का औपत नागरिक यह अनुभव करता था कि कोई ऐसी शक्ति जिसे वह देख नहीं पाता और जिसकी ओर वह निश्चित इंगित नहीं कर सकता उसके ऊपर हावी होने का प्रयत्न कर रही है, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे घोडा बनाकर उसपर नवारी कर रहा है और मनमानी दिशा में ले जा रहा है। भीतर-ही-भीतर वह अव्यक्त रूप से यह महसूस करता था कि यह शक्ति उसकी काम करने की स्वतन्त्रता को, उसके इच्छानुसार कार्य करने के अवसर को निष्फल कर रही है”।

को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट करने के लिए वह उसे अदृश्य सरकार, पैसे वाले लोग, धन कुबेर वाल स्ट्रीट या ट्रस्ट आदि नामों से पुकारता था।¹

सन् 1870 और 1917 के बीच इस सुधार आन्दोलन का समय और स्थान बदलते रहे और विभिन्न वर्गों ने उसका समर्थन किया। गृह-युद्ध के बाद के दशकों में अमेरिकनो का एक छोटा, किन्तु बहुत गोर-गुल मचाने वाला वर्ग समाजवाद की ओर मुका था, किन्तु उद्योग-व्यवसाय के अधिकतर आलोचक 'स्वतन्त्र व्यापार' व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत उद्योग के विचार को स्वीकार करते थे। उनके सुधार आन्दोलन का मुख्य आग्रह यह था कि अत्यधिक एकाधिकार को सीमित किया जाय, आय के वितरण के ढाँचे को बदला जाय, एक नियामक और प्रतिस्पर्धालुनकारी शक्ति के रूप में राज्य को सुदृढ़ बनाया जाय और लोकतन्त्रीय प्रक्रिया को शुद्ध किया जाय।

इन सुधार-आन्दोलनकारियों के उद्देश्य एक-दूसरे से बहुत भिन्न थे। सन् 1880 के दशक में कुछ धनी, किन्तु विचारशील, सम्भ्रान्त वर्गीय लोग राजनीति में सिर्फ इसलिए आए कि उस जमाने के सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार और भौतिकवाद घुस आया था, उसे चुनौती दे सकें। इससे भी पूर्व किसान, छोटे व्यापारी और बड़े पोतवणिक (शिपर) रेल-कम्पनियों की मनमाने भाड़े नियत करने की नीति के विरोध में आन्दोलन कर भाड़ों के नियमन की माँग करते रहे थे, जिसका परिणाम यह था कि 1887 में अमेरिका का पहला अन्तर्राज्यीय व्यवसाय अधिनियम पास हुआ। इस कानून ने रिबेट, पूल और भाड़े की दरों में बरते जाने वाले कुछ अन्य भेद-भावों का निषेध कर दिया था। इस कानून में यह भी कहा गया था कि— 'व्याज की दरें वाजिव' होनी चाहिए, किन्तु उसमें यह नहीं बताया गया था कि 'वाजिव व्याज-दर' की कसौटी क्या होगी। इस कानून के द्वारा संघीय सरकार के संगठन के रूप में एक अन्तर्राज्यीय व्यापार कमीशन भी बैठाया गया था।

1 'अवर टाइम्स दि युनाइटेड स्टेट्स', 1900-1925, खंड 2, न्यूयार्क, चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन, 1927।

इसके साथ ही छोटे व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों की ओर से बराबर आन्दोलन होता रहने के कारण एकाधिकार विरोधी और भी कानून बने। अनेक राज्यों ने खासकर दक्षिण और पश्चिम के राज्यों ने, कम्पनी-गुट विरोधी कानून पास किए, जिनमें एकाधिकार और व्यापार-नियन्त्रण सम्बन्धी सामान्य कानून बनाये गए थे। सन् 1890 में कांग्रेस ने शेरमन ऐंटी ट्रस्ट ऐक्ट (शेरमन कम्पनी-गुट विरोधी कानून) पास किया जिसमें 'ऐसे सब करारों, ट्रस्ट या अन्य रूप में बनाये गए कम्पनियों के गुटों और संघों या अन्य पद्धतियों को जो विभिन्न राज्यों के पारस्परिक अथवा अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार को प्रतिबन्धित करते हों, 'गैरकानूनी' ठहराया गया था। यह पहला मौका था, जबकि किसी सरकार ने उद्योग-व्यवसाय में हरेक को प्रतिस्पर्धा का खुला मौका देने के लिए एकाधिकार के विरुद्ध कदम उठाया था। इस प्रकार शेरमन कम्पनी-गुट विरोधी कानून अमेरिका के आर्थिक इतिहास में प्रगति की एक बड़ी मजिल का सूचक है।

परन्तु शुरू के वर्षों में न अन्तर्राज्यीय व्यापार अधिनियम प्रभावकारी सिद्ध हुआ और न ही शेरमन कम्पनी-गुट विरोधी कानून। इसका एक कारण यह था कि ये कानून पूरी तरह गठे हुए नहीं थे, और उनमें बहुत-सी त्रुटियाँ थीं। दूसरी बात यह कि अमेरिका की न्यायपालिका विचारों की दृष्टि से बहुत अनुदार थी और उसने इन कानूनों के प्रभाव को बहुत हल्का कर दिया था। सन् 1887 से 1905 तक सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में इन कानूनों के विरुद्ध 16 मामले गए, जिनमें से 15 मामलों में कोर्ट ने कमीशन के विरुद्ध फैसला दिया। इसी तरह 1890 और 1901 के बीच न्याय विभाग ने गुटों के विरुद्ध कुल 18 मामले चलाए और उनमें से भी चार मामले दरअसल ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध थे।

इसके अलावा कुछ राज्यों में शेरमन ऐक्ट का प्रभाव कम होने का एक कारण यह भी था कि वहाँ राज्यों के कानूनों ने विशेष कानूनी अनुमति लिये बिना ही कम्पनियों को दूसरी कम्पनियों के शेयर खरीदने का अधिकार दे दिया था। जब किसी कम्पनी के पास किसी अन्य कम्पनी के इतने शेयर होते थे कि वह उस पर नियन्त्रण कायम कर सके तो उस कम्पनी को 'होल्डिंग कम्पनी' (नियन्त्रक कम्पनी) कहा जाता था। मॉर्गन कम्पनी दर-

असल इन अनेक नियन्त्रक कम्पनियों की भी नियन्त्रक कम्पनी थी। उसके इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में एकाधिकार कितना प्रबल था और उसका विस्तार कितना व्यापक था। कम्पनियों के अनेक महत्त्वपूर्ण विलय, खासकर 1893-96 की मन्दी के बाद हुए विलय, इसी प्रणाली से हुए थे।

सन् 1893 के आतंक के बाद व्यवसायियों और उद्योग-पतियों की असीमित ताकत को सीमित और नियन्त्रित करने के आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ा। सन् 1893 से प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ तक अवन्ध व्यापार नीति (लेसे फेयर) की खूब आलोचना हुई, उसपर अनेक बार विचार और सशोधन हुए। जैसा कि हमने देखा है, स्वयं व्यापारी ही 'आत्मनियन्त्रण' और अनेक प्रकार के सघों और गुटों के निर्माण से स्वतन्त्र व्यापार में होने वाली ज्यादातियों को रोकने की माँग कर रहे थे।

पोपुलिस्ट आन्दोलन (सरकारी नियन्त्रणवादी दल का आन्दोलन) ने इन ज्यादातियों को दूर करने के लिए राजनीति और सुधार-कानूनों के द्वारा समस्या के समाधान का उपाय प्रस्तुत किया। यह आन्दोलन व्यापार में 'आत्म नियन्त्रण' की बात का खूब मजाक उड़ाता था और यही कारण है कि सन् 1890 के दशक के मन्दी के वर्षों में सारे राष्ट्र में उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर काफी आकृष्ट किया। पोपुलिस्ट दल का कहना था कि व्यापारियों के आत्म-नियन्त्रण के बजाय सरकार को ही व्यापार में हस्तक्षेप करके उसका नियन्त्रण करना चाहिए। इस दल के लोग यह माँग करते थे कि राष्ट्र की सम्पत्ति का वितरण अधिक व्यापक होना चाहिए, सरकार को लोगों को कर्ज और हल्की व्याज-दरों पर धन देना चाहिए और क्रमिक आय-कर लगाना चाहिए। यह दल काम के घटे आठ करने, गुप्त मतदान प्रणाली प्रारम्भ करने और रेलों और अन्य 'प्राकृतिक साधनों की इजारेदारियों' पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करने का भी समर्थक था।

पोपुलिस्ट दल के सिद्धान्तों का प्रमुख प्रवक्ता था नेब्रास्का का विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जिसे 1896 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। उस वर्ष डेमोक्रेटिक पार्टी में सस्ती व्याज-

दरो पर लोगो को धन मुहैया करने के सवाल पर मतभेद पैदा हो गए थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सम्मेलन हुआ, उसमें ब्रायन ने, जो स्वर्णमान के पूरक के रूप में चाँदी के सिक्के चलाने का पक्षपाती था, कहा था कि उसका यह चुनाव-संघर्ष धनियो और गरीब श्रमिक वर्ग के बीच होगा। सम्मेलन में भाषण देते हुए उसने प्रतिनिधियों को गोल्ड डेलीगेट (स्वर्ण प्रतिनिधि) कहकर सम्बोधित किया था और कहा था कि “आप मजदूर के सिर पर काँटों का यह ताज मत रखिए। आप मानव समाज को सोने की इस सूली पर मत लटकाइए।” उसके इस भावपूर्ण भाषण ने सारे सम्मेलन को अत्यधिक प्रभावित किया।

ब्रायन की इस भावुकताभरी वाक्पटुता ने उसे जनता का भी, खासकर पश्चिम और दक्षिण के छोटे किसानों का, काफी समर्थन प्राप्त कराया। किन्तु उसकी लोकप्रियता इतनी व्यापक नहीं थी कि वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता। सन् 1896 के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार विलियम मैकिनले के हाथों ब्रायन के पराजित होने के बाद पोपुलिस्ट विचारधारा की शक्ति बहुत कमजोर हो गई।

किन्तु सुधारके लिए आन्दोलन फिर भी जारी रहा। उन्नीसवीं शताब्दी को समाप्ति से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध में संयुक्त राज्य के प्रवेश तक इस आन्दोलन का नेतृत्व प्रगतिवादी लोग कर रहे थे। इन प्रगतिवादी लोगो का उद्गम और उनका झुकाव पोपुलिस्ट लोगो के उद्गम और झुकाव से बिलकुल भिन्न था। पोपुलिस्ट विचारधारा को कृषको के असन्तोष से पोषण मिलता था और जनता में फैली निराशा से उसका जन्म हुआ था, लेकिन प्रगतिवाद की जड़ गहरी मध्यवर्ग में थी और वह आर्थिक अभिवृद्धि और जनसाधारण की खुशहाली के युग में पनपता था।

लेकिन प्रगतिवादी तत्त्व कोई एक ही नहीं था। प्रगतिवादी आन्दोलन में अनुदार विचारधारा के उद्बुद्ध लोग, उदार विचारधारा के कृषिजीवी पेशेवर राजनीतिज्ञ सभी शामिल थे। किन्तु मुख्यतः प्रगतिवादी आन्दोलन व्यापारिक केन्द्रीकरण, नये आवासियों संयुक्त राज्य के पुराने नागरिकों में शामिल करने और राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्याओं पर ही अधिक ध्यान देता था।

‘राजनीतिक’ प्रगतिवादी लोग राजनीतिक लोकतन्त्र की पुनः स्थापना और शासन को फिर से जनता के हाथों में सौंपने की बातें करते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक दल प्रगामनिक पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन प्रत्यक्ष प्रारम्भिक चुनाव के जरिये करे। वे ‘प्रत्यक्ष’ लोकतन्त्र की जनमत संग्रह आदि पद्धतियों के भी समर्थक थे।

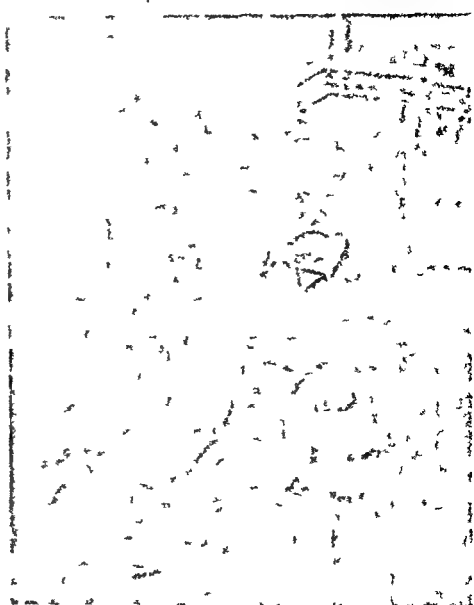
अन्य प्रगतिवादी लोगों ने नेशनल चाइल्ड लैबर कमेटी (राष्ट्रीय बाल श्रम समिति), नेशनल कंज्यूमर्स लीग (राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ) और जनरल फेडरेशन ऑफ वीमेन्स क्लब (महिला क्लबों का महामण्डल) आदि संस्थाएँ बनाई थीं। इन संस्थाओं और इसी तरह की अन्य संस्थाओं ने भी अनेक कानून बनाने का प्रस्ताव किया और उनके लिए संघर्ष भी किया। इन कानूनों का उद्देश्य बच्चों और स्त्रियों को शोषण से बचाना, श्रमिकों को विविष्ट परिस्थितियों में मुआवजा देना, मार्बजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना था। सन् 1902 से 1907 तक 43 राज्यों ने, मुख्यतः इन प्रगतिशील तत्त्वों के प्रयत्न से ही, बाल श्रम सम्बन्धी कानून पास किये।

प्रगतिवादी तत्त्वों में एक वर्ग पुराने सम्भ्रान्त सामन्त वर्ग का भी था। इस वर्ग के कुछ लोग इस बात से डरते थे कि कहीं जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप उग्र और आमूल परिवर्तन न हो जाएँ, इसलिए वे नर्म सुधारों के पक्षपाती थे। थ्योडोर रूजवेल्ट ने, जो स्वयं सम्भ्रान्त उच्च कुल में उत्पन्न एक अनुदार राष्ट्रवादी था, इस प्रकार के लोगों के दृष्टिकोण को बड़े सुविचारित ढंग से व्यक्त किया। सन् 1906 में उन्होंने लिखा था “मैं आज की सामाजिक परिस्थितियों को कतई पसन्द नहीं करता। आज के अत्यधिक धनी लोग निपट अन्धे और मूर्ख हैं, वे लोभी और घमण्डी हैं और योग्यतम वकीलों की सहायता से और अक्सर जजों की कमजोरियों और अदूरदर्शिता से अनुचित रूप से समृद्ध हो गए हैं। इन तथ्यों ने तथा व्यापार और राजनीति में फैले भ्रष्टाचार ने जनमानस में उत्तेजना और रोष की एक अत्यन्त अस्वस्थ अवस्था पैदा कर दी है, जिसकी अभिव्यक्ति हम समाजवादी प्रचार में हुई असाधारण वृद्धि के रूप में देख रहे हैं।”

सन् 1898 में वह स्पेन और अमेरिका की लड़ाई में अस्वारोही सेना

की 'रक राउटर्स' टुकड़ी के नेता के रूप में राष्ट्र का एक वीर नायक बन गया था। यह युद्ध स्पेनिश प्रभुत्व के विरुद्ध ब्यूवा के सश्रप का परिणाम था।

ब्यूवा के युद्ध में कर्नल रूजवेल्ट ने जो ग्यानि अर्जिन को उमने उमे सन् 1900 में उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनवा दिया। उन चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मैकिनले था। एक वर्ष बाद मैकिनले की हत्या हो जाने पर थोडर रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद पर ग्राह्य हो गया। उसही ग्यानि में कि वह काम करने वाला आदमी है वह



थोडर रूजवेल्ट

“वान बहुत नमी में करता है परन्तु अपने साथ एक बड़ी छड़ी रखता है।” उन ग्यानि में उसे सुधारवाधियों और पब्लिक व्यापारियों, दोनों में से बहुत-से नमयक जुटा दिये। यह एक निपुण राजनीति कुशल नेता बन गया जो ‘बुरे’ और ‘बुरे’ सम्पत्ती-गुटों में भेद को नमभन्ता था, पदाधितारवाद को नियमित और नियन्त्रित करने का नमभन्ता था और सामाजिक न्याय के लिए प्रयत्न करता था। उस जमाने के उच्च चित्रों में उसे सम्पत्तियों के गुटों और नशों को तोड़ने वाला निश्चित किया जाता था। व्यापक निष्कारण उसे बड़े व्यापार के ‘सहायकों’ के विरुद्ध एक भारी और लम्बा टका दिये हुए चित्रित करने थे।

थोडर रूजवेल्ट के पसायन में देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार की भूमिका और सम्मलेष को दहन दया दिया। उस जमाने के गान्धियों के स्वाधिनियों के स्वयं अपने-आपको नियन्त्रित और विनियमित करने के विचार

को चुनौती दी गई थी। उनमें इस विचार को भी अस्वीकार किया गया था कि यदि हर आदमी को बिना किसी नियंत्रण या बन्धन के अपने हित को समुन्नत करने की छूट दे दी जाय तो उनसे अन्ततः जनता का भला ही होगा। रूजवेल्ट ने व्यापार को नियन्त्रित करने वाले कानूनों को मजबूत बनाया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को अनेक बार सशोधित किया गया।

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद रूजवेल्ट का सुधारों का जोश और भी बढ़ गया। उनके उत्तराधिकारी विलियम हावर्ड टाफ्ट के, जिसे उनमें स्वयं अपना उत्तराधिकारी चुना था, अनुदार प्रशासन ने बहुत जल्दी ही उनका भ्रम भग कर दिया और उनका परिणाम यह हुआ कि जून, 1912 में प्रोग्रेसिव पार्टी का जन्म हुआ, जिसने राष्ट्रपति पद के लिए थ्योडोर रूजवेल्ट को अपना उम्मीदवार मनोनीत किया।

इससे रिपब्लिकनो के वोट टॉस्ट और रूजवेल्ट में बँट गए और परिणाम यह हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वुडरो विल्सन की जीत हो



वुडरो विल्सन

गई। विल्सन ने भी सुधारवादी कार्यक्रम को पूरा करने की गप्य ले रखी थी। सन् 1913 में राष्ट्रपति पद पर आरुढ़ होते नमय विल्सन ने राष्ट्र को सम्बोधन कर कहा था, “हमें अपनी औद्योगिक नफ़लता का गर्व रहा है, लेकिन हमने अब तक एक बार भी यह नहीं सोचा कि इसके लिए हमें कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है।” इस भाषण में आगे चलकर

उन्होंने ‘नई स्वतन्त्रता’ का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य था

विशेषाधिकारों को खत्म करना और 'नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा' की प्रणाली का निर्माण करना ।

वाद में अपने कार्यकाल में विल्सन ने जन-कल्याण के कानूनों को बुद्धि-मत्तापूर्ण बताया था । उसने कहा था, "प्रशासन का सुदृढ़ आधार है न्याय ... जन-जीवन में न्याय के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सबके लिए अवसरों की समानता, और यह समानता तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि पुरुषों स्त्रियों और बच्चों को उनके जीवन में महान् औद्योगिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के परिणामों से, जिन्हें वे परिवर्तित और नियन्त्रित नहीं कर सकते और न जिनका मुकाबला कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान न किया जाय ।"

विल्सन के प्रशासन के प्रथम कार्यकाल की कहानी सुधार कानूनों के निरन्तर निर्माण की कहानी है । वलेटन कानून ने शेरमनकम्पनी-गुट विरोधी कानून की कुछ मनमानियों का स्पष्टीकरण किया और खास तौर से श्रमिक यूनियनों और कृषि-सहकारी संस्थाओं को उसके अनुबन्धों से मुक्त कर दिया ।

सन् 1913 के फेडरल रिजर्व ऐक्ट (मधीय आरक्षित निधि कानून) से केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली का एक टाँचा तैयार किया गया, प्राइवेट महाजनों और बैंकों की शक्ति को कम किया गया और मुद्रा उपलब्धि पर सरकारी नियन्त्रण को मजबूत किया गया । उसी समय अण्डरवुड तटकर कानून भी लागू किया गया, जो गृह-युद्ध के बाद आयात कर में दली कभी करने का पहला प्रयत्न था । उनके अतिरिक्त ऐडम्सन कानून पान कर रेन कर्मचारियों के दैनिक काम के घण्टे घटाकर आठ किये गए और मरीय कृषि-श्रम कानून से किसानों को जमीनी दर पर श्रम देने की व्यवस्था की गई ।

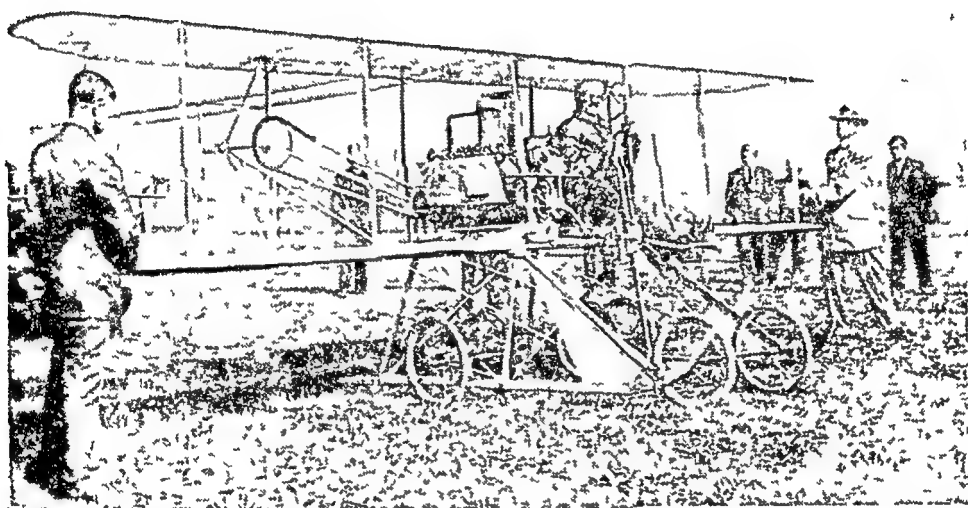
विन्तु नवने महत्त्वपूर्ण कार्य था 1914 में फेडरल ट्रेड कमीशन (मरीय व्यापार कमीशन) की स्थापना या जिसने उत्पादन क्षेत्र में भी मावजनिक नियन्त्रण और निरसन के निद्वान्त का विस्तार किया । कमीशन का काम था एकाधिकार की वृद्धि को रोकना और जनता की ज़ानों में धून भोजने वाले विनियमों के पनार पर रोक लगाना ।

इस काम का गान्धी महत्त्वपूर्ण काम था नविधान में दो सशोधन ।

एक सशोबन से कांग्रेस को श्रमिक आयकर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया था और दूसरे में संयुक्त राज्य के सीनेटर्स के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इससे पूर्व सीनेटर राज्यों के विधानमण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते थे।

सन् 1917 में वुड्रो विल्सन का पहला कार्यकाल समाप्त होने तक यह स्पष्ट हो गया था कि लोकतन्त्रीय प्रक्रियाएँ अमेरिकन जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा करने और उनके लिए आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ाने में पुनः सफल होने लगी हैं। विल्सन के दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में संयुक्त राज्य अपनी आन्तरिक समस्याओं की उलझनों से मुक्त होकर विश्व के राष्ट्रों के समूह में अधिकाधिक उत्तरदायित्व की स्थिति प्राप्त करने लगा।

संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर



किटो मे राइट ब्रदर्स, 1903

सन् 1870 से 1914 तक की साढे चार दशाब्दियो मे विग्व का शक्ति सन्तुलन बदल गया था । आधुनिक उपनिवेशवाद और अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाओ के उदय के साथ-साथ उद्योग और वाणिज्य मे देशो का ध्यान लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका आदि ससार के अल्पविकसित क्षेत्रो की ओर जाने लगा और वे उन्हे कच्चे माल के स्रोत और अपने कारखानो मे तैयार मस्ने माल की बिक्री के लिए बाजार के रूप मे देखने लगे । नये उभरते औद्योगिक देशो ने जब ब्रिटेन की सर्वोच्चता और प्रभुत्व की स्थिति को चुनौती देनी शुरू की तो कच्चे माल के स्रोतो और तैयार माल के बाजारो की यह प्रतिस्पर्धा और भी उग्र हो गई । सयुक्त-

राज्य भी, इन उभरते हुए नये औद्योगिक राष्ट्रों में से एक अधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र होने के कारण, स्वभावतः इस विश्व संघर्ष का एक भाग बन गया।

गृह-युद्ध से पूर्व संयुक्त राज्य की वैदेशिक नीति मुख्यतः कृषि-सम्बन्धी दृष्टिकोणों से या काटिनेटलिज्म (महाद्वीपवाद) अर्थात् आन्तरिक भौगोलिक और आर्थिक प्रसार के दृष्टिकोणों से निर्धारित होती थी। औद्योगिकीकरण ने वैदेशिक नीति को एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण दिया। यह दृष्टिकोण था समुद्र पारवर्ती देशों में प्रसार का। इससे वैदेशिक नीति में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। शुरु में यह परिवर्तन धीमी गति से था, किन्तु 1893 की मन्दो और 'आवश्यकता से अधिक उत्पादन' के संकट के बाद वह और स्पष्ट हो गया। प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व के दो दशकों में राष्ट्र लैटिन अमेरिकन देशों के मामलों में काफी गहराई तक, और यूरोप के मामलों में भी कुछ हद तक, उलझ गया था।

इन वर्षों के प्रसारवादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार व्यापार था। सन् 1869 और 1914 के बीच संयुक्त राज्य का विदेशी व्यापार सचमुच ही राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ा था। सन् 1870 में संयुक्त राज्य का समूचा आयात-निर्यात मूल्य की दृष्टि से 80 करोड़ डालर था, किन्तु 1914 में वह 4 अरब 20 करोड़ डालर हो गया। विदेशों में अमेरिकन सामान के बाजार के विस्तार के लिए निरन्तर बढ़ रहे दबाव के पीछे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि एक ओर अमेरिका में कृषि-उत्पादन देश की आन्तरिक आवश्यकता से बहुत अधिक हो रहा था और अनबिकी फालतू कृषि-जिन्सों के अम्बार लग रहे थे और दूसरी ओर उद्योग और परिवहन में तेज गति से परिवर्तन हो रहे थे।

औद्योगिक विस्तार और अभिवृद्धि से देश के आयात और निर्यात, दोनों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था। सन् 1865 में कारखानों में निर्मित माल संयुक्त राज्य के निर्यात में कुल 20 प्रतिशत था, किन्तु 1915 में वह कुल निर्यात के 50 प्रतिशत के लगभग हो गया। इसी अवधि में अन्य देशों से कारखानों में तैयार माल का आयात कम हो गया। इस बीच कच्चे माल का आयात, खासकर बढ़ते हुए उद्योगों के लिए आवश्यक खर, उष्ण-कटिबन्धीय रेशे, निकल, टीन और अन्य धातुओं आदि का आयात,

अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो गया ।

गृह-युद्ध के बाद यूरोप के साथ व्यापार घटने लगा, हालाँकि उस समय भी सयुक्त राज्य के उत्पादनो के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण बाजार था । सन् 1860 में सयुक्त राज्य से निर्यात किया गया 77 प्रतिशत माल यूरोप गया था, परन्तु 1914 में यह अनुपात गिरकर 63 प्रतिशत हो गया ।

लैटिन अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व अमेरिकन माल के बाजार और आवश्यक कच्चे माल के स्रोत का काम करने और इस कमी को पूरा करने लगे । किन्तु सयुक्त राज्य को इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य उभरते औद्योगिक राष्ट्रों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा लैटिन अमेरिका में । परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का निर्यात व्यापार करने वाला वर्ग सरकार से ऐसी वैदेशिक नीति अपनाने की माँग करने लगा, जो इन क्षेत्रों में सयुक्त राज्य के व्यापार को बढ़ा सके ।

सन् 1893 के बाद सरकार पर यह दबाव और भी बढ़ने लगा, क्योंकि कुछ औद्योगिक उत्पादनो की माँग देश के भीतर कम होने लगी थी । निर्यात व्यापारी यह माँग करने लगे कि सरकार विदेशों में अमेरिकन माल की बिक्री की सम्भावनाओं के बारे में जानकारी संग्रह करे, अमेरिकन सामान के साथ बरते जाने वाले भेद-भाव का प्रतिरोध करे और वाणिज्य दूतावासों की सेवा को सुधारे । जहाजरानी सर्विसों के मालिक भी इस आन्दोलन में शामिल हो गए और उन्होंने व्यापारिक जहाजरानी के लिए सरकारी सहायता की माँग प्रारम्भ कर दी ।

पूँजी-निवेशकों ने एक और आन्दोलनकारी वर्ग का भी निर्माण किया, जो समुद्रपार के क्षेत्रों में प्रसार का समर्थक था । सन् 1900 के बाद विदेशों में लगी अमेरिकन पूँजी अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो गई । सन् 1900 और 1912 के बीच विदेशों में, खासकर कच्चे माल के दोहन में और कनाडा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में परिवहन उद्योगों में, लगी अमेरिकन पूँजी की मात्रा 44 5 करोड़ डालर से बढ़कर 1 7 अरब डालर हो गई । उसके बाद दो वर्षों में यह मात्रा और भी बढ़कर 2 5 अरब डालर हो गई ।

इस पूँजी-निवेश के पीछे 'स्पष्ट नियति' की एक नई भावना काम कर

रही थी, जो आर्थिक उद्देश्यो, मानव सेवा और राष्ट्रवाद का एक सम्मिश्रण थी। परन्तु यह भावना बीसवीं शताब्दी की नई उपज नहीं थी। प्रायः शुरू से ही पश्चिम की ओर अमेरिकन लोगो के फैलाव का समर्थन यह कहकर किया जाता था कि “नियति ने हमारे भाग्य में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि हम इस महाद्वीप में आगे-आगे फैलते जाएँ, क्योंकि भगवान् ने हमारी बढ़ती हुई करोड़ों की जनसंख्या के स्वतन्त्र विकास के लिए यह महाद्वीप हमें दिया है।” बहुत-से सीमावर्ती लोग तो, द तोकविले के शब्दों में, पश्चिम की ओर आगे बढ़ना ईश्वर की ओर से किया गया एक पवित्र काम समझते थे।

महाद्वीपवर्ती संयुक्त राज्य के एक बार समूचे आश्रय हो जाने और उसकी सारी मुफ्त प्राप्य भूमि खत्म हो जाने पर अमेरिकन लोग नए प्रसार के लिए देश के बाहर नजर दौड़ाने लगे। किन्तु यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय ज्वर के रूप में कदापि नहीं थी। गृह-युद्ध से प्रारम्भ करके 1890 के दशक तक अमेरिका अपने आन्तरिक मामलों में ही इस कदर व्यस्त और उलझा हुआ था कि उसके लोगो में एक जवर्दस्त पृथक्त्ववाद की भावना पैदा हो गई थी। वास्तव में इन वर्षों में अमेरिका ने राजनयिक क्षेत्र में केवल एक ही बड़ी चाल चली जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः 1867 में उसने रूस से अलास्का प्रदेश खरीद लिया, किन्तु देश के प्रायः सभी लोगो ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किये गए इस एकमात्र कार्य की भी यह कहकर निन्दा की कि यह कांग्रेस की मूर्खता थी।

किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी समाप्त होने तक व्यापार की आवश्यकताओं, यूरोपीय शक्तियों के आक्रमण साम्राज्यवाद और अमेरिकन लोगो में अपने स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के आदर्शों को दूसरे लोगो तक भी पहुँचाने की ‘स्पष्ट नियति’ की भावना के पुनः उदयने पृथक्त्ववादी भावना को बदलकर बहुत हद तक प्रसार के लिए अत्युत्साह में परिणत कर दिया।

इन सब दवावों का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य ने दोनों महासागरों में कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया और कुछ को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने लैटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया दोनों में महत्वपूर्ण अमेरिकन हितों की रक्षा के समर्थन में भी जवर्दस्त रुख अपनाया। सन्

जमाने के सम्मान के विरुद्ध था। उनकी आवाजे प्रादेशिक विस्तार के लिए किये जा रहे प्रबल आन्दोलन में नक्काखाने में तूती की आवाज सावित हुई।

नई गताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में थ्योडर रूजवेल्ट एक शक्तिशाली विदेश नीति का जोर-शोर से समर्थन करने लगा। रूजवेल्ट के प्रथम राष्ट्र-पतित्व काल में उसका एक प्रिय काम था पनामा स्थल-संयोजक में, जो उस समय कोलम्बिया का एक भाग था, नहर निकालने का अधिकार प्राप्त करना।

सन् 1903 के मार्च में संयुक्त राज्य ने कोलम्बिया के साथ एक संधि की और एक करोड़ डालर देकर उससे इस स्थूल-संयोजक में छ मील चौड़ा एक नहर प्रदेश प्राप्त करने का फैसला कर लिया। संधि के अनुसार संयुक्त राज्य ने बाद में भी इसके लिए प्रति वर्ष 25 लाख डालर देना स्वीकार किया। लेकिन जब यह सन्धि कोलम्बिया की सीनेट के सामने पेश की गई तो उसने यह कहकर, कि संयुक्त राज्य ने इसके लिए जो रकम देनी स्वीकार की है वह थोड़ी है, संधि की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया।

कुछ महीने के भीतर ही पनामा के लोगों ने, संयुक्त राज्य सरकार के भडकाने पर कोलम्बिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह ठीक है कि पनामा की अधिकांश जनता कोलम्बिया के शासन से मुक्ति चाहती थी, किन्तु तो भी यदि अमेरिकन नौसेना ने पनामा स्थल-संयोजक के आर-पार कोलम्बियन सेना को जाने से रोका न होता तो यह विद्रोह अवश्य दबा दिया जाता। जो हो, पनामा ने कोलम्बिया से मुक्त होते ही उम संधि को हस्ताक्षर कर पुष्ट कर दिया जिसे कोलम्बिया की सीनेट ने पुष्ट करने से इन्कार कर दिया था।

इस स्थल-संयोजक पर नहर का निर्माण प्रारम्भ होते ही रूजवेल्ट ने यह अनुभव किया कि कैरेबियन क्षेत्र के साथ अमेरिका के सम्बन्धों को दृढ़ करना जरूरी है। मुनरो सिद्धान्त की दुहाई देकर उसने यूरोपियन राष्ट्रों को चेतावनी दे दी कि यदि उन्होंने मध्य अमेरिका में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया तो संयुक्त राज्य उसे सहन नहीं करेगा। किन्तु संयुक्त राज्य यह आश्वासन देने के लिए तैयार था कि कैरेबियन क्षेत्र में आमतौर पर

संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर

शान्ति बनाए रखने के लिए जरूरी हुआ तो वह ~~अपने~~ हस्तक्षेप करेगा ।

किन्तु इसी बीच संयुक्त राज्य के साम्राज्यवाद (याकी इम्पीरियलिज्म) के विरुद्ध लैटिन अमेरिकन देशों में रोष बढ़ने लगा, जो स्वाभाविक ही था, और उससे अमेरिका के दोनों खंडों के सम्बन्ध बिगड़ने लगे । रूजवेल्ट के बाद जब टाफ्ट और विल्सन राष्ट्रपति बने तो उनके शासनकालों में भी यह रोष समाप्त नहीं हुआ । लैटिन अमेरिकन देशों के साथ संयुक्त राज्य के सम्बन्ध 'डालर कूटनीति' पर आधारित थे—अर्थात् अमेरिका के बैंक मध्य अमेरिकन देशों को जो ऋण देते थे, उनके पीछे संयुक्त राज्य के परराष्ट्र विभाग का बल और समर्थन रहता था । इस प्रकार जब इनमें से किसी देश के आर्थिक ढाँचे पर खतरा पैदा होता तो संयुक्त राज्य सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए उसमें तुरन्त हस्तक्षेप करती । यह हालत तब तक चलती रही, जब तक कि दूसरे रूजवेल्ट ने मुनरो सिद्धान्त के इस एकतरफा उपयोग के स्थान पर अच्छे पड़ोसीचारे की नीति की प्रस्थापना नहीं की । यह नई नीति अमल में आने पर संयुक्त राज्य और लैटिन अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार होने लगा ।

इधर लैटिन अमेरिका में यह सब चल रहा था और उधर संयुक्त राज्य पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था । संयुक्त राज्य की सुदूरपूर्वीय नीति चीन के बाजार पर खासकर कच्चे माल से भरपूर मच्चूरिया पर, केन्द्रित थी । सन् 1890 के दशक के अन्तिम वर्षों में रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान धीरे-धीरे चीनी साम्राज्य पर अधिकार किए जा रहे थे । संयुक्त राज्य इस बात के लिए चिन्तित था कि चीन के लड़-खड़ाते राजनीतिक ढाँचे के परिणामस्वरूप कहीं उसका बाजार अमेरिका के लिए बन्द न हो जाय ।

इसलिए इस बाजार को अमेरिका के लिए खुला रखने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य के परराष्ट्र सचिव जॉन हे ने 1899 में चीन पर अधिकार करने वाली विभिन्न शक्तियों को अपना प्रसिद्ध 'खुला द्वार' पत्र भेजा, जिसमें उनसे यह गारंटी करने के लिए कहा गया था कि वे चीन में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में संयुक्त राज्य के व्यापार के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे और उससे किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं वरतेंगे । एक वर्ष बाद, चीन में

विदेशी लोगो के विरुद्ध हुए हास्यास्पद बाँक्सर विद्रोह के बावजूद सयुक्त राज्य ने चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर, अपनी 'खुला द्वार' नीति को आगे बढ़ाने और चीन पर विदेशी कब्जे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, एक और कदम उठाया।

'खुला द्वार' नीति की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि अमेरिका चीन में परस्पर प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादी ताकतों में शक्ति-सन्तुलन किम हद तक रख सकता है। थोडर रूजवेल्ट को यह आशा थी कि उत्तरी चीन में जापान को रूस के खिलाफ खड़ा करके वहाँ सयुक्त राज्य के व्यापार के लिए 'खुला द्वार' नीति को अधिक सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। लेकिन सयुक्त राज्य ने एक गलती कर दी और वह यह कि उसने एक दिशा में बहुत अधिक जोर दे दिया जिससे जापान का उस क्षेत्र में अधिक प्रभुत्व और प्रभाव हो गया।

इसलिए जब टॉपट राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ तो उसने दूसरी ही चाल चलना पसन्द किया। उसने यह विचार किया कि अमेरिका की प्राइवेट पूंजी चीन और मंचूरिया की रेल कम्पनियों और बैंकों में लगवा दी जाय। किन्तु इसमें भी सरकार असफल रही। शक्तिशाली यूरोपियन देशों और जापान की प्रतिस्पर्धा में सयुक्त राज्य को 1900 में अपना एक हक से बार-बार तब तक पीछे हटते रहना पड़ा, जब तक कि दिसम्बर, 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले से मामला बिलकुल चरम सीमा पर नहीं पहुँच गया।

सन् 1870 से 1914 तक अमेरिका के समुद्रपार प्रसार के बारे में चाहे कोई भी निष्कर्ष निकाला जाय, एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका इस अवधि में एक विश्व-शक्ति बन चुका था। उसका व्यापार भी उसके अपने पक्ष में सन्तुलित था और उसने पूंजी और सामान दोनों का निर्यात करना प्रारम्भ कर दिया था। राजनीतिक दृष्टि से भी एक शक्तिशाली नौसेना और दूर-दूर तक फैले अपने समुद्रपारीय प्रदेशों और सुरक्षित क्षेत्रों के कारण सयुक्त राज्य एक महा-शक्ति बन गया था। एक सवथा अक्षत और नये महाद्वीप के तट पर स्थापित यह कमजोर और लडखड़ाता देश, जिसके अपने इर्द-गिर्द के गम्भीर खतरों के कारण बचे रहने की बहुत कम आशा थी, अब ससार के महान् राष्ट्रों में से एक हो गया था।

तीसरा भाग

शक्ति और उत्तरदायित्व

विश्व-युद्ध का प्रभाव

सन् 1914 में यूरोप में एकाएक युद्ध छिड़ने से सयुक्त राज्य चकित रह गया। सयुक्त राज्य के समुद्रपारीय प्रयत्नों और अभियानों से अमेरिकन जनता में विदेशी मामलों में एक नई दिलचस्पी अवश्य पैदा हुई थी, किन्तु उसने यूरोप के गठबन्धनों और समझौतों की ओर, जो 1914 की शक्ति-परीक्षा की दिशा में सकेत करते, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था।

युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रपति विल्सन सयुक्त राज्य की तटस्थता कायम रखने के लिए दृढ़ सकल्प थे, हालाँकि अमेरिका वित्तीय दृष्टि से मित्र राष्ट्रों की ओर से इसमें काफी उलझा हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, विल्सन के लिए यह तटस्थता कायम रखना मुश्किल हो गया। तटस्थ बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण और युद्ध क्षेत्र में सयुक्त राज्य के निःशस्त्र व्यापारिक जहाजों पर जर्मन पनडुब्बियों के निरन्तर हमलों ने अमेरिकन जनता को उत्तेजित कर दिया। ब्रिटिश जहाज ल्युसिटेनिया के डूबाये जाने से, जिस पर सवार 1153 व्यक्तियों में 114 अमेरिकन भी थे, अमेरिकन जनता इतनी विक्षुब्ध हुई कि उसने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की माँग प्रारम्भ कर दी। इस शोरोगुल में विल्सन के पर-राष्ट्र मन्त्री विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने, जो पक्का पृथक्तावादी था और शुरू से ही मित्रराष्ट्रों की ओर से इस मामले में अमेरिका के किसी भी तरह उलझने के विरुद्ध था, इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद जब भी जर्मनों ने सयुक्त राज्य के जहाजों पर हमला किया, विल्सन ने जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और उससे जवाब तलब कर हरजाने की माँग की। धीरे-धीरे यह हालत हो गई कि अप्रैल, 1917 में उसे कांग्रेस से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने का अनुरोध करना पड़ा। अन्तिम क्षण तक वह यूरोप के राष्ट्रों से अनुरोध करता रहा था कि वे युद्ध को हार-जीत के फैसले तक पहुँचाए बिना समझौता करके गान्ति स्थापित कर दें।

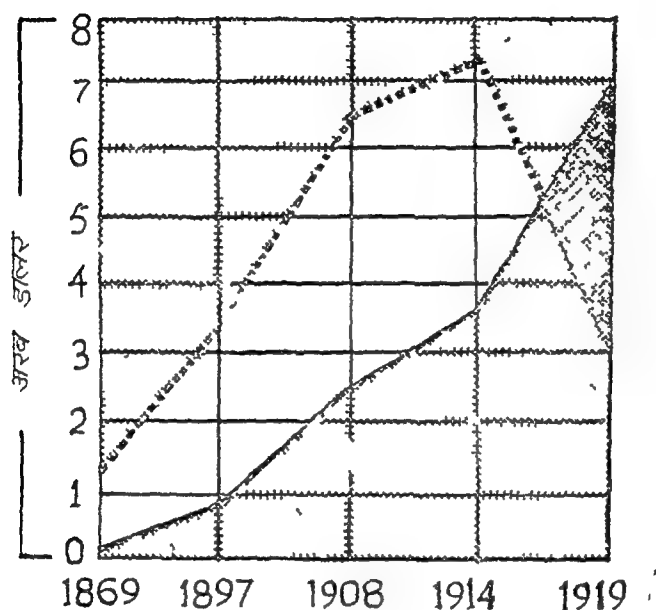
परन्तु अब उसकी गवित एक-दूसरे ही मार्ग पर प्रभावित होने लगी और वह 'ससार को लोकतन्त्र के लिए सुरक्षित करने' के धर्मयुद्ध में जुट गया।

संयुक्त राज्य की संघीय सरकार ने व्यापक आर्थिक नियन्त्रण और साधनों के बँटवारे के लिए जो युद्ध-कालीन कार्यक्रम बनाया, वह अमेरिका के इतिहास में अभूतपूर्व था। गृह-युद्ध के दौरान में संयुक्त राज्य और महा-संघ दोनों की सरकारों ने अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं पर नियन्त्रण स्थापित किये थे। प्रगतिवादी युग में द्रुत औद्योगिकीकरण ने उत्पन्न असमानताओं को रोकने और नियन्त्रित करने के लिए काफी कानून बनाये गए थे। लेकिन इनमें से कोई भी कानून इतना व्यापक नहीं था, जितने कि प्रथम विश्व-युद्ध काल में बनाये गए कानून थे।

विश्वयुद्ध में अमेरिका के प्रवेश से पूर्व अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था यूरोप के युद्धरत पक्षों को आवश्यक सामान बेचकर और उन्हें ऋण देकर फल-फूल रही थी। जनवरी, 1915 से अप्रैल, 1917 तक अकेले मित्रराष्ट्रों ने अमेरिका से जो ऋण लिया उससे संयुक्त राज्य के अर्थतन्त्र की क्रय-गवित में 5 अरब डालर की वृद्धि हो गई। उस समय संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय आय का यह काफी बड़ा प्रतिशत अंश था।

यूरोप में युद्ध छिड़ने के बाद मित्रराष्ट्र अपनी आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि के लिए संयुक्त राज्य पर बहुत अधिक निर्भर करने लगे। अमेरिकन उत्पादनों की उनकी भारी माँग ने संयुक्त राज्य में व्यापार के उत्कर्ष का ऐसा दौर पैदा किया कि यहाँ गडबडी सी मच गई। अमेरिकन कारखानों में कच्चे माल की कमी हो गई। तैयार माल के अपूर्ण आर्डरों के ढेर लगने लगे। श्रमिकों की कमी और हड़तालों में वृद्धि की मुसीबतें भी पैदा हो गईं। यूरोप को निर्यात करने के लिए इतना माल पूर्वी तट की ओर भेजा जाने लगा कि संयुक्त राज्य की रेलों के लिए उसे ढोना मुश्किल हो गया। जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ने लगी, संयुक्त राज्य में मित्रराष्ट्रों के ऋण-स्रोतों में कमी होने लगी। उनके लिए अपनी भारी खरीद का मूल्य चुकाने की समस्या अधिकाधिक विकट हो गई। मुद्रा स्फीति बढ़ने से कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी।

संयुक्त राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति 1869-1919



- संयुक्त राज्य में लगी विदेशी पूंजी
- विदेशों में लगी संयुक्त राज्य की पूंजी
- संयुक्त राज्य की अन्तिम स्थिति (देनदार)
- संयुक्त राज्य की अन्तिम स्थिति (लेनदारी)

सन् 1915 के अन्त में यह स्पष्ट हो गया कि इन आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि संघीय सरकार ही आयोजन और समझन का एक व्यापक राष्ट्रीय प्रोग्राम न बनाए। फलतः कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद् का निर्माण किया और उसे राष्ट्र को तैयार करने का एक कार्यक्रम बनाने का काम सौंपा। इसका लाभ यह हुआ कि अप्रैल, 1917 में संयुक्त राज्य के युद्ध में प्रवेश करने तक इस परिषद् द्वारा ऐसी अनेक संस्थाओं और संगठनों का जाल बिछ चुका था, जो युद्ध-प्रयत्नों को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। इनमें से

अनेक सगठनों के प्रमुख पदों पर औद्योगिक जगत् के ऐसे नेता थे, जो सरकार से 'एक डालर वार्षिक' का नाममात्र का वेतन लेकर मुफ्त काम कर रहे थे।

औद्योगिक वर्ग और सैनिक संस्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का भार 'युद्ध उद्योग बोर्ड' पर डाला गया, जिसके सभापति प्रतिष्ठित वित्तदक्ष पूंजीपति वर्नार्ड बारुच थे। बोर्ड ने संयुक्त राज्य में उपलब्ध तमाम सामरिक



वर्नार्ड बारुच, तत्कालीन सरकार के
आर्थिक मामलों के सलाहकार
और पूंजी-निवेशक

आवश्यकता की वस्तुओं और दुर्लभ कच्चे माल की सूचियाँ तैयार की। उसने अत्यावश्यक कच्चे माल की उपलब्धि और खरीद के लिए संसार के सभी देशों को अपने आदमी भेजे। माँगों का विग्लेपण किया गया और यह निर्धारित किया गया कि किन चीजों की खरीद को प्राथमिकता दी जाय, ताकि जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत हो वहाँ आवश्यक सामग्री ठीक समय पर पहुँच सके। बोर्ड ने इस सामग्री के विक्रय मूल्य निर्धारित किये और तैयार

वस्तुओं के वितरण को नियन्त्रित किया। इसके अलावा उसने निर्माताओं को अपने उत्पादनों के डिजायन और स्टाइलों में कमी करने की भी प्रेरणा दी। बच्चा गाड़ियों से लेकर स्मॉईघरों में बर्तन साफ करने के लिए लगाए जाने वाले बेसिनो तक, हर चीज के स्टैंडर्ड और मानक निर्धारित किये गए और साथ ही उनका सरलीकरण भी किया गया, ताकि उनका उत्पादन बढ़े और वितरण आसानी से किया जा सके।

माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए राष्ट्र की रेल कम्पनियों को रेल प्रशासन के नियन्त्रण में सौंप दिया गया और उसने सब

रेलो को मिलाकर एक राष्ट्रव्यापी रेल प्रणाली में परिणत करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया। इससे प्रशासन को छोटे-से-छोटे रास्ते से माल इधर-उधर भेजने की सुविधा हो गई और वह बिना किसी बाधा के इजनों और डिब्बों को जहाँ अधिक आवश्यकता होती वहाँ भेज सकता था और एक रेल के अन्तिम स्टेशनो का सभी रेले इस्तेमाल कर सकती थी। इस समन्वित और सगठित रेल कार्यक्रम का परिणाम यह हुआ कि 1916 में जहाँ एक रेल वैगन का औसत परिवहन 24.96 टन था वहाँ 1918 में वह 29.28 हो गया। सन् 1917 के प्रारम्भ में रेलों पर वैगनों की कमी थी, किन्तु वर्ष की समाप्ति तक उनके पास तीन लाख वैगन फालतू हो गए।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण को नियन्त्रित करने का कठिन काम हर्वर्ट हूवर के खाद्य प्रशासन के जिम्मे पड़ा। उसने कुछ जिन्सों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किये। खाद्य पदार्थों का राशनिंग करने के बजाय हूवर ने लोगों को अपने लिये प्रति सप्ताह या प्रति मास कुछ दिन गेहूँ और मॉस आदि के स्वेच्छया त्याग के लिए प्रोत्साहन दिया और दुर्लभ खाद्य पदार्थों की जगह दूसरे सुलभ खाद्य पदार्थ अपनाने की अपील की। कुछ विलासिता के खाद्य पदार्थों, जैसे शराब और मिठाई आदि, के उत्पादन को सोमित कर दिया गया।

युद्ध के दिनों में एक और नई बात हुई और वह यह थी कि सरकार के स्वामित्व में पहली बार कम्पनियाँ स्थापित हुईं। इसके दो मुख्य उदाहरण हैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेन कार्पोरेशन (संयुक्त राज्य अनाज कम्पनी), इमर्जेन्सी प्लैट कार्पोरेशन (आपातकालीन जहाजी कम्पनी)। किन्तु इन कम्पनियों का संगठन और संचालन प्राइवेट कम्पनियों की भाँति ही किया गया। अन्तर सिर्फ इतना ही था कि उनकी पूंजी सरकारी थी और उनका संचालन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करते थे। इन कम्पनियों की सफलता का परिणाम यह हुआ कि बड़ी मन्दी के दिनों में इसी तरह के सरकारी कार-बार और भी स्थापित हुए।

संयुक्त राज्य सरकार को प्रथम विश्वयुद्ध की कीमत करीब 24 अरब डालर चुकानी पड़ी। इसके अलावा करीब 9.5 अरब डालर उसने युद्ध के दिनों में मित्र देशों को ऋण के रूप में भी दिए। सन् 1914 से 1918 तक

सरकार का सामान्य खर्च कुल 3 37 अरब डालर हुआ। यह महत्त्व की बात है कि राष्ट्रीय ऋण (सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण) युद्ध से पूर्व के 1 अरब डालर के स्तर से बढ़कर 30 अगस्त, 1919 को 26 6 अरब डालर की चरम सीमा पर पहुँच गया।

युद्ध काल की असाधारण माँगों की सभावनाओं को देखकर कांग्रेस ने अक्टूबर, 1917 में एक रैवेन्यू ऐक्ट (राजस्व अधिनियम) पास कर दिया था। नये कानून ने सामान्य आयकर को 2 प्रतिशत से दुगुना यानी 4 प्रतिशत करके कर की आमदनी बढ़ा दी। यही नहीं, आयकर की दरों में भी आय की वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि कर दी गई जिससे उच्चतम आय वर्ग के लोगों को आमदनी का 68 प्रतिशत आयकर के रूप में दे देना पड़ता था। उत्पादन-कर और अतिरिक्त लाभ-कर में भी भारी वृद्धि कर दी गई। करो और आर्थिक गतिविधि, दोनों में वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि राज्य-कोष में सामान्य से 10 7 अरब डालर अधिक धन आया। लिवर्टी बाडो (स्वतन्त्रता बाडो) की विक्री से 21 अरब डालर और प्राप्त हुए।

ऊँचे करो और सरकारी नियन्त्रणों के बावजूद युद्ध काल में मूल्यों के आम सूचक अको में बराबर वृद्धि होती गई। सन् 1918 में सभी जिन्सों के थोक मूल्य 1913 के स्तर से 94 3 प्रतिशत ऊँचे थे। इसी अवधि में खाद्य पदार्थों के मूल्य 108 प्रतिशत और कारखानों में निर्मित वस्तुओं के मूल्य 98 4 प्रतिशत ऊँचे गए थे।

मूल्य-वृद्धि से कृषि और निर्माण उद्योग, दोनों को लाभ हुआ। कृषि-फार्मों के संचालकों और कृषि-जीवी श्रमिकों, दोनों की आय 1918 तक 25 प्रतिशत बढ़ गई। निर्माताओं को भी, खासकर सामरिक महत्त्व की वस्तुओं के निर्माताओं को, इससे लाभ हुआ।

युद्ध की समाप्ति तक औसत वार्षिक वेतन 1914 के स्तर से 63 प्रतिशत ऊँचे हो चुके थे। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि लोगों की क्रय शक्ति भी इसी हिसाब से बढ़ गई थी। वास्तव में औद्योगिक श्रमिकों की क्रय शक्ति तो 25 प्रतिशत घटी थी। सरकारी कर्मचारियों को भी नुकसान ही रहा था, क्योंकि उनके वेतन कानून से बढ़ते थे और उनमें बहुत कम वृद्धि की गई थी। इससे भी बुरी बात यह कि अनेक कर्मचारियों की आय अब कर-

मुक्त नहीं रही थी।

सम्भवतः सबसे अधिक नाटकीय युद्ध-कालीन आर्थिक परिवर्तन विदेशी व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में हुआ। संयुक्त राज्य के निर्यात का मूल्य 1914 में 23 अरब डालर था। किन्तु 1917 में वह बढ़कर 92 अरब डालर हो गया। दूसरी ओर उसके आयात में 1 अरब डालर से कुछ ही अधिक की वृद्धि हुई। सम् 1914 में वह 1.8 अरब डालर था, किन्तु 1917 में वह सिर्फ 2.9 अरब डालर ही हुआ। युद्ध के वर्षों में मित्र राष्ट्रों को अमेरिकन सामग्री की कीमत चुकाने के लिए 80 करोड़ डालर का सोना संयुक्त राज्य को देना पड़ा। इसी बीच विदेशों में लगी अमरीकी पूँजी भी 1914 के 35 अरब डालर के स्तर से बढ़कर 1919 में 69 अरब डालर तक पहुँच गई। इसी अवधि में अमेरिका में विद्यमान विदेशी परिसम्पत्ति 7.2 अरब डालर से घटकर 33 अरब डालर रह गई। यह पहला मौका था कि संयुक्त राज्य एक महत्वपूर्ण साहूकार (उत्तमर्ण) देश बन गया था।

नवम्बर, 1918 में विश्वयुद्ध की समाप्ति पर अमेरिकन जनता के मानसिक रुझान में परिवर्तन हो गया। युद्ध से पूर्व लोगों में समुद्र पार के प्रदेशों में पाँव फैलाने का जो आवेग था और जिस देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने मित्र राष्ट्रों के 'स्वतन्त्रता और विश्वशान्ति' के संघर्ष में महायत्ना दी थी—वे दोनों ही इस युद्ध में बहुत कुछ क्षीण हो गए थे। युद्ध समाप्त होते ही लोग 'फिर से सामान्य स्थिति की स्थापना' की कामना करने लगे। वे अब किसी भी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं थे और चाहते थे कि देश उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के पृथक्त्ववाद में फिर से लौट जाय।

इस अपसरण का एक कारण यह था कि लोग युद्ध में उठाई कठिनाइयों और कुर्वानियों को मन से भ्राष्ट्र-भोद्यकर फेंक देना और नई युद्धोत्तर कालीन समृद्धि का उपभोग करना चाहते थे। दूसरा कारण यह था कि युद्ध की समाप्ति के बाद जो शान्ति स्थापित हुई थी, उसने उनका भ्रम दूर कर दिया था। शान्ति-संधि सम्मेलन एक दुःखद छलना सिद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्रों को विल्सन के ऐसी शान्ति-संधि के प्रयत्नों में कोई उत्साह नहीं था, जिसमें पराजित शत्रु को दंड देने की कोई व्यवस्था न हो। इस प्रकार आधुनिक युद्ध

और समुद्र पार के देशों में व्यापार के लिए चल रही बड़े राष्ट्रों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं में अमेरिका ने पहली बार बड़े पैमाने पर नैतिक उत्साह से हस्तक्षेप किया और उससे जो विजय प्राप्त की वह लोकतन्त्र के लिए एक खोखली विजय सिद्ध हुई। अमेरिकन जनता का मन इससे तुरन्त कड़वाहट से भर गया और उसने यूरोप की समस्याओं की ओर से मुँह फेर लेना पसन्द किया।

राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिकन जनता में उत्तरदायित्व की भावना जगाने और राष्ट्र सघ (लीग ऑफ नेशन्स) के पक्ष में जनमत का समर्थन प्राप्त करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जनता विल्सन के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शवाद को और अधिक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। काफी कटु वाद-विवाद के बाद, जिसने सारे राष्ट्र में जनमत को भड़का दिया, सीनेट ने संयुक्त राज्य को लीग का सदस्य बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

सन् 1920 के चुनाव में विल्सन के नेतृत्व को लोगो ने ठुकरा दिया। यह स्पष्ट था कि रिपब्लिकन पार्टी ने वक्त की नब्ज को पहचान लिया था। उसने 'फिर से सामान्य स्थिति स्थापित करने' और 'पहले के समान कारवार करने' के नारों के साथ खूब आन्दोलन किया और उनके बल पर वह अपने उम्मीदवार वारेन हार्डिंग को बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्रपति के रूप में ह्वाइट हाउस में ले आई। इस प्रकार संयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीयवाद के एक युग पर पटाक्षेप हो गया और उसके साथ ही सरकारी हस्तक्षेप के युग पर भी यवनिकापात हो गया और यह यवनिका तब तक नहीं उठी, जब तक कि फ्रेकलिन ~~रूजवेल्ट~~ के 'पुनर्व्यवस्था प्रशासन' का सूत्रपात नहीं हुआ।

पुन. सामान्य स्थिति की ओर

युद्ध ने जो उखाड़-पछाड़ किये और उससे विश्व में जो व्यापक परिवर्तन हुए उनसे 'फिर सामान्य स्थिति' की ओर लौटना वास्तव में एक असम्भव स्वप्न-मात्र सिद्ध हुआ। कुछ समय तक ऐसा लगा कि यह स्वप्न अवश्य सत्य और साकार होगा, लेकिन घटनाओं के कदम जिस ढंग से और जिस दिशा में पड़ रहे थे, उनसे यह स्वप्न धीरे-धीरे विलीन होने लगा।

युद्ध काल में जो सैनिक संरचना स्थापित हुई थी और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशाल औद्योगिक ढाँचा खड़ा किया गया था, उसे बहुत द्रुत गति से शान्तिकालीन परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया। यद्यपि युद्धकालीन नियन्त्रणों के जल्दबाजी और हड़बड़ी में समाप्त किये जाने से कीमतों में एकदम बहुत वृद्धि हो गई, किन्तु सैन्य विघटन में प्रारम्भ में कोई खास कठिनाई और बाधा प्रतीत नहीं हुई और वह आशातीत सफलता के साथ चलता रहा। सघीय सरकार ने अपने व्यय में बहुत बड़ी कमी कर दी थी और लगभग चालीस लाख सैनिक हथियार छोड़कर फिर से औजार उठाने के लिए देश की श्रम-शक्ति में लौट आए थे, तो भी 1919 में पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रायः कोई कमी नहीं आई थी।

सन् 1920 में देश की 4.2 करोड़ की कुल श्रम-शक्ति में से सिर्फ 1.6 करोड़ व्यक्ति ही बेरोजगार थे। यह सख्या युद्ध से पूर्व की बेरोजगारी की औसत सख्या से काफी कम थी। किन्तु यह स्थिति किसी सुव्यवस्थित आयोजन का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक संयोग मात्र थी। रोजगार की यह स्थिति सिर्फ इसलिए सम्भव हुई कि सघीय सरकार के व्यय-कार्यक्रमों में कमी और कृषि-जिन्सों के अत्युत्पादन के दुष्प्रभाव बहुत हद तक असैनिक उद्योगों की नई अभिवृद्धि और यूरोप को किये जाने वाले निर्यात के बढ़ने से हल्के हो गए।

लेकिन दुर्भाग्य से युद्धोत्तर काल की प्रारम्भिक समृद्धि और खुशहाली

ऊषा की मिथ्या लाली थी। यह बात कृषि के क्षेत्र में और भी अधिक मत्य थी। युद्धकाल में सरकारी गारंटियो से व्यापार में जो तेजी आई थी और देश के भीतर और विदेशों में अन्न की जो कमी हो गई थी, उसने युद्ध के एकदम बाद कृषि-उत्पादन को असाधारण रूप से बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए 1917 में जितने रकबे में गेहूँ की खेती होती थी, 1919 में उससे 66 प्रतिशत अधिक रकबे में हुई। किसानों को अपनी उपज का जो मूल्य मिलता था, वह रहन-सहन के व्यय के अनुपात में अधिक था। इसलिए उनके पास जो फालतू धन बच रहता था उसे जमीनों के सट्टे और बन्धक-व्यापार में लगाने लगे और जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी। कृषि के यान्त्रिकीकरण ने उत्पादकता बहुत बढ़ा दी, किन्तु इससे किसानों के संचालन-व्यय भी बढ़ गए थे। इसलिए 1920 में जब यूरोप में कृषि फिर उभरी तो संयुक्त राज्य के किसान सकटापन्न स्थिति में पड़ गए।

सन् 1921 में कृषि-जिन्सों के मूल्यों में बहुत अधिक मन्दी आ गई और वे युद्धकाल के स्तर से 50 प्रतिशत ही रह गए। यद्यपि कृषि-संगठनों के नेताओं ने हमेशा की तरह फिर अपने उद्धार के लिए कांग्रेस का सहारा लिया और इसके लिए कांग्रेस की दोनों पार्टियों में कृषकों के पक्ष में प्रचार किया, तो भी उनका आन्दोलन बहुत कारगर नहीं हुआ। इस आन्दोलन के फलस्वरूप कुछ कानून बने अवश्य, परन्तु वे इस ढीले-ढाले और छुटपुट ढंग से बने कि किसानों की तकलीफ दूर करने में उनसे अधिक मदद नहीं मिली।

गाँवों के लोगों की क्रय-शक्ति कम हो जाने और युद्ध समाप्ति के बाद शुरू-शुरू में पैदा हुए वस्तुओं के अभाव की पूर्ति होने से 1920 में सामान्य आर्थिक गतिविधि मन्द होने लगी। सन् 1921 में वह और भी तेजी से गिरी जिससे करीब 50 लाख व्यक्ति बेरोज़गार हो गए और व्यापार ठप्प होने और दिवाले निकलने की घटनाएँ बढ़ने लगी। लेकिन कृषि-भिन्न व्यवसायों में 1921 को मन्दी बहुत स्वल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु इसलिए नहीं कि सरकार ने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कुछ विशेष कदम उठाये, बल्कि इसलिए कि संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था बुनियादी तौर पर स्वस्थ आरंभ कर रही थी।

युद्धोत्तरकाल में पुनः सामान्य स्थिति की स्थापना की आशा के मिथ्या

मिद्व होने का एक कारण यह भी था कि राष्ट्र ने विल्सन के उदार नेतृत्व को अस्वीकार कर हार्टिंग के अनुदार प्रशासन को अंगीकार कर लिया था। दुर्भाग्य से नए प्रशासन ने जिसका जनता ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया था, उसकी आजाओ और विन्यास को पूरा नहीं किया।

हार्टिंग प्रशासन के नए अनुदार रूढ़िवादी सब मिलाकर थ्योडोर रूजवेल्ट जैसे पिछली पीढ़ी के समादृत रूढ़िवादियों ने बिल्कुल भिन्न नज़र के थे। पिछली पीढ़ी के अनुदार पन्थी यह मानते थे कि जिसके हाथ में अधिकार और सत्ता है, उनके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। साथ ही वे अव्यवस्थित नीति (नेने फेयर) की ज्यादातियों के बारे में भी सजक थे और उन्हें दूर करने के लिए गम्भीरता से कृत सकृप थे। लेकिन नए युद्धोत्तर कालीन शासन में निरे राजनीतिक अवसरवादी भरे हुए थे।

हार्टिंग के जमाने में शासन में वैसा ही भ्रष्टाचार व्याप्त था जैसा कि गृह-युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के वर्षों में था। उन समय जो सबसे अधिक मनमनीयेश मामला जनता के सामने आया वह यह था कि स्वराष्ट्र मंत्री ने सरकार की तेल भंडार में भरी जमीनें प्राइवेट उद्योगपतियों को स्थान लेसर पट्टे पर दे दी थी।

उद्योग-व्यवसाय, श्रम, कृषि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, सभी क्षेत्रों में युद्ध ने कुछ नई पेचीदगियाँ और उलझने पैदा कर दी थी, जो आमानी से सुलझने वाली नहीं थी।

युद्धकालीन आयात-स्थिति में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप का विचार बहुत बढ़मूल हो गया था। सरकार ने जिन उद्योगों को अपने हाथ में लिया था, उनकी सफलता को देखकर कृषकों और श्रमिकों ने यह आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया कि युद्ध के बाद भी रेलों का संचालन सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने उन्हें पूर्णतः अपने नियन्त्रण में रखने के बजाय प्राइवेट कम्पनियों को लौटाकर सिर्फ़ उनको विनियमित करने का अपना अधिकार बढ़ा देना पसन्द किया। इसके साथ ही सरकार ने रेल-कम्पनियों को रेलों के संचालन में होने वाले नुकसान के लिए अतिरिक्त अनुपूर्ति (सन्सिडीज) भी दी।

रेल कम्पनियों और कुछ अन्य उद्योगों के नियमन का अर्थ यह नहीं था कि युद्ध से पहले के प्रगतिशील युग की स्थिति फिर लौट आई है। यद्यपि देश राजकीय हस्तक्षेप न करने की अवन्व नीति की ओर फिर से नहीं लौटा था और युद्ध से पूर्व कम्पनियों की गुट बनाने की प्रवृत्ति और उससे होने वाली हानियों को रोकने का कानून भी ज्यों के त्यों विद्यमान थे, तो भी यह बात जल्दी ही जाहिर हो गई कि युद्धकाल में सरकार अर्थ-व्यवस्था में जो हस्तक्षेप करती रही है, उसने वास्तव में व्यवसायी वर्ग और सरकार के बीच सम्पर्क और सम्बन्धों को अधिक सुदृढ़ बना दिया है। उद्योग-व्यवसाय पर कानून द्वारा लागू किये गए प्रतिबन्ध काफी शिथिल हो गए, क्योंकि इन कानूनों को लागू करने और उनकी व्याख्या करने का भार जिन नियामक कमीशनो, कम्पनी-गुट विरोधी कानून प्रतिपालक डिब्रीजन और अदालतों पर था, उनमें अधिकाधिक सख्या में ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी दिलचस्पी स्वयं उन हितों के पक्ष में हो गई थी, जिनके नियमन और नियन्त्रण का भार उन्हें सोपा गया था।

उद्योग-व्यवसायी वर्ग की शक्ति बढ़ जाने से श्रमिक मोर्चेपर भी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। युद्धकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने श्रमिकों और मालिकों, दोनों को सामूहिक सौदेबाजी के लिए

सफल प्रोत्साहन दिया था, किन्तु अब मालिकों को इस सम्बन्ध में सरकार के किसी निर्देश या प्रोत्साहन का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इसलिए जीवन-व्यय में वृद्धि के कारण श्रमिकों की तदनुकूल मजदूरी बढ़ाने की माग का वे दृढ़ता से मुकाबला करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1919 में कई हजार हड़ताले हुई, जिनमें 40 लाख से अधिक औद्योगिक श्रमिकों ने भाग लिया। किन्तु अधिकतर मामलों में उद्योगों के प्रबन्धकों ने श्रमिकों की माँगों के आगे झुकने बिना ये हड़तालें सफलतापूर्वक तोड़ दीं। मई 1920 के दशक में दश कर्मचारियों में एक स्थायी अनुदार ट्रेड यूनियनवादी प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु अर्द्ध कर्मचारी यूनियनों की सदस्यता से काफी नरका में हट गए और उनकी उन्नति भी कम हो गई।

कैल्विन कूलिज के राष्ट्रपतित्व काल के 'समृद्धि' के जमाने में भी किंग्स और श्रमिकों की हालत कमजोर थी, हालाँकि मोटे आँकड़ों को देखने में यह बात नहीं प्रतीत नहीं होती। इन आँकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय आय, दोनों में 25 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भी 13 प्रतिशत के करीब बढ़ी।

फिर भी यथार्थ स्थिति यही थी कि श्रमिकों और किसानों को समृद्धि का पूर्ण लाभ नहीं मिला था और यह बात उन आँकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चल जाती है। निर्माण-उद्योगों में 1923 और 1929 के बीच प्रति मानव घंटा उत्पादकता में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी,

1929 में शेयर बाजार के आकस्मिक और जबरदस्त ध्वस (क्रैश) के रूप में। कीमतें ऊँची हो जाने से कम्पनियों के शेयर भी ऊँची कीमतों में बिके। इस बिक्री से लोगों के हाथों में जो पैसा आया उसके दो परिणाम हुए। या तो उससे बाजार में ऐसी चीजों की बाढ़ आ गई, जिन्हें काफी लोग खरीद नहीं सकते थे, या उससे अन्य कम्पनियों के शेयरों का सट्टा होने लगा। सघीय आरक्षित निधि बोर्ड (फेडरल रिजर्व बोर्ड) की नीति के परिणामस्वरूप उधार और ऋण को प्रोत्साहन मिला और उससे लोगों के हाथों में सस्ती व्याज दरों पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ गया। इस पैसे से लोगों में शेयर खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ी और देखते-ही-देखते उनकी कीमतें उनके वास्तविक मूल्यों से कई गुनी बढ़ गई। बहुत कम लोगों ने इस अवाछनीय और अवास्तविक स्थिति और शेयरों की आन्तरिक कमजोरी की ओर ध्यान दिया। अन्त में 1929 में ऐसी स्थिति आ गई कि तेजी से उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए उद्योगों में माँग और उत्पादन लगभग बराबर हो गए और शेयर बाजार बुरी तरह टूट गया।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी युद्ध ने कुछ पेचीदा उलझने और अन्योन्य विरोध पैदा कर दिये थे। युद्धकाल में यूरोप के देशों को दी गई सामग्री और ऋणों के कारण संयुक्त राज्य एक अन्तर्राष्ट्रीय साहूकार देश बन गया था। यूरोपियन राष्ट्रों पर अमेरिका का 10 अरब डालर का युद्धकालीन ऋण चढ़ गया था और यह ऋण चुकाने की आशा वे तब तक नहीं कर सकते थे। जब तक कि संयुक्त राज्य उनके यहाँ अपनी पूँजी का निवेश न करे और उन्हें अमेरिका को अपना माल निर्यात करके डालरों की प्राप्ति न हो। इस स्थिति को अनुभव कर संयुक्त राज्य के प्राइवेट निवेशकों ने यूरोप के देशों में अपनी पूँजी का काफी निवेश किया भी, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यूरोप की युद्धध्वस्त अर्थ-व्यवस्था जैसे ही सँभलने लगेगी, वैसे ही उसकी सामान और सेवाओं की आवश्यकता बहुत बढ़ जाएगी। किन्तु यूरोप के अधिकतर देशों में लोगों की क्रय-शक्ति इतनी कम थी कि उनके लिए अपने अधिकांश उत्पादनों को निर्यात करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था।

किन्तु दुर्भाग्य से संयुक्त राज्य ने अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा

से सरक्षण देने के लिए तटकर बढ़ा कर यूरोपियन देशों के निर्यात के लिए अपने द्वार एक तरह से बन्द कर रखे थे। इन तटकरो का अमेरिका और यूरोप दोनों की अर्थ-व्यवस्थाओं पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अमेरिकन किसान की हालत और भी बदतर हो गई, क्योंकि यूरोप इन तटकरो के कारण अपने कारखानों में निर्मित सामान सयुक्त राज्य को निर्यात कर उसके बदले में अमेरिकन कृषि-जिन्से नहीं खरीद सकता था। इस स्थिति में यूरोप अपनी गेहूँ और रूई की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य देशों के बाजार टटोलने लगा।।

यूरोप की खरीद के अभाव में सयुक्त राज्य में कृषि उत्पादनों के भारी ढेर लगने लगे, क्योंकि अमेरिका में उनकी उतनी खपत नहीं थी। इसका स्वाभाविक परिणाम था मूल्यों में कमी। किसान इससे एक और मुसीबत में भी फँस गया। वह मुसीबत यह थी कि उसे अपना उत्पादन तो खुले बाजार में कम कीमतों पर बेचना पड़ता था, लेकिन अपनी आवश्यकता की चीजें उसे यूरोप से आयात के अभाव में एक प्रकार से सीमित और सरक्षण प्राप्त बाजार से खरीदनी पड़ती थी।

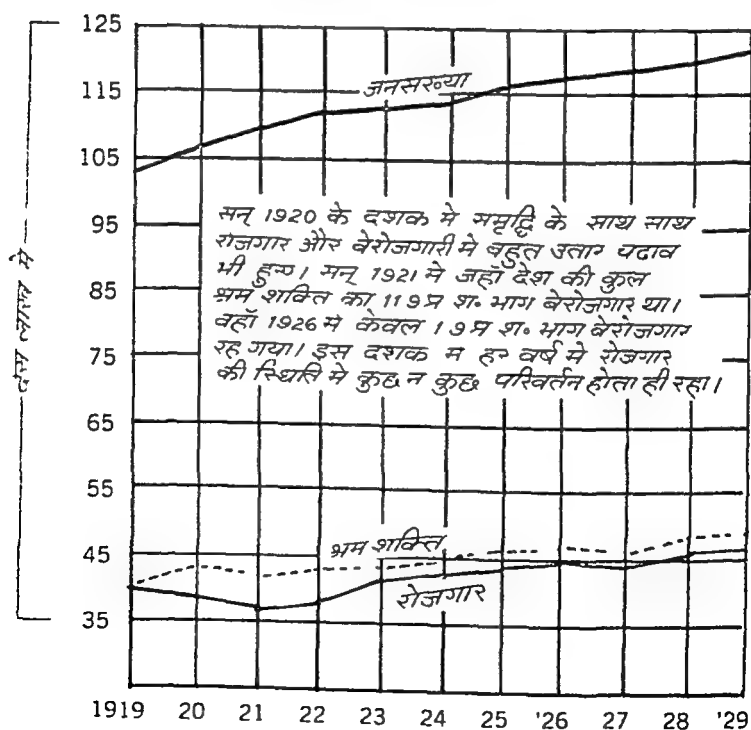
ऊँचे सयुक्त राज्यीय तटकरो के परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और भी गम्भीर थे। यूरोप के युद्ध-ध्वस्त और दरिद्रता-ग्रस्त देशों में सयुक्त राज्य के ऋणों को चुकाने की सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए धीरे-धीरे अनिच्छा से सयुक्त राज्य को इस ऋण का एक हिस्सा स्वयं ही छोड़कर बढ़ेछाते डाल देना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका के ऊँचे तटकरो के कारण यूरोप के भी अनेक देशों ने अपने यहाँ तटकरो की दरे ऊँची कर दी। अन्ततः इसका नतीजा यह हुआ कि सयुक्त राज्य के विदेशी व्यापार के सब स्रोत सूख गए, जबकि उस समय उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

सक्षेप में यह कहा जाता है कि 'पुन सामान्य स्थिति' स्थापित करने की आकांक्षा ऐसी अनेक उलझनों और विरोधात्मक गुत्थियों में फँस गई, जिनके परिणाम किमी भी दशा में महासंकट से कम नहीं थे। जस्टिस ब्रैडीज़ का यह कहना बिल्कुल सही था कि "यूरोप युद्ध से ध्वस्त हुआ और हम उसके परिणामों से।"

फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपनी अर्थ-

व्यवस्था में इतनी मंदी और ह्रास आ जानेपर भी अमेरिकन समाज भविष्य के लिए आशान्वित था। सन् 1920 के दशक में ऐसी बहुत-सी आर्थिक उपलब्धियाँ थी, जिन्होंने उत्पादन के और देश की जनता के भीतर उस की खपत के स्तर को एक नये ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया था। अन्य अनेक देशों की तुलना में संयुक्त राज्य में आर्थिक गति-विवि और उन्नति के अवसर और सामाजिक गतिशीलता का स्तर अधिक ऊँचा और लचीला था। अधिकतर बाहरी समार अमेरिका की सफलताओं और उपलब्धियों की प्रशंसा करता था।

संयुक्त राज्य की जनसंख्या, श्रम-शक्ति और रोज़गार की स्थिति, 19-1929



वास्तव मे 1920 का दशक एक 'लाभकारी विडम्बनाओं' का युग था। जिस पुराने जमाने को याद करके लोग तरसते थे, उसे फिर से लौटा लाने के बजाय उसने एक सर्वथा नवीन युग के लिए द्वार खोल दिया। आज हमारे सामने जो अत्यधिक जटिल आर्थिक समस्याएँ हैं, उनकी नींव इस दशक मे ही पड रही थी। ये समस्याएँ हैं—नई तकनीकी विधियों के आविष्कार से कुछ लोगो का अस्थायी तौर पर स्वल्पकाल के लिए बेरो-जगागार हो जाना, उपनगरो की स्थापना और उसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रो की स्थिति मे ह्रास, मूल्यो के स्तर का बराबर ऊँचा चढते जाना, और निरन्तर बढ रही जनसख्या के लिए देश के उपलब्ध साधनो का यथा-सम्भव समुचित उपयोग।

तब प्रश्न यह उठता है कि जब हम 1920 के इस दशक का सिंहावलोकन करते हैं, और यह दशक हमारे वर्तमान दशक से बहुत दूर भी नहीं है, तो हमे वह इतना विचित्र क्यों लगता है? इसका उत्तर यह हो सकता है कि 'आश्चर्यजनक विचित्र वेहूदगियों' का यह युग—एक अन्य सम-कालीन प्रेक्षक के शब्दो मे, 'पुरानी व्यवस्था का पतभड' था।

शेयर बाज़ार टूटा

सन् 1929 में शेयर बाज़ार में हुए जवर्दस्त ध्वंस और 1930 के दशक की जवर्दस्त मन्दी, दोनों ने अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था को इतने जोर के झटके से झकझोरा कि उसका कम्पन अभी तक विद्यमान है। शेयर बाज़ार को लगा झटका इतना जवर्दस्त और आकस्मिक था कि लोग चकित रह गए और सहसा उसपर विश्वास ही नहीं कर सके। अमेरिकन लोगो का आम खयाल यह था कि वे समृद्धि के विशाल शान्त सागर पर विहार कर रहे हैं। किन्तु एकाएक उनकी नैया तूफानी सागर को चचल लहरों के थपेड़े से गरीबी और मन्दी की कठोर चट्टान से जा टकराई। यह तूफान एकाएक कैसे आ गया ?

सन् 1920 के दशक में संयुक्त राज्य का अपनी अर्थ-व्यवस्था के प्रति निश्चिन्तता का जो भाव था, वह उतना मूर्खतापूर्ण नहीं था, जितना कि आज सिंहावलोकन करते हुए प्रथम दृष्टि में लग सकता है। उस दशक में व्यापार-व्यवसाय के उत्कर्ष को देखते हुए आशावादी होना किसी भी तरह स्वाभाविक नहीं था। इसमें सन्देह नहीं कि 1921 में कुछ मन्दी आई थी और 1924 में और उसके बाद 1927 में वृद्धि की गति मन्द हुई थी, परन्तु हर बार अर्थ-व्यवस्था मन्दी और शिथिलता से उबरकर ऊपर आ गई थी। इसलिए लोगो का यह समझना अस्वाभाविक नहीं था कि मन्दी के ये हल्के झोके प्रकृति की तेज धारा में उठने वाली लहरों से अधिक नहीं हैं। यही कारण है कि बहुत-से लोगो ने विश्व-युद्ध के बाद अर्थ-व्यवस्था में हुए इन तीन समझनों को काफी चिन्ताहीन और निरुद्दिग्न दृष्टि से देखा।

सन् 1929 तक, सघीय आरक्षित निधि (रिजर्व) के सूचक अंको के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन 1922 के स्तर से लगभग 50 प्रतिशत ऊँचा था। सन् 1923 से 1926 तक निर्माण-उद्योगों में नई मशीनरी और सयन्त्र लगाने पर औसतन दो अरब डालर प्रति वर्ष व्यय किया जाता रहा। इस अवधि

मे एक तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति थी और यही नहीं, कारखानों में काम के साप्ताहिक घंटों में भी कुछ कमी हो गई थी ।

इन प्रभावोत्पादक आँकड़ों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कुछ तकनीकी आविष्कार और नवीन प्रक्रियाएँ विद्यमान थी । निर्माण की कुछ नई विधियों का आविष्कार होने और शक्ति (पावर), परिवहन और संचार के साधनों में सुधार से नये पूँजी-निवेश और आर्थिक अभिवृद्धि की एक लहर आ गई । उद्योग-विद्या और तकनीक की क्रांति के साथ-साथ अमेरिका में और अमेरिकन जनता की जीवन-पद्धति में कुछ स्पष्ट और असाधारण परिवर्तन हुए ।

किस्तों पर खरीद और बिक्री की पद्धति ने मोटर कार और अन्य टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं की माँग पैदा कर दी । देश में सड़कों के जाल का तेजी से विस्तार हो रहा था और शहर सड़कों के जरिये गाँवों और ऐसे मनोरम और स्वास्थ्यवर्धक स्थानों से जुड़ते जा रहे थे, जहाँ लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते थे । गहरों से मुहल्ले के मुहल्ले उठकर उपनगरों में जा रहे थे ।

असेम्बली लाइन पद्धति (कारखानों में एक के बाद एक पुर्जों को जोड़-जोड़कर और उन्हें आगे बढ़ाते हुए सामान तैयार करने की 'संयोजन श्रृंखला' की प्रणाली) और बड़े पैमाने पर सामूहिक बिक्री की प्रणाली अधिकाधिक किस्मों की उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में इस्तेमाल की जाने लगी । इस्पात, रबर और काँच आदि बुनियादी और सहायक उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री का तेजी से विस्तार होने लगा । सन् 1923 से 1929 तक बिजली का उत्पादन दुगुना हो गया । सन् 1920 के दशक में रेडियो या अन्य सामूहिक प्रचार साधनों के जरिये वस्तुओं का विज्ञापन अपने-आपमें एक अरब डालर वार्षिक का विशाल उद्योग बन गया । उत्पादकों में टैकनीशियनों, व्यवसाय अधिकारियों और विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे धन्ये चलाने वालों के नये मध्यवर्ग की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति की होड़ लग गई ।

किन्तु इसके बावजूद देश का आर्थिक चित्र सत्र मिलाकर किनी भी कदर आकर्षक नहीं था । सन् 1920 के दशक में समृद्धि के बीच ही मंदी

और आर्थिक शिथिलता के बीज अंकुरित होने लगे थे। किसान उस समय भी सुदूरव्यापी मन्दी और शिथिलता के भँवर में फँसे हुए थे, हालाँकि उनमें से बहुतों ने नये यन्त्रों और मशीनों के लिए पैसा उधार ले लिया था। उनकी दुर्दशा में बीच-बीच में कभी-कभी कोई छोटा-मोटा कानून बन जाने से कुछ राहत मिल जाती थी। दक्षिणी राज्य गरीबी और अभावग्रस्तता के शिकार थे और यही हाल विदेशों से आए आवासियों से आवाद नई गन्दी शहरी वस्तियों का था। इस दशक में उत्पादकता में जो भारी वृद्धि हुई थी, उसके लाभ में से वेतन-भोगियों को समुचित हिस्सा नहीं मिला था। आज के स्तर के अनुसार उस समय राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत असमान ढंग से हो रहा था, इसलिए मोटरकारों, मकानों, घरेलू उपयोग के यन्त्रों और अन्य टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं के व्यापार में जो तेजी आई थी, उसका आधार बहुत छोटा जन-समुदाय था।

लोगों को सस्ती व्याज-दर पर धन उपलब्ध कराने की नीतियों का परिणाम यह हुआ कि लोग इस सस्ते सुलभ धन के लोभ से खूब कर्जदार हो गए और कर्ज में लिये हुए पैसे को सट्टे-फाटके में लगाने लगे। यद्यपि अधिकाधिक शेयरों की विक्री के कारण कम्पनियों में खूब पैसा आ रहा था, किन्तु तो भी कम्पनियों का यह ढाँचा, बुनियादी तौर पर भीतर से पोला और कच्चा था। नये उभर रहे उद्योगों की सुरक्षा का आधार सिर्फ यही था कि उन्हें उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति का एक व्यापक सहारा प्राप्त था। लेकिन मजदूरियों और वेतनों में वृद्धि इतनी नहीं हो रही थी कि वेतन-भोगियों और श्रमिकों को उपभोग्य वस्तुओं की खरीद के लिए अधिक गुंजायश मिल सके। उद्योगों के संचालकों की प्रवृत्ति यह थी कि मजदूरियाँ और वेतन बढ़ाए नहीं जाएँ और उससे कम्पनियों को जो बचत हो उसे फिर से दूसरी कम्पनियों में ही निवेश कर दिया जाय।

इसका परिणाम यह हुआ कि शेयरों में धन का निवेश तो बहुत अधिक हो गया, किन्तु उत्पादित वस्तुओं की खपत और विक्री में अनुपात की दृष्टि से कमी रह जाने के कारण उन (शेयरों) की असली कीमत कम हो गई। विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-व्यवस्था के दोषपूर्ण होने और बुनियादी जिनसों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अस्थिरता रहने से कम्पनियों का पहले से ही

अमन्तुलित ढाँचा और भी कमजोर होने लगा ।

परन्तु इन सब पेचीदा घटनाओं के लिए कोई एक वर्ग ही पूर्णतः जिम्मेदार नहीं था । उदाहरण के लिए, मधीय आरक्षित निधि बोर्ड (फेडरल रिजर्व बोर्ड) को इस बात के लिए दोषी ठहराया जाता है कि उसने 1920 के दशक में मस्ती दरो पर लोगों को धन उपलब्ध कराने की नीति अपना कर मट्टे-फाटके की प्रवृत्ति को बेलगाम कर दिया । यद्यपि यह कहा जाता है कि बोर्ड चाहता तो वित्तीय कारबार करने वाली नस्थाओं पर कुछ नैतिक दबाव डाल सकता था, परन्तु वास्तविकता यह है कि आज उसे शेयर बाजार को नियन्त्रित और विनियमित करने के जो अधिकार प्राप्त हैं, वे उसे उस समय प्राप्त ही नहीं थे । बोर्ड को उस समय अनुसूचित बैंको से यह कहने का भी अधिकार नहीं था कि वे अपनी जमा रकमों का अधिक भाग आरक्षित निधि के रूप में अपने पास ही रखें, ऋण के रूप में लोगों को न दें । कानून से बैंको के लिए जमा रकमों का कुछ 13 प्रतिशत ही आरक्षित निधि के रूप में रखना अनिवार्य था । (आज मधीय आरक्षित निधि बोर्ड बैंको को अपनी जमा रकमों की 26 प्रतिशत तक राशि आरक्षित निधि के रूप में रखने के लिए मजबूर कर सकता है ।)

आज मिहावलोकन करते हुए यह कहना बहुत आसान है कि उस समय राजनीतिक नेताओं ने ऐसे महत्त्वपूर्ण और कठोर निश्चय लिये नहीं कर डाले, जो राष्ट्र को उस आर्थिक महाविपत्ति से बचा सकते, जो बाद में उस पर आ पड़ी । यस्तुस्थिति यह है कि उस समय नयुक्त राज्ज जिन महानुत्तम समृद्धि का उपभोग कर रहा था, उसे देखते हुए मुद्रा की अवस्फीति की वकालत करने के लिए बड़े नाहन और अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता थी ।

सामना करना पड़े"—उन्होंने दूसरे विकल्प को ही पसन्द किया क्योंकि वे तात्कालिक विध्वंस से होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे।

किन्तु सब मिलाकर देश की आर्थिक प्रणाली में जनता का बड़ा गहरा विश्वास था, क्योंकि उसे अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धान्तों का कतई ज्ञान नहीं था। सट्टे-फाटके को लोग एक सम्मानित धन्धे के रूप में देखते थे। कम्पनियों के अध्यक्षों से लेकर दफ्तरों के छोकरो तक हर आदमी शेयरों के भावों पर नजर रखता था कि कैसे वह अच्छी चल रही कम्पनियों के शेयर खरीद या बेचकर आनन-फानन में अमीर बन जाय। वास्तव में इस उत्कर्ष के प्रारम्भिक दिनों में कुछ साधारण कम्पनियों के शेयर उनके वास्तविक मूल्य से भी नीचे थे, पर शेयरों की खरीद का ज्वर जैसे ही देश पर हावी हुआ, उन्हीं के मूल्य कल्पनातीत ऊँचाई पर पहुँच गए।

स्थावर सम्पत्ति का सट्टा-फाटका भी इसी तरह अन्धाधुन्ध चल रहा था। सन् 1920 के दशक में फ्लोरिडा पयटन की दृष्टि से बहुत ही लोकप्रिय हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ जमीनों की कीमतें चढ़कर आसमान से जा लगी। हालाँकि 1926 में फ्लोरिडा के जमीन के धन्धे में बुरी तरह गिरावट आ गई थी, किन्तु फिर भी लोगों की आँखें नहीं खुली और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में अन्धाधुन्ध सट्टा-फाटका करने की प्रवृत्ति पर कोई रोक नहीं लगी।

सन् 1926 और 1929 के बीच शेयरों की कीमतें दुगुनी हो गईं। सन् 1929 की 15 अक्टूबर को एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने घोषणा की कि शेयरों की कीमतें जिस ऊँचे स्तर पर पहुँच गई हैं, वह अब स्थायी रहेगा। लेकिन उसी दिन शेयर बाजार में आसतन हर शेयर में दस अंश (मूल्य की मुद्रा इकाई) गिरावट आ गई। यही चीज अगले दिन हुई। अगले सप्ताह फिर पिछले सप्ताह की भाँति शेयर बाजार की स्थिरता का विश्वास प्रकट किया गया। लेकिन 23 अक्टूबर को फिर शेयर बाजार में हर शेयर में औसतन 50 अंश की कमी आ गई। और अगले दिन यानी 24 अक्टूबर, 1929 को, जिसे अमेरिका के आर्थिक इतिहास में 'काला गुरुवार' कहा जाता है, शेयर बाजार एकदम उखड़ गया और एक ही दिन में 1 करोड़ 30 लाख

शेयर इस हाथ से उम हाथ गए। शेयरों की कीमतें उस दिन उतनी गिरी कि वाल-स्ट्रीट के उत्तिहाम में पहले कभी नहीं गिरी थी। इन वित्तीय सकट की चरम सीमा 29 अक्टूबर को आई, जबकि 1 करोड़ 65 लाख शेयर और बाजार में विक्री के लिए भोंक दिये गए। धनी बनने की अनि-रजित आशाओं का बुलबुला अन्न में फूट ही गया।

यह वित्तीय सकट 1932 तक चलता रहा, क्योंकि शेयरों की कीमतें गिरने पर सट्टा करने वालों में दलानों की मार्जिन की मांग बढ़ती गई। (जब कोई व्यक्ति नकद पना दिये बिना, मार्जिन यानी नॉदे की सम्भावित क्षति को पूरा करने के वचन पर, कुछ शेयर बरीदता है तो उसे उन शेयरों में से कुछ उस मार्जिन की जमानत के रूप में दलाल के पास रखने पड़ते हैं। अगर उस शेयरों की कीमत गिरती है तो मार्जिन की जमानत (कोलेटरल) के रूप में रखे गए शेयरों की कीमत भी गिर जाती है और उस मार्जिन के नुकसान की पूर्ति शेयर को बेचकर की जाती है।)

ग्रीष्म ऋतु से गिरने लगा था। सात वर्ष तक निरन्तर भवन-निर्माण में वृद्धि और यान्त्रिक माधन-सामग्री और निर्माण-उद्योगों के चरम उत्कर्ष के बाद यह गिरावट का रुझान आया था। उस समय तक जो वास्तविक माँग थी उसके एक बड़े भाग की पूर्ति हो चुकी थी। इसलिए भी कुछ गिरावट और शिथिलता आना स्वाभाविक था।

किन्तु 1929 और 1932 के बीच बहुत-सी ऐसी ताकतें काम करती रही, जिन्होंने अर्थ-व्यवस्था को नीचे गिराने की कोशिश की। यही वजह है कि अर्थ-व्यवस्था को माँस लेने के लिए सीधा खड़े होने का अवसर आसानी से नहीं मिला। राष्ट्रीय आय इस अवधि में सिकुड़कर आधी से भी कम रह गई और बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख तक पहुँच गई। फर्मों के पास इतनी भी शक्ति नहीं रही कि वे अपनी पूँजी पर सामान्य मूल्य ह्रास विधि (डेप्रिसियेशन) का अंश अपने लाभ में से काट कर निकाल सकें। इसलिए 1932 में नया वास्तविक पूँजी निर्माण जरा भी नहीं हुआ, बल्कि मूल्य ह्रास विधि में धन जमा न किये जाने से सामान्यतः जितना पूँजी-निर्माण होना चाहिए था, वह भी नहीं हो सका। दूसरे शब्दों में पूँजीगत सामग्री की उपलब्धि कई अरब डालर कम हो गई।

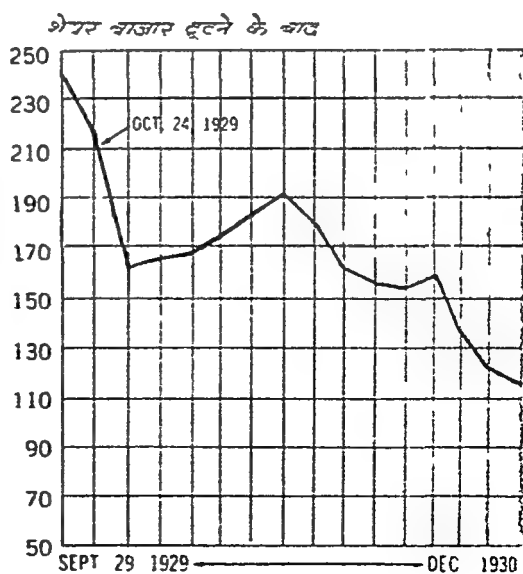
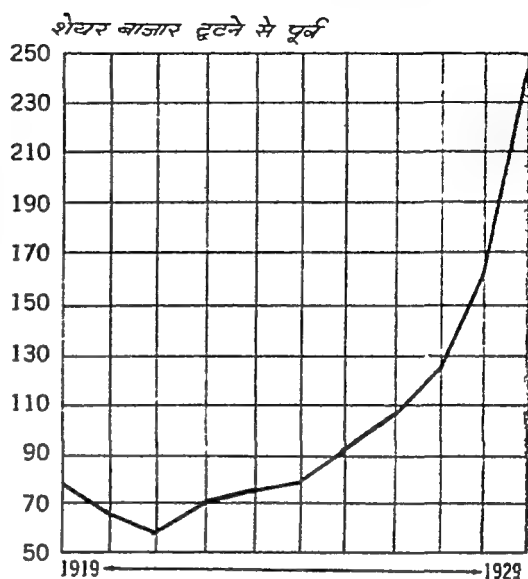
विश्व व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त उपलब्धि में गिरावट आ जाने से संयुक्त राज्य में मंदी का प्रारम्भिक दौर और भी उग्र हो गया। यूरोप प्रथम विश्वयुद्ध के ध्वंस से अभी तक उबर नहीं सका था और जब अमेरिका ने विदेशों को ऋण देने में कमी की, तो ब्रिटेन को भी मजबूरन वैसा ही करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी और आस्ट्रिया के बैंकों का सारा ढाँचा ही बैठ गया। यूरोप में आई इस मंदी की अमेरिका पर फिर प्रतिक्रिया हुई और यूरोप को संयुक्त राज्य का निर्यात घट गया। अमेरिका के वित्तीय संकट और अमेरिकी ऋण के अभाव के कारण डालरों की कमी हो जाने से न तो युद्ध-जर्जर यूरोप और न ही सदा कमजोर रहने वाले कच्चे माल के उत्पादक देश संयुक्त राज्य से अपना आयात का प्रवाह जारी रख सके।

ये सब घटनाएँ मोटे तौर पर एकसाथ ही, ऐसे ज़माने में हुईं, जब कि लोगों की आर्थिक अन्तर्दृष्टि कमजोर थी और साहसी सार्वजनिक नीति

अपनाने की इच्छा का अभाव था। एक स्वस्थ आदमी को अगर एक समय में एक ही रोग घेरे तो वह उस पर विजय पा सकता है, किंतु अगर एक साथ उमे बहुत-से रोग आ घेरे तो वह उनसे पार नहीं पा सकेगा और वे उसे धराशायी कर देगे। ठीक उसी तरह अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों ने मिलकर एक साथ अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को आ घेरा और उसी का परिणाम था कि वह 1929 के बाद आनेवाली भयंकर मंदी से अपने आपको बचा नहीं सकी।

यह विचित्र बात है कि 1920 का दशक समाप्त होने पर आमतौर पर सभी की यह राय थी कि 'मूलतः परिस्थितियाँ अच्छी' ही हैं। लोग कहते थे कि यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो देश की समृद्धि फिर

सामान्य शेयरों के मूल्यों के सूचक अंक 1935-39=100



लौट आएगी। जब यह जाहिर हो गया कि मन्दी उससे अधिक गम्भीर है जितनी कि प्रारम्भ में समझी जाती थी, तब भी लोग यही विश्वास प्रकट करते थे कि अर्थ-व्यवस्था का पुनरुद्धार होगा जरूर, चाहे उसमें कुछ विलम्ब हो जाय। लेकिन उनका कहना था कि अर्थ-व्यवस्था में किसी तरह की तबदीली या छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वैसा करने का अर्थ और भी अधिक सकट को आमन्त्रण देना होगा।

आज जब हम उन बीते दिनों पर दृष्टिपात करते हैं तब यह समझ पाना मुश्किल होता है कि मन्दी से हुए इतने भारी आर्थिक विनाश के बावजूद लोगों में इतना विश्वास क्यों था। किन्तु 1930 में आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। आर्थिक विश्लेषण के लिए जिन आँकड़ों की आवश्यकता थी, वे गलत और अपूर्ण थे। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर नीति निर्धारण की पद्धति काफी समय बाद अपनाई गई।

उस समय आर्थिक जानकारी का अभाव तो था ही, साथ ही आज जो वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी नीतियाँ हैं उनका भी उस समय कोई ज्ञान नहीं था। सन् 1932 में दोनों राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक ही वायदा करते थे कि वे वजट को सन्तुलित कर देंगे। उस समय दोनों ही दल स्वर्ण-मान के परित्याग और घाटे की वित्त-व्यवस्था की कल्पना से भी घबराते थे।

सन् 1930 के दशक में और उसके बाद बहुत-से ऐसे सुधार किये गए जिनसे मालूम होता था कि हमने 1920 के दशक से कुछ सबक लिये हैं। आज हमें बैंकिंग प्रणाली, कम्पनियों की रचना, उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के बारे में उस समय की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ज्ञान है।

लेकिन इसके बावजूद आज हम यह सोचकर निश्चिन्त नहीं हो सकते कि 1920 के दशक में लोगों ने अन्वायुन्व मट्टा-फाटका करने का जो पागल-पन किया था, वह फिर कभी नहीं होगा। कोई भी जिम्मेदार प्रेक्षक आज यह दावा नहीं कर सकता कि व्यापार में होने वाले तमाम उतार-चढ़ाव को

हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सिर्फ इतनी ही आशा की जा सकती है कि सही नीति का आश्रय लेकर इस उतार-चढ़ाव को एक सीमित दायरे के भीतर रखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में अधिक विश्वास कायम रख सकेंगे।

मन्दी के प्रारम्भिक वर्ष

यद्यपि अमेरिका में आई भारी मन्दी के राजनीतिक और आर्थिक परिणामों के बारे में आज भी लोगों की रायें अलग-अलग हैं तो भी इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि यह मन्दी अमेरिका के आर्थिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ थी। जिन ताकतों ने 1873 और 1893 की लम्बी मन्दियों के समय अर्थ-व्यवस्था का पुनरुद्धार किया था, वे अब सक्रिय नहीं थी और इस तथ्य को हृदयगम करने और उसके अनुसार अपने-आपको ढालने में लोगों को समय लगा और इस प्रक्रिया में उन्हें कष्ट भी उठाना पड़ा। गृह-युद्ध के बाद किसी भी अन्य आन्तरिक संकट ने अमेरिका के जीवन को इतना नहीं झकझोरा था।

सन् 1929 में शेयर बाजार के एकाएक टूटने के बाद दस वर्ष, यानी दूसरे विश्व-युद्ध के प्रारम्भ तक संयुक्त राज्य को आर्थिक जड़ता और गति-हीनता की एक लम्बी अवधि में से गुजरना पड़ा। इतनी लम्बी मन्दी इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी। सन् 1930 और 1940 के बीच सिर्फ 1937 का वर्ष ही ऐसा था जिसमें बेरोजगारी 80 लाख से नीचे गई। सन् 1933 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख मजदूर बेरोजगार थे, और पाँच वर्ष बाद भी देश की 20 प्रतिशत जन-शक्ति बेरोजगारी का शिकार थी।

मन्दी के प्रारम्भिक वर्षों में हुए आर्थिक ह्रास को और भी अनेक तरीकों से नापा जा सकता है। सन् 1929 और 1932 के बीच औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में 47 प्रतिशत की, कृषि-जिन्सों के मूल्यों में 54 प्रतिशत की और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 28 प्रतिशत की गिरावट आई। इन वर्षों में टिकाऊ उपभोग्य सामग्री के उत्पादन में 77 प्रतिशत की, व्यवसाय और उद्योगों द्वारा पूंजीगत सामग्री की खरीद में 79 प्रतिशत की और औद्योगिक और व्यापारिक भवन-निर्माण में 82 प्रतिशत की कमी आई।

सन् 1932 तक 85 हजार व्यावसायिक कंपनियों के दिवाले निकले।

यद्यपि कुछ बड़े उद्योग, जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का केन्द्रीकरण था, अपने उत्पादन को घटी हुई माँग के अनुसार कम करके, अपने मूल्य-स्तर को कायम रख सके, तो भी सब मिलाकर कम्पनियों के मुनाफों में बहुत कमी हो गई। सन् 1932 में कम्पनियों का कुल घाटा 3 अरब डॉलर था।

राष्ट्र के बैंक भी मुसीबत में थे, क्योंकि उनकी परिमम्पत्तियों का 25 प्रतिशत भाग सिक्क्योरिटियो (गेयर और सरकारी हुडी आदि) पर और 10 प्रतिशत भाग स्थावर सम्पत्ति पर ऋण के रूप में लगा हुआ था। जब सिक्क्योरिटियो और स्थावर सम्पत्ति दोनों के बाजारों में गिरावट आई (सन् 1931 तक न्यूयार्क के गेयर बाजार में सिक्क्योरिटियो के भाव 50 प्रतिशत से अधिक गिर गए थे), तो बैंक लडखड़ा गए। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की कठिनाइयों के कारण बड़ी मात्रा में मोना देय से बाहर गया, जिससे कुछ और नई दिक्कतें पैदा हो गईं। दूसरी ओर बैंकों में अपना रुपया निकालने के लिए आतंकग्रस्त खातेदारों ने भी हफ्ला बोल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बैंकों के फेल होने की घटनाओं की एक के बाद एक तीन भयंकर लहरें आईं।

उद्योग-व्यवसाय में धन का निवेश करने के अवसर और पूँजी के स्रोत दोनों ही बहुत कम हो गए। सरकार ने कोशिश की कि बैंक राष्ट्रीय आरक्षित निधि में अधिकाधिक ऋण लेकर आगे लोगों को उद्योग-व्यवसाय में निवेश के लिए दे, और इसके लिए उनसे व्याज की दर कम कर दी और बैंकों पर अपनी परि-सम्पत्ति की जो न्यूनतम मात्रा राष्ट्रीय आरक्षित निधि में रखने की पाबन्दी थी, उसमें भी कमी की। लेकिन इन सब प्रयत्नों के बावजूद बैंकों के ऋण 1929 के 36 अरब डॉलर के स्तर से गिरकर 1932 में 22 अरब डॉलर पर आ गए।

चुका नहीं सके ।

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार में भारी कमी आई । उदाहरण के लिए 1929 में 46 लाख मोटरो का उत्पादन हुआ था, किन्तु 1932 में कुल 11 लाख मोटरे ही तैयार हुई । परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक शहरों में बेरोजगारी खास तौर से बहुत उग्र हो गई । एक समय ऐसा आया, जब कि डोनोरा, पेनसिलवेनिया में 13,900 श्रमिकों में से कुल 277 ही ऐसे थे, जो नियमित रूप से काम पर लगे हुए थे । यद्यपि 1929 और 1932 के बीच वास्तविक मजदूरी में कुल 10 से 12 प्रतिशत तक कमी आई, तो भी इससे मजदूरों के कष्टों में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि बेरोजगार मजदूरों की संख्या की तुलना में रोजगार पर लगे मजदूरों की संख्या अत्यन्त नगण्य थी ।

इस संकट के सामाजिक परिणाम और भी कई गुने भयंकर थे, क्योंकि राष्ट्र की संस्थाएँ इस विपत्ति को सम्भालने के लिए कतई तैयार नहीं थी । आय में कमी होने से राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं के राजस्व में भी गिरावट आ गई । मिसाल के तौर पर एटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी की अदालतों ने दीवानी मुकदमों में स्थगित कर दिए क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए जूरी के सदस्यों को देने के लिए उनके पास धन नहीं था । कुछ शहरों की नगरपालिकाएँ नकद धन के अभाव में अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में कूपन या बाड आदि देने लगी । लॉस एंजेलिस की नगरपालिका ने तो आर्थिक कठिनाई के कारण अपना चिडियाघर ही नीलाम कर दिया । सबसे अधिक गम्भीर दुष्प्रभाव शिक्षा पर पड़ा, क्योंकि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ स्कूलों के सत्र छोटे कर दिये और रोड आइलैंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने अध्यापकों के वेतन घटा दिए ।

बेरोजगार लोगों के परिवारों को राहत और सहायता देने की क्षमता न सरकारी संगठनों में थी और न गैर-सरकारी संगठनों में । न्यूयार्क और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर कहीं भी राज्यीय स्तर पर इन लोगों को सहायता नहीं दी गई । डिट्रॉइट शहर की नगरपालिका ने बेरोजगारी में सहायता पाने वालों को मदद देने के लिए मोटर कंपनियों से पैसा उधार लिया और इस उधार से भी वह हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुल पाँच सेट ही सहायता दे सकती थी । गैरी, इंडियाना में बीस हजार परिवारों को नगर-

पालिका ने खाद्य सामग्री पैदा करने के लिए सहायता के रूप में जमीने दी। सन् 1932 में 100 से अधिक गृह ऐसे थे जिनके पास गरजमन्द लोगो को आर्थिक सहायता देने को कुछ भी नहीं था।

एक ओर मन्दी की भयकरता और दूसरी ओर जनता के कष्ट को दूर करने के लिए सुविधाओं की अपर्याप्तता, दोनों ने मिलकर अमेरिकन जनता के व्यक्तिगत जीवनो पर व्यापक प्रभाव डाला। सन् 1929 और 1932 के बीच विवाहों की संख्या में 30 प्रतिशत की गिरावट आ गई और जन्म-दर भी 19 बच्चे प्रति हजार व्यक्ति से घटकर 17 4 बच्चे प्रति हजार व्यक्ति रह गई। डबल रोटी के लिए लम्बी-लम्बी कतारे लगने लगे और जगह-जगह मुफ्त शेरवा लेने के लिए लोगो की भीड़ नजर आने लगी।

समाजशास्त्री रॉबर्ट और हेलेन लिण्ड ने अपनी 'मिडिल टाउन इन ट्रान्जिशन' नामक पुस्तक में एक औसत दर्जे के अमेरिकन नगर की जनता पर मन्दी के प्रारम्भिक वर्षों के प्रभाव का विशद वर्णन किया है और इस प्रभाव के अध्ययन के लिए यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है "मन्दी के जवर्दस्त और तेज चाकू ने अमीर-गरीब के भेद-भाव के बिना निष्पक्ष होकर राष्ट्र की सारी जनता को ही चीर डाला और उनके जीवन और आशाओं को विदीर्ण कर दिया, 'नगर के इतिहास में हाल के किसी भी लम्बे भावनात्मक अनुभव ने इतना सर्वव्यापी प्रभाव नहीं डाला था, जितना इस मन्दी ने डाला। इसका प्रभाव जन्म और मृत्यु के समय की व्यथाओं के समान ही पीडादायक था।"

आर्थिक गिरावट और जड़ता ने सरकार के प्रति जनता के रुख को भी बहुत बदला। इस परिवर्तन की झलक उस जमाने के अनुदार विचार-धारा के महत्वपूर्ण प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से मिल जाती है। सन् 1929 में इन प्रवक्ताओं ने यह अनुभव नहीं किया था कि यह मन्दी इतनी विनाशकारी होगी। उदाहरण के लिए उस समय 'न्यूयार्क टाइम्स' ने लिखा था कि इस मन्दी के 'इलाज के बुनियादी नुस्खे' बहुत आसान हैं, जैसे कि— "वचन करना, छुटनी करना, विवेक से काम लेना और अच्छे दिनों की आशापूर्वक प्रतीक्षा करना।"

एक इम्पान कम्पनी के उच्च अधिकारी चार्ल्स श्वैब ने कहा था, -

“मुस्कराते रहो और वेफिक्री से काम किये जाओ।” कोप-मन्त्री एण्ड्र्यू मैलन ने कहा कि ‘दिवाला और अवस्फीति का क्रूर चक्र’ तो चलता ही रहता है। सन् 1930 मे राष्ट्रीय निर्माता सघ (नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स) के अध्यक्ष ने कहा था कि ‘अपराध’ ही आज की राष्ट्र की मुख्य समस्या है।

किन्तु जैसे-जैसे मन्दी उग्र से उग्रतर होती गई, वैसे-वैसे ‘प्रवन्ध नीति’ और अर्थशास्त्र के ‘प्राकृतिक नियमों’ मे लोगो का विश्वास कुछ-कुछ विलीन होने लगा। व्यवसायी वर्ग सरकार की ओर महायता की, याचना की, दृष्टि से अधिकाधिक निहारने लगा। अब श्वैव ने यह स्वीकार किया कि “मैं डर रहा हूँ। बल्कि हर आदमी डर रहा है। मैं नहीं जानता, बल्कि हममे से कोई भी नहीं जानता कि आज जो कीमतें हैं, वे अगले मास वास्तविक कीमतें रहेगी या नहीं।”

अनेक उद्योगपतियो ने इसके हल मुझाए, किन्तु व्यवहार मे उन सबका अर्थ यह था कि कम्पनियों के गुट-निर्माण के विरुद्ध बनाये गए कानून कुछ समय के लिए स्थगित कर दिये जाएँ। स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी (न्यूजर्सी) के अध्यक्ष वाल्टर टीगल ने यह मत प्रकट किया कि उद्योगपतियो को थोड़े-से उपलब्ध बाजारो के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहने के बजाय कार्यक्रमो को सभावित माँग के अनुसार ढालने के लिए सहयोग से एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। बर्नार्ड बारुच ने, जो प्रख्यात वित्त विगेषज्ञ होने के साथ-साथ अनेक राष्ट्रपतियो के सलाहकार रह चुके थे, एव जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के अध्यक्ष गेराड स्वोप ने उद्योग-व्यवसाय के ‘योजना-बद्ध’ संचालन की सलाह दी। नवम्बर, 1931 मे राष्ट्रपति हूवर ने शिकायत के स्वर मे घोषणा की कि व्यवसायी-जगत् ने हार मान ली है और अब हाथ ऊपर उठाकर मर-कार को महायता के लिए पुकार रहा है।

इमलिए हूवर ने मन्दी के दबाव और सकट को हल्का करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया, उसे इन घटनाओ की रोगनी मे ही परखा जाना चाहिए। मन्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे राष्ट्रपति ने कहा था—“इस देश का उद्योग-व्यवसाय बुनियादी तौर पर, यानी वस्तुओ के उत्पादन और वितरण की दृष्टि से, एक सुदृढ और समृद्ध आधार पर प्रतिष्ठित है।” उनका यह कथन

अमेरिका के अधिकतर बड़े व्यवसायियों और राजनीतिक नेताओं के विचारों को ही प्रतिध्वनित करता था।

अन्य अनेक राजनीतिक नेताओं की भाँति राष्ट्रपति का भी यह विश्वास था कि यदि सरकार समाज के आर्थिक जीवन में सीधा हस्तक्षेप करे तो एक स्वतन्त्र समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उनका मत था कि यदि मजदूरी को उसके बाजार के स्तर तक गिरने दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है और गम्भीर मन्दी और अवस्फीति के बाद भी देश की अर्थ-व्यवस्था फिर से सभलकर उठ खड़ी होगी।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रपति स्थिति की गम्भीरता और कठोरता को हल्का करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालने वाले कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं थे। राष्ट्रपति ने सघीय आरक्षित निधि बोर्ड को ऋण देने की नीति को अधिक उदार और सरल बनाने और किसानों को सघीय सरकार के राजकोष से ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पुनर्निर्माण वित्त निगम (रिकन्स्ट्रक्शन फाइनेंस कार्पोरेशन) की स्थापना कराई, जिसका काम सकट ग्रस्त बैंकों और उद्योगों को सघीय सरकार से ऋण दिखाना था। यह निगम अपने ढंग की एक नई सस्था समझा जाता था। सन् 1930 के प्रारम्भ में हूवर की मिफारिशों पर कांग्रेस ने 6 करोड़ डालर बोल्टर बाँध बनाने के लिए, 75 करोड़ डालर सड़कों के निर्माण के लिए, 50 करोड़ डालर सर्वाजनिक निर्माण कार्यों के लिए और 15 करोड़ डालर नदी और बन्दरगाह परियोजनाओं के लिए स्वीकार किये।

किन्तु राष्ट्रपति ने किसी को भी व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सकट निवारण के लिए सघीय सरकार के कोश से ऋण देना अस्वीकार कर दिया। उसे वे सैद्धान्तिक रूप से अनुचित समझते थे। उन्होंने लोगों को बेरोजगारी का मुआवजा या फसलों के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए सरकारी सहायता देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनका खयाल था कि इससे लोगों की व्यक्तिगत साहस और अभिक्रम की भावना नष्ट होगी, जो अमेरिकन विचारधारा की बुनियाद है।

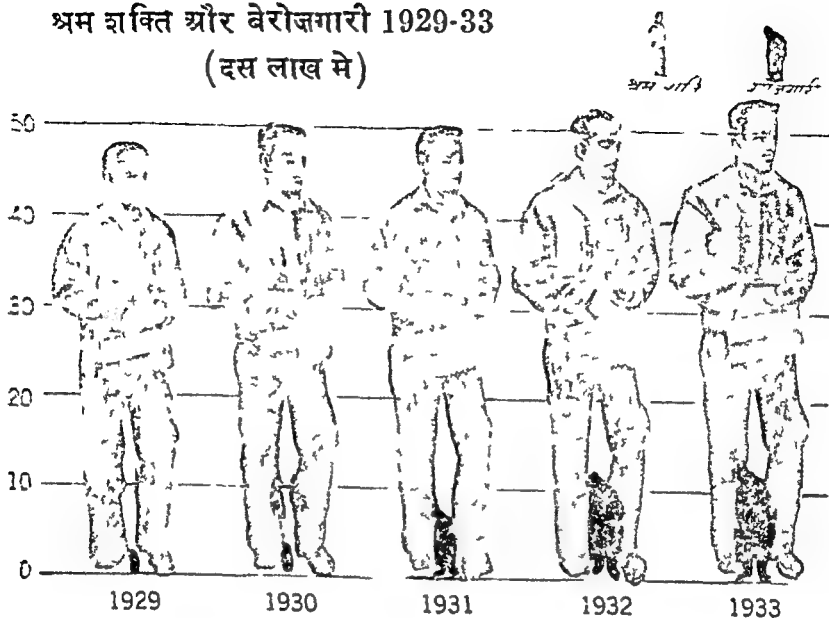
यद्यपि राष्ट्रपति हूवर के इन विचारों की गम्भीरता में मन्देह नहीं किया जा सकता, तो भी इन विचारों के आधार पर वह जो कदम उठाने थे, उन्हें

समझ पाना सकट-ग्रस्त जनता के लिए कभी-कभी कठिन हो जाता था। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में सूखा पड़ने पर हूवर ने अपने सिद्धान्त को इस हद तक त्यागना तो स्वीकार कर लिया कि किसानों को सघीय राजकोष से सहायता दी जाय, किन्तु वह सहायता सिर्फ पशुओं के चारे और फमलो के लिए बीज के रूप में ही थी। स्वयं किसानों को कोई सीधी सहायता नहीं दी गई। इसके लिए राष्ट्रपति की बड़ी कटु आलोचनाएँ की गईं। लोगो ने कहा कि राष्ट्रपति के दिल में भूखो मरते खच्चरो और टट्टुओं के लिए तो दर्द है, परन्तु भूख से तड़पते और विलखते मानवों को रोटी देना वे अपना नैतिक उत्तरदायित्व नहीं समझते।

हूवर ने 1932 की गर्मियों में जब 'बोनस एक्सपीडिशनरी फोर्म' (बोनस अभियानकारी दल) को टका-सा जवाब देकर टरका दिया, तब भी इसी तरह की आलोचनाएँ हुईं। दरअसल, बोनस एक्सपीडिशनरी फोर्स नाम प्रथम विश्वयुद्ध के उन भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया था, जो मन्दी के आर्थिक सकट से पीड़ित होकर दल बाँधकर वाशिंगटन में आए थे और यह माँग कर रहे थे कि लड़ाई के पुरस्कार के रूप में उन्हें दिये गए बोनस सर्टिफिकेटों का भुगतान 1945 की निर्धारित अवधि से पूर्व ही, तत्काल कर दिया जाय ताकि वे आर्थिक सकट से मुक्ति पा सकें। हालाँकि इन लोगो की सर्टिफिकेटों के नियत अवधि से पूर्व तत्काल भुगतान की माँग अस्वीकार कर दिये जाने का आम तौर पर समर्थन किया गया, तो भी जनता में ऐसे बहुत-से लोग थे जिनकी सहानुभूति इन भूतपूर्व सैनिकों के साथ थी। इन सैनिकों में से बहुत-से ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और जिन्हें नितान्त गरीबी में दिन काटने पड़ रहे थे। इसलिए जब हूवर ने इन गरीब भूतपूर्व सैनिकों के दल को तितर-बितर करने के लिए सेना को आदेश दिया तो जनता को बहुत आघात लगा।

हूवर ने निष्ठुर प्रतीत होने वाला यह रुख इसलिए नहीं अपनाया था कि उनके मन में इन गरीबों के लिए सहानुभूति का भाव नहीं था। बल्कि इसका कारण यह था कि वे अपने सिद्धान्त पर कट्टरता से अटल थे। उनका यह विश्वास था कि यदि लोगो को सीधी सहायता दी गई तो उससे व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व की परम्परागत अमेरिकन अवधारणाओं को

श्रम शक्ति और बेरोजगारी 1929-33 (दस लाख में)



चोट पहुँचेगी और जनता एक दूरवर्ती नौकरशाही की वशवर्ती हो जाएगी। वे लोगो को ऋण देने की बात तो स्वीकार कर सकते थे, किन्तु मुफ्त सहायता देना नहीं। सीधी सहायता उनकी राय में अमेरिकन जनता की आध्यात्मिक अनुक्रियाओं को क्षति पहुँचाने वाली थी।

हूवर के आलोचको का कहना था कि वे इस सत्य को पूरी तरह समझ नहीं सके कि लोगो के लिए स्वाधीनता का तभी कुछ अर्थ हो सकता है, जब कि उन्हें कुछ सुरक्षा भी मिले। उनके आलोचको की एक शिकायत यह भी थी कि वे (हूवर) यह स्वीकार नहीं करते कि एक औद्योगिक समाज में पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एक भ्रम है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एक सीमा तक ही हो सकती है। यही कारण है कि वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को यथार्थ बनाने की सरकार की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते। वे एक ऐसी दुनिया का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका पुनर्निर्माण और पुनरुज्जीवन हो नहीं सकता।

किन्तु ये सब आलोचनाएँ हूवर के साथ न्याय नहीं करती। हूवर के कामो को उस जमाने के प्रसंग में ही कसौटी पर कसा जाना चाहिए। मन्दी

के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रपति हूवर ही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी जिनमें रूजवेल्ट भी शामिल थे, देश की आर्थिक प्रणाली में किसी तरह की तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो हूवर की यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और वजट को सन्तुलित नहीं किया।

आज दोनों मुख्य राजनीतिक दल यह स्वीकार करते हैं कि मन्दी को रोकने का उपाय अवस्फीति (डिफ्लेशन) को अपनी चाल चलने देना नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाय कि अवस्फीति को अपने ढंग से चलते रहने देकर अन्ततः मन्दी का इलाज किया जा सकता है, तो भी वह मानवीय दृष्टि से बहुत महंगा होगा। इसके अलावा अवस्फीति का बहुत देर तक चलते रहना आर्थिक दृष्टि से अवाछनीय और राजनीतिक दृष्टि से अव्यावहारिक भी है। लेकिन यह विचार आज हम उस जमाने का सिंहावलोकन करते हुए ही प्रकट कर सकते हैं। उस समय के लोगो का तत्कालीन परिस्थितियों में यह विचार नहीं था। मन्दी के काले और अन्धकारपूर्ण वर्ष जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे स्थिति को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाना कठिन था। उस समय तक कोई भी यह नहीं जान सकता था कि अमेरिकन समाज के विकास का एक युग समाप्त हो गया है।

किन्तु अमेरिकन जनता ने 1932 में राष्ट्रपति पद के अगले चुनाव के आगे तक यह अच्छी तरह जान लिया था कि उस समय तक मन्दी के सकट को हल्का करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। वह एक नए प्रशासन के लिए, नई नीतियों के लिए उत्सुक और व्याकुल थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जब अपने चुनाव आन्दोलन में यह वचन दिया कि वे 'अमेरिकन जनता के लिए एक नई नीति' का निर्माण करेंगे तो लोगो को नई आशा की एक किरण दिखाई दी। यह नई नीति (न्यू डील) क्या होगी, यह चुनाव आन्दोलन के भाषणों में स्पष्ट नहीं किया गया, किन्तु 'नई नीति' शब्द ही जनता को आश्वासन देने के लिए पर्याप्त थे। रूजवेल्ट ने करीब दो-तिहाई मत प्राप्त करके चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त की।

अगले वर्षों में हूवर द्वारा चुनाव आन्दोलन में दिये गए इस वक्तव्य की यथार्थता असाधारण और कल्पनातीत रूप में सिद्ध कर दी कि "अर्थ-

व्यवस्था में अधिकाधिक सरकारी हस्तक्षेप के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव अमेरिकन जीवन-पद्धति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे यह चुनाव महज एक दल को हटाकर दूसरे दल का मत्तारूढ़ होना ही नहीं है। इस चुनाव का अर्थ है अगली एक शताब्दी के लिए राष्ट्र की प्रगति की नई दिशा निर्धारित करना।”

नई नीति



मैं आपके साथ और स्वयं अपने निज के साथ यह वायदा करता हूँ कि मैं अमेरिकन जनता को एक नई नीति प्रदान करूँगा।

—फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट
(मार्च 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए दिये गए भाषण का एक अंश)

नई नीति के अन्तर्गत प्रशमन मन्दी का मुकाबला करने के लिए अपनी समूची ताकत लगाने को तैयार था, इसलिए लोकतन्त्रीय पूँजीवाद और उसकी नये युग की जटिल समस्याओं का सामना करने की क्षमता में अमेरिकन जनता का विश्वास फिर जम गया। यह बात सही है कि नई नीति ने अर्थ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मन्दी के दुष्प्रभाव की कठोरता को कुछ हल्का कर दिया था, किन्तु अगर पूर्ण रोजगार को ही आर्थिक स्वास्थ्य की कसौटी मानकर चले, तो वह 1930 के दशक के आर्थिक संकट को हल करने में असफल रही थी। कारण, 1939 में भी संयुक्त राज्य में 94 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

यद्यपि फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट के प्रशमक और आलोचक दोनों ही थे, और दोनों ही उसके पक्ष और विपक्ष की बातें करते थे, किन्तु वास्तविकता

यह है कि रूजवेल्ट और उनकी सरकार की न कोई निश्चित सैद्धान्तिक विचारधारा थी और न कार्यक्रम। वे दोनों राजनीतिक व्यवहारवादी थे और जब जो समस्या सामने आती उसे तत्कालीन प्रयोजनों के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से निबटाते। जिन समस्याओं ने नई नीति को जन्म दिया, उनके बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं को दो मुख्य कालों में बाँटा जा सकता है—(1) नई नीति का प्रारम्भिक काल जब कि आर्थिक पुनरुद्धार पर मुख्यतः जोर दिया जाता था, और (2) सन् 1934 के आखिरी महीनों से प्रारम्भ होने वाला दूसरा काल जिसमें व्यापक समाज-कल्याण सम्बन्धी कानून बनाये गए।

नई नीति सम्बन्धी ये अवधारणाएँ धीरे-धीरे नहीं बनीं और न उनके पीछे कोई निश्चित योजना ही थी। एक इतिहास के शब्दों में “जो व्यक्ति नई नीति को एक सूत्र में बंधी शृंखलावद्ध नीति के रूप में या दूरगामी और दूरदर्शी नीति के रूप में देखने की आशा करता है, वह उसे कभी समझ नहीं सकेगा। यह वास्तव में कुछ कृत्रिम रूप से निर्धारित नीतियों की शृंखला है, इनमें से कुछ नीतियाँ बिल्कुल अचानक ही निर्धारित हुईं और कुछ परस्पर विरोधी भी थी। इस नीतियों में यदि ऐक्य और सामंजस्य था भी तो वह अर्थशास्त्रीय सामंजस्य नहीं था, बल्कि आर्थिक रणमंच पर रणनीति का ऐक्य और सामंजस्य था।”¹

नई नीति के प्रारम्भिक काल में टैनेसी घाटी प्रशासन की स्थापना को छोड़कर और किसी भी काम में सरकार ने अपने कोश में व्यय करने पर बल नहीं दिया—न सामान्य व्यावसायिक गतिविधिता और मन्दी की क्षतिपूर्ति के लिए और न व्यापक समाज कल्याण के लिए। इसके विपरीत सरकार ने इस प्रारम्भिक काल में देश के लड़खड़ाते वित्तीय ढाँचे को सुधारने और उसमें स्थिरता लाने, मकटग्रस्त कर्जदारों और बेरोजगारों को मदद देने और सरकारी कोश से अधिक धन खर्च किये बिना आर्थिक पुनरुद्धार करने के लिए प्रयत्न किया।

1 अमेरिकन पोलिटिकल डेज़िज़न रिचर्ड होल्ब्रूक, न्यूयार्क, 1948।

कांग्रेस ने डमर्जेन्सी बैंकिंग ऐक्ट (आयात कालीन बैंकिंग कानून) पास कर देश की लडखडाती बैंकिंग प्रणाली को वित्तीय स्थिरता प्रदान की। इस कानून से एक मधीय जमाखाता बीमा निगम की स्थापना की गई और यह व्यवस्था की गई कि बैंको के पास 5,000 डालर तक के जितने भी जमाखाते हों, उन सबका खातेदारों की सुरक्षा के लिए डम निगम में बीमा कराया जाय (मन् 1950 में यह सीमा बढ़ाकर 10,000 डालर कर दी गई)। इस कानून में बैंको के व्यापारिक और निवेश सम्बन्धी कारवार अलग-अलग करने की भी व्यवस्था थी। 1934 में सिक्जोरिटीज एक्मचेज ऐक्ट (सिक्जोरिटी विनिमय कानून) पाम किया गया। इस कानून ने एक अर्थन्यायिक गेयर एव विनिमय कमीशन की स्थापना की जिनका उद्देश्य वाल-स्ट्रीट के गेयर बाजार में 1929 में आए जबरदस्त विध्वंस की-सी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना था। इसके बाद 1935 में बैंकिंग ऐक्ट पाम किया गया, जिसने मधीय आरक्षित निधि बोर्ड के अधिकारों का काफी विस्तार कर दिया।

सरकार ने सफ्टग्रस्त कर्जदारों की सहायता का काम दो सरकारी संस्थाओं को सौंपा। इनमें से एक थी पुनर्निर्माण वित्त निगम, जिसकी स्थापना हूवर के प्रणामन ने की थी। यह निगम बड़ी वित्तीय और व्यावसायिक कंपनियों को ऋण देता था। दूसरी संस्था फार्म क्रेडिट एमोसियेशन (कृषि ऋण संघ) थी, जो सफ्टग्रस्त किसानों को ऋण देती थी। कांग्रेस ने मुसीबतजदा किसानों की मदद के लिए 'फ्रेजियर-लेमके ऐक्ट' के रूप में एक कानून और भी पास किया, जिसमें किसानों को अपनी जमीन-जायदाद बन्धक रखकर लिये गए कर्जों की अदायगी के लिए तीन साल की और मोहलत देने की सुविधा की व्यवस्था थी।

यद्यपि रूजवेल्ट के प्रशासन में बेरोजगार लोगों को पिछले प्रशासन की अपेक्षा अधिक सहायता दी गई, तो भी नई नीति के प्रारम्भिक काल में इसके लिए कोई व्यापक दीर्घकालीन कार्यक्रम नहीं बनाया गया, क्योंकि प्रशासन को यह आशा थी कि मन्दी में देश बैसे ही जल्दी उभर आएगा। सार्वजनिक निर्माण प्रणामन और असेनिक निर्माण प्रणामन को छोड़कर बाकी जितनी भी सहायता परियोजनाएँ अपनाई गई, वे सभी हूवर के जमाने की भाँति राज्यों और नगरों के प्रणामनों के जरिये दी गई अप्रत्यक्ष सहायता के रूप

मे ही अपनाई गई। उपर्युक्त दोनों मधीय कार्यक्रमों में से भी असैनिक निर्माण प्रशासन अधिक समय तक नहीं टिका।

सार्वजनिक निर्माण प्रशासन के लिए कांग्रेस ने 33 अरब डालर की मजूरी दी थी। इस राशि ने उसने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएँ प्रारम्भ की—कुछ परियोजनाएँ अन्य मधीय या राज्यीय मगठनों के जरिये और कुछ प्राइवेट ठेकेदारों के जरिये। सन् 1933 से 1939 तक सार्वजनिक निर्माण प्रशासन ने कितनी ही छोटी-बड़ी मडके बनवाई, जलोपलब्धि और मल-निकासी परियोजनाएँ क्रियान्वित कराई, गैस और बिजली के कारखाने बनवाये, स्कूल, अदालत, अस्पताल और जेल आदि के भवन बनवाए, मिचाई और बाढ़ नियन्त्रण के काम कराये तथा पुल, जहाजघाट और मुरग आदि का निर्माण कराया।

किन्तु सार्वजनिक निर्माण प्रशासन को लोगों को काम देने से पूर्व हर परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी पड़ती थी। इससे लोगों को रोजगार मिलने में देरी हो जाती थी, जबकि बेरोजगारी की समस्या इतनी विकट थी कि उमकातकाल समाधान जरूरी था। इसलिए असैनिक निर्माण प्रशासन के रूप में एक अन्य विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने जनवरी, 1934 में चार लाख परियोजनाओं पर चालीस लाख व्यक्तियों को काम पर लगा रखा था। इनमें से कुछ परियोजनाएँ ऐसी थी, जिनकी विस्तृतरूपरेखा अभियंत्रण में नैय र नहीं की जा सकी थी, इसलिए ये परियोजनाएँ दरअसल सिर्फ लोगों को रोजगार देने की योजना मात्र थी।

नई नीति के प्रारम्भिक काल में मूल्य वृद्धि—दूनरे शब्दों में मुद्रास्फीति—को प्रोत्साहन देने का परीक्षण भी किया गया, क्योंकि सरकार की यह धारणा थी कि इससे अवस्फीति, बेरोजगारी और मन्दी का दुश्चक्र टूट सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकतर कर्जदार लोगों ने डालर के अवमूल्यन की कार्रवाइयों का स्वागत किया और पश्चिम के उन राज्यों ने भी, जहाँ चाँदी की खानें हैं, उमका समर्थन किया। सरकार इस दिशा में जो कार्रवाइयाँ कर रही थी, उसकी अन्तिम परिणति जनवरी, 1934 में हुई जब कि सरकार ने डालर का अवमूल्यन कर उसकी कीमत उसके पिछले सरकारी स्वर्णमूल्य का 69 06 प्रतिशत कर दी। इसके बाद सरकार ने

डालर की कीमत और गिराना उचित नहीं ममभा ।

नई नीति के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये गए, उनमें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कदम यह था कि सरकार औद्योगिक उत्पादन और कृषि-जिनसों का वाकायदा योजनापूर्वक कृत्रिम अभाव पैदा करने लगी । इसके लिए कांग्रेस ने नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी ऐक्ट (राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार कानून) और एग्रीकल्चरल ऐडजस्टमेंट ऐक्ट (कृषि समजन कानून) पास किया ।

कृषि समजन कानून फार्म व्यूरो फेडरेशन और नेशनल ग्रेज के धनी कृषक सदस्यों के दबाव का परिणाम था । इस कानून में कुछ फसलों के उत्पादन को जान-बूझकर कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसान उन फसलों का उत्पादन नहीं करेंगे तो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार पैसा देगी । इस कानून को लेकर सारे देश में एक जवर्दस्त बहस छिड़ गई और लोग उसके औचित्य और उसकी प्रभावकारिता पर सन्देह प्रकट करने लगे ।

राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार कानून को लेकर भी देश में काफी वाद-विवाद खड़ा हो गया, हालांकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उसे 'अमेरिकन कांग्रेस द्वारा उस समय तक पास किया गया सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कानून' कहा था । यह कानून एक तरह से सरकार द्वारा स्थापित कार्टल प्रणाली (उत्पादन और मूल्यों को परस्पर समझौते से नियन्त्रित करने के लिए उत्पादक सब बनाने की प्रणाली) था । सरकार उसके अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादकों की एक-दूसरे का गला काटने की आपसी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और उत्पादन को नियन्त्रित कर केवल वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादन करने पर जोर देती थी । इसमें यह भी व्यवस्था थी कि जो कारखाने इस कानून के अन्तर्गत निर्धारित आचार-नियमों को पालन करना स्वीकार करेंगे, उनके मजदूरों को सरकार एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी । इस कानून के खंड 7-ए में पहली बार मजदूरों को अपना संगठन बनाने और मालिक के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार की गारंटी दी गई थी । यह खंड इसलिए रखा गया था ताकि मजदूरों का भी इस कानून के लिए समर्थन प्राप्त हो जाय ।

उत्पादको ने देश भर में लोगो की क्रय शक्ति बढ़ने की सम्भावना से उत्पादन बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि कारखानों में अधिकाधिक लोगो को रोजगार मिलने लगा। जून, 1933 में कारखानों में रोजगार का सूचक अंक 71.6 था, जो इसी वर्ष सितम्बर में 85.0 पर पहुँच गया (सूचक अंक का आधार 1923-25=100)। किन्तु सब मिलाकर देखा जाय तो राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार कानून देश की अर्थ-व्यवस्था में कोई नई क्रय शक्ति नहीं पैदा कर सका। सन् 1935 में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को असाविधानिक ठहरा दिया।

सन् 1934 के प्रारम्भ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के तमाम भाषणों में एक ही बात पर जोर दिया जाता था, जिसका सार यह था कि सरकार देश के सभी बड़े हितों में एकता, सामंजस्य और समायोजन करने वाली सस्था है और वह स्वयं (रूजवेल्ट) एक विशाल और विविधतापूर्ण देश के बहुविध हितों के बीच सम्पर्क कायम करने वाला प्रमुख दलाल है।

किन्तु सन् 1934 में नई नीति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। पहले जहाँ सरकार वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करके अर्थ-व्यवस्था का पुनरुद्धार करने और विभिन्न हितों के बीच सम्पर्क और सामंजस्य के लिए दलाल के रूप में काम करने की नीति पर चल रही थी, वहाँ उसने अब व्यापक जन-कल्याण के लिए सघीय कानून पास कराने की नीति अपना ली। यह नीति-परिवर्तन क्यों हुआ, यह पूरी तरह से कहना मुश्किल है। सन् 1934 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस पर भारी बहुमत से अधिकार कर लिया था, किन्तु यही इस नीति-परिवर्तन का पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार कानून और कृषि समज कानून अपने उद्देश्य में असफल हो गए थे, लेकिन यह अमफलता भी नीति में इस परिवर्तन की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सकती। इसलिए नई नीति का दूसरा काल प्रारम्भ होने के कारण कुछ अन्य ही थे।

नई नीति के शुरू के नाजुक महीनों में उद्योगपति, श्रमिक, किमान और सरकार—इन सबने मिलकर आपस में एक अनौपचारिक गठबन्धन कर लिया था। लेकिन यह गठबन्धन जल्दी ही टूटने लगा, और पाँच साल की अनवरत मन्दी के बाद अन्त में वह विलकुल ही छिन्न-भिन्न हो गया।

अगस्त, 1934 में नई नीति का प्रबल विरोध करनेवाली एक संस्था 'अमेरिकन लिबर्टी लीग' उठ खड़ी हुई, और वित्तीय और औद्योगिक समाज के शक्तिशाली वर्गों और अखबारों ने उसका समर्थन प्रारम्भ कर दिया।

अत्यधिक आर्थिक सकट और कठिनाई ने सुधारको और आन्दोलन-कारियों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। ह्यूई लॉग ने राष्ट्र की सम्पत्ति का समुचित वितरण करने की सव्जवाग दिखाने वाली योजना पेश की, फ्रांसिस टाउनसेंड ने बेरोजगार और अन्य सकटग्रस्त लोगों को पेन्शन देने की अव्यावहारिक योजना बनाई और फादर चार्ल्स कफ्लिन ने भी अभावग्रस्त लोगों के साथ विशेष व्यवहार की अपील की। इन सबने ही नहीं और भी अनेक वर्गों ने रूजवेल्ट के प्रशासन पर कड़ी चोटे की। ये आलोचनाएँ नई नीति के संचालकों के, जो पहले से ही परेशान थे, शरीर में काँटे की तरह गड़ रही थी।

नई नीति के अन्तर्गत निर्मित महत्वपूर्ण कानून

- (1) कृषि समजन कानून (1933) इस कानून के द्वारा कृषि जिन्सों के उत्पादन को नियन्त्रित कर उनके मूल्यों पर अकुश लगाया गया। किसानों ने कुछ फसलों की खेती कम कर दी, और सरकार ने उन्हें इसके लिए मुआवजा दिया। यद्यपि 1936 में यह कानून अवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो भी उसकी मुख्य-मुख्य बातें 1938 में दूसरे कृषि-समजन कानून में शामिल कर ली गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुकूल स्वीकार कर लिया।
- (2) टैनेसी घाटी प्रशासन (1933) कांग्रेस ने टैनेसी नदी की घाटी के साधनों का विकास करने के लिए इस प्रशासन के रूप में एक सरकारी निगम की स्थापना की। इसे टैनेसी और उसकी सहायक नदियों पर बाँध बनाने, उनमें नौकानयन को सुधारने, बाढ़-नियन्त्रण करने, भूमि-क्षरण को रोकने और पन-विजली पैदा करने के अधिकार प्रदान किये गए।
- (3) राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार कानून (1933) नई नीति के

प्रारम्भिक काल में बनाये गए इस कानून में हर उद्योग के लिए उचित प्रतिस्पर्धा के कुछ आचार सम्बन्धी नियम निर्धारित कर अर्थ-व्यवस्था में जान फूँकने की व्यवस्था की गई थी। इसमें उद्योगों के लिए मजदूरियाँ और उत्पादनों के मूल्य भी निर्धारित किये गए थे। इसमें श्रमिकों को मालिकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी प्रदान किया गया था। यह कानून 1935 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

(4) बैंकिंग कानून (1933) इस कानून में व्यावसायिक बैंकों को पूँजी-निवेश का कारबार करने से रोका गया था। उनके द्वारा बैंकों के खातों का बीमा करने के लिए एक मधीय खाता बीमा निगम की भी स्थापना की गई। यह कानून ग्लास-स्टीगल एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है।

(5) सिक्वोरिटी एक्सचेंज कानून (1934) इस कानून के अन्तर्गत एक सिक्वोरिटी एव एक्सचेंज कमीशन की स्थापना की गई, जिसका प्रयोजन स्टॉक एक्सचेंजों (शेयर बाजारों) को नियन्त्रित करना और शेयरों में पूँजी-निवेश करने वालों को जाली शेयर जारी करने वालों से बचाना था। इसमें मधीय आरक्षित निधि बोर्ड को शेयरों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उधार (मार्जिन) को नियन्त्रित और विनियमित करने का भी अधिकार दिया गया।

(6) सामाजिक सुरक्षा कानून (1935) इस कानून द्वारा बृद्धावस्था में मजदूरों को या मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को धन देने के लिए एक कर्मचारी बीमा योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें मजदूर और मालिक दोनों बराबर-बराबर अदादान करते हैं। उनसे ब्रेडबेनार्स के नाम पर मजदूरों को मुआवजा देने की एक प्रणाली भी स्थापित की जिसका नचालन राज्य करते हैं। उनके अतिरिक्त इसमें रेटिनार्ड में पड़े हुए उनके आश्रित बच्चों और अन्य व्यक्तियों की सहायता की

वाद यह कानून पास किया गया। इसमें मजदूरों को मालिकों के साथ मामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार की गारंटी दी गई और इस कानून का संचालन करने के लिए एक राष्ट्रीय श्रम सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना की गई। आम तौर पर यह कानून वैगनर एक्ट के नाम से मशहूर है।

(8) उचित श्रम स्तर कानून (1938) इस कानून में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे अधिकतर कर्मचारियों के लिए 30 सेट प्रति घंटे की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। इस मजदूरी में अब तक कई बार वृद्धि की जा चुकी है। घंटों के हिसाब से काम करने वाले श्रमिकों के लिए इसमें एक सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम लेने पर फालतू समय के लिए डेढ़ गुनी ओवर टाइम की भी व्यवस्था की गई।

रूजवेल्ट ने राजनीतिक स्थिति में आए उबाल को ठण्डा करने के लिए नई कार्रवाई करने का निश्चय किया। सन् 1934 के उत्तरार्द्ध और 1935 में उसने जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, उसका उद्देश्य स्पष्टतः नागरिकों की विनाश सख्या को सुरक्षा और अच्छा रहन-सहन का स्तर प्रदान करना था।

रूजवेल्ट ने 1935 में कांग्रेस को दिए वार्षिक सन्देश में अपना यह नया कार्यक्रम स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा “आज हम अपने देश की जनता को पुरानी असमानताओं से पीड़ित पा रहे हैं। इससे पूर्व इन असमानताओं को दूर करने के लिए जो छुटपुट इलाज किये जाते रहे हैं, उनसे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे प्रयत्नों और बातों के बावजूद, उचित से अधिक विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों को उखाड़ फेंकने और शोषितों को ऊँचा उठाने में हमें कामयाबी नहीं मिली।”

इस प्रकार रूजवेल्ट ने अपनी नीति में जो परिवर्तन किया, वह 1935 में पास किये गए कानूनों में स्पष्ट परिलक्षित होता था। ये कानून अमेरिकन इतिहास में सामाजिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के सबसे अधिक दूरगामी कानून कहे जाते हैं। वैगनर श्रम सम्बन्धी कानून और सामाजिक सुरक्षा कानून जैसे बड़े सुधार कानूनों में सरकार की यह परिवर्तित भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी, भले ही उसकी व्याख्या किसी भी रूप में की

जाय। वैगनर कानून में श्रमिकों को अपनी मनपसन्द युनियन वेतन और उसकी मार्फत मालिकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया था। सामाजिक सुरक्षा कानून एक न्यूनतम आर्थिक स्तर निर्धारित करने के लिए बड़ी आशाओं के साथ बनाया गया कानून था। इस कानून में श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेन्शन देने के लिए एक बीमा योजना बनाई गई थी, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन में से कुछ अग देते थे और उतना ही अग मालिक भी डालते थे। इस योजना का प्रशासन सरकार के हाथ में था। इसी कानून में श्रमिकों को बेरोजगारी के समय मुआवजा देने की भी व्यवस्था थी और उसका संचालन राज्य सरकारों के हाथ में रखा गया था। इसके अलावा, कानून ने अभावग्रस्त बूढ़ों, उनके आश्रित बच्चों, विधवाओं और अन्धों के लिए भी सहायता की व्यवस्था की थी।

रूजवेल्ट के पुन राष्ट्रपति चुने जाने पर उनके द्वितीय शासनकाल में भी इसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कानून बनाये गए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय में 'सुधार' करने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप स्वयं रूजवेल्ट की डेमोक्रेटिक पार्टी दो खंडों में विभक्त हो गई और उसमें रूजवेल्ट के कड़े विरोधी पैदा हो गए तो भी इन वर्षों में सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कानून पास कराने में सफलता मिल गई। इनमें उचित श्रम स्तर कानून भी शामिल था। इस कानून में अन्तर्राज्यीय व्यापार-व्यवसायों में लगे कर्मचारियों के लिए मजदूरी का एक न्यूनतम स्तर 30 सेंट प्रतिघंटा नियत किया और साथ ही एक सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम लेने पर अतिरिक्त समय के लिए डब्ल्यूडी मजदूरी देने की भी व्यवस्था की गई।

इन वर्षों में सुधार कानूनों के परिवर्तित स्वरूप को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड होफस्टेटर ने लिखा है "सन् 1937 तक यह स्पष्ट हो गया था कि सुधारवाद के सामाजिक आधार में कुछ नया तत्त्व समाविष्ट कर दिया गया है। श्रमिकों द्वारा देश में एक बड़े और शक्तिशाली श्रमिक आन्दोलन के जरिये की जा रही माँगों और बेरोजगार लोगों के हितों को दृष्टि में रखकर बाद की नई नीति को एक नया सामाजिक-लोकतन्त्रीय रंग मिल गया। यह रंग अमेरिका की सुधारवादी राजनीति में पहले कभी नहीं था।"¹

जिस समय रूजवेल्ट की सरकार सामाजिक कानूनों के निर्माण में व्यस्त थी, 1937-38 की जवर्दस्त आकस्मिक मन्दी मुँह बाय उसके सामने आ खड़ी हुई और उसके सामने यह स्पष्ट हो गया कि इसकी नई नीति के अन्तर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ इस मन्दी का सामना करने में समर्थ नहीं हैं। इस मन्दी का एक कारण यह था कि 1936 में सरकार की जिन नीतियों ने आर्थिक दृष्टि से देश का कुछ उद्धार किया था, वे उलट दी गई थी। ये नीतियाँ थी—सकट-ग्रस्त लोगों को सहायता देने, सार्वजनिक निर्माण कार्य कराने, कृषकों को ऋण देने और भूतपूर्व सैनिकों को बोनस देने की।

यह ठीक है कि आर्थिक पुनरुद्धार की इन नीतियों पर अमल करने के लिए सरकार को जो धन खर्च करना पड़ा, उससे राष्ट्रीय ऋण (सरकार के ऋण) में तेजी से वृद्धि हो गई। इस स्थिति में सरकार ने, जो अभी तक पुरानी वित्तीय नीतियों पर चल रही थी, बजट को सन्तुलित करने का प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सघीय आरक्षित निधि बोर्ड ने ऋण देने में सख्ती कर दी। इसके लिए उसने बैंकों पर यह पाबन्दी लगा दी कि उन्हें अपना जमा-खातों की कुल रकम का जितना भाग पहले आरक्षित निधि में रखना पड़ता था, अब उससे 50 प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। सरकार ने भी बजट का सन्तुलित करने के लिए अपने सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर खर्च आधा कर दिया। इस प्रकार पुरानी नीतियों को उलट देने से मन्दी का नया जवर्दस्त झुल्ला आ गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय में सरकार जो योग दे रही थी, उसमें 3 अरब डालर की कमी हो गई। औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक अगस्त, 1937 के 119 के स्तर से गिरकर मई, 1938 में 81 पर आ गया (आधार 1935-39=100) और बेरोजगारों की संख्या में 40 लाख की वृद्धि हो गई।

सन् 1937 की मन्दी की तीव्रता ने प्रशासन को अपनी पुराने ढंग की वित्तीय नीतियों का परित्याग कर घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सार्वजनिक निर्माण आदि पर सघीय सरकार के खर्च में फिर वृद्धि कर दी और उसका औचित्य सिद्ध करते हुए अप्रैल, 1938 में घोषणा की कि "आज की लोगों की क्रय-शक्ति इतनी नहीं है कि

वह आर्थिक प्रणाली को अधिक तेज गति से सक्रिय कर सके। शासन के उत्तरदायित्व का हमसे यह तकाजा है कि हम सामान्य आर्थिक प्रक्रियाओं को अधिक वेग प्रदान करें और यह देखें कि आर्थिक गतिविधि में होने वाली नई वृद्धि पर्याप्त हो।" देश के कुछ प्रभावशाली वर्गों ने इस नीति का जोरदार विरोध किया। ये वर्ग अब भी पुरानी दकियानूसी वित्तीय नीतियों से ही चिपटे रहना चाहते थे।

मन्दी के दिनों में सरकार द्वारा सहायता के लिए व्यय किये जाने का विचार आज अमेरिकन राजनीति में विवाद का महत्वपूर्ण विषय नहीं रहा है। यह हो सकता है कि किसी खास व्यय कार्यक्रम की विस्तृत वारीकियों के बारे में कुछ मतभेद हों और यह भी सम्भव है कि किसी कार्यक्रम के समय या उस पर व्यय की मात्रा के बारे में मतैक्य न हो, तो भी सब मिलाकर दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा अधिक धन व्यय किया जाना अत्यावश्यक है।

वाल्टन हैमिट्टन ने अपनी 'दि पॉलिटिक्स ऑफ इंडस्ट्री' नामक पुस्तक में नई नीति को सार रूप में इन शब्दों में व्यक्त किया है "इसके अन्तर्गत निर्धारित की गई नीतियाँ तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाई गई सामाजिक नीतियाँ थी। इन नीतियों के साधन के रूप में जो एजेन्सियाँ, कमीशन, बोर्ड या अथारिटियाँ स्थापित की गईं, वे अधिकतर अस्थायी थी। नई नीति के नाम से जो अनेक कानून बनाये गए और कदम उठाये गए, वे कुछ हद तक एक दूसरे के साथ पूर्णतः सगत नहीं थे, उनसे यह प्रतीत होता था कि सरकार अपनी विचारधारा में बार-बार परिवर्तन कर रही है और वे सत्या और स्वरूप में इतने विविध प्रकार के थे कि उन्हें किसी एक अखंड और सुगठित ढाँचे में नहीं बैठाया जा सकता था। इन सब कानूनों और कार्यों में अपनाई गई तकनीकें राजनीतिक कला के आविष्कार मात्र थी। राज्य और अर्थ तन्त्र के बीच जो पृथक्त्व चला आ रहा था, वह खत्म हो गया था।"¹

दूसरे विश्व-युद्ध-काल की अर्थ-व्यवस्था

नई नीति अपने समस्त आशापूर्ण प्रयत्नों के बावजूद अमेरिकन पूँजीवाद की शक्तिशालिता में लोगों का फिर से पूरा विश्वास नहीं जमा सकी। लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में संयुक्त राज्य ने जो अमाधारण आर्थिक करिश्मा कर दिखाया उसने अमेरिकन पूँजीवाद के बारे में रहे-सहे सन्देहों की निवृत्ति कर दी।

जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर 7 दिसम्बर, 1941 को आक्रमण किये जाने से काफी पहले ही विश्व-युद्ध ने संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था को उभारना शुरू कर दिया था। सन् 1939 के पतझड़ में ज्यों ही यूरोप एक विशाल रणक्षेत्र बना, नाजी आक्रमण की गम्भीरता के प्रति अमेरिकन जनता अत्यधिक सजग हो उठी और कुछ क्षेत्रों में पृथक्त्ववाद की पुरानी भावना मौजूद रहने पर भी यह नई चेतना पृथक्त्ववाद पर हावी हो गई। युद्ध छिड़ते ही संयुक्त राज्य की सरकार ने जो प्रकट रूप में तटस्थ थी, मित्र राष्ट्रों को नकद मूल्य लेकर युद्ध सामग्री देनी प्रारम्भ कर दी। इसी 'तटस्थ' सरकार ने अपने विमान उनकी निर्माता कम्पनियों को वापस कर दिये, ताकि वे मित्र राष्ट्रों को उनका 'पुनर्विक्रय' कर सकें। इसके अलावा 1940 के पतझड़ में अमेरिका ने ब्रिटिश वेस्ट इंडीज और बरमूडा के नौमैनिक अड्डों के उपयोग के लिए अधिकार प्राप्त कर उनके बदले में ब्रिटेन को 50 'पुराने' विक्सक जहाज भी दिये। कांग्रेस ने शान्ति काल में (क्योंकि संयुक्त राज्य ने अभी युद्ध घोषणा नहीं की थी) पहली बार अमेरिका में सैनिक भर्ती का कानून पास किया और दोनों महासभाएँ (प्रगन्त और अटलांटिक) में नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 अरब डालर का कार्यक्रम स्वीकार किया। सैनिक संगठन के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की गई।

सन् 1941 में बड़े पैमाने पर मित्र राष्ट्रों को उधार पट्टे पर युद्ध

सामग्री देना प्रारम्भ हो गया। उस वित्तीय वर्ष में कुल सैनिक व्यय 7 अरब डालर था, जो युद्ध से पूर्व के वर्षों के सघीय सरकार के कुछ औसत वार्षिक बजट के बराबर था। दिसम्बर, 1941 तक सैनिक साधन-सामग्री पर व्यय 2 अरब डालर मासिक पर पहुँच गया। बेरोजगारी घटकर 1930 के बाद के निम्नतम स्तर पर उतर आई, हालाँकि 55 लाख से अधिक ग्रादमी उस समय भी काम की तलाश में थे।

संयुक्त राज्य के अधिकृत रूप में युद्ध में पड़ जाने के बाद एक नये युद्ध उत्पादन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री के उत्पादन और उपलब्धि को समन्वित और समायोजित करने के लिए अभूतपूर्व अधिकार प्रदान किये गए। युद्ध-कालीन जन-शक्ति कमीशन को सैनिक कर्मचारियों और अधिकतर असैनिक कर्मचारियों पर उसी तरह के अभूतपूर्व अधिकार दिये गए। मूल्यों में स्थिरता कायम रखने के लिए एक मूल्य प्रशासन कार्यालय स्थापित किया गया। इस कार्यालय को प्रथम विश्व-युद्ध के वर्षों की भाँति मुद्रा-स्फीति को असाधारण रूप से बढ़ने से रोकने का काम भी सौंपा गया।

सैनिक, असैनिक और निर्यात क्षेत्रों में युद्ध की निरन्तर बदलती आवश्यकताओं को देखकर ही सारा आर्थिक आयोजन किया जाता था। उपलब्ध साधनों का यथासम्भव उन आवश्यकताओं के अनुकूल उपयोग किया जाता था। उद्योगों पर अनेक नियन्त्रण स्थापित किये गए, परन्तु प्रारम्भिक परीक्षण के बाद उनमें से बहुत-से नियन्त्रण हटा भी लिये गए। कुछ नियन्त्रणों को अमल में लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तरीका चाहे कोई भी बरता जाय, आवश्यकता इस बात की अनुभव की जाती थी कि जहाँ भी स्वतन्त्र व्यापार को अत्यन्त मन्द, अशुभ और मकट-कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त समझा जाय, वही समुचित आर्थिक आयोजन किया जाय।

उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका यह था कि प्राइवेट उद्योगों को अपने कारखानों का विस्तार करने या उनमें उत्पादन वृद्धि के लिए समुचित परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिए सरकार ने उन्हें ऋण या उधार दिये अथवा बैंकों के ऋण की गारंटियाँ दी।

उसने उद्योगों को टैक्स में मूल्यह्रास की छूट के रूप में अरबों डालर का लाभ दिया और दुर्लभ कच्चे मान के उत्पादकों को, उनके घाटे की पूर्ति के लिए काफी अनुपूर्तियाँ दी।

किन्तु इतने प्रोत्साहन मिलने पर भी उत्पादकों ने उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं की। उनकी इस अनिच्छा का कारण सम्भवतः यह था कि युद्ध काल में बहुत-सी खास किस्म की मशीनरी की आवश्यकता होती है, परन्तु युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कभी-कभी उसकी कोई जरूरत नहीं रहती।

इस पर सरकार युद्धकालीन सयन्त्रों का निर्माण स्वयं करने लगी। इसके लिए उसने 16 अरब डालर व्यय किये। यह राशि नये युद्धकालीन सयन्त्रों पर खर्च की गई राशि का लगभग 83 प्रतिशत थी। कृत्रिम रबर, मैग्नेशियम, समुद्री जहाजों और विमानों का 90 प्रतिशत, एल्युमीनियम के सामान का 70 प्रतिशत और मशीनी औजारों का 50 प्रतिशत उत्पादन सरकार के हाथ में था। इसके अलावा दो बड़ी तेल की पाइप लाइनें भी सरकार द्वारा ही स्थापित की गईं। यद्यपि इन में से अधिकतर कारखाने चलाने के लिए सरकार ने दूसरों को पट्टे पर दे दिये, तो भी कुछ कारखाने ऐसे थे जिनका मंचालन उसने स्वयं किया।

सरकार द्वारा सीधा नियन्त्रण किये जाने का परिणाम यह हुआ कि युद्ध के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, जैसे असैनिक मोटरकार आदि, उनका उत्पादन सीमित हो गया। अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए एक प्राथमिकता-क्रम निर्धारित किया गया। इसके अलावा उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं के नियन्त्रण, अधिग्रहण, उत्पादन सूचियों के निर्माण और वितरण के लिए आवश्यक निर्देश आदि के तरीके भी अपनाये गए, जिससे जरूरी वस्तुओं का उत्पादन अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन से पहले हो और सरकार को समुचित मात्रा में उनकी उपलब्धि हो सके। सरकार ने एक 'नियन्त्रित सामग्री योजना' तैयार की जिसका प्रयोजन इस्पात, ताँबा और एल्युमीनियम आदि कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धि को नियन्त्रित करना था। लेकिन यह योजना बहुत प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि

अक कुल 22 प्रतिशत बढ़ा ।

मुद्रा स्फीति को और महँगाई को बढ़ने से रोकने वाला मुख्य कारण मूल्य प्रशासन कार्यालय द्वारा मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण था । इन नियन्त्रणों का लाभ यह था कि वे वस्तुओं की उपलब्धि कम और माँग अधिक होने से सम्भावित मूल्य वृद्धि को रोके रखते थे । लेकिन मूल्यों पर नियन्त्रण के दूसरे दुष्परिणाम अव्यय हुए । सामान और सेवाओं की किस्म गिर गई और अनेक क्षेत्रों में काला बाजार चल निकला । इसके अलावा मूल्य प्रशासन कार्यालय की तरह-तरह से आलोचनाएँ की जाने लगी ।

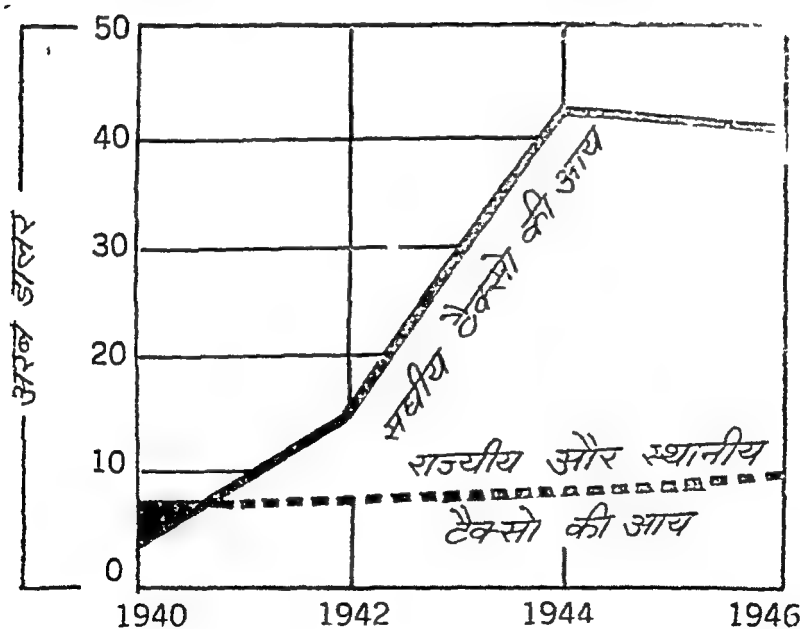
इन सब मानवीय, कानूनी और सांस्थानिक कमजोरियों के बावजूद संयुक्त राज्य के विशाल मानवीय और औद्योगिक साधनों के संगठन के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की कुल युद्ध सामग्री का दो तिहाई भाग अकेला अमेरिका ही मुहैया कर सका । इस संगठन का परिणाम यह हुआ कि 1940 और 1945 के बीच संयुक्त राज्य का औद्योगिक उत्पादन 75 प्रतिशत बढ़ा और राष्ट्र की कुल आय (डालरों के स्थिर मूल्यों में) इसी अवधि में 48 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई ।

किन्तु संयुक्त राज्य के युद्ध प्रयत्नों को 'पूर्ण युद्ध' के प्रयत्न नहीं कहा जा सकता । जिस समय ये युद्ध प्रयत्न अपनी चरम सीमा पर थे, उस समय भी देश की 6 करोड़ 60 लाख की कुल जन-शक्ति में से सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति ही सेना में थे । सन् 1944 में राष्ट्र की कुल आय 2 खरब 11 अरब डालर थी जिसमें से कुल 44 प्रतिशत राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च की गई और उसके बाद तो उममें और भी कमी हो गई, हालाँकि लड़ाई उस समय भी जारी थी । एक बात और भी हुई कि संयुक्त राज्य ने इतना युद्ध-प्रयत्न जारी रखने पर भी अपने देशवासियों के असैनिक उपभोग को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया ।

उपभोग्य वस्तुओं का राशन कर दिये जाने पर भी अमेरिकन नागरिकों को युद्ध प्रयत्नों के लिए अपेक्षाकृत कम बलिदान करना पड़ा । यह ठीक है कि अमेरिकनो को कुछ चीजों की खरीद के लिए कतारों में खड़े होकर इन्तजार करना पड़ता था, उन्हें चीनी, कॉफी, मास और चिकनाई वाली चीजों की कुछ कमी महसूस हुई, उनके मोटरों के उपयोग में कमी

कर दी गई, कुछ घरेलू मशीनों की खरीद उन्हें स्थगित करनी पड़ी, और जूते और डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के उपयोग में उन्हें कुछ अधिक सावधानी चरतनी पड़ी। यह भी ठीक है कि नौकरो, विक्रेताओं, बेघरो और नर्सों की कमी के कारण उन्हें कुछ असन्तोष था, परन्तु इसका कारण मजदूरी और वेतन में अन्तर पड़ जाना था, सरकार इसके लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं थी। सब मिलाकर सरकार द्वारा उत्पादन और उपभोग पर लागू किये गए नियन्त्रणों के बावजूद अमेरिकन नागरिक किसी भी अन्य युद्धरत राष्ट्र के नागरिकों से अधिक स्वतन्त्र थे।

सघीय सरकार की टैक्सों से होने वाली आय में वृद्धि 1940-46



युद्ध ने सघीय, राज्यीय और स्थानीय प्रशासनो के कर-संग्रह के कार्यों को एकदम उलटा कर दिया। युद्ध से पूर्व सघीय प्रशासन की करो की आय राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासनो की आय से कम थी पर युद्ध के बाद यह स्थिति उलटी हो गई। शीत युद्ध में भी अब यही परिवर्तित स्थिति जारी है।

इसमें नन्देह नहीं कि एक विश्वयुद्ध—चाहे वह परम्परागत हथियारों

से लडा जाने वाला पुराने ढग का युद्ध ही हो, मानव के लिए बहुत बडा सकट होता है। किन्तु मानवीय प्राणो के रूप मे उसकी जो कीमत चुकानी पडती है, उसे यदि छोड भी दिया जाय तो भी आर्थिक दृष्टि से भी उसकी बहुत बडी कीमत चुकानी पडती है। सयुक्त राज्य को आर्थिक दृष्टि से दूसरे विश्व-युद्ध की जो कीमत चुकानी पडी, उसका मूल्यांकन बहुत दिलचस्प होगा। सेना ने विश्व-युद्ध मे जो सेवाएँ प्रदान की उनका डालरो मे हिसाब लगाना अवश्य कठिन होगा। किन्तु जहाँ तक युद्ध सामग्री के उत्पादन का सम्बन्ध है, युद्ध उत्पादन बोर्ड के अनुसार जुलाई, 1940 से जुलाई, 1945 तक सयुक्त राज्य ने चालू मूल्यो के हिसाब से 1 खरब 86 अरब डालर की कुल युद्ध सामग्री तैयार की। इसमे से 36 अरब डालर की सामग्री मित्र राष्ट्रों को उधार-पट्टे पर दी गई। सयुक्त राज्य के कुल राष्ट्रीय ऋण मे भी भारी वृद्धि हो गई। नई नीति के द्वितीय काल मे युद्ध से पूर्व सयुक्त राज्य का राष्ट्रीय ऋण 42 अरब डालर था, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर वह बढ़कर 2 खरब 58 अरब डालर हो गया।

यद्यपि राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव किया कि किसी भी व्यक्ति को 25,000 डालर से अधिक वेतन न दिया जाय, तो भी युद्ध-कालीन वित्त-व्यवस्था के लिए स्पष्ट रूप से कभी भी आय के समुचित पुनर्वितरण का लक्ष्य नहीं रखा गया। इसके विपरीत, यह आशा की गई कि टैक्स की दर बढ़ा देने और अधिक लोगो पर टैक्स लगाने से और साथ ही युद्धकालीन नियन्त्रणों और विनियमों से मुनाफाखोरी और शोषण को रोका जा सकेगा।


युद्ध पर वास्तव मे जो भारी खर्च हुआ वह बहुत हद तक लोगो की नजर मे नहीं आया, क्योंकि युद्ध-जन्य समृद्धि का उपभोग प्राय सभी व्यक्ति कर रहे थे। मुनाफे के आँकड़ो से आम तौर पर यह बात जाहिर नहीं हो पाती कि कम्पनियों के मुनाफे अन्य मुनाफो की अपेक्षा कम थे। सन् 1939 और 1944 के बीच कम्पनियों के मुनाफे (टैक्स काटने से पूर्व) बढ़कर साढे तीन गुने से भी अधिक हो गए थे। किन्तु टैक्स काटने के बाद कम्पनियों के शुद्ध मुनाफे पहले की अपेक्षा केवल दुगुने ही थे, जबकि कुल राष्ट्रीय आय डालर के चालू मूल्य के अनुसार, 2 33 गुने के लगभग हो गई थी।

इसमे सन्देह नहीं कि मोटे तौर पर आँकड़ो की यही तसवीर थी किन्तु

फिर भी कुछ उद्योग-व्यवसाय ऐसे थे, जो इससे कहीं अधिक समृद्ध हो गए। उदाहरण के लिए सरकार की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार गढ़े हुए धातु के ढाँचों के उद्योग में युद्ध-पूर्व की अपेक्षा 26 गुना मुनाफा (टैक्स काटने के बाद) था। छोटी फर्मों के मुनाफे सबसे अधिक थे। इसका एक कारण संभवतः यह था कि उनके लिए कठोर नियन्त्रणों से बचने की गुंजायश बड़े उद्योगों

संघीय सरकार की वित्तीय स्थिति

1940


9 अरब डालर
वार्षिक व्यय


429 अरब डालर
अवशिष्ट भूरा

1945


98.4 अरब डालर
वार्षिक व्यय


2 खम्ब 58 अरब
10 करोड़ डालर
अवशिष्ट भूरा

युद्ध के वर्षों में संघीय सरकार के वार्षिक व्यय के साथ-साथ उसके ऋणों में भी भारी वृद्धि हुई। सन् 1960 में संघीय सरकार पर 286 अरब डालर से अधिक का ऋण था जिस पर उसे 9 अरब डालर व्याज देना था।

मजदूर यूनियन ने युद्धकालीन में हड़ताल न करने का वचन दे चुकी थी, इसलिए मूल्य बढ़ने पर वेतनों में तदनुसार वृद्धि के लिए वे सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देखती थी। जुलाई, 1942 में सरकार ने वेतनों में 15 प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फार्मूला निकाला, जिसका उद्देश्य उस समय

तक मृत्यो मे हुई वृद्धि को वेतन-वृद्धि से सन्तुलित करना था। इसके अलावा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मे और भी सुधार हुआ क्योंकि कम्पनियो ने उनके लिए पेन्शन और डाक्टरी देख-भाल आदि की योजनाएँ लागू कर दी थी। स्त्रियो और नवोदित तरुणो के भी रोजगार पर लग जाने से परिवारो की आमदनियाँ बढ गई। कर्मचारियो के वेतनो मे से कुछ रकम काटकर उसके बदले मे उन्हें बाड दिए जाते थे और बाजारो मे चीजो की उपलब्धि कम होने से लोग स्वयं भी कुछ बचत कर लेते थे। इन दोनो का लाभ यह था कि अनिरुद्ध परिमम्पत्ति (लिक्विड एसेट) की उपलब्धि की सम्भावना काफी बढ जाती थी।

युद्ध के दिनो मे किसानो की हालत भी अच्छी थी, क्योंकि सरकार ने सिर्फ उत्पादन वृद्धि को ही प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि विदेशो को भेजने के लिए उनसे कृषि-उत्पादन अधिकाधिक मात्रा मे खरीदे भी। युद्धकाल मे करीब 50 लाख व्यक्ति कृषि से हटकर दूसरे कामो मे लगे, फिर भी कृषि की उत्पादकता बढ गई। इस प्रकार कृषि-जन्य आय कुछ लोगो के लिए उचित स्तर से नीची होने पर भी काफी बढ गई। सन् 1939 मे प्रति व्यक्ति आय 249 डालर थी, परन्तु युद्ध समाप्त होने तक वह बढकर 700 डालर हो गई।

द्वितीय विश्व-युद्ध मे जो अनुभव और परिवर्तन हुए उन्होंने सयुक्त राज्य की युद्धोत्तर कालीन नीतियो को प्रभावित किया। युद्ध-काल मे पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाने से लोगो के मन मे यह आम धारणा पैदा हो गई थी कि शान्ति काल मे भी यह स्थिति कायम हो सकती है। यह मान लिया गया कि अर्थ-व्यवस्था मे सरकार का थोडा-बहुत हस्तक्षेप आवश्यक ही है। तब से सघीय सरकार का बजट गिरकर राष्ट्रीय आय के 15 प्रतिशत से भी कम हो गया है और सैनिक बजट इस बजट का कम-से-कम आधा रहता है।

युद्ध समाप्त होने पर सयुक्त राज्य के सामने राष्ट्र के भीतर बहुत-सा अधूरा काम पडा था। प्राय सभी स्तरों (सघीय, राज्यीय और नागरिक) पर सरकार के युद्ध-प्रयत्नो मे व्यस्त रहने के कारण सार्वजनिक सेवाएँ बहुत पिछड गई थी। युद्ध-काल मे अविकाधिक लोगो के श्रमिक बन जाने से सामाजिक दृष्टि से भी देश को कुछ क्षति पहुँची थी। लोगो के लिए आवास

शान्ति और उसका परिणाम

सयुक्त राज्य ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के युग के लिए तैयारी करते हुए उन आर्थिक भूलों के अनुभव और सबक को ध्यान में रखा, जो उसने प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद की थी। किन्तु इन पुरानी गलतियों से सीखे गए सबक मूल्यवान् होने पर भी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। कई पुरानी बड़ी भूलें फिर से दुहरा दी गईं और कुछ नई भूलें भी हो गईं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक अनिश्चितताएँ थी, देश के बहुत-से आन्तरिक विग्रहों का समाधान नहीं हुआ, बल्कि वे कुछ समय के लिए स्वगित हो गए और बहुत-सी घटनाएँ बड़ी जटिल हो गईं और उनमें तेजी से परिवर्तन हुए। लेकिन इस सबके बावजूद सयुक्त राज्य ने अपने-आपको पहले विश्व-युद्ध के बाद की अपेक्षा दूसरे विश्व-युद्ध के बाद अधिक अच्छे ढंग से परिस्थितियों के साथ समन्वित किया।

युद्ध समाप्त होने से काफी पहले ही शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए योजनाएँ तैयार की जाने लगी थीं। जून, 1944 में ही युद्ध सामग्री उत्पादन बोर्ड ने सामरिक उद्योगों को शान्तिकालीन उद्योगों में परिवर्तन की तैयारी कर ली थी। युद्ध के लिए औद्योगिक संगठन धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा था और कुछ नियन्त्रण ढीले कर दिये गए थे। सैन्य-विघटन की प्रेरणा इतनी प्रबल थी कि मई, 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त होने ही कुछ नियन्त्रण समय से पूर्व ही हटा लिये गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगस्त में जापान की आखिरी पराजय तक के लिए उन्हें फिर आशिक रूप में लागू करना पड़ा।

सन् 1945 की ग्रीष्म ऋतु में राष्ट्रपति ट्रुमन के एक आदेश में कहा गया था कि “हमारा लक्ष्य मूल्यों, मजदूरियों, सामग्रियों और सुविधाओं पर लगाये गए युद्धकालीन नियन्त्रणों को धीरे-धीरे व्यवस्थित ढंग से बदलना है और इस संक्रान्ति काल में राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना

है।" कुछ महीनों के भीतर ही जन-शक्ति और व्यापारिक वाहनो के उपयोग पर से नियन्त्रण उठा लिये गए, चीनी को छोड़कर ग्रेप सभी उपभोग्य वस्तुओ पर से राशन खत्म कर दिया गया और बहुत-से मूल्य-नियन्त्रण हटा लिये गए। अतिरिक्त लाभ-कर भी खत्म कर दिया गया और जिन युद्धकालीन उद्योगो को शान्तिकालीन उद्योगो मे परिणत किया गया, उन्हें टैक्सो मे राहत दी गई। कच्चे माल, आवास-व्यवस्था और निर्यात पर कुछ प्राथमिकताएँ कायम रखी गई और उनके लिए राशियाँ निर्धारित करने के बारे मे कुछ नियन्त्रण भी बरकरार रखे गए। इन युद्धकालीन नियन्त्रणो मे से कुछ अभी तक लागू है।

ग्राम तौर पर सरकार की इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप राष्ट्र के साधनो को युद्धकालीन उपयोगो से हटाकर शान्तिकालीन उपयोगो मे लगाने का काम शान्तिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो गया। जो लोग मूल्य प्रशासन कार्यालय को विघटित करने के समर्थक थे, उन्होंने उसके पक्ष मे यह दलील दी कि उद्योग-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उनका कहना था कि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तित करने और उपभोक्ताओ की बहुत समय मे चली आ रही अपूर्ण आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि व्यापार को मुक्त और स्वतन्त्र रूप मे चलने दिया जाय। दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो व्यापार को यह स्वल्पकालिक लाभ देने के पक्षपाती नही थे। उनका कहना था कि सरकार को दूरदृष्टि मे मोचना चाहिए और मूल्य-वृद्धि को नियन्त्रणो के जरिये रोककर नामूलिक तौर पर जनता की क्रय-शक्ति को बनाए रखना और मुद्रामफीति को बढ़ने से रोकना चाहिए।

जो हो, जनता नियन्त्रणो मे तग आ गई थी और वह दान्तविक प्रश्नो और मग्म्याओ को नही नमस्ती थी। मजदूर मजदूरी के नियन्त्रण से चिढ़े हुए थे और उद्योगपति एव व्यापारी मूल्य और ऋण नियन्त्रण से बिगड़े हुए थे। इसलिए जनता के इस बढ़ते हुए विरोध के कारण, मूल्य-नियन्त्रण धीरे-पारे हटा लिये गए और 1946 के पतभंड मे उनका पूर्णतः अन्त हो गया।

यह नियन्त्रण हटते ही मजदूरी और कीमत, दोनों में तत्काल वृद्धि हो गई। थोक मूल्यों का सूचक अंक, जो लड़ाई के दौरान में कभी भी 14 प्रतिशत से अधिक ऊँचा नहीं गया, 1946 के 9 महीनों में 33 प्रतिशत ऊँचा हो गया। इसी अवधि में खुदरा मूल्य भी 17 प्रतिशत बढ़े। सौभाग्य से, यह मूल्य-वृद्धि, जो लड़ाई के वर्षों में लोगों की माँगे दबी रहने के कारण रूकी हुई थी और अब लोगों को खुलकर खरीदने का अवसर मिलते ही बहुत तेजी से बढ़ गई थी, कुछ समय बाद धीमी पड़ गई। इसके बाद कोरिया की लड़ाई शुरू होने तक अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था में बहुत धीरे-धीरे मन्दगति से स्फीति आती रही।

मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि की समस्या के अलावा युद्ध के बाद दूसरी मुख्य समस्या थी उत्पादक और रोजगार को यथासम्भव उच्चतम स्तर पर रखना। इस समस्या की चुनौती को 1946 के रोजगार कानून में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। इस कानून में कहा गया था कि सघीय सरकार की नीति “ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें उन सब लोगों को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकें, जो काम करने में समर्थ हैं, काम करना चाहते हैं और काम की तलाश में हैं। रोजगार के इन अवसरों में अपना निजका धन्धा भी शामिल है। सरकार की नीति का उद्देश्य अधिकतम रोजगार, अधिकतम उत्पादन और अधिकतम क्रय-शक्ति को समुन्नत करना भी है।”

इस कानून में ये व्यवस्थाएँ भी की गई थी—(1) राष्ट्रपति प्रति वर्ष आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, (2) उनकी सहायता के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद् स्थापित की जाय, और (3) इन वार्षिक रिपोर्टों के अध्ययन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति स्थापित की जाय। रोजगार कानून वास्तव में पूर्ण रोजगार को कायम रखने के लिए आवश्यक नीतियों को स्वीकार करने के सरकार के नैतिक उत्तरदायित्व की एक उद्घोषणा था। इसलिए दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने उसका समर्थन किया। अनुदार और उदार दोनों प्रकार के विचारों के सदस्यों की राय में अमेरिकन जनता को यह विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी सरकार पर थी कि उन्हें भविष्य में फिर कभी भी 1930 के

दशक की-सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यह एक विचित्र विडम्बना है कि सरकार के पूर्ण रोजगार का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेने का अर्थ विभिन्न वर्गों ने यह समझ लिया कि वे लागत-वृद्धि के नाम पर, और दण्ड में की गई कमी का लाभ उठाकर, अपने आर्थिक स्वार्थों की खुलकर पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी औद्योगिक कम्पनियों ने अपनी बाजार में खड़े होने और व्यापार में टिकने की अधिक शक्ति देखकर मजदूर यूनियनों की वेतन-वृद्धि की माँग के कारण उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को अपनी जेब से भरने के बजाय उप-भोक्ताओं पर डालना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी ओर मजदूर यूनियनों ने भी उपलब्ध श्रम-शक्ति पर अपना काफी नियन्त्रण होने के कारण मजदूरी बढ़ाने के लिए माँगें पेश करना और उन्हें मनवाने के लिए जोर डालना शुरू किया। इस लागत-वृद्धि और उससे उत्पन्न महँगाई का तात्कालिक नुकसान बेचारे बँधी आमदनी वाले वर्गों को उठाना पड़ता था। इन वर्गों में रिटायर्ड पेन्शनयापता अथवा ऐसे लोग थे जो बाड़ों और बन्धक सम्पत्ति (मॉर्टगेज) की बड़ी आमदनी से निर्वाह करते थे।

मन्दी का मुकाबला करने के लिए जो वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी उपाय कारगर समझे जाते थे, महँगाई और मुद्रा-स्फीति का मुकाबला करने के लिए उनका उलटा उपयोग करने से आसानी से काम नहीं चल सकता था। महँगाई और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनुपूरक वित्तीय नीति के रूप में टैक्सों में वृद्धि की जा सकती थी, किन्तु शान्तिकाल में इस उपाय का सहारा लेने के परिणाम राजनीतिक दृष्टि में प्रतिकूल हो सकते थे। अनेक क्षेत्रों में मधीय सरकार द्वारा किये जा रहे व्यय को सीमित करने का प्रयत्न किया गया, खास कर जन-कल्याण और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्रों में, किन्तु इसका लाभ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ नए दवाव और नई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई जिन्होंने मधीय सरकार के कुल दण्ड को बढ़ाकर फिर उतना ही कर दिया। सरकार की मुद्रा नीति में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह व्याज की दरें नीची रखना चाहती थी और साथ ही यह भी चाहती थी कि अवशिष्ट सरकारी बाँटों की कीमतें स्थिर रहे। अधिक-से-अधिक सरकार यही कर सकती थी कि

वैको के पान सघीय सरकार के जो ऋण-पत्र हो, उनका वह वजट के अधि-
शेष (वचत) के अनुमार भुगतान कर दे और खास-खान कामो के लिए
ऋण देने पर नियन्त्रण लगा दे ।

सन् 1940 के दशक के युद्धोत्तरकालीन वर्षों में संयुक्त राज्य के
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उलझने के कारण मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और भी
बढ़ गई । दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति से काफी पहले ही सरकार ने युद्धोत्तर-
कालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए योजनाएँ बनाना और वार्ताएँ करना प्रारम्भ
कर दिया था । सन् 1943 के प्रारम्भ में खाद्य और कृषि की युद्धोत्तर-
कालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन
का आयोजन किया गया । उसी वर्ष के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र संघ के
तत्वावधान में एक महायत्ना एवं पुनर्निर्माण भी काम करने लगा था ।
सन् 1944 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड) और
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की, जो विश्व बैंक के नाम से
अधिक प्रख्यात है, स्थापना के भी प्रस्ताव किये गए ।

युद्ध के तत्काल बाद युद्ध कालीन व्यवस्था से शान्तिकालीन व्यवस्था
की ओर संक्रान्ति अत्यधिक आनानी और निर्विघ्नता से हो गई थी, इस-
लिए अनेक प्रेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि युद्ध समाप्त होने से पूर्व
ही बुद्धिमत्तापूर्वक दूरदर्शिता में आयोजन प्रारम्भ कर देने के कारण ही
यह युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण सम्भव हुआ है । यूरोपियन देशों में कई
उद्योग एक वर्ष के भीतर ही युद्ध-पूर्व के स्तर पर उत्पादन करने लग गए,
जबकि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उन्हें युद्धपूर्व के स्तर पर आने में छ वर्ष
लग गए थे । किन्तु 1947 के बाद के तीव्र घटनाचक्र ने सामान्य स्थिति
के पुनर्गोचर स्थापित होने की सारी आशाएँ धूल में मिला दी । इस
घटनाचक्र के फलस्वरूप द्रुत पुनर्निर्माण के वजाय अन्तर्राष्ट्रीय संकटों की
बार-बार पुनरावृत्ति होती रही ।

संयुक्त राज्य यह आशा नहीं कर सकता था कि वह अपनी घरेलू
समस्याओं की निजी दुनिया में लौटकर इन संकटों से बच जाएगा । नैतिक,
राजनीतिक या आर्थिक, किसी भी दृष्टि से अमेरिका के लिए फिर से
पृथक्त्ववाद को अपनाना सम्भव नहीं था । युद्ध के बाद स्थिति यह थी कि

ससार-भर में उद्योग व्यवसाय में जितनी पूँजी लगी हुई थी, उसका तीन-चौथाई भाग अमेरिका का, और इसी तरह ससार के कुल सस्थापित उद्योगों का दो-तिहाई भाग भी अमेरिका का था। इस पर मजा यह कि संयुक्त राज्य की आबादी ससार की कुल आबादी का सिर्फ सोलहवाँ भाग थी। यह जाहिर था कि ससार-भर के अल्पविकसित क्षेत्रों में उन्नति की उभरती हुई आकाशाओं की जो क्रान्ति उठ रही थी, उसके सामने यह एकतरफा 'शक्ति मन्तुलन' कायम नहीं रह सकता था। इसके अलावा राजनीतिक जगत् में अराजकता की स्थिति से बचने के लिए पश्चिमी यूरोप की युद्ध-ध्वस्त अर्थ-व्यवस्थाओं का युद्ध से पूर्व की स्थिति में फिर से गीघ्र लौट आना भी आवश्यक था।

युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू-शुरू में संयुक्त राज्य में जो वैदेशिक आर्थिक नीतियाँ अपनाई वे मोटे तौर पर अपने आप में उत्तरदायित्वपूर्ण और सर्वथा उपयुक्त थीं। संयुक्त राज्य के अन्य देशों को तत्काल राहत देने और उद्योग-व्यापार के लिए उधार की सुविधा प्रदान करने की जो नीति अपनाई थी, वह एक सुविचारित नीति थी। इसके अतिरिक्त विश्व, बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की मार्फत सहायता देकर विश्व की अर्थ-व्यवस्था को फिर से सभलने और ऊपर उठाने के लिए दीर्घकालीन योजनाएँ भी बनाई गई थी। इस प्रकार तात्कालिक और दीर्घकालीन सहायताओं की योजनाएँ तो बना ली गई, किन्तु मध्यवर्ती काल के लिए दम्यानी योजनाओं का निर्माण अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा।

संयुक्त राज्य के बाहर पश्चिमी यूरोप ही सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र था और यह आवश्यक था कि विश्व के उत्पादन और व्यापार का पुनरुद्धार करने के लिए उसे पहले उबारा जाय। सन् 1946 में वहाँ जो उत्साहवर्धक आर्थिक पुनरुद्धार दिखाई दिया था वह दर-असल एक भ्रममात्र था। इस भ्रम का कारण यह था कि वित्तीय और अन्य प्राकृतिक साधनों की वहाँ एकाएक कमी हो गई और लोगों ने इससे उत्पन्न अवस्फीति का अर्थ यह समझा कि आर्थिक स्थिति सभलने लगी है। इस भ्रम का निवारण होने पर बहुत बड़ी सख्या में लोग पूर्ण रोजगार की गारंटियाँ माँगने लगे और जन-कल्याण सम्बन्धी उन कार्यक्रमों को

पूरा करने के लिए आन्दोलन करने लगे, जिनकी बहुत-समय पहले ही पूर्ति हो जानी चाहिए थी। इन माँगों की पूर्ति के लिए सरकारों ने अपना खर्च बढ़ाने की जो वित्तीय नीतियाँ अपनाई, उनमें मुद्रा-स्फीति और बढ़ गई। संयुक्त राज्य और लैटिन अमेरिकन देशों की मुद्रास्फीति और महँगाई ने यूरोप के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कच्चे माल और मशीनरी आदि का मूल्य बहुत बढ़ा दिया। युद्ध में जो जहाज ध्वस्त होने से बच गए, वे भी खस्ता हालत में थे। इसके अलावा यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेशों में जो पूँजी लगाई हुई थी और उससे जो मुनाफा आ रहा था, वे दोनों ही धीरे-धीरे उनके हाथों से खिसकते जा रहे थे।

शीत-युद्ध के प्रारम्भिक गर्जन ने स्थिति को और भी उलझा दिया। अंग्रेजों को समुद्र-पार के देशों से अपने जगह-जगह फैले और महँगे सैनिक सस्थानों और जिम्मेदारियों को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के ग्रीस और टर्की से सेनाएँ हटाने पर वहाँ जो रिक्तता आई, उसे भरने के लिए संयुक्त राज्य को उमका स्थान लेना पड़ा। उसे सोवियत रूस के आर्थिक और राजनीतिक दबाव का सामना करने के लिए ईरान को भी मजबूर बनाना पड़ा। सन् 1947 में दो व्यापक वैदेशिक सहायता कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। इनमें से एक कार्यक्रम था ट्रुमन सिद्धान्त, जिसका उद्देश्य था ग्रीस और टर्की को सैनिक और आर्थिक सहायता देना और दूसरा कार्यक्रम था मार्शल योजना, जो उससे अधिक व्यापक था और जिसका प्रयोजन यूरोप को फिर से अपने पाँवों पर खड़ा करना था। इन कार्यक्रमों के द्वारा संयुक्त राज्य ने मध्यम अवधि की आर्थिक सहायता को वैदेशिक नीति के साधन के रूप में अपनाया। सब मिलाकर इन कार्यक्रमों के द्वारा संयुक्त राज्य ने 1948 से 1952 तक चार वर्ष की अवधि में यूरोप को 12 अरब डालर की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

इतिहास में इतनी बड़ी और व्यापक सहायता इससे पूर्व पहले कभी नहीं दी गई थी। पश्चिमी यूरोप में संयुक्त राज्य की सहायता स्पष्टतः आर्थिक और राजनीतिक उफान को रोकने और यूरोप को फिर से अपने पाँवों पर खड़ा करने के लिए बहुत उपयोगी थी। इसके लिए जो वास्तविक कार्यविधि अपनाई गई वह बड़ी पेचीदा थी। इसके लिए 1948-49 की विश्वव्यापी

मन्दी के दिनों में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और कुछ अन्य कदम भी उठाये गए। इसके साथ ही दीर्घकाल से चली आ रही अन्य मुद्रास्फीति और महंगाई की प्रवृत्तियों पर भी नियन्त्रण करना पड़ा। लेकिन यह स्पष्ट नजर आने लगा कि पश्चिमी यूरोप का पूर्णतः आर्थिक उद्धार हो जाएगा। दुर्भाग्य से शीत-युद्ध जन्य सन्देहों के कारण सोवियत रूस के पिछलग्गू पूर्वी यूरोपीय देशों ने मार्शल-योजना के कार्यक्रम में शामिल होने से इन्कार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपियन महाद्वीप का व्यापार और विकास कम-से-कम भविष्य में काफी समय के लिए विभक्त हो गया।

मार्शल-योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि पश्चिमी यूरोप के किसी एक देश का नहीं, बल्कि समग्र रूप से सारे पश्चिमी यूरोप का पुन-रुद्धार हो। इसके लिए

पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक सहयोग की आवश्यकता थी। संयुक्त राज्य ने यह शर्त लगा दी थी कि सभी देश मिलकर अपनी आवश्यकताओं का हिसाब लगाएँ। इसका लाभ यह हुआ कि यूरोपियन आर्थिक सहयोग सगठन के जरिये संयुक्त रूप से पारस्परिक सहयोग से मिलकर यूरोप के देश कार्यक्रम बनाने लगे।



जॉर्ज सी० मार्शल

मार्शल-योजना के निर्माता

पश्चिमी यूरोप के इस प्रादेशिक सगठन और एकीकरण के आन्दोलन के बाद यूरोपियन कोयला एवं इस्पात संधि और वेंनीलक्स सीमाकर संधि की स्थापना से और भी बल मिला। उत्तरी अटलांटिक संधि सगठन के जरिये पश्चिमी

यूरोप के देशों और अमेरिका में जो सैनिक सहयोग स्थापित हुआ उसने पारस्परिक सन्देशों को दूर कर इन राष्ट्रों में और भी मजबूत आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये। अमेरिका के अनुभवों से लाभ उठाकर यूरोप में भी उत्पादकता वृद्धि और बड़े पैमाने पर विक्री के लिए प्रयत्न किये गए और उससे यूरोपियन पूँजीवादी प्रणाली में परम्परा से चली आ रही उत्पादकों के गुट बनाकर बाजार पर अधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न होने लगी।

इस अवधि में अल्पविकसित देशों को सयुक्त राज्य से अपेक्षाकृत कम आर्थिक सहायता मिली। वे सयुक्त राज्य की प्राइवेट पूँजी को भी, जो उनकी अर्थ-व्यवस्था में जान डाल सकती थी, अधिक आकृष्ट नहीं कर सके। सिर्फ तेल और कुछ अन्य सामरिक महत्व की वस्तुओं के उद्योगों के लिए ही इन देशों में प्राइवेट अमेरिकन पूँजी गई। राष्ट्रपति ट्रुमन ने 1949 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हुए अपने भाषण में जिस प्रसिद्ध चतुर्थ सूत्र (प्वायट फोर) का उल्लेख किया था। उसने गरीबों, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ एक नये साहसपूर्ण कार्यक्रम की आशाएँ पैदा कर दी। किन्तु इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने धन बहुत आहिस्ता-आहिस्ता दिया और साथ ही उसमें बड़े पैमाने पर विकास के लिए पूँजी देने के बजाय तकनीकी सहायता पर अधिक जोर दिया जाने लगा। लेकिन इसमें सन्देह है कि यदि बड़े पैमाने पर पूँजी दी भी जाती तो भी अनेक अल्पविकसित देश उसका लाभकारी ढंग से उपयोग कर पाते। जो भी हो, उस दिशा में यदि पूँजी-निवेश की कोई सम्भावना थी भी तो वह 1950 में कोरिया की लड़ाई छिड़ने पर पश्चिमी देशों का पुनः शस्त्रीकरण का बोझ बढ़ जाने पर खत्म हो गई।

अमेरिका द्वारा एक अनिश्चित भविष्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व स्वीकार किये जाने से सयुक्त राज्य की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की कुछ समस्याएँ उभरकर सामने आ गईं। यह आवश्यक था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर काफी राशि खर्च की जाय, इसलिए संघीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व दोनों को निभाने की आवश्यकता के कारण अपने बजट को कम नहीं कर सकती थी और न ही महँगाई और मुद्रास्फीति के दबाव को घटा सकती थी।

इसके अलावा देश की आबादी भी बढ़ रही थी, इसलिए उसकी आवश्यकताएँ भी तेजी से बढ़ रही थी, जबकि सरकार उनको उतनी रफ्तार से पूरा नहीं कर पा रही थी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे अधिक दूरगामी कार्यक्रम था सैनिक अधिकार विधेयक, जो युद्ध की समाप्ति के आसपास पास किया गया। इस विधेयक में भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी व्यय से शिक्षा देने और गृह-निर्माण और छोटे-मोटे व्यापार के लिए सरकारी गारंटी से युक्त ऋण देने की व्यवस्था थी।

किन्तु सार्वजनिक निर्माण-कार्य के क्षेत्र में सरकार बुरी तरह पिछड़ गई। सन् 1950 में कुल सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (सघीय, राज्यीय और नागरिक तीनों) का खर्च 1940 के खर्च से कुछ ही अधिक था। लेकिन इन दस वर्षों में निर्माण कार्यों की लागत बहुत ऊँची हो गई थी, इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि 1950 में वास्तविक निर्माण-कार्य 1940 की तुलना में कम हुआ।

आर्थिक जीवन और भी अधिक सांस्थानिक हो गया, क्योंकि समृद्धि में जो वृद्धि हो रही थी, उसका अधिक भाग बड़ी कम्पनियों को प्राप्त हो रहा था। जिन बड़ी कम्पनियों के पास हिस्सेदारों में वितरित न किये गए भारी मुनाफे जमा हो गए थे उन्होंने अपने निज के जन-कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए और साथ ही वे अपनी ही आन्तरिक पूँजी से अपना विस्तार करने लगीं। ट्रेड यूनियन भी विशाल दैत्याकार संगठन बन गईं, जिनके पास पेशन और श्रमिक कल्याण कोष के रूप में अरबों डालर जमा थे। ये ट्रेड यूनियन अपने इस धन को पूँजी के रूप में उद्योग-व्यवसाय में निवेश करने लगीं और पूँजी-निवेश के मामले में बीमा कम्पनी, बैंक और निवेश-ट्रस्ट जैसी परम्परागत पूँजी-निवेशक संस्थाओं से होड़ लेने लगीं।

बाजारों में परम्परा से चली आ रही पुरानी प्रतिस्पर्धात्मक ताकतों का ह्रास हो जाने पर अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में छोटे व्यवसायों का महत्व घट गया। बड़ी फर्मों का बड़ी यूनियनों के साथ मुकाबला होता था और बड़ी सरकार ही उनके मामलों में पंच-निर्णय करती थी। कम शक्तिशाली वर्गों का अपने हितों को समुन्नत करने का अपना अलग ही तरीका था। उदाहरण के लिए किसान अब भी सरकारी सहायता के कार्यक्रमों पर निर्भर रहते थे।

उपभोक्ता और छोटे व्यापारी नियन्त्रक और नियामक सरकारी सगठनों से सरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे ।

जन-हित की रक्षा के लिए आर्थिक दबाव डालने वाले बड़े शक्तिशाली वर्गों के बीच पंच-निर्णय की यह समस्या युद्धोत्तर काल की एक बड़ी और अत्यधिक परेशान करने वाली समस्या बन गई । किन्तु जून, 1950 में दक्षिणी कोरिया पर कम्युनिस्टों के आक्रमण से इस समस्या में ही नहीं, इसी प्रकार की अन्य आर्थिक समस्याओं में भी सरकार का सिर खपाना और जनता का चिन्तित होना एकाएक रुक गया । अमेरिकन अर्थ व्यवस्था के बड़े सगठनों के हाथों में अधिकाधिक चले जाने की समस्या पर जनता ने उस समय तक दुबारा कोई चिन्ता नहीं की, जबतक कि आइसनहोवर का प्रशासन-काल आधा नहीं गुजर गया ।

आइसनहोवर काल

सन् 1952 में ड्वाइट डी० आइसनहोवर की विजय से संयुक्त राज्य के आर्थिक इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआ। सन् 1920 के 'स्वर्णिम दशक' और भारी मन्दी के प्रारम्भिक वर्षों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में कोई खास राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई थी। इन बीस वर्षों में दुनिया में भारी बुनियादी परिवर्तन हुए थे। इन नई वास्तविकताओं के प्रति अनुक्रिया ही आइसनहोवर युग के दीर्घकालीन महत्त्व को समझने की कुंजी है।



आइसनहोवर

ऐसा लगता था जैसे अन्तराष्ट्रीय रंगमंच पर एक पीढ़ी नहीं, बल्कि एक पूरा मन्वन्तर गुजर गया हो। संयुक्त राज्य के सामने सोवियत संघ की सैनिक और अर्थिक चुनौती और विश्व कम्युनिज्म की आदर्शवाद की चुनौती मुंह बाये खड़ी थी। साथ-ही-साथ उन्नीसवीं शताब्दी के साम्राज्यों की ढलती साँझ और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आधुनिक राष्ट्रवाद और सामाजिक क्रान्ति के उगते प्रभात ने नई समस्याएं खड़ी कर दी थी और नये क्षेत्रों के द्वार प्रगति के लिए खोल दिये थे।

सयुक्त राज्य के आन्तरिक रगमच पर भी कूलिज हूवर युग के बाद कितने ही दूरगामी परिवर्तन हो चुके थे। मन्दी और युद्ध, रूजवेल्ट की नई नीति और ट्रुमन के न्याय-व्यवहार ने मिलकर देश की अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे और आर्थिक क्षेत्र में सरकार के कर्तृत्व में गम्भीर परिवर्तन कर दिये थे। सघीय सरकार ने जन-कल्याण सम्बन्धी कार्यों के लिए नई जिम्मेदारियाँ अपने कन्धे पर ले ली थी। अर्थ-व्यवस्था का नियन्त्रण करने वाले सरकारी सगठनों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और वे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि सरकार ने कानूनी तौर पर देश में पूर्ण रोजगार का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था।

चुनाव आन्दोलन से समय डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि रिपब्लिकन पार्टी की विजय से शासन फिर से प्राइवेट 'स्वार्थों' हितों की कठपुतली बन जाएगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अपने चुनाव आन्दोलन में जिस आदर्श का प्रचार किया, वह 'राष्ट्रीय समाजवाद के ध्येय' से बहुत भिन्न था। उसने डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह आरोप भी लगाया कि वह अपने 'राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए वर्ग-विद्वेष पैदा कर रही है।' रिपब्लिकन पार्टी यह चाहती थी कि सघीय सरकार जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए जो बड़ी राशियाँ खर्च कर रही है, उन्हें वह घटा दे और टैक्सों में भी कमी कर दे। इसके विपरीत प्राइवेट पूँजी के विनियोग के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जाएँ। मोटे तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का कहना था कि सघीय सरकार राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कम भाग अदा करे, उसका बजट सन्तुलित हो, राष्ट्रीय ऋण धीरे-धीरे चुका दिया जाय और मुद्रा और वित्त सम्बन्धी नीतियाँ ऐसी हो, जो मूल्य-स्तर को स्थिर रख सके।

राष्ट्रपति आइसनहोवर ने अपने प्रशासन के पहले वर्ष कहा था, "पिछले बीस वर्षों में समाजवाद धीरे-धीरे सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर आक्रमण करता रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि "नए रिपब्लिकन प्रशासन ने अपने जमाने के सघीय शासन में एक तरह की क्रान्ति कर दी है। वह देश की अर्थ-व्यवस्था में सरकार के कर्तृत्व को बढ़ाने के बजाय छोटा करने का प्रयत्न करता रहा है, और उसे नए काम सौंपने के बजाय

उसके ऐसे काम तलाश करता रहा है, जिन्हे करने से उसे रोका जा सकता है।"

अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों पर आइसनहोवर प्रशासन ने जो नीति सवधी निश्चय किये, वे इस बात के द्योतक थे कि वह अवन्य नीति अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप को खत्म कर व्यापार-व्यवसाय को स्वतन्त्रता प्रदान करने की नीति का समर्थक था। उदाहरण के लिए उसके कुछ निश्चय और कार्य इस प्रकार थे

- कोरिया की लडाई के दिनों में गम्भीर मुद्रा स्फीति और महंगाई को रोकने के लिए लागू किये गए मूल्य और वेतन सम्बन्धी अनेक नियन्त्रण हटा दिये गए।

- पुनर्निर्माण वित्त निगम को खत्म कर दिया गया।

- प्रशासन में व्यवसायी वर्ग के लोगों को अथवा उनमें सहानुभूति रखने वालों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिये गए।

- सन् 1954 में टैक्सों में इस प्रकार के परिवर्तन किये गए, जिसने निजी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिले।

- कुछ नए वर्गों में सामाजिक सुरक्षा कानून के प्रसार के सिवाय और सभी जन-कल्याण सम्बन्धी सरकारी खर्चों में वृद्धि गैर दी गई। कानून में मशोधन कर नियमों को 62 वर्ष की आयु में अदकाश ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की गई। मधीय सरकार का जन-कल्याण सम्बन्धी प्रति-व्यक्ति व्यय 1958 में 1918 की अपेक्षा कम था, लेकिन उसका एक कारण सम्भवत यह था कि भारी विद्युतव्यापी मन्दी के दिनों में पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए जन-कल्याण सम्बन्धी जो कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए थे। उनमें से कुछ को 1950 के समृद्ध दशक में कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी।

- कृषि-जिन्नों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता कम कर दी गई और साथ ही उनमें कुछ लचकीलेपन का समावेश भी किया गया।

- प्राइवेट उद्योग-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक उद्यम उठाए गए। उदाहरण के लिए तटवर्ती नगरों में मधीय सरकार ने जो तेज-भंडार

संग्रह किये हुए थे, वे राज्यों को मौप दिए गये, हैल की कैनियन विजली परियोजना आदि अनेक सरकारी व्यवसाय प्राइवेट कम्पनियों को बेच दिये गए और 1946 के प्रमाणु शक्ति कानून में सशोषण कर गैरसरकारी व्यावसायिक संस्थानों के लिए भी परमाणु शक्ति के विकास के द्वार खोल दिये गए ।

किन्तु आइसनहोवर के अनुदार प्रशासन ने 1946 के रोजगार कानून को अस्वीकार नहीं किया, जिसके द्वारा सरकार ने पूर्ण रोजगार की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था । साथ ही उसने उस वित्तीय और मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भी अस्वीकार नहीं किया जिनका प्रयोजन मन्दी के दिनों में संघीय सरकार के खर्च को बढ़ाकर उत्पादन और रोजगार में वृद्धि को प्रोत्साहन देना था ।

इस प्रकार आइसनहोवर प्रशासन की अनुदार वित्तीय नीतियाँ पिछली पीढ़ियों की अनुदार नीतियों से बहुत भिन्न थी । यद्यपि राष्ट्रपति आइसनहोवर की 1954 की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया था कि “सरकार के व्यय और हस्तक्षेप को कम करना वाछनीय है,” तथापि उसी रिपोर्ट में आगे चलकर यह भी कहा गया था कि “हमारा समाज इतना जटिल और पेचीदा हो गया है कि प्रतिरक्षा की निरन्तर और भारी आवश्यकताओं का वहन तो सरकार को करना ही पड़ता है, साथ ही उसे ऐसे भी अनेक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने पड़ते हैं जिन्हें हम पिछली पीढ़ियों में जानते भी नहीं थे ।”

सन् 1955 की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया था कि “यदि सरकार वक्त रहते बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई करे तो वह बाद में आने वाली गम्भीर कठिनाइयों को टाल सकती है ।” और 1956 की रिपोर्ट में कहा गया था कि “सरकार हमारी अर्थ-व्यवस्था में एक प्रधान तत्त्व के रूप में हावी हुए बिना आर्थिक उतार-चढ़ाव को हल्का कर सकती है ।”

यह ठीक है कि आइसनहोवर प्रशासन द्वारा मन्दी और स्फीति का मुकाबला करने के लिए उठाये गए कुछ वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी कदमों की खासी आलोचना हुई, किन्तु तो भी आर्थिक नियन्त्रण के इन साधनों के काफी व्यापक उपयोग में यह साबित होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रशासन में सरकार ने पूर्ण रोजगार की व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व अपने

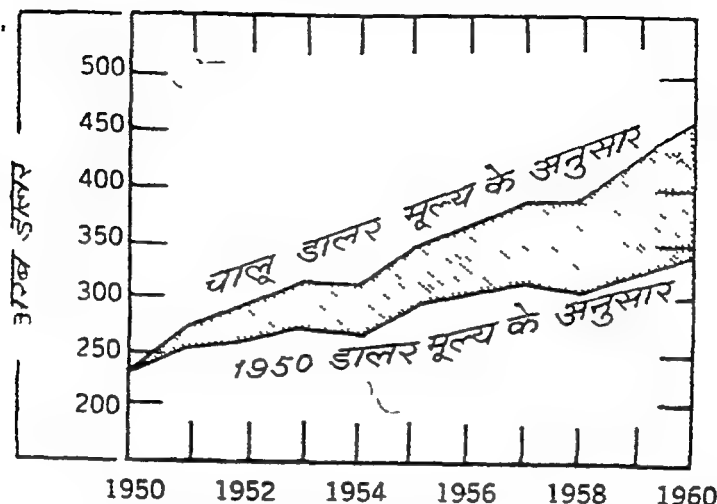
ऊपर लिया था, उसका रिपब्लिकन सरकार ने भी अपनी नीतियों से दृढ़ता से मर्मर्शन किया। नए प्रशासन द्वारा मन्दी और महँगाई की बार-बार पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए नए प्रशासन द्वारा उठाये गए कदमों पर सक्षेप से विचार कर इस तथ्य को भली-भाँति समझा जा सकता है।

आइसनहोवर प्रशासन को दो मदियों का सामना करना पड़ा— 1953-54 की और 1957-58 की। सन् 1953-54 के सकट का कारण यह था कि कोरिया की लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने अपने भारी खर्चों को एकदम कम कर दिया था (1953 की दूसरी तिमाही में जहाँ संघीय सरकार का व्यय 53 2 अरब डालर था वहाँ 1954 की चौथी तिमाही में वह घटकर 40 5 अरब डालर रह गया)। चार वर्ष बाद 1957-58 में कठिनाई होने का कारण भी ऐसा ही था। उस समय देश का निर्यात बहुत गिर गया और सैनिक सामग्री के आर्डर भी बहुत कम हो गए जिससे मशीनरी आदि के खर्चों में बहुत कमी हो गई। इन दोनों सकटों के समय बेरोजगारी बढ़ी। सन् 1958 की दूसरी तिमाही में देश की सात प्रतिशत श्रम-शक्ति बेकार पड़ी हुई थी।

हर सकट में सामाजिक सुरक्षा मुविधायें, कृषि-जन्मों के मृत्यों के स्थिरीकरण के लिए सहायता, बेरोजगारी का भत्ता और टैक्सों में स्वतः कमी आदि अस्थिरता निवारक उपायों ने सकट के प्रभाव की भयकरता को कुछ कम किया। इनके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वायत्त आय में उतनी कमी नहीं हुई, जितनी कि राष्ट्रीय आय में हुई। राष्ट्रीय आय की तुलना में व्यक्तिगत स्वायत्त आय कुल 49 प्रतिशत ही घटी। उपभोक्ताओं को अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता में अब भी इतना भरोसा था कि लोगों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय 1954 और 1958 के मन्दी से पूर्व के उच्चतम स्तर में कुल एक ही प्रतिशत घटा।

इनके साथ ही प्रशासन की नीतियों ने व्यापार-उद्योग की हर मन्दी के प्रभाव को हल्का करने की कोशिश की। सन् 1953-54 की मन्दी में एक और संघीय आरक्षित निधि बोर्ड ने ऋण और उधार को नीति की अधिक उदार बनाकर निवेश को प्रोत्साहन दिया और दूसरी ओर टैक्सों में पहले

कुल राष्ट्रीय आय 1950-60



कुल राष्ट्रीय आय का अभिप्राय देश में उत्पादित तमाम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह स्पष्ट है कि 1950 और 1960 के बीच राष्ट्रीय आय में 76.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किंतु इस वृद्धि का कुछ अंश भ्रामक है, क्योंकि डालर की क्रय-शक्ति में इस अवधि में ह्रास हो गया। इसलिए डालर के स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि कुल 36.8 प्रतिशत हुई, परन्तु यह भी काफी बड़ी वृद्धि है।

से ही सुयोजित कटौती ने अर्थ व्यवस्था में नई क्रय-शक्ति भर दी।

सन् 1957-58 की मन्दी के समय सरकार ने उसका मुकाबला करने के लिए कुछ भिन्न किस्म की नीति अपनाई। प्रशासन ने टैक्सों में और भी अधिक कमी करने की व्यापक माँग का दृढ़ता से सामना किया। किन्तु टैक्सों में कमी न करते हुए भी सरकार ने स्थानीय और राज्यीय ऋणों और पूँजी-निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया।

इसके अलावा सरकार ने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कुछ और उपाय भी वरते। उदाहरण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उसने

1958 के पूर्वार्द्ध में 1957 के उत्तरार्द्ध की अपेक्षा सैनिक सामग्री के दुगुने आर्डर दिए। सरकार के अन्य व्यय-कार्यक्रमों ने भी लोगों की आय बढ़ाने और माँग को गिरने से बचाने में योग दिया। सघीय सरकार ने जून, 1957 में समाप्त वित्तीय वर्ष में 80 अरब डालर खर्च किया था, किन्तु जून, 1959 में समाप्त वर्ष में उसका व्यय बढ़कर 94 अरब डालर हो गया। सघीय ऋण की सीमा में भी वृद्धि हो गई। सन् 1959 के वित्तीय वर्ष में सघीय बजट में 12.5 अरब डालर का घाटा था, जो राष्ट्र के इतिहास में शान्ति काल का सबसे अधिक घाटा था।

यद्यपि हर बार मन्दी से राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था बहुत जल्दी उभर आई और कुल राष्ट्रीय आय भी मन्दी से पहले के स्तर से 4 प्रतिशत से अधिक नीचे नहीं गई, तो भी इन मन्दियों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ अवश्य हुईं। इन प्रतिक्रियाओं का ही यह परिणाम था कि 1954 और 1958 के कांग्रेस के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने विजय प्राप्त की। मन्दी से ग्रस्त इलाकों में जनता ने सरकार से असन्तुष्ट होकर डेमोक्रेटिक पार्टी को जो वोट दिए, वे यह सिद्ध करते थे कि जनता पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति को स्वीकार करने के लिए किसी भी तरह राजी नहीं थी।

अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति के अनुकूल बनाने के प्रयत्न 1950 के दशक के आर्थिक इतिहास का सिर्फ एक पहलू है। इसका एक पहलू और भी है। वह पहलू है इस स्थिति को कायम रखने के प्रयत्नों से उत्पन्न स्फीति और महँगाई की सम्भावनाओं को रोकने की प्रयासों की कोशिश। सन् 1950 के दशक के मध्य में महँगाई को रोकने की यह समस्या और भी स्पष्ट रूप में सामने आई। सन् 1952 के मध्य तक कोरिया की लड़ाई से उत्पन्न स्फीति और महँगाई का जोर घट गया और अगले चार वर्षों में देश में काफी हद तक मूल्य स्थिर रहे। किन्तु इसके बाद मार्च, 1956 से मार्च, 1958 तक दो वर्षों में उपभोग्य वस्तुओं का सूचक अंक फिर 7.5 प्रतिशत बढ़ गया।

स्फीति और महँगाई के कारणों के बारे में अर्थ-शास्त्रियों में बहुत मत-भेद रहा। कुछ लोग इसका कारण पुरानी परम्परागत दलील के अनुसार बताते थे। उनका कहना था कि वस्तुओं की उपलब्धि कम है और माँग

अधिक। दूसरे लोगो का कहना था कि महँगाई बढ़ने का कारण वस्तुओ के उत्पादन की लागत बढ़ जाना है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह था कि देश की उपलब्ध श्रम-शक्ति पर अनेक औद्योगिक ट्रेड यूनियनों ने पूर्ण अधिकार स्थापित किया हुआ था और इसका लाभ उठाकर वे बाजार की स्थिति को ध्यान में रखे बिना मनमानी वेतन-वृद्धि माँगती थी जिससे वस्तुओ का उत्पादन-व्यय बढ़ जाता था। इसी तरह कुछ कम्पनियों की बाजार में एकाधिकार की-सी स्थिति थी, जिससे वे अपने उत्पादनों का मनमाना मूल्य रख सकती थी, दरअसल, उद्योगों के संचालकों की ओर से अक्सर यह तर्क दिया जाता था कि मजदूरी और वेतनों के बढ़ जाने के कारण उनका अपने माल की ऊँची कीमत रखना अत्यन्त आवश्यक है। जो भी हो, यह सही है कि मजदूरी और अन्य चीजों की लागत के, बाजार की स्थिति की परवाह किए बिना बढ़ते जाने के कारण कीमतें ऊँची हो गई थी।

महँगाई और स्फीति का कारण चाहे जो हो, प्रशासन ने उसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। सन् 1955 और 1958 के बीच सघीय आरक्षित निधि बोर्ड की नीति 1920 के दशक की अपेक्षा वही अधिक कठोर और मुट्ठी-भीच थी। सघीय सरकार ने अपने खर्च में कमी कर दी। इस कटौती ने मुद्रा-स्फीति को कुछ हद तक रोका अवश्य, किन्तु 1950 के दशक के मध्य में मूल्य-वृद्धि ने मुद्रा और वित्त सम्बन्धी नियन्त्रणों और मितव्ययिता की प्रभावकारिता के बारे में गम्भीर सन्देह पैदा कर दिए।

अनुदार विचारधारा के लोग जब स्फीति की गम्भीर समस्या का मुकाबला कर रहे थे, तब कुछ वस्तु-स्थितियाँ उनके सामने स्पष्ट होकर खड़ी हो गईं। यह जाहिर हो गया कि सन्तुलित बजट बनाना सरकार के निश्चयों पर उतना अवलम्बित नहीं है, जितना कि अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर। कारण, सरकार अगर अपने खर्च में कमी करना भी चाहे, तो अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाएँ उसके मार्ग में खड़ी हो जाती हैं।

पहली बात यह कि स्वयं स्फीति का अस्तित्व ही सरकार की खर्च की योजनाओं में कटौती करना कठिन बना देता है। इसके अलावा कृषि-जिनसों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सहायता देने के कार्यक्रमों भूतपूर्व सैनिकों

की पेन्शनो और स्टाक जमा करने के लिए सामान की खरीद के दायित्वों को भी सरकार को पूरा करना पड़ता है। इसी तरह श्रमिकों को वृद्धापे की पेन्शन और बेरोजगारी का मुआवजा आदि देने के लिए ट्रस्ट निधियों में भी उनके लिए धन डालना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त हवाई यातायात नियन्त्रण, राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण और चिकित्सा अनुसन्धान आदि अन्य अनिवार्य कार्यक्रम भी सरकार के खर्च में वृद्धि करते हैं।

किन्तु बजट में सबसे बड़ी खर्च की मदें थी प्रतिरक्षा और वैदेशिक सहायता की। रिपब्लिकन प्रशासन प्रतिरक्षा के भार को अधिक घटाने में समर्थ नहीं था, और न वह उसके लिए तैयार ही था, क्योंकि सैनिक टेक्नोलॉजी में भारी क्रान्ति हो रही थी और उसके लिए अधिक व्यय करना आवश्यक था। उसके अलावा राष्ट्रपति ने मित्र राष्ट्रों और अन्य विकसित देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता देने के काफी बड़े वायदे किये हुए थे।

संयुक्त राज्य के 1960 के दशक में प्रवेज के समय अमेरिकन प्रशासन के सम्मुख सबसे प्रधान प्रश्न यह था "क्या वर्तमान परिस्थितियों में, जब कि शीत-युद्ध जोरों पर है, सरकार ने मूल्य-स्थिरीकरण और सैनिक पेन्शन आदि के उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं, राष्ट्रीय ऋण काफी बढ़े हुए हैं और बैंकिंग प्रणाली भी काफी उदारता से ऋण दे रही है, यह सम्भव है कि प्रशासन व्यापारिक उत्कर्ष को एकदम खण्ड-वण्ड करने गिरा देने वाला मन्दी का चक्कर आने में पूर्व ही मूल्यों की वृद्धि को रोक सके ? यदि यह मान लिया जाए कि आज की परिस्थितियों में, जब कि मजदूर वर्ग और उद्योग-व्यवसाय, दोनों ही बहुत बड़े हो गए हैं, पुराने तरीकों में काम चल सकता है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार उन पुराने तरीकों से महंगाई और स्फीति को समस्या को हल कर सकेगी ?"

युद्धोत्तर काल की समीक्षा

संयुक्त राज्य आज अधिकतम रोजगार, अधिकतम उन्नति और अधिकतम मूल्य-स्थिरता, तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक निकट प्रतीत होता है। किन्तु दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में आई तीन मन्दियाँ और निरन्तर चली आ रही हल्की स्फीति इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था ऐसी स्थिति में नहीं पहुँची, जहाँ वह संकटों में पूर्णतः मुक्त हो।

युद्ध के वर्षों में अनेक अत्यधिक आदरणीय अर्थशास्त्री, खास कर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एल्विन एच० हैन्सन, यह दलील देते थे कि संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था ऐसी परिपक्व 'निश्चल' अवस्था में पहुँच गई है, जहाँ उसके लिए आर्थिक अभिवृद्धि का ऐसा स्तर कायम रखना, जो अधिकतम रोजगार के अनुकूल हो, अधिकाधिक कठिन होगा। हैन्सन ने यह आशंका प्रकट की थी कि जनसंख्या में वृद्धि की गति का मन्द होना, प्राकृतिक साधन-सम्पदा का धीरे-धीरे क्षीण और विलुप्त होते जाना और बड़ी कम्पनियों में अपने लाभ को पुनः व्यवसाय में लगाने के बजाय बचाए रखने की प्रवृत्ति का बढ़ना—इन सबके परिणाम बहुत गम्भीर और विनाशकारी होंगे।

लेकिन इन सब आशंकाओं के बावजूद संयुक्त राज्य की युद्धोत्तर-कालीन अर्थ-व्यवस्था बहुत सफलता से अग्रसर होती रही। मई 1959 में प्रचलित डालर मूल्य के हिमाव से 1946 में संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय आय 3 खरब 19 अरब 50 करोड़ डालर थी, किन्तु 1960 में वह बढ़कर 5 खरब डालर हो गई। यह वृद्धि 56 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी प्रकार इसी अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्त आय (डिस्पोजेबल इनकम) भी 36 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।

इस वृद्धि को समझने में निम्न कारण सहायक सिद्ध हो सकते हैं

- श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि राष्ट्रीय आर्थिक अनुमन्धान व्यूरो (नेशनल व्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च) की 1959 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति

मानव-घण्टा उत्पादन, जो दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व हर दशक में औसत 29 प्रतिशत बढ़ता था, इस युद्ध के बाद 35 से 40 प्रतिशत तक प्रति दशक के हिसाब से बढ़ा। यह उत्पादकता वृद्धि अधिकांशतः स्वचालित यन्त्रों और नये टेक्नोलॉजिकल और वैज्ञानिक अनुसन्धानों और आविष्कारों का परिणाम थी।

● **आवादी में वृद्धि** सन् 1930 के दशक में विशेषज्ञों की भविष्यवाणी थी कि 1970 तक संयुक्त राज्य की आवादी 14 करोड़ हो जाएगी। किन्तु वास्तव में जनसंख्या-वृद्धि इससे कहीं अधिक तेज गति से हुई और 1950 के मध्य में ही वह 17 करोड़ हो गई और 1960 में वह और भी अधिक बढ़कर 18 करोड़ तक पहुँच गई।

● **उधार ऋण की सुविधाओं का साधारण विस्तार** सन् 1946 में स्वल्प और मध्यम अवधि के ऋण, खासकर लोगों को किस्तों पर उधार सामान खरीदने के लिए दिये गए ऋण 84 अरब डालर थे, किन्तु 1959 में वही बढ़कर 50 अरब डालर हो गए। इसी अवधि में कृषि-भिन्न बन्धक ऋण (सम्पत्ति गिरवी रखकर लिया गया ऋण) 23 अरब डालर से बढ़कर 1 खरब 31 अरब डालर तक पहुँच गया। बन्धक ऋण में हुई इस वृद्धि का लाभ यह हुआ कि कृषकेतर परिवारों में से 60 प्रतिशत के 1960 तक अपने मकान हो गए। यह ऋण अधिकतर सरकार ने ही सस्ती व्याज दरों पर दिए। सन् 1959 में दिये गए बन्धक ऋणों का लगभग आधा भाग या तो मधीय सरकार के आवास विभाग ने दिया था या भूतपूर्व सैनिक विभाग ने।

● **सरकार की कार्यवाहियों में वृद्धि** मन्दी के चक्रों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रा और वित्त सम्बन्धी नीतियों ने सकट के समय राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को सकट से उवारा। इन मुद्रा सम्बन्धी और वित्तीय नीतियों को बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यक्रमों ने भी बल दिया, जो मन्दी को रोककर स्वतः अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों ने मन्दी के समय देश की अर्थ-व्यवस्था में नई आय के द्वार खोले। इसीलिए 1949, 1954 और 1956 की मन्दियों के दौरान में उत्पादन और रोजगार में होने पर भी लोगों की व्यक्तिगत स्वायत्त आय खासे ऊँचे स्तर पर बनी रही।

सरकार के कर्तृत्व में वृद्धि का दूसरा पहलू था सरकारी व्यय में वृद्धि। सन् 1929 में जहाँ मधीय, राज्यीय और नागरिक सरकारों ने सब मिलाकर कुल राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत खर्च किया था, वहाँ 1959 में उन्होंने 20 प्रतिशत व्यय किया। दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद के बारह वर्षों में अकेले प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए ही सरकार ने 4 खरब डालर खर्च किये।

युद्धोत्तरकाल में कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ, जो अमेरिकन समाज रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती थी, अधिक स्पष्ट हो उठी।

इनमें से एक प्रवृत्ति थी, एक नये मध्य वर्ग की अभिवृद्धि। सन् 1870 से 1940 तक मफेद पोश मध्यवर्ग (वेतन भोगी दफ्तर कर्मचारी आदि) ही आवादी की दृष्टि में सबसे अधिक बढ़ा। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद इस वर्ग की अभिवृद्धि का रुझान और भी स्पष्ट और प्रखर हो उठा।

इससे भी अधिक नाटकीय परिवर्तन यह था कि लोग अब निर्माण-कार्य से हटकर दूसरे कामों में रोजगार पर जा रहे थे। आज संयुक्त राज्य ही एक मात्र ऐसा देश है, जहाँ सामान के उत्पादन की अपेक्षा उसके वितरण और सेवाओं में अधिक लोग लगे हुए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि निर्माण-उद्योगों में उत्पादकता बहुत बढ़ गई है (खासतौर से स्वचालित यन्त्रों के प्रयोग से) और दूसरे विश्व-युद्ध के बाद तो यह वृद्धि का रुझान और भी तीव्र हो गया है। सन् 1947 के बाद निर्माण-उद्योगों में उत्पादन का काम करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग दस लाख कम हो गई है, फिर भी उत्पादन 50 प्रतिशत बढ़ा है। निर्माण-उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि सिर्फ ऐसे ही वर्गों में हुई है, जो उत्पादन नहीं करते—उदाहरण के लिए दफ्तरों के कर्मचारी और विक्रय विशेषज्ञ आदि। वास्तव में युद्धोत्तरकाल में नये रोजगार के अवसर अधिकतर देश की अर्थ-व्यवस्था के सेना सम्बन्धी क्षेत्र में ही पैदा हुए हैं, निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में नहीं।

सामाजिक रचना में दूसरा दीर्घकालीन परिवर्तन था बड़े आर्थिक वर्गों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक सत्ता की अधिक प्राप्ति। युद्धोत्तर काल में विशाल कम्पनियों की आर्थिक अभिवृद्धि के साथ ही विशाल राष्ट्रीय श्रमिक

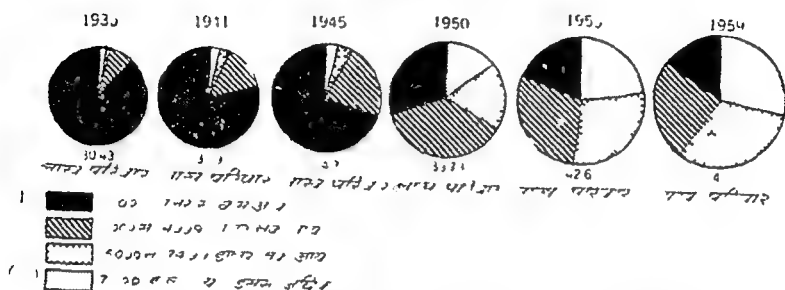
सघो की शक्ति मे भी भारी वृद्धि हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि मूल्यो और वेतनो का निर्धारण बाजार मे होने के बजाय कम्पनियो के सम्मेलन कक्षो मे मेज के चारो ओर बैठकर सम्बद्ध पक्षो की आपसी सौदेबाजी से होने लगा । इसके बावजूद मूल्य अन्ततः अब भी उपभोक्ताओ की माँग मे घट-वढ से काफी हद तक प्रभावित होते है, हालाँकि प्रारम्भ मे कुछ समय तक उनमे काफी स्थिरता रहती है । लेकिन सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मूल्यो मे कमी नही हो रही, निरन्तर वृद्धि ही हो रही है और यही कारण है कि युद्धोत्तर अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था मे धीरे-धीरे महँगाई और स्फीति बढ रही है ।

कृषि पर टैकनोलॉजी के दीर्घकालीन प्रभावो ने खेती की पुरानी समस्या को फिर उभार कर सामने ला खडा किया । दूसरे विश्वयुद्ध मे और उसके बाद कोरिया की लडाई मे भी समुद्र पार के बाजारो मे अमेरिका की कृषि-जिन्सो की बहुत माँग रही । लेकिन 1953 के बाद फालतू कृषि उत्पादनो की समस्या ने फिर उग्र रूप धारण कर लिया । कृषि मे उत्पादकता 1946 और 1959 के बीच बढकर लगभग दुगुनी हो चुकी थी, इसीलिए खेती मे लगे लोगो की सख्या इस अवधि मे 31 प्रतिशत कम हो जाने पर कृषि उत्पादन 25 प्रतिशत बढ गया । स्पष्टतः इसका कारण यह था कि कृषि-टैकनोलॉजी देश की कृषि-उत्पादनो को खपाने की गति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ रही थी । अभी तक इस समस्या के समाधान की दिशा मे बहुत कम प्रयत्न किया गया है ।

टैकनोलॉजी की उन्नति ने अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था की एक और दीर्घ-कालीन समस्या को उग्र से उग्रतर कर दिया है और वह समस्या है देश की सामान्य खुशहाली और समृद्धि के बीचोबीच गरीबी के कुछ अवशेषो का अस्तित्व । देश के कुछ इलाको मे जो मन्दी और उद्योग-व्यापार की गिथिलता के हमेशा शिकार रहते है, टैकनोलॉजी की उन्नति ने गरीबी को और बढा दिया है और रहन-सहन का स्तर गिरा दिया है, क्योंकि स्वयंचालित यन्त्रो और टैकनोलॉजी के अन्य अभिनव आविष्कारो के उपयोग ने वहाँ खेती, खानो और निर्माण-उद्योगो मे कर्मचारियो की छटनी मे वेरोअगारी बढा दी है । पश्चिमी वर्जोनिया के कोयला खान क्षेत्र इसका एक ज्वलन्त उदाहरण

है। संयुक्त राज्य में आय के असमान वितरण से सम्बद्ध इन तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर गम्भीर और व्यापक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

पारिवारिक आय का विभाजन (वार्षिक आय के विभिन्न वर्गों का प्रतिशत हिसाब)



सन् 1930 के दशक की भारी मन्दी के बाद संयुक्त राज्य में लोगों की पारिवारिक आय में भारी वृद्धि हुई है, जैसा कि इस चार्ट से स्पष्ट है।

ये समस्याएँ अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालीन रुझानों का परिणाम हैं। लेकिन युद्धोत्तरकालीन वर्षों में राष्ट्र के सामने कुछ और नई समस्याएँ भी आ खड़ी हुईं। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी आर्थिक अभिवृद्धि की प्रक्रिया की। अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, दोनों ही आज राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की मात्रा और स्वरूप को लेकर बहस-मुवाहसे में पड़े हुए हैं।

पिछले चालीस वर्षों में संयुक्त राज्य की आर्थिक अभिवृद्धि पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो, कम से-कम जहाँ तक इस अभिवृद्धि की मात्रा और विस्तार का सम्बन्ध है, चिन्ता का कोई कारण नजर नहीं आया। सन् 1919 और 1959 के बीच राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय में औसत 29 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद आर्थिक वृद्धि की गति मन्द होने लगी। सन् 1947 और 1958

युद्धोत्तर काल की समीक्षा

के बीच कुल राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि का औसत 1.6 प्रतिशत था। इस अवधि में मन्दी से रहित वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मन्दी के वर्षों में वृद्धि बिल्कुल नगण्य थी। इससे यह भी प्रतीत होती है कि एक हल्की-सी मन्दी भी सयुक्त राज्य के आर्थिक विकास की गति को शिथिल कर सकती है।

अन्य देशों की आर्थिक अभिवृद्धि के साथ तुलना करने पर मालूम होगा कि सयुक्त राज्य की अभिवृद्धि वैसी प्रभावोत्पादक नहीं है। यद्यपि विभिन्न देशों की कुल राष्ट्रीय आयों की तुलना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो भी इस बात के प्रमाण हैं कि सयुक्त राज्य की आर्थिक अभिवृद्धि की गति पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों की अभिवृद्धि की गति से धीमी है। किन्तु यह तुलना करते हुए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि युद्ध के बाद सप्ताह के अनेक राष्ट्र सयुक्त राज्य की अपेक्षा विकास के कहीं नीचे स्तर पर थे। यदि अभिवृद्धि की प्रतिशतकता के हिसाब से नापा जाय तो स्वभावतः जो राष्ट्र विकास के नीचे स्तर से प्रारम्भ करेगा, उसकी प्रतिशत अभिवृद्धि पहले से ही ऊँचे स्तर पर विद्यमान राष्ट्रों से अधिक सिद्ध होगी। फिर भी सयुक्त राज्य में लोग अब इस बात पर बल देने लगे हैं कि वार्षिक अभिवृद्धि की गति को और भी बढ़ाया जाना चाहिए।

हमारी आर्थिक समृद्धि का दूसरा विवादग्रस्त पहलू उसका स्वरूप रहा है। सन् 1950 के दशक में इस विवाद में अनेक अलोचकों ने यह कहा है कि राष्ट्र के धन और साधनों का समुचित वितरण नहीं हो रहा। उनका कहना था कि श्रम और पूँजी दोनों का जितना उपयोग उपभोक्ताओं के काम की टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण में हो रहा है, उसकी तुलना में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर-सुधार आदि आधारभूत सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में उनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है।

सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में ऐसा प्रतीत होना है कि आधारभूत सामाजिक सेवाओं की बहुत उपेक्षा होती रही है। उदाहरण के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा-शुल्क में काफी वृद्धि कर देने पर भी भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सरकारी क्षेत्र में भी, जहाँ अलोचकों को सबसे अधिक कमियाँ और त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, स्कूलों

कोई देश अच्छी नहीं रही। अधिकतर स्कूलों में छात्रों की संख्या उससे कहीं अधिक रही, जितनी संख्या को भली-भाँति शिक्षा दी जा सकती थी। विरोधियों का कहना है कि 1945 के बाद संयुक्त राज्य के सरकारी स्कूलों में 1,80,000 नये कक्षा भवनों का निर्माण किया गया है, फिर भी 1959 में सारे राष्ट्र में 1,30,000 कक्षा-भवनों की कमी थी। अस्पताल की सुविधाओं में भी बहुत अधिक कमी रही है। अनेक गहरों में भीड़-भाड़ इतनी कदर रही है कि उनमें मोटरों और बसों का चलाना प्रायः असम्भव रहा है। स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि राष्ट्रपति के सार्वजनिक निर्माण कार्यों के विरोध सहकारी मेजर-जनरल जे० एस० ब्रैगडन ने 1959 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि “क्या अस्पताल और क्या स्कूल या नागरिक मनोरंजन केन्द्र—सभी सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में हमें कमी नजर आ रही है और यह कमी अपवाद नहीं, नियम बन गई है।”

उपभोक्ता भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यद्यपि अमेरिकन लोग संसार के अन्य सभी देशों से अधिक सामाजिक सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, फिर भी उनमें घरेलू मशीनों और घरों में काम आने वाली अन्य टिकाऊ वस्तुओं पर बहुत अधिक खर्च करने की और शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर बहुत कम खर्च करने की प्रवृत्ति है।

फिर भी संयुक्त राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि 1950 के दशक में इन त्रुटियों के बावजूद संयुक्त राज्य जिस समृद्धि का उपयोग कर रहा था, वह संसार के सभी देशों के लिए, यहाँ तक कि सोवियत संघ के लिए भी, ईर्ष्या और स्पृहा की वस्तु था। कारण यह कि 1950 के दशक में संयुक्त राज्य को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, एक समझदार आलोचक के शब्दों में, वे समृद्धि और बाहुल्य से उत्पन्न समस्याएँ थीं। यदि अमेरिकन लोग यह अनुभव करने लगे थे कि उपभोग और सामान्य भौतिक सुख-सुविधाओं का ऊँचा स्तर ही मानवीय सुख में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उनका इस बात पर बल देना भी सही था कि समृद्धि और बाहुल्य की समस्याओं को मनुष्य अभाव और गरीबी की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सहन कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से अन्य देश भी स्वयं बाहुल्य की ही समस्याओं के समाधान के लिए

चिन्तित और व्याकुल थे ।

युद्धोत्तर काल में अमेरिकन अर्थ-व्यस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्ण रोजगार, मूल्यों की स्थिरता और आर्थिक अभिवृद्धि को कायम रखने के लिए साधन खोजने की थी । उपलब्धियों के किसी भी पैमाने से नापने पर यह बात निश्चय होकर कही जा सकती है कि अमेरिकन जनता ने 1950 के दशक का उपयोग इन चुनौतियों का प्रभावकारी ढंग से सामना करने के लिए किया । फिर भी जो काम अबूरे रह गए, उन्हें भविष्य में पूर्ति के लिए छोड़ा जा सकता है ।

नये युग की चुनौती

उपसंहार

संयुक्त राज्य की जनता को आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में नये युग की यथार्थताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कुछ थोड़े से चुने हुए विशेषज्ञों या



जॉन एफ० कैनेडी

मत-निर्धारकों का वक्त की आवश्यकताओं को पहचानना एक बात है और सारे समाज का अपने अतीत के कार्यों का सिंहावलोकन करना, अपनी वर्तमान कमजोरियों और ताकतों का मूल्यांकन करना और भविष्य की आवश्यकताओं को पहले से ही अनुमान कर उनके अनुरूप अपनी मनोवृत्ति बनाना बिल्कुल दूसरी ही बात है।

एक अपेक्षाकृत स्वतन्त्र समाज में, जहाँ विविध प्रकार की सम्मतियों,

रुचियों और यहाँ तक कि पूर्वग्रहों को भी अभिव्यक्त करने की गुंजायश है और उन्हें अभिव्यक्त किया भी जाता है, वहाँ न तो जन-कल्याण की सहज में ठीक-ठीक व्याख्या ही की जा सकती है और न उसे आसानी से हीन रूप

मे प्रस्तुत कर उपेक्षित ही किया जा सकता है। आठ नवम्बर, 1960 का आम चुनाव ऐसे वक्त आया जब कि संयुक्त राज्य के भविष्य के बारे में विचारों को काफी स्पष्ट रूप दिया जा चुका था, और उन्हें क्रियान्वित करने या न करने के प्रश्न को सार्वजनिक विवाद का विषय बनाया जा सकता था। जनता ने राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवारों में से, जिन्होंने अमेरिकन समाज के सामान्यतः स्वीकृत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी-अपनी दृष्टि से आवश्यक और उपयुक्त कार्यक्रम पेश किए, एक को चुन लिया।

आज हम फिर एक नई सोमा पर खड़े हैं, चाहे, हम उसे पसंद करें या न करें। इस सोमा के पार जाकर हमें विज्ञान और अंतरिक्ष के अज्ञात प्रदेशों की खोज करनी है, शान्ति और युद्ध की अनसुलझी समस्याएँ सुलझानी हैं, अज्ञान और पूर्वाग्रह के अविजित स्थलों को जीतना है और गरीबी और इफरात के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर खोजना है।

—जॉन एफ० कॅनेडी

15 जुलाई, 1960 को राष्ट्रपति-पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए।

जॉन एफ० कॅनेडी की विजय बहुत कम मतों के अन्तर से हुई, इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मिट्टान्तों के मामले में देश में पूर्ण ऐक्य नहीं था। इसीलिए नये प्रशासन को न गलियों में किसी उपद्रव का सामना करना पड़ा और न ही समझ ने उसके मार्ग को अव्यर्थ किया। चुनाव आन्दोलन में नव दलों ने अपने-अपने पक्ष में प्रचार किया और मत-दाताओं में अपील की, किन्तु जहाँ एक बार चुनाव सम्पन्न होने पर यह आन्दोलन अतीत की वस्तु बन। कि नारे राष्ट्र ने दलगत भेदभाव भुलाकर सत्ता के सुव्यवस्थित और निर्विघ्न हस्तान्तरण का न्वागत किया और वह भविष्य की समस्याओं और अवसरों का सामना करने के लिए उत्तुंग हो उठा। वारण, देश का अत्यन्त जाहिल और जाहिल नागरिक भी यह अनुभव कर

~~समस्या थी~~ कि 1960 के दशक की नई आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए निपुणता, सामंजस्य-कौशल और अनुक्रियाशीलता के एक विशिष्ट मिश्रण की जरूरत होगी। युद्धोत्तर काल अब समाप्त हो चुका था। इसलिए स्वभावतः देशवासियों के लिए अभिनव क्षेत्रों में प्रवेश का वक्त आ गया था।

अमेरिका के आर्थिक इतिहास को किसी भी अन्य राजनीतिक स्थिरता वाले समाज की भाँति उतार-चढ़ाव के न्यूनाधिक नियमित चक्रों में बाँटा जा सकता है। खास तौर से गृह-युद्ध की समाप्ति के बाद, जब कि आज के उद्योग-व्यापार सम्पन्न सयुक्त राज्य का वास्तविक उदय प्रारम्भ हुआ, हमें ये उतार-चढ़ाव स्पष्ट नजर आते हैं। इन चक्राकार उतार-चढ़ावों में हम एक बार अनुदार प्रशासन को सत्तारूढ़ देखते हैं तो दूसरी बार उदार प्रशासन को, एक बार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप-रहित अद्वन्द्व नीति का बोलवाला देखते हैं तो दूसरी बार सरकारी नियन्त्रणों और प्रतिबन्धों का, एक बार तीव्र गति से आर्थिक अभिवृद्धि का युग देखते हैं तो दूसरी बार मन्दी और ह्रास का एव राष्ट्र के अपने-आपको तदनुकूल बनाने के प्रयत्नों का। ये उतार-चढ़ाव अमेरिकन समाज में पाई जाने वाली एक 'अपूर्णता' के परिणाम हैं, किन्तु यह अपूर्णता भी लाभकारी है, क्योंकि वह विचारों की विविधता को भी एक युग में परिणत कर देती है और लोगों के व्यक्तिगत निश्चयों और आकांक्षाओं के भीतर से एक राष्ट्रीय लक्ष्य को निकालकर देश के सामने रख देती है। सयुक्त राज्य की आर्थिक प्रणाली निर्विघ्न भाव से बिना किसी विच्छेद के चली आ रही है, यह अमेरिकन जनता के आत्म-विश्वास का बहुत बड़ा प्रमाण है। और यह प्रणाली भविष्य में भी इसी तरह चलती रह सकती है, क्योंकि अमेरिकन जनता में स्वशासन की विशेष प्रतिभा और क्षमता है।

किन्तु एक अपूर्ण समाज की उपज होने के कारण, (और पूर्ण समाज है ही कहाँ ?), अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था की भी कुछ अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं, जिन्हें 1960 के दशक में देश को हल करना है। ये समस्याएँ एक सुविकसित अर्थतन्त्र की समस्याएँ हैं, जिसमें जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम उतना नहीं है, जितना कि जीवन की पूर्णता को पूर्णतर

वनाने का काम है, जहाँ वस्तुओं की अपर्याप्तता उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या उनका अत्यधिक बाहुल्य है।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद एक दशक से भी अधिक समय तक अमेरिकन जनता अपने जीवन-स्तर में आई उस गिरावट को पूरा करने में व्यस्त रही, जो इस विश्वव्यापी युद्ध के कारण आ गई थी। इस अवधि में उपभोग्य वस्तुओं की खरीद में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि देश की अर्थ-व्यवस्था एक नये ऊँचे स्तर पर पहुँच गई। सन् 1959 तक अमेरिका में तीन-चौथाई परिवारों के पास अपनी निज की मोटर कारें थीं। 90 प्रतिशत अमेरिकन घरों में टेलीविजन सेट और कपड़े धोने की मशीनें थीं। और ऐसा तो गायब एक भी घर नहीं होगा जहाँ रेडियो न हो और रेफ्रिजरेटर भी प्रायः हर घर में पाया जाता था।

टिकाऊ उपभोग्य सामग्रियों का इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकन जनता द्वारा उपयोग स्पष्टतः यह सिद्ध करता है कि अमेरिकन समाज के एक विशाल भाग को जीवन की भौतिक सुख-सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सन् 1970 के लिए अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के जो लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, वे भी किसी तरह निरुत्साहित करने वाले नहीं हैं। यदि एक दशक के भीतर जनसंख्या में 20 प्रतिशत भी वृद्धि हो जाय तो भी एक दशक के भीतर राष्ट्रीय आय को 7 खरब 90 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य पूरा हो जाने पर प्रतिव्यक्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य की दृष्टि से 36 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जब हम अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था की 'नमस्याओं' का उल्लेख करते हैं तो हमारा अभिप्राय नमस्या के सामान्य अर्थ से नहीं होता।

आज अमेरिकन जनता के मन में जिन आर्थिक स्तर की आकांक्षा है, वह निःसन्देह बहुत ऊँचा है। कारण युद्धोत्तर काल के समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका की स्थिति में एकाएक नाटकीय परिवर्तन हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसके अनेक प्रतिद्वन्दी पैदा हो गए हैं। उन नई स्थिति ने अमेरिका की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर सुदृढ़, किन्तु गम्भीर प्रभाव डाला है, जिससे अमेरिकनों के लिए अपने मन के अनुकूल भावी समाज के निर्माण में अनेक बाधाएँ पैदा हो गई हैं।

यदि नवीन जनता आज जिन ऊँचे लक्ष्यों को पाना चाहती है, उनमें से पहला यह है कि उसे आय की अबसे अधिक सुरक्षा और सुनिश्चितता प्राप्त हो। आर्थिक दृष्टि से मन्दी के शिकार रहने वाले इलाकों में, या बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से सामान तैयार करने वाले उन उद्योगों में, जो अपनी युद्धोत्तरकालीन अभिवृद्धि की तीव्र गति को कायम नहीं रख सके हैं, बेरोजगारी अधिक होने के कारण देश की कुल असैनिक श्रम-शक्ति का कम-से कम पाँच प्रतिशत भाग 1959 से बेरोजगार चला आ रहा है। यद्यपि देश के बेतनोपजीवी लोगों की एक विशाल संख्या की आय अन्य देशों की तुलना में काफी ऊँची है, फिर भी टेक्नोलॉजिकल आविष्कारों और नवीन विधियों एवं बाजार की माँग में तेजी से होने वाले परिवर्तनों ने करीब 27,00,000 व्यक्तियों को न्यूनाधिक बेरोजगार बना दिया है। इसके साथ ही समय-समय पर आने वाले व्यापारिक मन्दी के चक्करों, बड़े लोगों की लम्बी बीमारी के खर्च को वहन करने की असमर्थता, बड़ी व्यापारिक कंपनियों और संगठनों एवं मजदूर यूनियनों के बीच आपसी समझौते से हुए निश्चयों के सार्वजनिक प्रभाव, स्फीति और महंगाई में धीरे-धीरे किन्तु सतत रूप से हो रही वृद्धि और आगामी दशकों के अत्यन्त आवश्यक कामों के लिए प्रशिक्षण पा रहे युवकों की गलत शिक्षा से इन समस्याओं और कठिनाइयों में और भी वृद्धि हो रही है।

आज जब अमेरिकन जनता अपने समाज के सामने फैले नये विस्तृत सीमान्त की ओर नजर डालती है तब उसे ये और इसी तरह की दूसरी समस्याएँ मुँह बाये खड़ी दिखाई देती हैं। यदि ये समस्याएँ स्वयं अमेरिकनो की ही पैदा की हुई हो तो वे समाधान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उनकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। युद्धोत्तरकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना शायद यह है कि आज लोगों ने उपभोक्तृओं, प्राइवेट व्यवसायियों और सरकार तीनों के बीच समन्वय की अनिवार्यता को भली भाँति महसूस कर लिया है। उन्होंने यह सत्य भी अच्छी तरह हृदयगम कर लिया है कि समाज के इन तीनों वर्गों की अपनी विशिष्ट शक्तियाँ और क्षमताएँ हैं, जिनसे वे आर्थिक व्यवस्था में शेष दोनों के योग की कमी पूरी कर सकते हैं।

नये क्षेत्रों में प्रवेश एक ऐसा साहसपूर्ण अभियान है जिसमें हर अमेरिकन

अपनी योग्यता के अनुसार भाग लेगा। जब ससार में सभी जगह जनता भौतिक प्रगति की ओर जमकर पग बढ़ाने लगेगी, तब इतिहासकार शायद यह कहेंगे कि विश्व की इस प्रगति में अमेरिकन जनता ने एक विशिष्ट योगदान किया और वह योगदान यह है कि उसने व्यक्तिगत उद्यम और अभिक्रम को तुलनात्मक दृष्टि से अन्य प्रणालियों से अधिक मूल्यवान् सिद्ध कर दिया।

यह है प्रगति की सतत और अनवरत दौड़ में उठने वाली नित्य नूतन समस्याओं का सामना करने की अमेरिकन पद्धति की अतीत, वर्तमान और भविष्य की रोमांचक कहानी।